{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 1 जुलाई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

पुलिस राज की शुरुआत

पिछली लोकसभा में पारित नये कानूनों के सोमवार से लागू होने के साथ ही भारत में नये सिरे से पुलिस राज की शुरुआत हो रही है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के विकसित व लोकतांत्रिक देशों की सरकारें अपने नागरिकों को अधिक आजाद और अधिकार सम्पन्न कर रही हैं, भारत को 'लोकतंत्र की जननी' कहने वाली सरकार ने जिस न्याय संहिता को लागू करने का ऐलान किया है, उससे नागरिकों पर पुलिस के जरिये उसका सख्त पहरा बैठ जायेगा। उसकी आजादी को जैसा बड़ा खतरा नयी न्याय संहिता से होने जा रहा है, वैसा पहले कभी नहीं रहा।

अनेक पुराने कानूनों को हटाकर या बदलकर औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के नाम पर भारतीय दण्ड संहिता में व्यापक फेरबदल कर दिये गये हैं जिनसे जहां एक तरफ काफी समय तक व्यवहारिक दिक्कतें तो आयेंगी ही, पुलिस दमन की राहें भी खुल जायेंगी। अनेक न्यायविद एवं वकालत के पेशे में रहने वाले भी इस परिवर्तित संहिता से खौफ़ज़दा दिख रहे हैं। उनका मानना है कि नये कानून पुलिस के हाथ मजबूत करेंगे और नागरिकों को न्याय मिलने की आशाएं धूमिल हो जायेंगी। न्याय पाना और भी कठिन हो जायेगा, जो पहले से दुरुह है। भारत के सन्दर्भ में पहले ही कहा जाता है कि यहां की न्यायिक प्रक्रिया अपने आप में सज़ा पाने से कम नहीं है, जिसमें दोषी व निरपराध दोनों एक सरीखे पिसते हैं। सिर्फ पहुंच और पैसा राहत देता है- निर्दोष को भी, अपराधी को भी।

वैसे तो नये कानूनों को लेकर पहली आपत्ति यही की गई है कि अपराधों को दर्ज करने से लेकर मुकदमे चलाने सम्बन्धी धाराओं का अभ्यस्त होने में पुलिस अधिकारियों, वकीलों व जजों को काफी समय लग जायेगा। न सिर्फ समझना, बल्कि उसकी व्याख्या करना व कोर्ट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना अपने आप में बड़ी कवायद होगी, जिसका खामियाजा और किसी को नहीं वरन मामले के पक्षकारों को भुगतना होगा। पहले से लाखों की तादाद में न्यायालयों में लम्बित मामलों के ढेर बढ़ते जाने तय हैं। अब तक जिन धाराओं के अंतर्गत विभिन्न अपराधों को परिभाषित किया गया था, वे सभी सम्बन्धित एजेंसियों एवं पेशेवरों की जुबानों पर रटे हुए थे। अब इसके क्रमांक भी बदल दिये गये हैं। अनेक की परिभाषाएं एवं व्याख्याएं भी बदल गई हैं। इनकी सज़ाओं में भी बदलाव कर दिये गये हैं। पूरे पुलिस विभाग को अपराधों को पंजीबद्ध करने, वकीलों को उन्हें प्रस्तुत एवं न्यायपालिका को उन्हें समझकर न्याय देने में नयी माथापच्ची करनी पड़ेगी।

यह तो रहा नये कानूनों का व्यवहारिक पक्ष, लेकिन जिन इरादों के साथ ये कानून लाये गये हैं और जैसा उनका प्रभाव पड़ने जा रहा है, वह कहीं अधिक भयावह है। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को रखने की वैध मियाद को 15 दिनों से बढ़ाकर अब 90 दिनों तक कर दिया गया है। यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि अपराधी हों या निर्दोष, इन दोनों तरह की कस्टडियां किस तरह सभी के लिये एक जैसी नारकीय हैं। फिर, पुलिस लॉकअप हो अथवा जेलें- दोनों में क्षमता से अधिक आरोपी या सज़ायाफ़्ता रखे जाते हैं। मानव गरिमा के विपरीत परिस्थितियां तो उनमें पहले से मौजूद हैं, इस बात की कल्पना सहज की जा सकती है कि बढ़ी हुई संख्या में वे किस तरह से सलाखों के पीछे दिन काटेंगे। उन्हें जीवनावश्यक सुविधाएं मुहैया कराना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी।

'राजद्रोह' शब्द तो नयी न्यायिक संहिता से हटा दिया गया लेकिन बहुत से नये आधार बनाकर लोगों को जेलों में बगैर मुकदमा चलाना आसान तथा जमानत प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया है। देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों के खिलाफ लाये गये कानून अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को खामोश करने का बढ़िया ज़रिया बन जायेंगे। यह धारा लगाने का विवेकाधिकार भी अपेक्षाकृत निचले स्तर के अधिकारी के पास हो गया है। इनमें भी लम्बे समय तक जमानत न मिलने के प्रावधान कर दिये गये हैं। इसका अनुमान लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि जिस सरकार ने विपक्षी नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, ट्रेड यूनियन व किसान संगठनों के नेताओं आदि के खिलाफ पहले से एक अभियान जैसा छेड़ रखा है उसका व्यवहार ये काले कानून हाथ में लग जाने के बाद कैसा होगा। जिस गैरकानूनी गतिविधियां (प्रतिबंध) कानून यानी यूएपीए के चलते न जाने कितने मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी लम्बे समय से जेलों में सड़ रहे हैं, सरकार के हाथ नये कानूनों से और भी ताकतवर हो जायेंगे। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इसके जरिये परम्परागत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त स्वतंत्र मीडिया (सोशल) का गला घोंटना भी आसान हो जायेगा। सरकार विरोधी खबरों, रिपोर्ताज या समीक्षाओं को देश की एकता-अखंडता के लिये खतरा बतलाकर ऐसे पत्रकारों तथा मीडिया संस्थानों को सरकार द्वारा डराना बेहद आसान हो जायेगा।

याद हो कि पिछली लोकसभा के अंतिम दिनों में ये कानून एक सुनियोजित षडयंत्र के अंतर्गत पास कराये गये थे। पहले दोनों सदनों के तकरीबन डेढ़ सौ सांसदों को निलम्बित कराया गया तत्पश्चात केवल सत्ता पक्ष या गिनती के विरोधी दलों के सदस्यों की उपस्थिति में ये कानून पारित किये गये। नोटबन्दी, जीएसटी, कृषि कानून, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पीएम केयर फंड आदि की ही तरह इस पर न तो पर्याप्त चर्चा हुई और न ही न्यायविदों व कानून विशेषज्ञों की राय ली गई। सरकार निश्चित ही जानती रही होगी कि नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ होगा।

विश्व गुरु करते कुछ नहीं बस विश्व गुरु हैं!

हम तो देश के एंगल से बात करते हैं। मोदी जी ने दस साल गंवा दिए। न नेहरू और इन्दिरा गांधी की तरह बड़े-बड़े काम किए। देश के नवनिर्माण के। और न ही वह अन्य काम जो आसान थे। केवल हिन्दू-मुसलमान किया मगर उससे क्या हुआ?

देश ने कौन सी तरक्की कर ली। लोगों को रोजगार मिल गए। महंगाई कम हो गई। और हिन्दू-मुसलमान क्या नफरत और विभाजन की राजनीति का अंत है? नहीं यह तो शुरूआत थी। बात उसके बाद दलित आदिवासी और ओबीसी तक आ गई है। धर्म के बाद जातियों में और फिर प्रदेशों में हर जगह नफरत और विभाजन फैल गया है।

क्रिकेट जो भारत को जोड़ता था उस तक में पहुंच गया। भारत टी-20 का वर्ल्ड कप जीता। पूरा देश खुशी से पागल हो गया। मगर जो पहले से पागल थे इसमें जाति और प्रदेश ढूंढने लगे। सूर्यकुमार यादव ने एक बहुत मुश्किल कैच पकड़ा। ठीक बाउन्ड्री पर। क्रिकेट खेले लोग जानते हैं उस गति में एक साथ दो काम करना कैच पकड़ना भी और पांव को बाउन्ड्री लाइन से बाहर जाने देने से रोकना कठिन प्रक्रिया होती है। करने से नहीं होती अपने आप जो अच्छा खिलाड़ी होता है उससे होती है। हो जाती है।

यादव ने वर्ल्ड कप जीता दिया। हेडिंग यही थी। मगर नफरत की राजनीति ने इन दिनों यादवों को निशाने पर रख लिया है। इसलिए कहा जाने लगा कि पंड्या के ओवर ने मैच जिताया। पंड्या गुजरात का है इसलिए उसे और समर्थन मिला। अच्छी बात है। सबके योगदान की चर्चा होना चाहिए। मगर सूर्यकुमार यादव ने मैच छीन लिया। असली हीरो वही है और पूरी भारतीय टीम।

1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव ने भी ऐसा ही अविस्मरणीय कैच लिया था। पूरी टीम की जय जयकार हुई थी। इन्दिरा गांधी का जमाना था। मगर किसी ने इन्दिरा गांधी को श्रेय नहीं दिया। इन्दिरा जी के तो लेने का सवाल ही नहीं। उन्होंने तो कभी भारत के पहले परमाणु परीक्षण, अंतरिक्ष में भारतीय यात्री राकेश शर्मा के जाने, बांग्ला देश बनाकर दुनिया का भुगोल बदलने, हरित क्रान्ति करके देश के गोदाम अनाज से भरने, राजा रानी के प्रिवीपर्स प्रिवलेज खत्म करके देश के आम आदमी को उनके बराबर खड़ा करने, बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके उन्हें गरीबों के लिए खोलने और ऐसे ही जाने कितने बड़े-बड़े काम करने का भी कभी श्रेय नहीं लिया।

मुझे ईश्वर ने भेजा है इन कामों को करने के लिए या संसद में छाती ठोककर सब पर भारी जैसे बड़बोलेपन का तो सवाल ही नहीं उठता इसीलिए जब 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो देश में कहीं जाति, धर्म, प्रदेश की बात ही नहीं थी। नफरत फैलाई ही नहीं गई थी तो नफरत विभाजन की बात कोई कैसे करता? समकालीन परिस्थितियों से ही आदमी बनता है तो कपिल उस समय की मिलीजुली संस्कृति प्रेम, सद्भाव से निकले खिलाड़ी थे। कप लाने के बाद इन्दिरा जी जब उनसे मिलीं तो दोनों एक दूसरे को थैंक्यू कह रहे थे।

प्रधानमंत्री कहीं से नहीं लग रहीं थी कि वे इन खिलाड़ियों से बड़ी हैं। आज तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी जी की वजह से टीम जीत गई। यह नफरत और विभाजन के साथ अहंकार की राजनीति भी है। इन सबसे बचना एक बड़े नेता का काम होता है। तभी वह देश के लिए कुछ कर पाता है। नेहरू और इन्दिरा गांधी ने ऐसे ही किया था।

शकील अख्तर

दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है। राज्य सरकार किसी की हो केन्द्र सरकार अपने उप राज्यपाल के माध्यम से चलाती है और जिस लूटियन जोन में मंत्रियों और सांसदों के बंगलों में पानी भरने के फोटो हैं वह इलाका नई दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (एनडीएमसी) के अन्तर्गत आता है। और एनडीएमसी पूरी तरह केन्द्र सरकार के आधीन होती है। दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण हो तो डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। विदेशी दूतावासों सहित।

मगर जैसे कि हमने शुरू में लिखा कि बड़े काम तो छोड़िए दूसरे काम जो वे आसानी से कर सकते थे वह भी नहीं किए। इन दूसरे कामों में हमें हमेशा याद आता है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया मोदी जी का स्वच्छता अभियान। हमने उसी दिन लिखा था इस पर। कुछ संदेहों के साथ मगर फिर भी आशावाद के साथ कि अगर मोदी जी ने इसे प्रतीकात्मकता तक ही सीमित नहीं रखा तो भारत बदल जाएगा। एक साफ सुथरा आगे बढ़ता हुआ भारत होगा। मगर हमारी राजनीतिक समझ सही निकली। हम चाहते थे कि मोदी जी उसको गलत साबित कर दें। मगर नहीं किया। जो भाजपा की राजनीति है टोकनिज्म की प्रतीकात्मकता की वही किया। झाडू के साथ नए-नए पोज, कूड़ा उठाने का अभिनय और नतीजा गदंगी और बढ़ती चली गई।

जी हां प्रतीकात्मक राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है जितना काम हो रहा है वह भी फिर नहीं होता। सब प्रतीकात्मकता में मतलब दिखावे में उलझ जाते हैं। और उसी को काम भी समझ लेते हैं। जो सामान्य तौर पर हो रहा होता है वह भी कम या बंद हो जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण महिला सुरक्षा है।

2014 में चुनाव ही यह कहकर जीते थे अब नहीं नारी पर वार अबकी बार मोदी सरकार। मगर उसके बाद क्या हुआ? खुद की पार्टी के विधायक सेंगर से लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह तक ने क्या किया? पीड़ितों का साथ किस ने दिया? उल्टा उन्हें और प्रताड़ित किया गया। मणिपुर जैसी वीभत्स नारी विरोधी घटना के बाद भी मोदी मणिपुर नहीं गए। उल्टे दूसरी जगहों के उदाहरण देने लगे कि वहां भी तो होते हैं। हाथरस दलित लड़की मर गई उसकी लाश तक घर वालों को नहीं दी। उल्टे उसके घर के सामने महीनों घरना प्रदर्शन किए गए। प्रतीकात्मकता इस तरह से मूल समस्या पर से लोगों का ध्यान हटा देती है। और नारे भाषण में उन्हें उलझा देती है।

जब इससे भी काम न चले तो उसने यह नहीं किया वह नहीं किया की तरफ लोगों का ध्यान ले जाते हैं। काम करने के छोटे होते हैं। मगर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले, दोष दूसरों पर डालने वाले वह सामान्य काम भी नहीं करते। उन्हें सबसे आसान लगता है पर निंदा। छिद्रान्वेष।

बरसात हर साल होती है। जलभराव की समस्या भी। मगर इस तरह की तुलनाएं कोई नहीं करता। जैसी अब देख रहे हैं। हरिद्वार से लेकर देश में कई जगह गाड़ियां डूब रही हैं। मगर मीडिया भक्त कह रहे हैं दिल्ली का हाल देखो। दिल्ली का हाल बुरा है। मगर उसका पूरा दोष केजरीवाल पर रखना और बुरा।

दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है। राज्य सरकार किसी की हो केन्द्र सरकार अपने उप राज्यपाल के माध्यम से चलाती है और जिस लूटियन जोन में मंत्रियों और सांसदों के बंगलों में पानी भरने के फोटो हैं वह इलाका नई दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (एनडीएमसी) के अन्तर्गत आता है। और एनडीएमसी पूरी तरह केन्द्र सरकार के आधीन होती है।

दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण हो तो डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। विदेशी दूतावासों सहित। मगर इसका हल करने के बदले केजरीवाल पर तोहमतें लगाना शुरू हो जाता है। अरे केजरीवाल भी आपका ही था। संघ भाजपा केजरीवाल सब ने मिलकर एक नकली आंदोलन किया था। एक मुखौटे अन्ना हजारे को सामने रखकर।

इतने ताकतवर प्रधानमंत्री जिनके बारे में मीडिया और भक्तों के साथ भाजपा के मंत्री नेता भी कहते हैं कि उन्होंने रुस युक्रेन युद्ध रुकवा दिया था। और यह तो खुद मोदी जी ने कहा कि उन्होंने रमजान में गाजा में युद्ध रुकवा दिया। उन्होंने जल निकास, दिल्ली का प्रदूषण और जिस का सबसे पहले जिक्र किया सफाई, नारी सुरक्षा जैसे काम नहीं किए। पेपर लीक तक पर बात नहीं की। नीट के पेपर लीक ने देश के स्टूडेंटों को सबसे बड़ा सदमा पहुंचाया है। इस किशोर और युवा उम्र में उन्हें संदेश गया कि देश में मेहनत और ईमानदारी से कुछ नहीं होता है। नेहरु, इन्दिरा, राजीव गांधी छात्र युवा में उत्साह भरते थे। ये छात्र युवा को निराश हताश कर रहे हैं।

कोई काम नहीं। न छोटे न बड़े। केवल बातें। पचास साल पुरानी इमरजेन्सी उससे पहले 75 साल पहले नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बन गए। और पहले मुगल काल की अकबर ने यह यह नहीं किया। शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया? गए तो यह त्रेता युग में भी हैं कि राम को हम लाए। मगर बस दस साल में क्या किया इसी पर नहीं आते हैं। खुद को विश्व गुरु कह देते हैं। बस सब मान जाते हैं। मगर विश्व गुरु करते क्या हैं? क्या किया यह कोई नहीं पूछता?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

मोदी 3.0 सरकार 1 जुलाई से पहली अग्निपरीक्षा से गुजरेगी

■ डॉ. ज्ञान पाठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल (मोदी 3.0) में1 जुलाई से पहली अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के क्रियान्वयन की तिथि एक जुलाई से ही निर्धारित की गई है। देश भर में राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है और भारत की संसद द्वारा व्यापक समीक्षा की मांग की जा रही है, जहां देश के लोगों ने अभी-अभी बहुत मजबूत विपक्ष को चुनावों में जिताकर भेजा है।

ये कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) की जगह लेंगे। देश भर के राज्यों के बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों की ओर से कई ज्ञापन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को भेजे गए हैं, जिसे बीसीआई ने 26 जुलाई को पारित अपने प्रस्ताव में स्वीकार किया है, जिसमें तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ कड़ा विरोध व्यक्त किया गया है और जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता या निलंबित नहीं किया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने की उनकी मंशा का संकेत दिया गया है, जिसमें भारत की संसद द्वारा व्यापक समीक्षा सहित गहन राष्ट्रव्यापी चर्चा शामिल है।

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तीन कानूनों को लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस विचार को छोड़ना पड़ा क्योंकि कानूनों ने पूरे देश में कड़ा प्रतिरोध और विरोध ने आकर्षित किया। अधिसूचना के एक सप्ताह बाद ही, देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने नये आपराधिक कानूनों के कुछ प्रावधानों के खिलाफ तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। पूरे देश को आपूर्ति में अभूतपूर्व व्यवधान का सामना करना पड़ा।

यह याद रखने योग्य है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में लगभग पूरे विपक्षी सदस्यों को निलंबित कराकर लोकसभा में तीन आपराधिक कानूनों पर किसी भी सार्थक चर्चा से सफलतापूर्वक परहेज किया था। इन्हें 21 दिसंबर को पारित किया गया, सरकार ने 25 दिसंबर, 2023 को जल्दबाजी में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की और उसी दिन अधिसूचित किया।

गृह मामलों पर विभागीय संसदीय स्थायी समिति के विपक्षी सदस्यों ने अंतिम रिपोर्ट में अपनी असहमति दर्ज कराई थी, हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा लगभग पूरे विपक्ष को लोकसभा से निष्कासित करने की कार्रवाई के बाद मोदी सरकार ने भारत की संसद में बहुमत के बल पर इन कानूनों को पारित करवाया था। हाल ही में, विपक्ष ने इन तीनों कानूनों की संसदीय समीक्षा की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर आग्रह किया है कि केंद्र को इन कानूनों को लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्हें अनुचित जल्दबाजी में पारित किया गया था। उन्होंने इनकी व्यापक संसदीय समीक्षा की मांग भी की। हालांकि, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र ने कहा है कि वह 1 जुलाई, 2024 से तीनों आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से और व्यापक रूप से तैयार है। अब तक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किये हैं, जिसके तहत अब देश के हर पुलिस स्टेशन में सभी मामले दर्ज किये जाते हैं। एनसीआरबी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नयी प्रणाली लागू करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने तीन ऐप विकसित किए हैं- ई-सक्ष्य, न्यायश्रुति और ई-समन - जो अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, न्यायिक सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती समन की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेंगे।

शुरू में, मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तीन कानूनों को लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस विचार को छोड़ना पड़ा क्योंकि कानूनों ने पूरे देश में कड़ा प्रतिरोध और विरोध ने आकर्षित किया। अधिसूचना के एक सप्ताह बाद ही, देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने नये आपराधिक कानूनों के कुछ प्रावधानों के खिलाफ तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। पूरे देश को आपूर्ति में अभूतपूर्व व्यवधान का सामना करना पड़ा, जिसने 2 जनवरी, 2024 को हड़ताल के दूसरे दिन केंद्र को यह महसूस करने के लिए मजबूर किया कि तीन नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन का सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान पर बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ना तय है। इसने घोषणा की कि परिवहन क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों को तब तक लागू नहीं किया जायेगा जब तक कि आंदोलनकारी अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के साथ उन पर चर्चा नहीं की जाती। केंद्र और ट्रक चालक संघ के साथ बातचीत के बाद, परिवहन कांग्रेस ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन उस हड़ताल ने यह स्पष्ट कर दिया कि तीन नये आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन भानुमति का पिटारा साबित होगा, जिसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, जो कार्यान्वयन के दौरान सामने आयेंगी।

भारतीय बार (वकील समुदाय) को विनियमित करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने 26 जून के अपने प्रस्ताव में, अब पूरे भारत में बार एसोसिएशनों और राज्यों की बार काउंसिलों से अनुरोध किया है कि वे नये आपराधिक कानूनों के खिलाफ इस समय किसी भी तरह के आंदोलन या विरोध से दूर रहें, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि वह केंद्रीय गृहमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली केंद्र सरकार के साथ चर्चा शुरू करेगी, ताकि उनकी चिंताओं से अवगत कराया जा सके।

बीसीआई ने कानूनी बिरादरी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है, जिसमें उनकी धारणा है कि इन नये आपराधिक कानूनों के कई प्रावधान जनविरोधी हैं, औपनिवेशिक काल के उन कानूनों से भी अधिक कठोर हैं जिन्हें ये नये कानून बदलने का इरादा रखते हैं, और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर के बार एसोसिएशनों ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों की नये सिरे से जांच करने का आह्वान किया है, क्योंकि ये कानून भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार के सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। बीसीआई ने देश के सभी बार एसोसिएशनों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे नये आपराधिक कानूनों के विशिष्ट प्रावधानों को प्रस्तुत करें जो असंवैधानिक या हानिकारक हैं ताकि वह केंद्र के साथ एक उत्पादक बातचीत शुरू कर उनमें आवश्याक सुधार सुनिश्चित करवा सके। सुझाव प्राप्त होने पर, बीसीआई इन नये आपराधिक कानूनों में आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पूर्व न्यायाधीशों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की एक समिति गठित करने का इरादा रखता है।

बीसीआई ने बार एसोसिएशनों और राज्यों की बार काउंसिलों को आश्वासन दिया है कि उनके द्वारी उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस बीच, इन तीन आपराधिक कानूनों के खिलाफ 27 जून को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें इन तीन नये कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन करने और उनकी पहचान करने के लिए तत्काल एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए विशिष्ट निर्देश देने और उनके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने इन आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के खिलाफ 1 जुलाई का काला दिवस के रूप में विरोध करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वकील विरोध में सभी न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। देश भर में कई और विरोध प्रस्ताव पारित होने की संभावना है, हालांकि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने संयुक्त संसदीय संबोधन के दौरान कहा है कि ये कानून सजा के बजाय न्याय प्रदान करेंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

गुरवाणी विचार

कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साह

नानक ओखरे मना सुणिये सिख सही
लेखा रन मंगेसिया बैठा कड़ वही
तलवां घौसन आकिंया बाकी जिना रही
अजराइल फरेसत होसी आये लई
कुड़ि निखुटे नानका ओड़का सच रही।

यह शब्द गुरू ग्रंथ साहिब के पन्ना 963 ले लिया गया है इसमें गुरुनानक देव जी मानव मन समझाइश दे रहे हैं कि ऐ मानव, इस लोक में भेजने से पहले जितनी तुझे परमात्मा ने श्वांसों की पूंजी दी थी वह खत्म हो जाने पर तुझे वापस उस प्रभु परमात्मा के पास जाना है। वहां तुझ से उन्हें दी गई श्वांसों का हिसाब मांगा जाएगा जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को कुछ पूंजी देकर व्यापार करने के लिए भेजता है और कुछ दिन बाद जब वह पुन: कमा कर वापस आता है तो उसे शाबासी मिलती है और अगर गंवाकर आता है तो उसे पिता की डांट-फटकार सहनी पड़ती है। ज्यादा नुकसान कर आने पर हो सकता है पिता उसे घर से भी बाहर कर दे। मां कोई छोटा मोटा काम करने को मजबूर कर देवे ठीक इसी प्रकार जब जीत परमात्मा के दरबार में पहुंचता है तो वहां पर धर्मराज तेरे द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब किताब देखता है। वहां पर अगर तू ने कोई अच्छा कार्य न किया होगा तो तुझे आरी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और तुझे धर्मराज बहुत ही कष्ट देगा और वहां पर यमदूतों की मार से तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा और तेरे द्वारा किए गए पापों का फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा। क्यों कि वहां पर

उथे अमला दे होंगे। निबेड़े, ते जात किसे पुछनी नहीं।

वहां पर सिर्फ तेरे किए गए कर्मों के अनुसार फैसला होगा। ऊंच-नीच, जात-पांत, रंगभेद पर कोई विचार नहीं होगा। इसलिए प्राणी इस जनम को अकारण मत गंवा और भगवन भजन करते रहा कर जिससे तेरे पुण्यों का खाता बढ़ जाएगा। और वहां पर तुझे मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेगा। गुरु तेग बहादुर साहिब जी इस बात को समझा रहे गै कि-

राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछतायेगा।
पापी जीवड़ा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा।
सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटां खायेग
धर्मराज जब लेखा मांगे किया मुख लेकर जाएगा।

सार बात यही है कि समय रहते परमात्मा की भजन बंदगी कर ले सिमरन कर ले, साध संगत में जाकर भगवद भजन सुना कर। उठते बैठते परमात्मा का ध्यान किया कर परमात्मा के बनाए हुए समस्त जीव-जंतुओं से प्रेम का व्यवहार किया कर। दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की भलाई में अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर इनकी भलाई में खर्च किया कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मन को हटा कर परमात्मा भजन में लगाए रखा कर जिससे तेरे पुण्यों का बैलेंस बढ़ जाएगा और इस लोक में सुख से रहकर परलोक में भी सुख से रह सकेगा इसलिए फिर कहता हूं कि जब तक श्वांस है परमात्मा का भजन सिमरन करते रहो।

कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साह।

इंदर सिंह आहुजा

आपके पत्र

चिकित्सकों को कलम और कैमरों का शिकार न बनाएं

मानवीय समाज में ऐसा कोई पेशा नहीं जिसे कमतर आंका जा सके। हर पेशा अपनी महत्ता जरूरत पर सिद्ध कर दिखाता है। हम मानवों के बीच एक ऐसा पेशा भी है , जिसे सभी पेशों से अलग और अत्यंत ही जिम्मेदार माना जा सकता है। जी हां! मैं बात करना चाहता हूं हमारे मानवीय समाज के ऐसे ही पेशे से जुड़े डॉक्टर्स की। मैंने अनुभव किया है लंबे और तनावपूर्ण काम के घंटे, डॉक्टर्स की नौकरी और मरीजों के प्रति उनके जुनून को जो उन्हें अधिक जवाबदार श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। यह भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स को खुद के लिए खाली समय निकालने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कारण यह कि उन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा देखभाल और मरीजों को उपचार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। यही कारण है कि अवकाश, विश्राम और परिवार के लिए समय देने में उनका पेशा उन्हें सीमित करता रहा है।

डॉक्टर को उसके द्वारा दी जा रही सेवा के लिए उसके मरीज अथवा परिवार द्वारा उपहार भी दिए जाते हैं। इन उपहारों का स्वरूप अन्य अवसरों पर दिए जाने वाले उपहारों से पृथक होता है। जब एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होकर अपने घर लौटता है, तब उन परिवारों द्वारा डॉक्टर को धन्यवाद और कृतज्ञता के रूप में जो टिप्स प्राप्त होते हैं वे किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होते। यही तोहफे उन्हें अधिक सेवा के प्रति ऊर्जा प्रदान करते हैं। हर एक बार जब कोई डॉक्टर किसी जटिल बीमारी के इलाज का जिम्मा लेता है तो उसके पेशेवर विकास के अवसर उसके भविष्य के दरवाजे पर दस्तक देते दिखाई पड़ते हैं। इस तरह की चुनौती डॉक्टर के पेशे को विकसित करने और उसमे गुणवत्ता हासिल करने के लिए जरूरी समझी जानी चाहिए। वास्तव में गंभीर रूप से चिंतन किया जाए तो चिकित्सकीय पेशा सम्मान का हकदार है। हम कह सकते हैं कि चिकित्सक हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कारण यह कि पूरा मानवीय समाज उनकी सेवाओं पर ही निर्भर है।

हम और हमारा समाज इस बात को जानता है कि वर्तमान में चिकित्सक के पेशे को लेकर किंतु -परंतु वाली स्थिति सामने आती रही है। एक सफल अथवा समर्पित चिकित्सक उसे ही माना जाता है जो अपने मरीज की समस्याओं को सुने और उस पर चिंतन करे। मरीज के लक्षणों के आधार पर इलाज का मार्ग तलाशना भी अच्छे चिकित्सक की पहचान माना जाता है। एक डॉक्टर जो अभी-अभी अपना पेशा शुरू कर रहा है उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं - हर कदम पर आपके फैसलों पर सवाल उठाए जायेंगे। यह एक डॉक्टर के जीवन में बड़ी निराशा होगी कि उनके पेशेवर जीवन में हर दिन उनके इरादों पर सवाल उठाए जाते रहें। अनेक बार ऐसी भी स्थिति आती है जब मरीज और डॉक्टर के बीच तनाव कायम हो जाते हैं। मामला यहां तक पहुंच जाता है कि डॉक्टर को अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर के सिर पर लटकी इस तरह की तलवार को मैं सर्वथा अनुचित समझता हूं। कारण यह कि कोई भी चिकित्सक अपनी ओर से बीमार व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता क्योंकि उसका पेशा ऐसा है जो पीड़ित को राहत देने के साथ उसे बुलंदियों पर पहुंचाता है। हमारे देश में प्राय: डॉक्टर्स को बदनाम किया जाता है। छोटी सी चूक हुई नहीं कि मीडिया अपने कैमरे और कलम लिए तैयार रहता है कि कैसे डॉक्टर को कटघरे में लाया जाए। बिना यह जानें और समझे कि त्रुटि डॉक्टर से हुई है या फिर स्वयं मरीज ने डॉक्टर की सलाह के परे अपनी स्थिति को बिगाड़ा है? यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि मीडिया में शामिल कुछ लोग अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर कमरे में सबसे ऊंची आवाज बनने की कोशिश करते है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग यह नहीं समझते कि डॉक्टर्स अराजकतावादी नहीं होते हैं। वे विरोध प्रदर्शन करने और लाठी चार्ज का सामना करने के बजाय मरीजों का इलाज करने में अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अपवाद कहां नहीं होते? इतने बड़े चिकित्सा समाज में कुछ लोगों की लापरवाही अथवा अनदेखी की सजा पूरे कुनबे को देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता है।

डॉ. सूर्यकांत मिश्रा

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

एक पेड़ मांके नाम

लोकसभा चुनावोंके कारण लगभग चार महीनेके अन्तरालके बाद रविवारको रेडियो कार्यक्रम 'मनकी बात' के १११वें एपिसोड और अपनी सरकारके लगातार तीसरे कार्यकालके पहले एपिसोडमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने देशवासियों और चुनाव आयोगको धन्यवाद दिया और कहा कि जनताने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थापर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। २०२४ का चुनाव दुनियाका सबसे बड़ा चुनाव था। दुनियाके किसी भी देशमें इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ, जिसमें ६५ करोड़ लोगोंने अपने मताधिकारका इस्तेमाल किया है। 'मनकी बात' में प्रधान मंत्रीने हूल दिवस, रथयात्रा-अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियाके हिन्दी शो, ओलम्पिक खेलों सहित अनेक विषयोंकी चर्चा की लेकिन सबसे बड़ी भावपूर्ण अपील 'एक पेड़ मांके नाम' लगानेकी की और कहा कि हम मांको कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने दुनियाके लोगोंसे अपील की है कि एक पेड़ मांके नाम जरूर लगायें। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपसे पूछूं कि दुनियाका सबसे अनमोल रिश्ता कौन-सा होता है तो आप जरूर कहेंगे 'मां'। हम सबके जीवनमें 'मां' का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर अपने बच्चेका पालन-पोषण करती है। हर मां अपने बच्चोंपर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मांका यह प्यार हम सबपर एक कर्जकी तरह है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। हम मांके नाम एक पेड़ लगाकर उनके लिए कुछ जरूर कर सकते हैं। इसी सोचसे इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवसपर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियानका नाम है 'एक पेड़ मांके नाम' मैंने भी एक पेड़ अपनी मांके नाम लगाया है। पूरे विश्वकी जनतासे प्रधान मंत्री मोदीकी यह अपील न केवल भावपूर्ण है अपितु मानव और सभी जीव-जन्तुओंकी प्राणरक्षाके लिए आवश्यक भी है। पूरा विश्व जलवायु परिवर्तनसे उत्पन्न हालातकी विभीषिकासे पूरी तरह ग्रसित है। अंधाधुन्ध पेड़ोंकी कटाईसे स्थिति और भी भयावह हो गयी है। इसलिए हर क्षेत्रमें अधिकसे अधिक पेड़ लगानेकी जरूरत है जिससे कि प्राण वायुका संकट उत्पन्न न हो सके। हर नागरिकका गुरुतर दायित्व है कि वह प्रकृतिका दोहन बंद करे और पर्यावरणके संरक्षणके लिए प्राणप्रणके साथ आगे आये। एक पेड़ मांके नाम लगानेके साथ ही उसका संरक्षण और पालन-पोषण भी उसी तरहसे होना चाहिए जिस तरहसे मां अपने बच्चोंका भरण-पोषण करती है और बच्चोंपर अपने प्यार और स्नेहकी वर्षा करती है। पेड़ लगानेके महाअभियानको आन्दोलनका रूप देना होगा जिससे धरतीपर हरित क्षेत्रका विस्तार हो सके। इस संकल्पको साकार करनेमें जन-जनकी सहभागिता आवश्यक है तभी हमारा और अगली पीढ़ीकी जीवन रक्षा सम्भव है।

लद्दाखमें सैनिकोंकी शहादत

अभ्यासके दौरान नदीमें टैंक डूबनेसे एक जेसीओ समेत पांच जवानोंकी शहादत देशकी अपूर्ण क्षति है। देशको मर्माहत कर देनेवाला यह हादसा शनिवारको उस समय हुआ जब पूर्वी लद्दाखमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सेनाका टी-७२ टैंक श्योक नदीमें अचानक आयी बाढ़में डूब गया। इस हादसेमें एक जेसीओ समेत पांच जवान शहीद हो गये। सेनाने सभी जवानोंके शव बरामद कर लिये हैं। यह दुर्घटना गलवान घाटीके पास दौलत बेग ओल्डीमें हुई। इसी घाटीमें २०२० में चीनने घुसपैठ की थी, जहां भारतीय सैनिकोंने चीनी सैनिकोंको अविस्मरणीय सबक सिखाया था। वैसे तो यह एक प्राकृतिक आपदा लगता है लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि अचानक बाढ़ कैसे आयी, क्योंकि गलवान घाटीमें घुसपैठके दौरान दोनों देशके सैनिकोंके बीच द्वन्द्व युद्धके बादसे ही सैन्य तनाव जारी है और चीन इसका बदला लेनेके लिए किसी भी स्तरतक जा सकता है, इसलिए इस घटनामें चीनकी किसी गहरी साजिशकी आशंकासे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस समय दौलत बेग ओल्डीमें सेनाकी ५२ आर्म्ड रेजिमेण्टका युद्धाभ्यास जारी है। इसीके तहत एक अभियानमें शामिल टी-७२ टैंकके साथ पांच सैन्यकर्मियोंका दस्ता लौट रहा था उसी दौरान यह हादसा हुआ। इसके पूर्व भी पूर्वी लद्दाखमें सासेर ब्रांगसाके पास विगत २८ और २९ जूनको मध्यरात्रिको सैन्य अभ्याससे लौट रहा सेनाका एक टैंक श्योक नदीमें अचानक जल स्तर बढ़नेसे फंस गया था। ऐसा दूसरी बार हुआ जब सैन्य अभ्याससे लौट रहा सैन्य टैंक प्राकृतिक कहरकी चपेटमें आया। ऐसे प्राकृतिक आपदासे निबटनेके लिए सुरक्षाके व्यापक प्रबन्ध होना चाहिए। सैनिकोंकी शहादतसे आहत प्रधान मंत्री नरेनद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह और कांग्रेसके नेताओंने शोक संवेदना प्रकट की है। युद्धाभ्यासके बाद सैनिकोंके वापसीके समय ही नदीमें अचानक बाढ़ क्यों आती है, यह यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब मिलना चाहिए।

लोक संवाद

कुत्सित प्रयास

महोदय,-पचीस जून, १९७५ की काली रात हम कभी नहीं भूल पायंगे, जब सारा देश आपातकालके नामपर लोकतन्त्रकी नृशंस हत्या कर गुलामीकी जंजीरोंमें जकड़ा जा रहा था। गरीबी हटाओके खोखले नारोंसे १९७१ के लोकसभा चुनावमें विजयी रहनेके बाद, देशमें व्याप्त भ्रष्टाचारके कारण गुजरातमें चिमनभाई पटेलकी सरकारके विरुद्ध युवाओं द्वारा छेड़े गये नवनिर्माण आन्दोलनसे सत्ताधारी दल एवं व्यवस्थाकी चूलें हिल गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप विधानसभाके चुनाव कांग्रेस हार गयी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीके लोकसभा चुनावके समय की गयी अनियमितताओं तथा चुनाव जीतनेके लिए अपनाये गये भ्रष्ट तरीकोंके कारण समाजवादी नेता श्री राजनारायण जी द्वारा दायर चुनाव याचिकाको स्वीकार कर श्रीमती इंदिरा गांधीको छह वर्षके लिए चुनाव लड़नेसे अयोग्य करार दे दिया गया था। गुजरातके नवनिर्माण आन्दोलनकी तर्जपर बिहारमें अब्दुल गफ्फारकी सरकारके विरुद्ध छात्र युवा आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायणको सौंपा गया तथा आंदोलन सारे देशमें समग्र क्रांति आन्दोलनके रूपमें फैल गया। इन सभी घटनाओंके कारण श्रीमती इंदिरा गांधीने देशमें लोकतंत्रका गला घोंट कर जनताको मौलिक अधिकारोंसे वंचित कर दिया। राजनीतिक दलोंके नेताओं एवं कार्यकर्ताओंको मीसामें जेलके सींखचोंके पीछे डाल दिया गया। कचहरियोंको किसी सुनवाईका अधिकार नहीं था। न अपील, न वकील, न दलील, इमरजेंसीका मूल मंत्र था। आजादीकी लड़ाईके समय अंग्रेजों द्वारा रौलेट एक्ट जैसे कानून बनाये गये थे। उनसे ज्यादा अलोकतांत्रिक, फासीवादी कानून बनाकर प्रेसका गला घोंटा गया। अखबारमें छपनेवाला एक-एक शब्द सरकारी अधिकारीकी मंजूरीके बिना छप नहीं सकता था। कांग्रेसके बाबू जगजीवन राम तथा श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जैसे नेताओंकी जुबान भी बंद कर दी गयी थी। कांग्रेसके युवा तुर्क नेताओं श्री चंद्रशेखर, श्री मोहनधारिया तथा श्री कृष्णकांत जैसे नेताओं, जनसंघके श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोकदल तथा सीपीआई (एम) के नेताओंको भी बंदी बना लिया गया था। हजारों-लाखों लोकतंत्र चाहनेवाले एवं १९ महीने जेलके सींखचोंके पीछे रहे तथा लाखों कार्यकर्ताओंको पुलिसके अत्याचारका शिकार होना पड़ा। परिवार नियोजनके नामपर जबरन नसबंदी की गयी। २०२४ के लोकसभा चुनावमें संविधान बदलनेका झूठा प्रचार करनेवाले नेताओंकी दादी तथा उनकी पार्टी कांग्रेसने ४२वां संविधान संशोधन पारित कर डा. अम्बेडकर द्वारा बनाये संविधानकी आत्माको कुचल कर रख दिया। न्यायपालिकातकका मुंह बंद करनेका प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्टके तीन वरिष्ठतम न्यायधीशोंने पद त्याग दिया। कांग्रेस पार्टीके अध्यक्ष देवकांत बरुआ द्वारा इंदिरा इज इण्डिया और इण्डिया इज इंदिरा जैसे नारे लगाये गये। लोकनायक जय प्रकाश नारायण सरीखे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियोंपर अपनी कुर्सीको बचानेकी चाहमें अमानुषिक अत्याचार किये गये। आपातकाल कांग्रेस और नेहरु-गांधी परिवारकी तानाशाही प्रवृत्तिका जीवन्त उदाहरण है। लोकतंत्र बहालीकी लड़ाईमें हजारों-लाखों लोग स्वर्गसिधार गये, अपंग हो गये तथा व्यावसायिक दृष्टिसे समाप्त हो गये। आपातकालके २१ महीने कांग्रेस तथा गांधी-नेहरु परिवारकी तानाशाही प्रवृत्तिका जीता जागता उदाहरण है। संविधान बदलनेकी झूठी बात करने वाली पार्टी और परिवारने संविधानकी आत्मा कही जानेवाली प्रस्तावना (प्रींबल) तकको नहीं छोड़ा। उसमें भी आपातकालमें किये गये ४२वें संविधान संशोधन द्वारा नये शब्द जोड़े गये। जनताके मौलिक अधिकार समाप्त कर दिये गये थे। निर्धन आदिवासी तथा दलित समुदायमें युवाओंकी जबरन नसबन्दी की गयी। दिल्लीके तुर्कमैन क्षेत्रसे लगभग सात लाख गरीब लोगोंको बेघर कर दिया गया था। कांग्रेसकी तानाशाही प्रवृत्तिका परिणाम है कि विरोधी दलोंकी राज्य सरकारोंको अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत भंग कर दिया गया। लोकतंत्र भारतवासियोंकी नस-नसमें व्याप्त है। अमानुषिक अत्याचारोंके बावजूद १९७७ में पहला अवसर मिलते ही श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री संजय गांधीका सफाया हो गया। लाखों लोकतंत्र प्रहरियोंने संघर्ष करके देशको पुन: बाबा साहेब अम्बेडकरके संविधानको बहाल करनेमें सफलता प्राप्त की और देश आज विश्वगुरु बनने और विकसित भारत बननेकी ओर अग्रसर है। भारतीय इतिहासमें इमरजेंसी एक काला अध्याय है। इसने लोकतंत्रको खत्म कर दिया था लेकिन जागरूक जनताने प्रजातंत्रको बहाल कराया और यह आज भी फल-फूल रहा है। -**सुरेश भारद्वाज, वाया ईमेल।**

वेंकैया गारू-भारत की सेवा में समर्पित जीवन

❑ **नरेंद्र मोदी**

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक हमारे श्री एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है। वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। देश में उनके लाखों चाहते वाले हैं। मैं उनके सभी शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बधाई देता हूं। वेंकैया जी का 75वां जन्मदिवस एक विशाल व्यक्तित्व की व्यापक उपलब्धियों को समेटे हुये है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए।

राजनीति में अपने प्रारम्भिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आपमें एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है। वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है, जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला।

वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था। लेकिन उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं बीजेपी को मजबूत किया।

लगभग 50 साल पहले जब कॉंग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें लोकनायक जेपी को आंध्र प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए जेल जाना पड़ा। लोकतंत्र के लिए उनकी ये प्रतिबद्धता, उनके राजनीतिक जीवन में हर जगह दिखाई देती है। 1980 के दशक के मध्य में, जब महान एनटीआर की सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था, तब वे फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे।

1978 में आंध्र प्रदेश ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद, राज्य चुनाव में एनटीआर की लोकप्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। तब भी वे बीजेपी के विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में बीजेपी के लिए भविष्य के बीज बोये थे। युवा विधायक के रूप में ही, वे विधायी मामलों में अपनी दृढ़ता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित होने लगे। उनकी वाकपटुता, शब्दशैली और संगठन सामर्थ्य से प्रभावित होकर एनटीआर जैसे दिग्गज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। एनटीआर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वेंकैया गारू हमेशा की तरह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई, गांवों में जाकर सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े। उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। 1990 के दशक में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुये उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 में यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति, जो किशोरावस्था में अटल जी और आडवाणी जी के दौरों की तैयारी करता था, उनके लिए ये कितना बड़ा मुकाम था। पार्टी महासचिव के रूप में, उनका एक ही लक्ष्य था कि अपनी पार्टी को सत्ता में कैसे लाया जाए! उनका एक ही संकल्प था कि कैसे देश को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री मिले। दिल्ली आने के बाद, उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

कुछ ही समय बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे तो वो वेंकैया गारू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो वेंकैया गारू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना। उनकी इस पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था। क्योंकि, उसके पहले नेताओं के लिए दूसरे मंत्रालय पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन, वेंकैया गारू की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी- वह एक किसान पुत्र थे, उन्होंने अपने शुरुआती दिन गांवों में बिताए थे और इसलिए, अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह काम करना चाहते थे, तो वह ग्रामीण विकास था। उस समय एक मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी।

2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। शायद, वह उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए काम किया है।

2014 के उन शुरुआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे भी बहुत काम आया था। मैं उस समय दिल्ली के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। मेरा करीब डेढ़ दशक गुजरात में ही काम करते हुये बीता था। ऐसे समय में वेंकैया गारू का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। वो सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। साथ ही, जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात आती थी, तब वो नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नज़र आते थे। वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ये हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था। हम ये जानते थे कि वेंकैया गारू के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा। लेकिन साथ ही, हमें ये भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है। मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद किया तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है। उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ी। वह राज्यसभा के एक उत्कृष्ट सभापति थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा सांसदों, महिला सांसदों और पहली बार चुने गए सांसदों को बोलने का अवसर मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया, समितियों को अधिक प्रभावी बनाया। उन्होंने सदन में बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया।

जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय राज्यसभा के पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वह युवा जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, जब वह सपना पूरा हुआ तो वह सभापति के पद पर आसीन था। किसी निष्ठावान देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा!

काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। दिल्ली के लोगों के बीच, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो शहर में गौरवशाली तेलुगु संस्कृति लेकर आए। उनके द्वारा आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं। मैं वेंकैया गारू को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं। लेकिन, पिछले कुछ समय से उनका संयम भी सबके सामने दिखने लगा है। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि वह अभी भी बैडमिंटन खेलना और ब्रिस्क वॉक करना पसंद करते हैं।

उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी, वेंकैया गारू सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं। वह लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को मुझसे बात करते रहते हैं। हाल ही में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाक़ात हुई थी। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं।

विपक्ष समझे मतदाताकी चेतावनी

मजबूत विपक्ष लोकतंत्रको मजबूत बनाता है। इस बार लोकसभामें विपक्ष पिछली बारकी तरह इतना कमजोर नहीं है कि सरकार उसे हल्केमें ले सके। विपक्षको भी समझना होगा कि देशका मतदाता उससे भी बहुत अपेक्षाएं रखता है।

❑ **विश्वनाथ सचदेव**

अट्ठारहवीं लोकसभाका अधिवेशन प्रारंभ हो गया है। संसदमें सरकारकी नीति और नीयतको लेकर बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर सरकार और विपक्ष दोनों संविधानकी रक्षाकी दुहाई देकर आमने-सामने हैं। सदनके बाहर विपक्षके सांसद संविधानकी रक्षाके नारे लगा रहे थे और भीतर सत्तारूढ़ पक्ष भी यही बात कह रहा था। बात दोनों एक ही कर रहे थे, परन्तु संदर्भ अलग-अलग थे। ऐसेमें एक सामान्य नागरिकका असमंजस समझमें आनेवाली बात है। आखिर संविधानकी रक्षाका मतलब क्या है। मतलब यह है कि जिन मूल्यों और आदर्शोंको आधार बनाकर संविधानकी रचना की गयी थी, सांसद पूरी ईमानदारीके साथ उनका पालन करें। यह तो आनेवाला कल ही बतायेगा कि हमारे राजनेता कितनी ईमानदारीके साथ यह काम करते हैं, लेकिन संसदके इस अधिवेशनका आगाज बता रहा है कि अंजाम कुछ हल्लेदार ही होगा। शुरुआत प्रधान मंत्रीने कर ही दी है। सत्र प्रारंभ होनेसे पहले मीडियाको संबोधित करते हुए उन्होंने दो-तीन ऐसी बातें कही हैं जिनकी तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। मसलन उन्होंने यह दोहराना जरूरी समझा कि मतदाताने उनकी पिछली सरकारकी नीति और नीयतमें विश्वास प्रकट करके ही उन्हें लगातार तीसरी बार सरकार बनानेका दायित्व सौंपा है। बात यहींसे शुरू होती है। यह सही है कि लगातार तीसरी बार एनडीएकी सरकार बनी है परन्तु यह नहीं भूल जाना चाहिए कि पिछली दो पारियोंमें भाजपाका अपना स्पष्ट बहुमत था और सहयोगी दल भाजपाकी अनुकम्पासे ही सरकारका हिस्सा बन सके। इस बार स्थिति ऐसी नहीं है, भाजपा सबसे बड़ा दल जरूर है, परन्तु यह मिली-जुली सरकार बैसाखियोंके सहारे राज करेगी। इसलिए प्रधान मंत्रीको अपनी छवि बनाये रखनेके लिए समझौतावादी दृष्टिकोणके साथ काम करना होगा। यह रुख विपक्षके प्रति ही नहीं, अपने सहयोगी दलोंके प्रति भी अपनाना होगा। चन्द्रबाबू नायडूकी तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) और नीतीशकी जेडीयू कब क्या रुख अपना ले, कहा नहीं जा सकता। यह सही है कि फिलहाल इन दो दलोंकी भूमिकाको लेकर कोई आशंका नहीं है, परन्तु राजनीति संभावनाओंका खेल है। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि २०१९ में प्रधान मंत्री मोदीने एक सार्वजनिक सभामें नायडूपर व्यंग्य करते हुए उन्हें दल बदलनेमें और खुदके ससुरकी पीठमें छुरा घोंपनेमें सीनियर बताया था और इसके कुछ ही अर्सा बाद टीडीपीके नेता नायडूने यह कहकर जैसे बदला चुकाया था कि मैं पहला आदमी था जिसने २००२ के दंगोंके बाद उनसे (मोदीसे) इस्तीफा मांगा था। तब चंद्रबाबू नायडूने मोदीको अतिवादीतक कह दिया था। राजनीतिक स्वार्थके चलते हमारे नेता ऐसी बातोंको भुला देनेका नाटक अच्छी तरह कर लेते हैं, परन्तु राजनीतिमें कुछ भी असंभव नहीं होता।

संसदका सत्र प्रारम्भ होनेसे पहले प्रधान मंत्रीने मीडियाके समक्ष दो-तीन ऐसी बातें की हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए। प्रधान मंत्रीका यह कहना कि जनता सदनमें तमाशा नहीं देखना चाहती, हो-हल्ला भी नहीं, विपक्षके निशानेपर रहेगा। मजबूत विपक्ष लोकतंत्रको मजबूत बनाता है और इस बार लोकसभामें विपक्ष पिछली बारकी तरह इतना कमजोर नहीं है कि सरकार उसे हल्केमें ले सके। स्पष्ट है पिछली दो बारकी तरह अब प्रधान मंत्री मोदी मनमानी नहीं कर पायंगे। स्थिति यह है कि एक ओर तो विपक्ष जो अब पहलेसे कहीं अधिक बलशाली है और अधिक आक्रामक हो सकता है। दूसरी ओर भाजपाके भीतर भी ऐसी स्थितियां पनप सकती हैं जो प्रधान मंत्रीको कमजोर बना दें। इस संदर्भमें भाजपाकी पितृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके नेतृत्वके बदले तेवरोंको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

भाजपाके नेतृत्वको यह भी समझना होगा कि चुनावमें इस बार पहले जैसी सफलताका न मिलना यह भी बताता है कि उसका जन-समर्थन कम हुआ है। बात सत्ताविरोधी रुखतक सीमित नहीं है। यह एक चेतावनी है भाजपाके लिए, विशेषकर प्रधान मंत्रीके लिए कि उनकी शासन-व्यवस्थामें खामियां थीं। महंगी और बेरोज़गारी जैसे बुनियादी सवालोंको पिछली सरकारने उतनी गम्भीरतासे नहीं लिया, जितनी गम्भीरतासे लेना चाहिए था। यह बात भाजपाके नेतृत्वको समझनी होगी कि मतदाताको जेबमें रखनेवाली सोच कभी सही नहीं हो सकती। मुफ्त अनाज और नकद सहायता जैसे कदम मतदाताको सीमित रूपसे ही प्रभावित करते हैं। भरोसा नहीं जगाते सरकारके प्रति। प्रधान मंत्री तो यह भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि वे दैवी कृपाका पात्र बनकर ईश्वर द्वारा भेजे गये हैं। हालमें उन्होंने इस आशयका बयान भी दिया था कि उन्हें ईश्वरने किसी बड़े कामके लिए भेजा है! यह बड़ा काम क्या है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन चुनाव-परिणाम बता रहे हैं कि कुल मिलाकर मतदाता उनकी ऐसी बातोंसे प्रभावित नहीं हुआ है। जनताको ठोस परिणाम चाहिए, जुमलोंका गुलदस्ता नहीं। इस संदर्भमें प्रधान मंत्रीने अपने छोटेसे भाषणमें कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। हां, २५ जूनके हवालेसे उन्होंने एक बात अवश्य कही जिसपर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह बताना जरूरी समझा कि ५० साल पहले इसी दिन देशमें आपातकाल लागू किया गया था और विरोधी नेताओंको जेलमें डाल दिया गया था। वह काल हमारे लोकतंत्रका एक काला अध्याय है। यह बात कहकर संभवत: प्रधान मंत्री कांग्रेस पार्टीको एक तरहसे चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अब कोई देशमें आपातकाल लागू नहीं कर पायेगा। संविधानमें संशोधन करके जनता पार्टीकी सरकारने ऐसी व्यवस्था तो कर दी थी कि फिर कोई शासक आपातकाल लागू न कर पाये, परन्तु शासकके मनमें एकाधिकारवादी सोच पनप ही न पाये ऐसी व्यवस्था सिर्फ देशका मतदाता ही कर सकता है। इस बातको भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि अति लोकप्रियता किसी भी शासकको अहंकार और तानाशाही सोचसे भर सकती है। इसलिए चुनाव-परिणामको इस तरहसे भी समझा जाना जरूरी है कि मतदाताने एक गम्भीर चेतावनी दी है। यह चेतावनी सिर्फ सत्तारूढ़ पक्षके लिए ही नहीं है, विपक्षको भी समझना होगा कि देशका मतदाता उससे भी बहुत अपेक्षाएं रखता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और विपक्ष दोनों ही इस चेतावनीकी गम्भीरताको समझेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस संकेतको हमारे राजनेता समझेंगे।

प्रसन्नताके मायने

❑ **जग्गी वासुदेव**

खुशहाली अपने भीतर प्रसन्नताकी एक गहरी भावना है। यदि आपका शरीर सुखद महसूस करता है तो हम उसे स्वास्थ्य कहते हैं। यदि वह बहुत सुखद बन जाता है तो हम उसे सुख कहते हैं। यदि आपका मन सुखद बनता है तो हम उसे शांति कहते हैं। यदि वह बहुत सुखद बन जाता है तो हम उसे खुशी कहते हैं। यदि आपकी भावना सुखद बनती है तो हम उसे प्रेम कहते हैं, यदि वह बहुत सुखद बन जाती है तो हम उसे करुणा कहते हैं। यदि आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद बनती हैं तो हम उसे आनन्द कहते हैं। यदि वे बहुत सुखद बन जाती हैं तो हम उसे परमानंद कहते हैं। आप पूरा बस यही खोज रहे हैं, भीतर और बाहरकी प्रसन्नता। जब प्रसन्नता भीतर होती है तो उसे शांति, आनन्द या खुशी कहते हैं। जब आपके चारों ओरका माहौल सुखद बन जाता है तो उसे सफलताका नाम दिया जाता है। यदि इनमेंसे किसीमें भी रुचि नहीं है और आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो क्या खोज रहे हैं। बस दूसरी दुनियाकी सफलता! तो मुख्य रूपसे, सारे मानव अनुभव बदलते स्तरोंकी प्रसन्नता और अप्रसन्नतासे आते हैं। लेकिन अपने जीवनमें आप कितनी बार पूरे दिनभर आनन्दमय रहे हैं, बिना एक पलकी भी चिन्ता, बेचैनी, चिढ़ या तनावके। कितनी बार आप चौबीस घंटेके लिए निरी प्रसन्नता और पूरे आनन्दमें रहे हैं। पिछली बार आपके साथ ऐसा कब हुआ था। हैरानीकी बात यह है कि इस धरतीपर ज्यादातर लोगोंके लिए, एक दिन भी ठीक वैसा नहीं बीता है जैसा वे चाहते हैं! यकीनन ऐसा कोई भी नहीं है जिसने खुशी, शांति या आनन्द अनुभव नहीं किया हो, लेकिन वह हमेशा अस्थायी होता है। वे उसे कायम नहीं रख पाते। वे वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिर गिरते रहते है और उसके गिरनेके लिए कोई भीषण चीज होनेकी जरूरत नहीं है। सबसे साधारण चीजें लोगोंको संतुलनसे बाहर फेंक देती हैं और बेतरतीब कर देती हैं। क्या यह जाना-पहचाना लगता है-आपको अपने भीतर प्रसन्न रहनेकी जरूरत क्यों है। जब आप प्रसन्नताकी एक आन्तरिक अवस्थामें होते हैं, तब आप स्वाभाविक रूपसे अपने आसपास हर किसीके साथ और हर चीजके साथ मधुर होते हैं। जब आप अपने भीतर अच्छा महसूस कर रहे हों तो वह उसका स्वाभाविक परिणाम है। इसके अलावा दुनियामें आपकी सफलता मुख्य रूपसे इसपर निर्भर करती है कि आपने शरीर और मनके कौशलका कितने अच्छेसे उपयोग किया है। सफलता हासिल करनेके लिए, प्रसन्नताको आपके भीतर एक बुनियादी गुण होना होगा।

विश्वव्यापी समस्या बनता वनाग्नि

❑ **सत्यपाल वशिष्ठ**

वनाग्नि विश्वव्यापी समस्या है। दुनियाके कई हिस्सोंमें भीषण आग लगनेसे धरतीपर जंगलोंको भारी नुकसान हो रहा है। वनाग्निके पीछे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंगको भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। भारतमें हिमाचल, नागालैंड, मणिपुर सीमा, मध्य ओडीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगानाके जंगली क्षेत्रोंमें आगका सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। भारतमें ३६ प्रतिशत जंगलोंमें बार-बार आग लगती है। चार प्रतिशत जंगल ऐसे हैं जो गम्भीर रूपसे आग लगनेवाले हैं। इस वर्ष शुष्क मौसम एवं कम बारिश होनेके कारण वनाग्निकी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेशका २७७३ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रमें है जिसमें २७६९.६२ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रमें चीड़के वन हैं। ये चीड़के वन आगके लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हिमाचलमें कुल २०२६ वन बीट हैं, इनमेंसे ३३९ अति संवेदनशील, ६६७ संवेदनशील तथा शेष १०२० कम संवेदनशील हैं। इस वर्ष वनाग्निके सीजनमें मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर, नाहन, सोलन, बिलासपुर, शिमला, चम्बा, रामपुर, कुल्लू वृत्त, सिरमौरके पच्छाद, नैना टिक्करके वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। चौपालके नेरवामें एक व्यक्तिके खिलाफ थानेमें धारा २८५ के तहत मामला दर्ज किया गया। वह बार-बार जंगलमें आग लगा रहा था। सोलनके डगशाईके जंगलोंमें लगी आगसे कई हेक्टेयर वन जमीनमें आग लगी। डलहौजीके जंगलोंमें लगी आगकी चपेटमें सरकारी दफ्तर भी आ गया। आग बुझानेके लिए वायु सेनाकी मदद ली गयी। कई जगह तो घरों, बागीचों, स्कूलों तथा सरकारी दफ्तर आदिको भी वनाग्निसे काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा आगकी घटनाओंसे प्रभावित धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर सर्कल हैं, क्योंकि यहां चीड़के जंगल हैं। हिमाचलके वनोंमें लगी आगसे ऐसा लगता है कि वन विभागने कोई कारगर योजना वनाग्निसे निबटनेके लिए नहीं बनायी है। वन विभाग १७६७ वनाग्निकी घटनाओंके बावजूद अब भी वनाग्निको बुझानेके लिए बारिशके इंतजारमें है। वनाग्निको रोकनेके लिए वन विभागके पास बजटकी कमी है। दूसरी तरफ सरकार पर्यावरण दिवस तथा वन महोत्सव मनानेके लिए लाखों रुपये खर्च करती है। वन विभागको वनाग्निसे निबटनेके लिए कारगर योजना बनाकर इसका कार्यान्वयन करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण ईकोसिस्टमको बचाया जा सके। हिमाचल सरकारको इस ओर ज्यादा ध्यान देनेकी आवश्यकता है, क्योंकि हिमाचलमें पर्यटन प्राकृतिक सुन्दरता एवं पर्यावरणपर निर्भर करता है। साधारणतया वनाग्निके मुख्य कारण हैं- प्राकृतिक रूपसे बिजली गिरना, कोयले जलनेकी वजह बीड़ी-सिगरेट पीनेवालोंकी भूल तथा जान-बूझकर जंगलोंको आग लगाना आदि। ज्यादा गर्मी और शुष्क मौसमके कारण भी वनोंमें आग लग रही है। वनाग्निका एक और कारण है, सरकारी एवं वन विभागकी जमीन जिसकी सीमा वनोंके साथ लगती है। इस जमीनपर लोगोंने अवैध कब्जे किये हैं।

न्यायालयोंने अवैध कब्जे हटानेके आदेश दिये हैं परन्तु सरकार और वन विभाग ये जमीनें वापस नहीं ले पा रहे हैं। ये अवैध कब्जाधारी ही इस जमीनपर घास/झाड़ियां आदि जलानेके लिए आग लगाते हैं, ताकि बरसातमें घास अधिक हो। यही आग साथ लगते जंगलोंमें फैल जाती है। कई बार ये लोग साथ लगते वनोंमें जान-बूझकर आगको लगाते हैं। ९५ प्रतिशतसे अधिक जंगलकी आग जान-बूझकर एवं इनसानी लापरवाहीके कारण लगती है। जंगलकी आग विभिन्न तरहसे प्रभावित करती है जैसेए अर्थव्यवस्थाको प्रभावित करना, मिट्टी कटावका खतरा बढ़ जाना, वातावरणको प्रदूषित करना, स्वास्थ्य सम्बन्धित स्मस्याएं, पेड़ोंके नुकसानसे जलवायु परिस्थितियां बाधित होना, बहुतसे जंगली जानवरोंका बच्चे देनेका सीजन भी प्रभावित होता है। कई जानवरोंकी मौत कुछ जानवरोंका शहरकी तरफ भागना, वनस्पति तथा जीवोंका नष्ट होना, मिट्टीकी गुणवत्तापर विपरीत प्रभाव पड़ना, आगसे जंगलोंमें बीज बैंकको क्षति पहुंचती है तथा अंकुर और पौधे नष्ट हो जाते हैं। जंगली आग जानवरोंके प्रजनन जोड़ेकी अखंडताको लम्बे समयके लिए प्रभावित करती है। वनाग्निसे वृक्षोंका फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। वनाग्निको बुझानेके लिए पारम्परिक एवं आधुनिक तरीके प्रयोगमें लाये जाते हैं। ये ही तरीके ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। ये तरीके हैं- अग्नि रेखाका निर्माण करना तथा उसकी मरम्मत करना, नियंत्रित आग, अग्नि छत, पीछे और जवाबी फायर, पत्थरकी दीवार, आगपर नजर रखनेके लिए हर गांवमें संयुक्त वन प्रबंधन कमेटी गठित करना। आगपर नजर रखनेके लिए टावर, मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, सम्मोच्च खाइयां, गली प्लग्स, ढीले पत्थर संरचना, जल संचयन संरचना आदि। आधुनिक तरीके- अग्नि चेतावनी प्रणाली, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, आग बुझानेके दस्ते, पत्तोंको उड़ाने वाले लीफ ब्लोअर। सामाजिक सहभागिता- संयुक्त जंगल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक टूल है। इसमें जंगलके प्रबंधनमें सभी लोग भाग लेते हैं और ये वन विभागके सहयोगसे कार्य करते हैं। गांवके लोगोंको जागरूक करना तथा आगसे लड़नेके तरीके बताये जाते हैं। इसके लिए वन विभागको वनोंके सारे हक-हकूक गांववासियोंको देने होंगे तथा उनकी आर्थिक सहायता भी करनी होगी। चीड़के पेड़ोंकी नीडल्जको ईंटोंका बनाने तथा सीमेंट फैक्टरीके प्रयोगके लिए भेज देना चाहिए। उपरोक्त उपायोंके अतिरिक्त हिमाचल वन विभागको वनोंमें पानीके स्रोतोंका निर्माण करना चाहिए। वन, जल शक्ति तथा ग्रामीण विकास विभागोंको समन्वय करना चाहिए।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

उपलब्धियों का उल्लेख

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की अनेक उपलब्धियों का उल्लेख किया है। हालांकि, 18वीं लोकसभा का उद्घाटन सत्र आगे बढ़ने के साथ ही स्पष्ट हो गया है कि यह पहले की तुलना में ज्यादा जीवन्त और घटना प्रधान होगा। इसका कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष की संरचना है। यह बात पहले ही दिन से और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधन से स्पष्ट है। उनके संबोधन ने महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया, पर वह विवाद का विषय भी बना। संसद के संयुक्त सत्र को अपने परंपरागत संबोधन में राष्ट्रपति मूर्मू ने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया जिनमें व्यापक कल्याणकारी योजनायें तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता शामिल हैं। लेकिन सरकार की विभिन्न उपलब्धियां उजागर करने वाला अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर मौन भी था। इस कारण विपक्ष ने अभिभाषण की विषयवस्तु तथा उसमें छूटी चीजों, खासकर मणिपुर हिंसा को बाहर रखने के लिए उसकी आलोचना की। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उद्देश्य संसदीय सत्र की दिशा निर्धारित करना होता है और इसमें अनेक आलोचनात्मक मुद्दों तथा उपलब्धियों का उल्लेख किया गया था। महत्वपूर्ण रूप से इसमें परीक्षाओं में अनियमितताओं समेत 1975 में लागू किए 'आपातकाल' का ऐतिहासिक संदर्भ भी शामिल था। आपातकाल के संदर्भ से कांग्रेस आगबबूला हो गई और उसने इसे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से ध्यान भटकाने की चाल बताया।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने परीक्षा पेपरों की लीक की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया कि इसका प्रभाव अकादमिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर पड़ता है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्थाओं में अपनी सरकार की पारदर्शिता व सुधारों के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की तथा निष्पक्षता एवं निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता भी रेखांकित की। आपातकाल का संदर्भ 'संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और अंधकारमय अध्याय' के रूप में दिया गया। यह ऐतिहासिक भूल याद दिलाने का एक रणनीतिक कदम था। यह संदर्भ लोकतंत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित करने के लिए था, पर इससे कांग्रेस में घबराहट पैदा हुई क्योंकि उसे यह ऐसे समय की याद दिलाता है जिससे वह स्वयं को दूर रखना चाहती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूर्वोत्तर में सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी देते हुए 'एक्ट ईस्ट पालिसी' के अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं और पहलों के लिए आबंटन बढ़ाने का उल्लेख किया, हालांकि बहुत से सांसदों की राय है कि इतना आबंटन नाकाफी है। लेकिन अभिभाषण में मणिपुर हिंसा का सीधा उल्लेख न होने के कारण विपक्ष ने इस संकट को महत्व न देने तथा जवाबदेही से बचने का प्रयास बताया। विपक्ष के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को नहीं उठाया गया जबकि वर्तमान समय में इनको संबोधित करना जरूरी है। इसके विपरीत सत्तारूढ़ पक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को 'विकसित भारत' की दिशा में देश की प्रगति का महत्वपूर्ण रोडमैप बताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में रेखांकित सरकार की भावी पहलों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सर्वानुमति विकसित करने पर जोर दिया है। इसे देखते हुए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच रचनात्मक राजनीतिक संवाद का रास्ता खुलता है जो पार्टियों के संकीर्ण दायरों से आगे जाता है।

वेंकैया गारू: भारत की सेवा में समर्पित

वेंकैया नायडू ने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं बीजेपी को मजबूत किया।

नरेंद्र मोदी
(लेखक, भारत के प्रधानमंत्री हैं)

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक हमारे श्री एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है। वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायुहोने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। देश में उनके लाखों चाहते वाले हैं। मैं उनके सभी शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बधाई देता हूं। वेंकैया जी का 75वां जन्मदिवस एक विशाल व्यक्तित्व की व्यापक उपलब्धियों को समेटे हुये है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए।

राजनीति में अपने प्रारम्भिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आपमें एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है। वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है, जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगोंके प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला।

वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था। लेकिन उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं बीजेपी को मजबूत किया। लगभग 50 साल पहले जब काँग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें लोकनायक जेपी को आंध्र प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए जेल जाना पड़ा। लोकतंत्र के लिए उनकी ये प्रतिबद्धता, उनके राजनीतिक जीवन में हर जगह दिखाई देती है। 1980 के दशक के मध्य में, जब महान एनटीआर की सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था, तब वे फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे।

1978 में आंध्र प्रदेश ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद, राज्य चुनाव में एनटीआर की लोकप्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। तब भी वे बीजेपी के विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में बीजेपी के लिए भविष्य के बीज बोये थे। युवा विधायक के रूप में ही, वे विधायी मामलों में अपनी दृढ़ता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित होने लगे।

उनकी वाकपटुता, शब्दशैली और संगठन सामर्थ्य से प्रभावित होकर एनटीआर जैसे दिग्गज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। एनटीआर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वेंकैया गारू हमेशा की तरह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई, गांवों में जाकर सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े। उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। 1990 के दशक में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुये उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 में यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति, जो किशोरावस्था में अटल जी और आडवाणी जी के दौरों की तैयारी करता था, उनके लिए ये कितना बड़ा मुकाम था। पार्टी महासचिव के रूप में, उनका एक ही लक्ष्य था कि अपनी पार्टी को सत्ता में कैसे लाया जाए। उनका एक ही संकल्प था कि कैसे देश को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री मिले। दिल्ली आने के बाद, उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने।

वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे तो वो वेंकैया गारू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो वेंकैया गारू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना। उनकी इस पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था। क्योंकि, उसके पहले नेताओं के लिए दूसरे मंत्रालय पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन, वेंकैया गारू की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी- वह एक किसान पुत्र थे, उन्होंने अपने शुरुआती दिन गांवों में बिताए थे और इसलिए, अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह काम करना चाहते थे, तो वह ग्रामीण विकास था। उस समय एक मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी।

2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। शायद, वह उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए काम किया है। 2014 के उन शुरुआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे भी बहुत काम आया था। मैं उस समय दिल्ली के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। मेरा करीब डेढ़ दशक गुजरात में ही काम करते हुये बीता था। ऐसे समय में वेंकैया गारू का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। वो सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। साथ ही, जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात आती थी, तब वो नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नज़र आते थे।

वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ये हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था। हम ये जानते थे कि वेंकैया गारू के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा। लेकिन साथ ही,हमें ये भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है। मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद किया तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है। उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ी। वह राज्यसभा के एक उत्कृष्ट सभापति थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा सांसदों, महिला सांसदों और पहली बार चुने गए सांसदों को बोलने का अवसर मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया, समितियों को अधिक प्रभावी बनाया। उन्होंने सदन में बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया।

जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय राज्यसभा के पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वह युवा जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए अपना जीवन समर्पित किया था,जब वह सपना पूरा हुआ तो वह सभापति के पद पर आसीन था। किसी निष्ठावान देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा!

काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। दिल्ली के लोगों के बीच, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो शहर में गौरवशाली तेलुगु संस्कृति लेकर आए। उनके द्वारा आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं। मैं वेंकैया गारू को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं। लेकिन, पिछले कुछ समय से उनका संयम भी सबके सामने दिखने लगा है। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि वह अभी भी बैडमिंटन खेलना और ब्रिस्क वॉक करना पसंद करते हैं। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी, वेंकैया गारू सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं। वह लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को मुझसेबात करते रहते हैं। हाल ही में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाक़ात हुई थी। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं।

स्वास्थ्य पर समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक

भारत को 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, नवाचार और पहुंच पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है।

सुगंध अहलूवालिया
(लेखिका, स्तम्भकार हैं)

जबकि भारत मोदी 3.0 सरकार के तहत पहले व्यापक केंद्रीय बजट के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहा है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र खुद को एक महत्वपूर्ण चौराहे पर पाता है। अंतरिम बजट ने एक प्रारंभिक रोडमैप निर्धारित किया है, फिर भी स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तनकारी सुधार को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है।

भारत के महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सेवा उद्देश्यों का समर्थन करने वाले एक नए पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, नवाचार और पहुंच के लिए बढ़ी हुई निधि को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। आगामी बजट से प्राथमिक अपेक्षाओं में से एक अस्पतालों को बुनियादी ढांचे के निवेश के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना है। इस पुनर्वर्गीकरण में पर्याप्त निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है, जो देश भर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा उपकरणों के लिए ब्याज दर में छूट देने से अस्पतालों पर वित्तीय दबाव कम हो सकता है, जिससे प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3त तक बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करना होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा व्यय को 18.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान लक्ष्य 2025-26 तक स्वास्थ्य सेवा पर 2.5 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय और 2030-31 तक 3 प्रतिशत प्राप्त करना है।

हालांकि ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और रणनीतिक क्रियान्वयन की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा लागत का आर्थिक बोझ भारत में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय, बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागत और बीमा बाधाओं के साथ, तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उन्नत उपचार विधियों को शामिल करना और निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को इसी तरह की प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इन समूहों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को काफी हद तक बढ़ा सकता है। सरकार को अपने बजट आवंटन में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर भी जोर देना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा कर्मियों में प्रत्यक्ष निवेश, साथ ही डॉक्टरों और अस्पतालों को कम सेवा वाले क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए लक्षित प्रोत्साहन, महत्वपूर्ण हैं। यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य सेवा कवरेज का विस्तार करेगा और बीमा उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देगा, जिससे सभी के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो जाएगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढांचा भी ज़रूरी है।

2030 तक यूएचसी हासिल करने की भारत की आकांक्षा का समर्थन करने के लिए तर्कसंगत नियम और नीतियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसे नियमों से सभी हितधारकों के बीच सहज सहयोग संभव होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने और देश में समग्र स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूएचसी को प्राप्त करने के लिए सेवा वितरण में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटना आवश्यक है, विशेष रूप से गैर-संचारी और संचारी रोगों के दोहरे बोझ को संबोधित करने में। सभी के लिए स्वास्थ्य की ओर यात्रा में स्वास्थ्य बीमा एक महत्वपूर्ण घटक है। कम बीमा कवरेज के साथ, कई व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश करते समय काफी अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है। अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा को लागू करना और धीरे-धीरे स्व-नियोजित पेशेवरों और अन्य वर्तमान में बहिष्कृत समूहों को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार करना अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह रणनीति सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिकों को वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच हो। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सभी के लिए मौलिक है, और इस संबंध में यूएचसी महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, यूएचसी का अर्थ है वित्तीय कठिनाई के बिना सस्ती दवाओं और टीकों सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। यूएचसी को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों और आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र का निवेश इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में 2030 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करना कई अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने की भी आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने और उसे प्रदान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल प्रणालियों को एकीकृत करने वाला एक स्थायी स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय मॉडल विकसित करना महत्वपूर्ण है।

इस तरह के मॉडल में वहनीयता और उच्च गुणवत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे भारतीय स्वास्थ्य सेवा की प्रतिष्ठा बढ़े। अस्पताल क्षेत्र के लिए पर्याप्त समर्थन भी आवश्यक है, जिसमें निवेश और कर राहत का संयोजन शामिल है, ताकि देश भर में बुनियादी ढांचे की संपत्ति का निर्माण किया जा सके और शीर्ष स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके।

2030 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं में ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना अनिवार्य है।

आप की बात

झूठा विपक्षी प्रचार

दिल्ली टर्मिनल एक पर हुए हादसे में एक कार चालक की मृत्यु हो गयी। विपक्ष ने इसका ठीकरा प्रधानमंत्री पर मढ़ने का प्रयास किया और जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ परोसना शुरू कर दिया। कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया कि प्रधानमंत्री ने टर्मिनल एक का उद्घाटन 2024 में किया था, जबकि 2009 में कांग्रेस सरकार के अंतर्गत निर्मित हिस्सा टूटा और दुर्घटना हुई। इसी प्रकार अटल टनल के बारे में भी झूठी खबर फैलाई गयी। सर्विस रोड को मुख्य मार्ग बताकर छायाचित्र प्रचारित किए गए। राममंदिर को लेकर भी झूठी खबरें फैलाई गयी कि पहली बारिश में ही राममंदिर की छत टपकने लगी जबकि राममंदिर ट्रस्ट द्वारा इसका खंडन किया गया। चुनाव से पहले और उसके दौरान अनगिनत झूठ प्रचारित-प्रसारित किए गए। इसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में भुगतना पड़ा। इसी प्रकार यदि विपक्ष जनता को झूठ परोसता रहा और उस पर कोई अंकुश नहीं लगा तो भविष्य में समस्या पैदा हो सकती है। सरकार को संचार माध्यमों द्वारा झूठ का खंडन कर सच सामने लाना चाहिए। इस प्रकार हुई दुष्प्रचार की अनेक घटनाओं से सबक लेकर सरकार को झूठे प्रचार पर रोकथाम के कठोर उपाय अवश्य करने चाहिए।

– **मनोज पुरुषार्थी,** मेरठ

न्याय की उम्मीद

गिरफ्तारी के करीब 5 महीने बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई, जबकि केजरीवाल फिर जेल चले गए हैं। इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी गई थी मगर सारेन को नहीं। देश में एक संविधान और समान कानून होने के बावजूद अलग-अलग तरह के फैसले आते हैं जिनसे आम जनता कई बार भ्रमित हो जाती है। बड़े नेताओं, अभिनेताओं, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों तथा आम जन के मामले में होने वाले फैसलों में कई बार साफ फर्क नजर आता है। इससे न्याय व्यवस्था में अकूत विश्वास रखने वाली जनता को भी लगने लगा है कि न्यायालयों में पैसे से मजबूत लोगों को ही न्याय मिल पाता है। पैसे वाले तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मगर पूरे भारत में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी जेल में बंद है। इनकी चार्ज शीट तक महीनों तक पेश नहीं की जाती और उन्हें कई कई महीनो तक बिना वजह बंद करके रखा जाता है। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। देश में लागू होने वाले तीन नए अपराध न्याय कानूनों से आम आदमी को राहत दिलाने का वादा सरकार ने किया है। देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इन कानूनों का क्रियान्वयन जनता की न्याय की उम्मीद कहां तक पूरी करता है।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

सरकार का कामकाज

भाजपा नीत एनडीए ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में किसी भी अन्य सरकार द्वारा किए कार्यों के मुक़ाबले तीव्र गति से समर्पित होकर कार्य किया है। मोदी न सिर्फ18 घंटे कार्य करते हैं बल्कि अपनी मिनिस्ट्री के सभी साथियों से भी निश्चित समय पर सभी कार्य निपटने के लिए प्रेरित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आज भारत की साख एवरेस्ट की तरह उच्च स्तर पर है। मगर हमारा विपक्ष सब कार्यों को नजरअंदाज करके सरकार को जनता की नजर में गिरने के लिए अनवरत प्रयासरत रहता है। ऐसी नकारात्मक राजनीति के चलते अब की बार मोदी को देश के बाहर और देश के भीतर दोनों तरफ से पहले की तुलना में अधिक चुनौतियां मिल सकती हैं। उन्हें इनसे निपटना होगा। विडंबना है कि कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दल अपने राजनीतिक व दलगत स्वार्थ के चलते राष्ट्रहित की भी चिन्ता नहीं करते हैं। विपक्ष संभवत: अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े करने की तैयारी कर रहा है जिससे देश की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। एनडीए सरकार ने पिछले दस साल में देश की सुरक्षा मजबूत करने में असाधारण योगदान किया है। इसे स्वीकार करते हुए अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े करना बिल्कुल गलत होगा।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

द्रोपदी मुर्मू का अभिभाषण

राष्ट्रपति सत्ता-विपक्ष के साथ ही दोनों सदनों के लिए सम्माननीय हैं। उनके अभिभाषण का सम्मान करते हुए सबको तर्कसंगत बात करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष सत्ता की आलोचना करते-करते राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना में भी नहीं चूका और इस दौरान शोरगुल भी किया। हालांकि, अभिभाषण एक प्रकार से सरकारी होता है और उसमें सरकार की उपलब्धियों पर ही अधिक विचार होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तथा उसमें व्यक्त सरकार की नीतियों व विकास की दिशा पर आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इसे सत्ता पक्ष को ब्लैमेल करने या उस पर अपना राजनीतिक एजेंडा थोपने का प्रयास नहीं बनाना चाहिए। अत: अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने से पहले नीट पर चर्चा के लिए जोर देना और खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता के संसद के वेल में जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। द्रोपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में प्रश्नपत्रों की लीक का मामला भी उठाया है, इसलिए नीट का मामला उस चर्चा का हिस्सा बन सकता है। समुचित चर्चा के बजाय संसदीय कामकाज में बाधा डालने से विपक्ष का सम्मान नहीं बढ़ेगा।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/epaperpioneer

गडकरी की दो टूक

इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि गुणवत्ता की सेवा दिए बिना कोई टैक्स वसूलना उपभोक्ता के साथ अन्याय है। यह बात हर सरकारी व निजी महकमे पर लागू होती है। लेकिन यथार्थ में ऐसा होता नहीं है और बेहतर सेवा के बिना टैक्स वसूलने के खिलाफ लोग लोक अदालतों से लेकर विभिन्न अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। यह बात सर्वविदित है, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हालिया बयान ने इस बहस को तेज किया है। अपनी बात को बेबाकी से कहने वाले नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि यदि सड़कें अच्छी हालत में न हों और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो राजमार्ग पर एजेंसियों द्वारा टोल टैक्स वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स वसूलने से पहले हमें अच्छी सेवाएं देनी चाहिए। लेकिन हम अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये टोल टैक्स वसूलने की जल्दी में रहते हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने स्वीकारा कि सड़कें अच्छी नहीं होने पर तमाम शिकायतें हमें मिलती हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। सही मायनों में गुणवत्ता की सड़क प्रदान करने पर ही हमें टोल वसूलने का अधिकार मिलता है। जाहिर सी बात है कि गड्ढों व कीचड़ वाली सड़कों पर टैक्स वसूलने पर पब्लिक की नाराजगी स्वाभाविक रूप से सामने आएगी। निस्संदेह, परिवहन मंत्री की स्वीकारोक्ति एक अच्छा कदम है और हर विभाग के मंत्री को अपने अधीनस्थ विभागों की कारगुजारियों पर नजर रखनी चाहिए। मंत्री को विभाग की खामियों पर पर्दा डालने के बजाय सेवा में सुधार की पहल करनी चाहिए। अब चाहे मामला राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यरत एजेंसियों का हो या फिर बिजली-पानी जैसे मूलभूत जरूरतों वाले विभागों का, अधिकारियों को उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि शिकायत दर्ज करने और शिकायतों के तुरंत निवारण हेतु एक स्वतंत्र तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए। निस्संदेह, इसमें दो राय नहीं कि राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे आदि के बनने से यात्रियों का आवागमन सुविधाजनक हुआ है। लोगों के समय व वाहनों में पेट्रोल-डीजल में बचत हुई है। लेकिन कई स्थानों पर सड़कों की गुणवत्ता में कमी या सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियों का उजागर होना, उपभोक्ताओं को परेशान करता है। पहले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स चुकाने के लिये घंटों लाइन में लगना पड़ता था। कालांतर फास्टैग व्यवस्था से टोल कटने लगा। आज 98 फीसदी वाहनों में स्मार्ट टैग के माध्यम से निर्बाध यात्रा की जा रही है। मंत्री श्री गडकरी के बयान का स्वागत करना चाहिए। उनका बयान अधिकारियों को कर्तव्यबोध भी कराता है कि सड़कों की गुणवत्ता हर हाल में बनाये रखें।

‘वेंकैया गारू- भारत की सेवा में समर्पित जीवन’

पूर्व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जन्मदिन पर लिखा प्रधानमंत्री का आलेख

नरेंद्र मोदी, (प्रधानमंत्री)

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक हमारे श्री एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिन है। वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। देश में उनके लाखों चाहते वाले हैं। मैं उनके सभी शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बधाई देता हूं। वेंकैया जी का 75वां जन्मदिन एक विशाल व्यक्तित्व की व्यापक उपलब्धियों को समेटे हुए है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए।

राजनीति में अपने प्रारम्भिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आपमें एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है। वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है, जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला।

वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था। लेकिन उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं बीजेपी को मजबूत किया।

लगभग 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें लोकनायक जेपी को आंध्र प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए जेल जाना पड़ा। लोकतंत्र के लिए उनकी ये प्रतिबद्धता, उनके राजनीतिक जीवन में हर जगह दिखाई देती है। 1980 के दशक के मध्य में, जब महान एनटीआर की सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था, तब वे फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। 1978 में आंध्र प्रदेश ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद, राज्य चुनाव में एनटीआर की लोकप्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। तब भी वे बीजेपी के विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में बीजेपी के लिए भविष्य के बीज बोये थे। युवा विधायक के रूप में ही, वे विधायी मामलों में अपनी दृढ़ता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित होने लगे।

उनकी वाकपटुता, शब्द शैली और संगठन सामर्थ्य से प्रभावित होकर एनटीआर जैसे दिग्गज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। एनटीआर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वेंकैया गारू हमेशा की तरह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई, गांवों में जाकर सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े। उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी बने।

1990 के दशक में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुये उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 में यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति, जो किशोरावस्था में अटल जी और आडवाणी जी के दौरों की तैयारी करता था, उनके लिए ये कितना बड़ा मुकाम था। पार्टी महासचिव के रूप में, उनका एक ही लक्ष्य था कि अपनी पार्टी को सत्ता में कैसे लाया जाए! उनका एक ही संकल्प था कि कैसे देश को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री मिले। दिल्ली आने के बाद, उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने।

वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे तो वो वेंकैया गारू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो वेंकैया गारू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना। उनकी इस पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था। क्योंकि, उसके पहले नेताओं के लिए दूसरे मंत्रालय पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन, वेंकैया गारू की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी- वह एक किसान पुत्र थे, उन्होंने अपने शुरूआती दिन गांवों में बिताए थे और इसलिए, अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह काम करना चाहते थे, तो वह ग्रामीण विकास था। उस समय एक मंत्री के रूप में ह्यप्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाह्न को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी।

2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने ह्यस्वच्छ भारत मिशनह्न और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। शायद, वह उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए काम किया है।

2014 के उन शुरूआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे भी बहुत काम आया था। मैं उस समय दिल्ली के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। मेरा करीब डेढ़ दशक गुजरात में ही काम करते हुये बीता था। ऐसे समय में वेंकैया गारू का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। वो सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। साथ ही, जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात आती थी, तब वो नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नजर आते थे।

वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ये हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था। हम ये जानते थे कि वेंकैया गारू के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा। लेकिन साथ ही, हमें ये भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है। मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद किया तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है। उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ी। वह राज्यसभा के एक उत्कृष्ट सभापति थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा सांसदों, महिला सांसदों और पहली बार चुने गए सांसदों को बोलने का अवसर मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया, समितियों को अधिक प्रभावी बनाया। उन्होंने सदन में बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया।

जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय राज्यसभा के पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वह युवा जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, जब वह सपना पूरा हुआ तो वह सभापति के पद पर आसीन था। किसी निष्ठावान देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा!

काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। दिल्ली के लोगों के बीच, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो शहर में गौरवशाली तेलुगु संस्कृति लेकर आए। उनके द्वारा आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं। मैं वेंकैया गारू को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं। लेकिन, पिछले कुछ समय से उनका संयम भी सबके सामने दिखने लगा है। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि वह अभी भी बैडमिंटन खेलना और ब्रिस्क वॉक करना पसंद करते हैं।

उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी, वेंकैया गारू सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं। वह लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर मुझसे बात करते रहते हैं। हाल ही में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं।

आजादी के बाद से लोकसभा अध्यक्ष का निवास

विवेक शुक्ला

ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। इस तरह उनका राजधानी के 20 अकबर रोड पर ही सरकारी आवास रहेगा। पहली लोकसभा के 1952 में गठन के साथ ही जामुन और अमलतास के पेड़ों से लबरेज अकबर रोड के 20 नंबर के बंगले का भारतीय संसद के निचले सदन से अटूट संबंध कायम हो गया था। वो रिश्ता अब भी बना हुआ है। दरअसल, 1952 में कांग्रेस के गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे।

मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार से लेकर ओम बिरला 20 अकबर रोड में ही रहे। लुटियन जोन में गिनती के ही सरकारी बंगले डबल स्टोरी हैं। उनमें एक यह भी है। इसका निर्माण 1925 तक हो गया था। यानी इसे बने हुए अब लगभग 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इस बीच, ये बताना मुनासिब होगा कि 10 राजाजी मार्ग (पहले हेस्टिंग रोड) का बंगला भी डबल स्टोरी है। इसी बंगले में दो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब कुमार मुखर्जी भी रहे।

अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पता चलेगा कि 20 अकबर रोड में सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज पाटिल, पी.ए. संगमा, जीएमसी बालयोगी, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन भी रहे। इन सबने लोकसभा स्पीकर के पद को सुशोभित किया। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष बालयोगी का इसी 20 अकबर रोड में रहते हुए निधन हुआ था। वे देश के पहले दलित समुदाय से लोकसभा अध्यक्ष बने थे।

बलराम जाखड़ को 22 जनवरी, 1980 को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यद्यपि जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था, तथापि उन्हें सौंपी गई नई भूमिका के बहुत बड़े उत्तरदायित्व से वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। जाखड़ ने सातवीं लोकसभा में सदन की कार्यवाही का जिस तरीके से संचालन किया, उसकी सर्वत्र सराहना की गई और वह सभा के सभी वर्गों के प्रिय बन गए। इसलिए, दिसम्बर, 1984 के आम चुनाव में उनके राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित होने पर वे नई सभा की भी अध्यक्षता करने के लिए स्वाभाविक पसंद बने। सोलह जनवरी, 1985 को उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से आठवीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

दिसम्बर, 1989 में आठवीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पर जब जाखड़ ने अध्यक्ष पद का त्याग किया तो उन्हें स्वतंत्र भारत में लगातार दो बार लोकसभा की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एक मात्र अध्यक्ष का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ। यह अवधि (अर्थात? 22 जनवरी, 1980 से 18 दिसम्बर, 1989 तक) एक दशक से मात्र एक माह कम थी। अब ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। इस तरह वो जाखड़ के बाद लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे राजनेता बन गए हैं।

इस बीच, सुमित्रा महाजन 20 अकबर रोड में रहते हुए सांसदों के लिए भोज की मेजबानी करती रहती थीं। उनकी दावतों में मेहमान मेंगो रबड़ी, रबड़ी मालपुआ, श्रीखंड, भुट्टे का खास व्यंजन, साबूदाना खिचड़ी, मूंग दाल कचौरी, कैरी पना और ठंडाई के अलावा अन्य व्यंजनों का आनंद लेते थे।

कहते हैं, सुमित्रा महाजन युवा सांसदों से विशेष रूप मिला करती थीं ताकि उन्हें संसद की कार्यवाही के संबंध में विस्तार से जानकारी दे सकें। 20 अकबर रोड के बंगले में बदलते वक्त के साथ बहुत से बदलाव भी हुए। उदाहरण के रूप में इसमें 1978 में लिफ्ट लगाई गई थी। उस दौर में इसमें लोकसभा के अध्यक्ष के.ए. हेगड़े रहा करते थे। इसके बेडरूम पहली मंजिल में हैं। उनकी सेहत को देखते हुए लिफ्ट लगाई गई थी। यह आठ बेडरूम का बंगला है। इससे पहले शायद ही किसी बंगले में लिफ्ट लगी हो। 20 अकबर रोड के बंगले के आगे-पीछे बड़े से बगीचे हैं। उनमें भांति-भांति के पौधे और फूल लगे हुए हैं। बंगले के पिछले वाले हिस्से में सेवकों के घर भी हैं। अकबर रोड पर आजादी के बाद से ही सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हस्तियां रहती रही हैं। अकबर रोड का आगाज इंडिया गेट से होता है और यह सड़क रेस कोर्स तक जाती है। करीब पौने तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क के दोनों तरफ कुल जमा 26 सरकारी बंगले हैं। इधर कुछ प्राइवेट बंगले भी हैं। अकबर रोड पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उमा भारती, सुरेश प्रभु जैसे शक्तिशाली मंत्री भी रहे हैं। इधर के बंगलों की छतों पर आपको सुबह-शाम मोर मंडराते हुए मिल जाएंगे।

संयोग से उसी अकबर रोड के 24 नंबर के बंगले में 1978 से कांग्रेस का मुख्यालय भी चल रहा है। दरअसल, एक जमाने में इस बंगले को बर्मा हाउस भी कहते थे। तब इसमें बर्मा (म्यांमार) की भारत में एंबेसडर दा खिन केय रहा करती थीं। वो म्यांमार की शिखर नेता आंग सान सू की मां थीं। इसी सड़क पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट भी है। इसी अकबर रोड के 12 नंबर के बंगले में विजय लक्ष्मी पंडित रहा करती थीं। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की छोटी बहन थीं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड के नाम करने की भी नाकाम कोशिशें हुई थीं। तब कुछ लोगों ने अकबर रोड के संकेतक पर महाराणा प्रताप रोड का पोस्टर चस्पा कर दिया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और उन्होंने ताउम्र अकबर से लोहा लिया था। बहरहाल, अकबर रोड नाम के फिलहाल बदलने की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह से यह भी तय है कि आगे भी 20 अकबर लोकसभा अध्यक्ष का सरकारी आवास रहेगा।

दिसम्बर, 1989 में आठवीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पर जब जाखड़ ने अध्यक्ष पद का त्याग किया तो उन्हें स्वतंत्र भारत में लगातार दो बार लोकसभा की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एक मात्र अध्यक्ष का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ। यह अवधि (अर्थात? 22 जनवरी, 1980 से 18 दिसम्बर, 1989 तक) एक दशक से मात्र एक माह कम थी। अब ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। इस तरह वो जाखड़ के बाद लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे राजनेता बन गए हैं। इस बीच, सुमित्रा महाजन 20 अकबर रोड में रहते हुए सांसदों के लिए भोज की मेजबानी करती रहती थीं। उनकी दावतों में मेहमान मेंगो रबड़ी, रबड़ी मालपुआ, श्रीखंड, भुट्टे का खास व्यंजन, साबूदाना खिचड़ी, मूंग दाल कचौरी, कैरी पना और ठंडाई के अलावा अन्य व्यंजनों का आनंद लेते थे। कहते हैं, सुमित्रा महाजन युवा सांसदों से विशेष रूप मिला करती थीं ताकि उन्हें संसद की कार्यवाही के संबंध में विस्तार से जानकारी दे सकें। 20 अकबर रोड के बंगले में बदलते वक्त के साथ बहुत से बदलाव भी हुए। उदाहरण के रूप में इसमें 1978 में लिफ्ट लगाई गई थी। उस दौर में इसमें लोकसभा के अध्यक्ष के.ए. हेगड़े रहा करते थे। इसके बेडरूम पहली मंजिल में हैं। उनकी सेहत को देखते हुए लिफ्ट लगाई गई थी। यह आठ बेडरूम का बंगला है। इससे पहले शायद ही किसी बंगले में लिफ्ट लगी हो। 20 अकबर रोड के बंगले के आगे-पीछे बड़े से बगीचे हैं। उनमें भांति-भांति के पौधे और फूल लगे हुए हैं। बंगले के पिछले वाले हिस्से में सेवकों के घर भी हैं। अकबर रोड पर आजादी के बाद से ही सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हस्तियां रहती रही हैं। अकबर रोड का आगाज इंडिया गेट से होता है और यह सड़क रेस कोर्स तक जाती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

साइबर क्राइम : बेरोजगारी बढ़ा रही पढ़े लोगों को अपराध की तरफ

देश और प्रदेश में साइबर क्राइम का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। पुलिस एक साइबर क्राइम के पैटर्न को तोड़ती है तो दस नए तरीके तैयार हो जाते हैं। इसमें लोग बड़ली तादाद में ठगी का शिकार हो रहे हैं। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दें हाल ही में राजस्थान के जयपुर में एक बैंक मैनेजर स्तर की महिला अधिकारी से ही सत्रह लाख रुपए की ठगी कर दी गई। 18 जून को मध्यप्रदेश के भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने निवाड़ी से आशीष यादव नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। आशीष अपने गैंग के साथ मिलकर सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका था। साइबर क्राइम में पकड़े जा रहे अपराधी सभी पढ़े लिखे हैं। राजस्थान में अलवर और भरतपुर के मेवात इलाके में साइबर क्राइम तो एक इंडस्ट्री की तरह फलफूल रहा है। जितनी पुलिस की कार्रवाई है उससे हजारों गुणा अधिक बेरोजगार युवा अपराध के इस दलदल में हर दिन कूद रहे हैं। नौकरी करने के बजाय ये युवा जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने के लिए फ्रॉड के इस तरीके को अपना रहे हैं। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच में फ्रॉड की कई शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 51 मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की। इनमें जितने आरोपी पकड़े गए, उनमें से 50 फीसदी ग्रेजुएट हैं। आखिर साइबर क्राइम में पढ़े-लिखे युवाओं की संख्या क्यों बढ़ रही है? इन आंकड़ों का क्या बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़ों से कुछ संबंध है? जानकारों के अनुसार बेरोजगारी और क्राइम का सीधा संबंध है। ज्यादा पैसा कमाने की चाह और लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए भी युवा साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। एक मामला इंदौर का है। क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी कि इंदौर से ऑक्टा ट्रेडिंग के नाम से एक फर्जी वेबसाइट संचालित हो रही है। इसके जरिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले ग्राहकों का नंबर ऑनलाइन हासिल कर उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ट्रेडिंग करने वालों को विदेशी करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता था। पुलिस ने जब इंदौर में छापा मारा तो निपानिया के रहने वाले 19 साल के आयुष ठाकुर और 21 साल के नितिन ठाकुर और पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार किया। नितिन और पृथ्वी दोनों ग्रेजुएट हैं। आयुष और नितिन ग्राहकों को कॉल करके संपर्क करते थे। उन्हें फर्जी वेबसाइट पर डीमैट अकाउंट खोलने और इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपए खाते में डालने का काम करते थे। पृथ्वी सिंह वेबसाइट के मेंटेनेंस का काम देखता था। आरोपियों ने बताया कि वे शेयर मार्केट की वेबसाइट से ट्रेडिंग करने वालों के नंबर निकालते थे। ऑनलाइन विदेशी करेंसी में बल्क ट्रेडिंग करने के नाम पर उनका ऑक्टा ट्रेडिंग वेबसाइट पर डीमैट अकाउंट खुलवाते थे। एक और तरीका देखिए एक महिला ने इंटीग्रेटी मोबाइल नाम के पेज पर आईफोन का एक विज्ञापन देखा। जिसमें सस्ते दामों पर आईफोन दिया जा रहा था। युवती ने एक मोबाइल बुक किया। इसके बाद वॉट्सऐप के जरिए युवती से बुकिंग अमाउंट के साथ कस्टम ड्यूटी और रीफंड के नाम पर 1 लाख 90 हजार ठग लिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि निवाड़ी जिले से पूरा सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा था। गिरोह के सभी सदस्यों का काम बंटा हुआ था। आशीष यादव इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देने का काम करता था। फर्जी बिल वो ही तैयार करता था। अंकित नामदेव का काम फर्जी खाते खुलवाना था। पकड़े गए आरोपियों में से 3 ग्रेजुएट हैं। बेरोजगारों को इस तरह अपराध के दलदल में उतरना देश के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है।

लोकसभा चुनाव में राजस्थान भाजपा में डाउन फॉल की खुल रही है परते!

लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में ग्यारह सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा और मोदी का जादू नहीं चला। तमाम दिग्गज नेताओं का हालत खराब हो गई। कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगीं हुई थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 में कोटा सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिड़ला का लगातार दूसरी बार इस पद पर काबिज होना राजस्थान में बदलाव की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है, वहीं विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं।

अशोक भाटिया

हाल ही में राजस्थान के उदयपुर पहुंचीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित विशिष्ट जन सम्मान समारोह और व्याख्यान माला कार्यक्रम को वसुंधरा राजे संबोधित कर रही थी।उस दौरान उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह भंडारी ने चुन-चुनकर लोगों को भाजपा से जोड़ा। सुंदर सिंह भंडारी ने एक पौधे को वृक्ष बनाया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। कार्यकर्ताओं को ऊंचा उठाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि भंडारी जी ने राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी अंगुली को पहले काटने का प्रयास करते हैं, जिसको पकड़ कर वह चलना सीखते हैं। अब वसुंधरा राजे के इस बयान के बाद तमाम तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से वसुंधरा राजे और पार्टी नेतृत्व के बीच तल्खी देखने को मिली थी, उसकी परते खुलने लगी हैं। चुनाव के दौरान मन में जो कसक थी, वो अब धीरे-धीरे बयानों के जरिये सामने आ रही है। कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद रहे। राजे ने कहा कि गुलाबचंद कटारिया ने चुन-चुनकर लोगों को भाजपा से जोड़ा है। कटारिया अब असम के महामहिम हैं, लेकिन वह दूर रहकर भी हम लोगों के पास है और ख्याल रखते हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया के बीच भी तल्खी की खबरें सामने आयी थी। इसके अलावा चुनावी नतीजों के बाद पार्टी आलाकमान ने राजे को नजरअंदाज करके भजनलाल शर्मा को राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। ऐसे में दबे स्वर में ही सही भाजपा शीर्ष नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच मनमुटाव की खबरें गाहे-बगाहे सुर्खियां बनती रही हैं।

पहले प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बड़ा पावर सेंटर हुआ करती थीं। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। अब एक पावर सेंटर बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। इससे अलग लोकसभा अध्यक्ष बिरला प्रदेश में नए पावर सेंटर के रूप में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिरला की गिनती मोदी-शाह के नजदीकी नेताओं में होती है। दरअसल, राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा को नजरअंदाज करने का दौर चल रहा हैज् वसुंधरा राजे को चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री फेस घोषित नहीं किया। इसके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। लगातार नजरअंदाज किए जाने का दर्द हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की जुबान पर भी आ गया। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी वे केवल अपने बेटे दुष्यंत के लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ तक ही सीमित रहीं। प्रदेश में स्टार प्रचारक की सूची में शामिल होने के बावजूद राजे झालावाड़ के अलावा एक या दो जगह ही प्रचार के लिए पहुंची थीं। जिसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद से राजे का कोई भी राजनीतिक बयान सामने नहीं आया था। लेकिन लंबे समय बाद अब राजे ने चुप्पी तोड़ी हैज् इस बयान के जरिए राजे उनके संरक्षण में आगे बढ़ने वाले नेताओं को निशाने पर लिया है। वहीं राजस्थान के सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कभी वसुंधरा राजे के नजदीकियों में हुआ करते थे। इन्हीं नजदीकियों के चलते पहली बार विधायक बनने पर ही बिरला वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव बनने में सफल रहे। वहीं जल्द ही बिरला ने दिल्ली में बेहतर संबंधों के आधार पर अपना अलग वजूद बना लिया।और 2023 में वसुंधरा के मुकाबले मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने जाने लगे। अब वे प्रदेश के राजनीति में वसुंधरा के बराबरी में आकर खड़े हो गए हैं,और वे एक नए पावर सेंटर बनकर उभरे हैं।

वहीं प्रदेश की राजनीति में भविष्य के निर्णयों में अब बिरला की अहम भूमिका होगी। इसके संकेत खुद गृहमंत्री अमित शाह ने 20 अप्रैल को कोटा की रैली के दौरान दिए थे। शाह ने कहा था कि आप ओम बिरला को संसद भेज दो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। बिरला के पदग्रहण के साथ ही प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता उन्हें बधाई देने दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि बिरला 2003 से अब तक तीन बार विधानसभा। और तीन बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पीएम मोदी की पसंद और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर पिछले कार्यकाल के बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए बिरला को दोबारा मौका मिला है। पीएम मोदी संसद में दिए भाषण में भी ओम बिरला की तारीफ कर चुके हैं। बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। यह पांचवी बार है जब कोई स्पीकर एक लोकसभा के कार्यकाल से अधिक इस पद पर रहेगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान के हाड़ौती की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली है।

विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा को हाड़ौती में कम नुकसान हुआ था। इसलिए 61 साल के ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद देकर एक बड़ा संकेत दिया है। अभी तक हाड़ौती क्षेत्र से वसुंधरा राजे बड़े नेता के तौर पर जानी पहचानी जाती थीं। वहीं बिरला इस बार बड़े मुश्किल से चुनाव जीतकर आए हैं और उन्हें 50 हजार से कम वोटों से जीत मिली है, जबकि, पिछली बार 2.5 लाख वोटों से जीत मिली थी। इसलिए इस बार उनकी असल परीक्षा थी। आपको बता दें कि हाड़ौती में अभी तक वसुंधरा राजे को बड़ा नेता माना जा रहा था। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला अब इस क्षेत्र के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की पूरी राजनीति बदल जाएगी और हाड़ौती क्षेत्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो भी भितरघात हुआ था अब उसे ठीक करना भी बिरला के जिम्मे होगा। दूसरी तरफ, राजे के कई समर्थक विधायक अभी भी बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं, उन्हें संभालना भी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा।आपको बता दें कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद बसुंधरा राजे से किनारा कर लिया है जिससे राजे को बहुत ठेस पहुंचा है। वहीं अब राजे आने वाले दिनों में क्या फैंसला करती है। यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। पर अब यह तय है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में डाउन फाल की परते धीरे - धीरे खुल रही है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

वृष
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

मिथुन
किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

कर्क
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

सिंह
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

कन्या
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

तुला
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

वृश्चिक
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

धनु
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

मकर
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

कुंभ
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

मीन
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी। सुख-शांति बनी रहेगी।

शख्सियत

अख्तर हुसैन
(एमईएस)

नमस्कार दोस्तों आज हमारी शख्सियत कॉलम के सुपर डुपर स्टार हैं सन 1970 में अलवर में जन्मे अख्तर हुसैन। 25 दिसंबर 1981 का दिन अख्तर और उनके परिवार के लिए सच में कयामत का दिन था। महज 11 साल की उम्र में अब्बू अचानक अल्लाह को प्यार हो गए। अपने 3 साल के छोटे भाई अनवर और 15 साल की बहन रशीदा की जिम्मेदारी महज 11 साल के सब अबोध बालक के कंधों पर आ गई। इतना छोटा बालक जिसकी उम्र खेलने कूदने की मौज मस्ती की और पढ़ाई लिखाई करने की होती है उसे काम धंधा ढूंढना पड़ा। अपनी मां अपने भाई और बहन की परवरिश के लिए अख्तर एक स्कूटर की दुकान पर जा लगा जहां उसे दुकान मालिक 5 रु. हर सप्ताह देते थे। यूँ तो पिताजी की पेंशन मां को मिलती थी पर उस जमाने में तनख्वाह भी कम होती थी तो 116 रुपए मां की पेंशन मिलती जो कि परिवार का भरण पोषण और बच्चों की परवरिश के लिए काफी कम थी। इसलिए अख्तर के नन्हे हाथ भारी भरकम ओजारो पर चले, हाड़ कपकपाने वाली कड़ाके की ठंड में जब लोग रजाई में दुबके रहते तब ये बालक सर्विस की गाड़ियों को धोता था,तेज गर्मी में जब लोग कूलर पंखों का सहारा लेते तब ये बालक आग में तप रहे औजारों से खेलता था और दो साल बाद नन्हा किशोर अख्तर हैड मिस्त्री बन गया। संघर्ष के थपेड़ों ने अख्तर को कुंदन बना डाला जिसने परिवार की परवरिश की बहन की शादी की। लंबे संघर्ष के बाद पिताजी की जगह सन 2002 में एमईएस में नोकरी लगी। आज हमारे अख्तर भाई एमईएस(मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस) ईटाराना में रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। दोस्तों सही मायने में ऐसे लोग ही शख्सियत हैं जिन्होंने अपने उन संघर्ष के दिनों में अपना आत्मविश्वास नहीं खोया बल्कि आत्मविश्वास और कर्तव्य निष्ठा के पद पर चले। अख्तर भाई बहुत सरल, सहज, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ और लास्ट में कहूंगा कि यारों के यार हैं। अच्छे वक्त में खड़े हो ना हो पर बुरे वक्त में ये हमेशा खड़े रहते हैं। दु:खी लोगों की सेवा करना इनकी सच्ची इबादत है। पेड़ पौधों का रख रखाव करना,उन्हें पानी देना इनके शौक हैं। मैं व्यक्तिगत इन्हें जानता हूं समय चाहे कैसा भी हो हमेशा मुस्कान चेहरे पर बनाए रहते हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

आज का इतिहास

1 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज सेना के बीच पोर्टो नोवो (अब परांगीपेट्टई) का युद्ध 1781 में हुआ।
- 1 जुलाई, 1852 को सिन्ध के मुख्य आयुक्त सर बर्टलेफ्रोरे द्वारा सिर्फ़ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए ' सिंध डाक ' नामक डाक टिकट जारी किया गया।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में हुआ।
- कनाडा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1878 में शामिल हुआ।
- भारत में 1879 को पोस्टकार्ड की शुरुआत हुई।
- 1881 में आज ही के दिन टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल की गई।
- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना 1921 में हुई।
- मुहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का उद्घाटन किया
- त्रावनकोर-कोचीन राज्य 1949 में बना दिया गया किंतु मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन रहा।
- इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया।
- यूएस पोस्ट ऑफिस ने 1963 में जिप कोड प्रणाली को लागू किया।
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की।
- इलेक्ट्रानिक उपकरण बनाने वाली कंपनी सोनी ने 1979 में वाकमैन पेश किया।
- न्यूयॉर्क में खेल को 1987 में समर्पित स्टेशन 'डब्लूएएफएन' स्थापित किया किया।
- पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच सीमा रेखा की समाप्ति एवं पश्चिमी जर्मनी की मुद्रा को पूर्वी जर्मनी में 1990 को मान्यता मिली।
- बारसा संधि 1991 में भंग की गयी।
- यासर अराफात 1994 में 27 साल के निर्वासन के बाद स्वदेश वापस लौटे थे।
- रोमान हर्जोग द्वारा जर्मनी के नये राष्ट्रपति के रूप में 1994 को शपथ ग्रहण की।
- सं.रा. अमेरिका ने 1995 में ताईवान के ख़िलाफ़ लगाये गये प्रतिबंध को हटाया।
- ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में 1996 को स्वेच्छा मृत्यु क़ानून विश्व में पहली बार लागू।
- ब्रिटिश सरकार ने 1997 में हांगकांग का शासन चीन को सौंपा था।
- देश की पहली साइंस सिटी 1997 को कोलकाता में स्थापित की गई।
- लार्ड्स के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 2000 में वेस्टइंडीज को हराया।
- समुद्र में 2003 को सबसे गहराई तक जाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाली जापानी पनडुब्बी प्रशांत महासागर में लापता।
- आसियान ने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने हेतु ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया।
- एशियाई युवा शतरंज चैम्पियनशिप में भारत ने 2006 में 8 स्वर्ण जीते।
- अमेरिकी संसद की समितियों ने 2006 में भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते को मंजूरी प्रदान की।

विशेष आलेख

सोनाक्षी और इकबाल की शादी रोमांचक किंतु चुनौतीपूर्ण होते हैं ऐसे विवाह

अनुज अग्रवाल

शादी कहने को तो निजी मामला है पर हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में यह स्त्री एवं पुरुष के शारीरिक संबंधों को सामाजिक स्वीकृति से अधिक सामाजिक , आत्मिक एवं आध्यात्मिक आयाम लिए हुए है। भारत में विवाह दो व्यक्तियों का नहीं दो परिवारों का होता है। ऐसे में हिंदू फ़िल्म अभिनेत्री सोनाक्षी अगर एक मुस्लिम युवक इकबाल से विवाह बंधन में बंधे तो यह केवल चर्चा का मुद्दा बन जाता है बल्कि अनेक विवादों को भी जन्म दे देता है।

शुद्ध हिन्दुवादियों के लिए लव जिहाद का एक उदाहरण है जिसमें अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह एक कॉंट्रैक्ट मैरिज जैसा भी कुछ पका है (जिसके लिए सोनाक्षी को बड़ी रक़म जिहादियों द्वारा दी गई है) जो तीन साल बाद समाप्त हो जाएगी किंतु इससे प्रेरित होकर हज़ारों हिंदू युवतियाँ मुस्लिम युवकों से शादी करने के लिए प्रेरित हो सकती हैं और लव जिहाद की शिकार हो सकती हैं। कट्टर मुस्लिम और जिहादी भी इस विवाह को इसी रूप में ले रहे हैं और इसको इस्लाम की जीत बता रहे हैं। मध्यममार्गी हिंदुओं के अनुसार इस विवाह में कुछ गलत नहीं है। दोनों सोनाक्षी एवं इकबाल कई वर्षों से एक दूसरे को जानते थे और प्यार करते थे। स्वाभाविक है एक दूसरे की कमज़ोरियों एवं ताकत का उनको अंदाज़ा होगा ही। दोनों के परिवार भी एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो चुके होंगे और दो धर्मों के युवक युवती के इस विवाह की चुनौतियों को गहराई से समझते होंगे। फिर इस विवाह में सोनाक्षी ने ना तो धर्म बदला और ना ही मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी की है। वे कोर्ट मैरिज के माध्यम से इक़बाल से जुड़ी हैं और आज भी हिंदू हैं। यद्यपि उनके विवाह को इस्लाम में निकाह ही समझा जाएगा और उसी के अनुरूप उनको आचरण करना होगा। अगर गहराई से देखें तो जीवन शैली एवं आचरण में न तो सोनाक्षी पूर्ण रूप से सनातनी हैं और न ही इकबाल इस्लामिक। दोनों परिपक्व वयस्क हैं तथा सफल व्यावसायिक जीवन जी रहे हैं। दोनों नारीवादी सोच , किसी हद तक स्वतंत्र सोच एवं जीवन जीने वाले, पाश्चात्य जीवन शैली एवं विचारों से प्रभावित हैं और अपना भला बुरा जानते हैं। ऐसे में वे जो कर रहे हैं वो उनका निजी मामला और क़ानूनी अधिकार है , जिस पर कोई कैसे आपत्ति कर सकता है। जिस हिंदू माता पिता को लगता है कि उनकी बेटी सोनाक्षी से प्रभावित होकर लव जिहाद का शिकार हो सकती है , या तो उसके पालन पोषण में कोई कमी हो सकती है या बच्ची को दिए गए संस्कारों में। जो हिंदू धर्म से गहराई से जुड़ा होता है वह युवक - युवती सनातन की शिक्षा व संस्कारों से जुड़ा व बंधा होता है और इन खोखले आकर्षण का शिकार नहीं होता। सोनाक्षी जैसे लोग जो खुली सोच के नाम पर कटी पतंग जैसे बन जाते हैं उनको किसी ग़ैर हिंदू से विवाह से होने वाले काल्पनिक झटकों के लिए भी स्वयं को तैयार रखना होगा क्योंकि अगर कुछ बुरा उनके साथ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उनकी और उसके दुष्परिणाम भी उनके। निश्चित रूप से ऐसे में वो प्रहसन की पात्र भी होंगी और नितांत अकेली भी। इसलिए रोमांचक किंतु चुनौतीपूर्ण होते हैं ऐसे विवाह।

व्यस्तता बढ़ी लेकिन सक्रियता नहीं, आज के समय में स्मार्टफोन में उलझे इंसान में घर कर रही सुस्ती की बीमारी

जब किसी व्यक्ति को सुस्त देखा जाता है, तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वह आलसी है। मगर यह इसलिए भी संभव है कि उसकी सक्रियता में कई वजहों से कमी आ रही हो और उसका कारण कोई शारीरिक बीमारी नहीं हो। हालांकि बीमारी की वजह से अगर सक्रियता में कमी आती है तो यह भी सही है कि सक्रियता में कमी से शरीर में बीमारी घर बनाती है। विडंबना यह है कि वक्त के साथ विस्तृत होते दायरे के बीच ज्यादातर लोगों की व्यस्तता तो बढ़ी है, मगर उनकी शारीरिक सक्रियता में तेजी से कमी आई है। 'द लांसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह उजागर हुआ है कि सन 2022 में भारत की सत्तावन फीसद महिलाएं शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थीं, जबकि पुरुषों में यह दर बयालीस फीसद थी। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर मौजूदा परिपाटी जारी रही तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़ कर साठ फीसद तक पहुंच जाएगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी देश की साठ फीसद आबादी अगर शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे तो आने वाले वक्त में वहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी।

संपादकीय

“ सोच-समझकर जोखिम उठाएं। यह जल्दबाजी करने से बिल्कुल अलग है। -जॉर्ज एस. पैटन

संयुक्त राष्ट्र की ताजा एसडीजी रिपोर्ट को एक चेतावनी की तरह लिया जाना चाहिए, जो सावधान करती है कि सात अरब लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए तय किए गए वैश्विक लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। जरूरी है कि सभी देश इन लक्ष्यों की गंभीरता को समझें और तदनुरुप प्रयासों का पुनर्मूल्यांकन भी करें।

इसे चेतावनी मानें

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट को एक चेतावनी के तौर पर लिया जाना चाहिए कि जो सावधान करती है कि बेहतर दुनिया की उम्मीद में तय किए गए सतत विकास लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा जारी रिपोर्ट साफ कहती है कि दुनिया के सात अरब से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए 169 लक्ष्यों में से केवल 17 फीसदी लक्ष्य ही 2030 तक पूरे होने की संभावना है, बाकी 83 फीसदी लक्ष्यों पर प्रगति या तो रुकी हुई है या स्थिति पहले से भी खराब हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के प्रारूप को स्वीकारा गया था, जिनके तहत निर्धारित लक्ष्यों को 2015 तक पूरा किया जाना था। लेकिन जब निर्धारित अवधि में ये लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, तब 2015 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की सत्रहवीं बैठक में सदस्य देशों द्वारा सत्रह सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्हें फिर 169 लक्ष्यों में बांटा गया और इनके लिए 2030 की समय-सीमा भी तय की गई, जो एक बार फिर कम पड़ती दिख रही है। ताजा रिपोर्ट का यह कहना कि कोरोना के चलते 2019 की तुलना में 2022 में गरीबी और भुखमरी की चपेट में आए लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, साथ ही, ऊर्जा व शिक्षा संबंधी लक्ष्यों में भी हम काफी पीछे हैं, दर्शाता है कि शांति, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय वित्त सहित गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में दुनिया की विफलता, विकास को कमजोर कर रही है और भावी पीढ़ियों के लिए इन लक्ष्यों को पाना और भी मुश्किल बना रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के एक दिन बाद जारी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि चुनौतियां अब भी बेशक बड़ी हैं, पर भारत कई संकेतकों पर अच्छा काम कर रहा है। नवजात शिशुओं की

मृत्यु का आंकड़ा 2015 के 25 से 2020 में 20 प्रति हजार पहुंच गया है, तो पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों (12-23 महीने की उम्र के बीच) की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 76.6 प्रतिशत हो गई है। उच्चतर माध्यमिक में प्रवेश करने वाले बच्चों का अनुपात भी बढ़ा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में एसडीजी दुनिया के सामने मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का एक समावेशी प्रयास है, जिनमें नाकामी चिंताजनक है। ऐसे में, एक समृद्ध, सुरक्षित व न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए जरूरी है कि सभी देश इन लक्ष्यों की गंभीरता को समझते हुए अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें।

इस दांव में जोखिम बहुत है

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पहली प्रेसिडेंशियल बहस में जो बाइडन याद की गई पंक्तियां और आंकड़े भूल रहे थे। यह दिल दहलाने वाला है, क्योंकि वह परमाणु कोड भी नियंत्रित करते हैं। भले ही उनके सहयोगी रक्षात्मक दीवार और ऊंची कर दें, लेकिन उन्हें समझना होगा कि इस दांव में जोखिम बहुत है।

वह स्वार्थी हो रहे हैं। वह खुद को देश के आगे रख रहे हैं। वह अवसरवादी समर्थकों से घिरे हैं। वह वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जहां हमें कहा जाता है कि जो साफ दिख रहा है, उस पर भरोसा न करें। उनका अभिमान क्रोधित करने वाला है। वह कहते हैं कि वह यह सब हमारे लिए करते हैं, जबकि वास्तव में अपने लिए कर रहे हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि दूसरे राष्ट्रपति की बात कर रही हूं। वाशिंगटन में लोग अक्सर वही बन जाते हैं, जिसकी वे शुरुआत में निंदा करते हैं। ठीक यही बाइडन के साथ हुआ। दूसरे कार्यकाल की गुमराह खोज (जिसके अंत में वह 86 वर्ष के हो जाएंगे) में वह ट्रंप के जैसा ही व्यवहार करने लगे हैं। और वह उसी लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, जिसे बचाने का दावा करते आए हैं। बाइडन से मेरा पहला परिचय 1987 में हुआ, जब वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के अग्रणी नेता के रूप में सराहा जाता था। मैंने उन्हें उस दौड़ से बाहर कर दिया, जब मैंने लिखा कि किस तरह वह नील किन्नॉक की नकल करते हैं, जो ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता और एक प्रखर वक्ता थे और किस तरह उन्होंने शायद अनजाने में ही रॉबर्ट एफ. कैनेडी (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई) और अमेरिका के अड़तीसवें उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री की बातों का अपने भाषण में उपयोग किया। मुझे याद है कि मैं बाइडन से सीनेट की सीढ़ियों पर मिली थी, जब वह भाषण देने के लिए जा रहे थे। वह अकेले थे और अपने भाषण की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उस पल के बोझ से दबे हमने खामोशी से एक-दूसरे को देखा और अलग-अलग रास्तों से एक ही न्यूज कॉन्फ्रेंस में पहुंचे।

मौरीन दाउद

बाइडन काफी उत्साही व्यक्ति थे, जिन्हें शुरुआत से ही यह बताया गया कि उन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए, क्योंकि वह महज 29 वर्ष की उम्र में ही सीनेट चुने गए थे। ऐसे में, भाषण चोरी के आरोप और स्वास्थ्य समस्याओं के बाधा बनने का कोई सवाल ही नहीं था। 1998 में उन्हें दो बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं और बाद में उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि अगर वह चुनाव प्रचार जारी रखते हैं, तो जीवित नहीं बचेंगे। उन्होंने मुझसे मजाक में कहा था कि मैंने उनकी जान बचाई। उन्होंने अन्य समस्याओं को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं हैरान तो थी, पर खुश भी कि बाइडन ने मुझे माफ कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेहतर होगा कि हम अच्छे संबंध बनाए रखें। मैं घृणित सुनवाइयों के दौरान सीनेट न्यायिक समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके काम की आलोचक रही हूं। लेकिन उन्होंने मुझसे नाता नहीं तोड़ा। जब वह उपराष्ट्रपति बने, तो कई अवसरों पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। ओबामा के सहयोगी, पत्रकारों के सामने बाइडन की बुराई करते थे।

बाइडन एक अच्छे और वफादार उपराष्ट्रपति थे और मुझे लगता है कि यह ओबामा की गलती थी कि उन्होंने 2016 में उनके बजाय हिलेरी को प्राथमिकता दी। हिलेरी एक अभिजात्य एवं यथास्थितिवादी उम्मीदवार थीं, और मतदाता अभिजात्य एवं यथास्थितिवाद के खिलाफ थे।

ओबामा की टीम ने इस विचार को प्रसारित किया कि ब्यू (बाइडन के पुत्र) की मौत से बाइडन इतने दुखी थे कि उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन बाइडन अकेले ऐसे व्यक्ति थे, जो अपने दुख का इस्तेमाल अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में सहानुभूति जुटाने के लिए कर सकते थे। अगर उस समय बाइडन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता, तो वह जीत जाते और अब अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करते हुए स्वर्णिम सेवानिवृत्ति के लिए तैयार होते।

इसके बजाय उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत बहुत देर से शुरू की। पिछले कुछ वर्षों से उनका प्रदर्शन स्पष्ट रूप से गिरता जा रहा है, जो लगातार अस्थिर होती दुनिया में खतरनाक बात है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश में क्रांति ला रही है और धार्मिक कट्टरपंथियों से भरा सुप्रीम कोर्ट अमेरिकियों के जीवन को बदल रहा है। यही वजह है कि लगभग दो साल पहले एक कॉलम में मैंने बाइडन को सुझाव दिया था कि आप अपने अच्छे कामों के लिए जीत हासिल करें और पार्टी के युवा सितारों को मौका दें।

लेकिन वह यह साबित करना चाहते थे कि वह उस व्यक्ति से बेहतर राष्ट्रपति हो सकते हैं, जिसने उन्हें किनारे कर दिया था। उनकी पत्नी जिल बाइडन अपने पति को जरूरत से ज्यादा प्रेरित कर रही हैं और उन्हें बचा रही हैं। बृहस्पतिवार की बहस में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद उन्होंने बाइडन को प्रोत्साहित करते हुए कहा-'आपने बहुत अच्छा बोला! आपने हर सवाल का जवाब दिया! आप सब कुछ जानते हैं!' यह उस व्यक्ति से कहा गया, जो परमाणु कोड को नियंत्रित करता है।

सीएनएन के वैन जोन्स ने कहा कि एक अश्वेत नेता ने उन्हें फोन कर इस घटना का सही आकलन करने के लिए खरी-खोटी सुनाई। इस बहस को 'आपदा' बताने वाले डेमोक्रेटिक रणनीतिकार पॉल बेगाला ने सीएनएन पर कहा कि 'जो भी डेमोक्रेटिक नेता बाइडन को पहले पद छोड़ने के लिए कहेगा, उसका कॅरिअर खत्म हो जाएगा। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडन एक प्रिय व्यक्ति हैं।'

बहस के वक्त वह याद की गई पंक्तियां और आंकड़े भूल रहे थे। वह उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो केवल एक ही दिशा में जाती हैं। यह दिल दहलाने वाला है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हैं और बच्चों की तरह हकला रहे हैं। भले ही उनकी पत्नी और उनके कर्मचारी रक्षात्मक दीवार को और ऊंची कर देंगे और पत्रकारों को भगा देंगे, लेकिन बाइडन, जिल और डेमोक्रेटिक नेताओं को इस तथ्य का सामना करना पड़ेगा कि इस दांव में असाधारण जोखिम है। दांव पर लोकतंत्र है। जेम्स कार्विल, जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि राष्ट्रपति को दूसरे कार्यकाल को त्याग देना चाहिए, ने कहा कि बाइडन को चार जुलाई को अपने भाषण में घोषणा कर देनी चाहिए कि वह डेमोक्रेटिक नेताओं की अगली पीढ़ी को मौका देना चाहेंगे। 79 वर्षीय रणनीतिकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'आप उम्र के साथ रेस नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि मैं उम्र को हराने के लिए हर संभव कोशिश करता हूं, पर कोई फायदा नहीं है।'

लेकिन बाइडन और जिल अगर टिके रहे, तो क्या होगा? इस प्रश्न के जवाब में कार्विल ने पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर्ड के अधीन काम कर चुके शीर्ष अर्थशास्त्री हर्ब स्टेन के उद्धरण को दोहराया-'जो जारी नहीं रह सकता, वह जारी नहीं रहेगा।'

वेंकैया गारू: भारत की सेवा में समर्पित जीवन

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है। वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की यात्रा है। अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, उन्होंने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी विनम्रता से पार किया, वह अपने आपमें एक उदाहरण है। उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला।

वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और जनसंघ एवं भाजपा को मजबूत किया। लगभग 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए। 1980 के दशक के मध्य में, जब एनटीआर सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था, तब वह फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे।

वेंकैया नायडू आज 75 वर्ष के हो गए हैं। राजनीति में अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, उन्होंने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी विनम्रता से पार किया, वह अपने आपमें एक मिसाल है।

वर्ष 1978 में आंध्र प्रदेश ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद भी वह भाजपा विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में भाजपा के लिए भविष्य के बीज बोए थे। उनसे प्रभावित होकर एनटीआर जैसे दिग्गज उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, पर वह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी बने।

1990 के दशक में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुए उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे, तो अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय को चुना। एक मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी।

2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। वह एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात होती थी, तब वह नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नजर आते थे। वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा, महिला और पहली बार चुने गए सांसदों को बोलने का मौका मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया, समितियों को अधिक प्रभावी बनाया और बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया।

जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। वह युवा, जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' के संकल्प के लिए जीवन समर्पित किया था, जब वह सपना पूरा हुआ, तो वह सभापति के पद पर आसीन था।

काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं, जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं।

दूसरा पहलू

अफ्रीका की सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में भोजन, ईंधन और दवा की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।

गरीब मरीजों को साग-पात अमीरों को हड्डियों का शोरबा

अफ्रीका की सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में भोजन, ईंधन और दवा की कीमत सातवें आसमान पर है। दो साल पहले तक अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा नाइजीरिया आज चौथे स्थान पर खिसक गया है। स्थिति यह है कि मुफ्त का चावल लेने के चक्कर में अनेक नाइजीरियाई भगदड़ में मारे जा चुके हैं। कैल्शियम के अभाव में शरीर ऐंठ जाने की बीमारी वाली महिला मरीजों से देश के तमाम अस्पताल भरे पड़े हैं। नाइजीरिया की इस बदतर स्थिति के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो करीब पंद्रह महीने पहले चुने गए राष्ट्रपति ने ईंधन की सब्सिडी खत्म कर दी है। इसके अलावा, मुद्रा के अवमूल्यन से भी स्थिति खराब हो गई है।

रुथ मैक्लीन

पोषण के अभाव में बीमार महिलाओं से नाइजीरिया के अस्पताल भरे पड़े हैं। डॉक्टर महिलाओं को उनकी आर्थिक हैसियत के मुताबिक पोषण लेने के लिए कह रहे हैं।

नाइजीरिया की इस बदतर स्थिति के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो करीब पंद्रह महीने पहले चुने गए राष्ट्रपति ने ईंधन की सब्सिडी खत्म कर दी है। इसके अलावा मुद्रा के अवमूल्यन से भी स्थिति खराब हो गई है।

नाइजीरिया के लोगों को उद्यमिता में महारत हासिल है। वे बिजली के उत्पादन से लेकर पानी के इंतजाम तक का काम खुद करते हैं, और सरकार पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। जब जरूरत पड़ती है, वे हथियार लेकर अपने देश की रक्षा में जुट जाते हैं, और इस काम में अपने सुरक्षा बलों को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन बदतर आर्थिक स्थिति के कारण फिलहाल वे कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। पोषण के अभाव में बीमार महिलाओं से नाइजीरिया के अस्पताल भरे पड़े हैं। उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि डॉक्टर महिलाओं को उनकी आर्थिक हैसियत के मुताबिक पोषण लेने के लिए कह रहे हैं। जैसे, गरीब महिलाओं को टाइगर नट्स जैसी वनस्पति का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है, तो अपेक्षाकृत समृद्ध स्त्रियों को हड्डियों का शोरबा पीने के लिए कहा जा रहा है। देश में दूध की इतनी कमी है कि बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी यह सुलभ नहीं है।

नाइजीरिया में 8.7 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। लेकिन विश्व बैंक का मानना है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से नाइजीरिया में गरीबों की संख्या में और वृद्धि होगी। इस महीने की शुरुआत में यूनियनों ने निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए अस्पतालों, बैंकों, स्कूलों और अदालतों में ताला लगाने के साथ-साथ संसद और हवाई अड्डों तक को बंद कर दिया था। हालांकि वास्तविकता यह है कि नाइजीरिया के 92 फीसदी लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, और उनके समर्थन में कोई यूनियन नहीं है।

आंकड़े

शीर्ष दूरसंचार सेवा प्रदाता

भारतीय दूरसंचार में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के मामले में इन पांच शीर्ष सेवा प्रदाता कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 98.35 फीसदी है।

रिलायंस जियो	47.85
भारती एयरटेल	26.96
वीआई	12.65
बीएसएनएल	2.467
एट्रिया	0.224

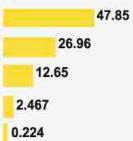

आंकड़े करोड़ में, फरवरी, 2024 तक के | स्रोत : TRAI

ऋषि शृंग की सलाह पर यज्ञ कराने से अंगदेश में वर्षा हुई, जिससे खुश होकर राजा रोमपद ने शांता का विवाह ऋषि से करा दिया।

शांता का विवाह

अंतर्यात्रा
संकलित

माता कौशल्या की बेटी शांता बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। एक बार महारानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी उनसे मिलने आई थी। वर्षिणी का विवाह अंगदेश के राजा रोमपद के साथ हुआ था, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिणी ने शांता की शालीनता से मोहित होकर कहा, 'मेरी कोई भी संतान नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि शांता जैसी ही मेरी भी एक पुत्री हो।'

वर्षिणी की इस बात पर राजा दशरथ ने उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंगदेश के राजा रोमपद की पुत्री बन गई। एक दिन राजा रोमपद किसी काम में इतना खोए थे कि उन्हें चौखट पर आए एक ब्राह्मण की आवाज सुनाई ही नहीं दी। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटना पड़ा।

देवराज इंद्र को ब्राह्मण का यह अपमान ठीक नहीं लगा। उन्होंने अंगदेश में वर्षा न करने का निश्चय कर लिया। ऐसे में, बिना वर्षा के अंगदेश में सूखा पड़ गया और अकाल की स्थिति पैदा हो गई। राजा रोमपद ऋषि शृंग के पास उपाय पूछने गए। ऋषि ने राजा को यज्ञ कराने की सलाह दी, ताकि रूठे इंद्र देव को मनाया जा सके। राजा रोमपद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद अंगदेश में पुनः वर्षा हुई। ऋषि शृंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने उनसे शांता का विवाह करा दिया। उसी ऋषि शृंग ने राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कामाक्षी यज्ञ कराने की सलाह दी थी।

आज का इतिहास

देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू

देश की अर्थव्यवस्था के लिए साल के सातवें महीने का यह पहला दिन इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना गया, जब केन्द्र की नरेन्द्र मोदी नीत सरकार 2017 में इसी दिन देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को अमल में लेकर आई। देश की कर प्रणाली में सुधार की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम करार दिया गया। 1781 में हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध। 1852 में सिंध के मुख्य आयुक्त सर बर्टलेफ्रेरे द्वारा सिफ.रु सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए 'सिंध डाक' नामक डाक टिकट जारी किया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया।

चांदी हो रही सोना

सोने की बढ़ती कीमतों से चांदी की मांग तो बढ़ी ही है, इलेक्ट्रिक वाहन व सोलर पैनल इत्यादि को बढ़ावा दिए जाने से भी इसकी मांग बढ़ रही है।

ऋषभ मिश्रा | धातु

बीते कुछ महीनों में गर्मी की तरह ही चांदी ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह 92,873 हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई और भारत में ऑलटाइम हाई का रिकॉर्ड बना दिया। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में बुलियन बाजार में चांदी की इसी तरह से चांदी चलती रहेगी। वैसे बीते चार दशकों के दौरान इसके दाम 26 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं।

गौरतलब है कि उद्योगों-खासकर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों, सोलर पावर के सोलर पैनल्स और 5-जी टेक्नोलॉजी में चांदी की खपत ज्यादा हो रही है। इससे चांदी की सालाना मांग में सात से आठ फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इस तरह मांग बढ़ने से इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। मांग की तुलना में चांदी की

खनन गतिविधियां लगभग स्थिर हैं, बल्कि इसमें आंशिक गिरावट भी आई है। 2015 में जहां चांदी का वैश्विक खनन 89.7 करोड़ आउंस (एक आउंस यानी 28.34 ग्राम के बराबर) हुआ था। वहीं, 2023 में यह गिरकर 82.4 करोड़ आउंस रह गया। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब कई लोग, खासकर माध्यम वर्ग आभूषणों के लिए चांदी की तरफ देख रहे हैं। वस्तुतः पिछले दो दशक में उद्योगों और प्रौद्योगिकी में चांदी की उपयोगिता बढ़ी है।

'इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी' की हालिया रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक साल में सोलर पावर में इस्तेमाल होने वाले फोटोवोल्टेइक पैनल्स में निवेश एक साल पहले की तुलना में दोगुना होकर 80 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फोटोवोल्टेइक पैनल्स में चांदी का काफी इस्तेमाल होता है। साल 2024 में ही चांदी की वैश्विक मांग में 1.2 अरब आउंस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लिहाजा, चांदी की कीमतों के भी लगातार ऊंचे होते चले जाने की संभावना है। दरअसल, चांदी दुनिया की सबसे बढ़िया सुचालक धातु है। इसलिए सोलर पैनल्स पर चांदी का पेस्ट किया जाता है। जब सूरज का प्रकाश उसके पैनल्स पर गिरता (स्ट्राइक) है, तब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और चांदी विद्युत को तुरंत गतिशील कर देती है।

आज भी सिनेमा को सिल्वर स्क्रीन कहकर संबोधित किया जाता है। दरअसल सिनेमा की शुरुआत में फिल्में प्रोजेक्टर के जरिये दिखाई जाती थीं। इसके लिए जिस परदे पर तस्वीर प्रोजेक्ट की जानी होती थी, उसका चमकदार होना जरूरी था, ताकि परावर्तन (रिफ्लेक्शन) बढ़ने से तस्वीरों की गुणवत्ता बढ़ सके। परदे को ज्यादा चमकदार बनाने के लिए तब स्क्रीन को 'मैटेलिक सिल्वर' से 'कोट' किया जाता था। उसी से यह शब्द उत्पन्न हुआ और आज भी अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है।

दरअसल, चांदी सबसे ज्यादा सूर्य की किरणों को परावर्तित करने वाली धातु है। भारत में चांदी का 50.7 प्रतिशत इस्तेमाल उद्योगों में, 17.8 प्रतिशत आभूषणों में, 24.5 प्रतिशत कॉइन्स-बार्स निवेश में, 2.8 प्रतिशत फोटोग्राफी में और 4.2 प्रतिशत चांदी के बर्तनों में उपयोग किया जाता है।

चार मई, 1989 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह की सतह की 'मैपिंग' के लिए 'मैगलेन' स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था। चूंकि चांदी में प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसके मद्देनजर इसे घातक सौर विकिरण से बचाने के लिए इस पर 'सिल्वर कोटेड क्वार्ट्स टाइल्स' लगाई गई थीं। इसके बाद से सभी स्पेस क्राफ्ट के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाने लगी है। इससे स्पेस क्राफ्ट के तापमान को कम करने में मदद मिलती है। दुनिया में छोटी-बड़ी मिलाकर कुल 757 सक्रिय चांदी की खदानें हैं। इनमें से भारत में केवल छह हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 138 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

अमेरिका में क्यों जमा हुई 29 देशों की सेना? भारत की नेवी भी पहुंची, चीन-रूस में मचा हड़कंप

गाजा, यूक्रेन और सूडान में जंग चल रही है। रूस और अमेरिका की तरफ से अपने अपने मित्र देशों के साथ सुरक्षा समझौते करने में लगा है। चीन ताइवान पर कब्जे की फिराक में बैठा है। दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है। तमाम देश अपने अपने तरीके से खुद को मजबूत बनाने और शांति कायम करने के प्रयासों में भी लगा हुआ है। वहीं चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में यूएस पैसिफिक फ्लीट हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी कर रहा है। हर दूसरे वर्ष आयोजित होने वाला, रिमपैक इस वर्ष बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए तैयारियों को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ चार सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए 29 देशों की सशस्त्र सेनाओं को एक साथ लाता है। वैसे तो भारत कई देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहता है, जिससे उसकी ताकत में तो इजाफा होता ही है और उन देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत होते हैं। भारत ने फिर ऐसे ही एक मेरीटाइम एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है।

150 लड़ाकू विमान, 40 जंगी जहाज, 3 पनडुब्बियां और करीब 25 हजार सैनिक भाग ले रहे हैं। वैसे तो ये युद्धभ्यास 1971 से लगातार होता आ रहा है, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग ही है। इस बार के रिमपैक में इजरायल भी शामिल हो रहा है। इतिहास में ये तीसरा बार है। इजरायल की भागीदारी इसलिए भी खास है क्योंकि वो गाजा में पिछले 9 महीने से जंग लड़ रहा है। इसमें युद्धअपराध जैसे आरोप झेल रहे इजरायल के शामिल होने की वजह से कई देशों की तरफ से आपत्ति भी जताई गई है। कुल मिलाकर कहे तो रिमपैक पर विभिन्न मुद्दों को लेकर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। रिमपैक की स्थापना 1971 में हुई थी। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके संस्थापक देश हैं। इसका मकसद अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के बीच संबंधों में मजबूती और इंडो पैसिफिक के त्रासदियों और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अमेरिका इसे लीड करता है और इसका मुख्यालय पर्ल हार्बर में है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, ब्रूनेई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजरायल, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरु, साउथ कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाइलैंड और टोंगा। रिमपैक हर दो साल पर जून और जुलाई के महीने में होता है। 2024 में ये 27 जून से 1 अगस्त तक चलेगा। ये कोई औपचारिक संगठन नहीं है इसलिए इसमें देशों की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। उसी अनुपात में सैनिकों और जहाजों की संख्या कम और ज्यादा होती रहती है। 2022 में 26 देश शामिल हुए थे, 2014 में 22 देशों ने हिस्सा लिया था, जबकि 2024 में ये संख्या बढ़कर 29 हो गई है। 1971 के शुरुआत में सिर्फ आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका की सेना शामिल हुई थी। चीन ने 2014 और 2016 में रिमपैक में भाग लिया था, लेकिन बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच, 2018 में उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। इस वर्ष के आयोजन में उसे आमंत्रित नहीं किया गया है।

इस महीने की शुरूआत में सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग शिखर सम्मेलन में एक भाषण में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने जोर देकर कहा कि एशिया प्रशांत अमेरिकी सुरक्षा रणनीति के केंद्र में था। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका केवल तभी सुरक्षित हो सकता है जब एशिया सुरक्षित हो। जब एक चीनी प्रतिनिधि ने पूछा कि क्या अमेरिका इस क्षेत्र में नाटो जैसा गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ऑस्टिन ने जवाब दिया कि समान मूल्यों वाले और स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के समान दृष्टिकोण वाले समान विचारधारा वाले देश एक साथ काम कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, और हमने अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत किया है और हम देखते हैं कि क्षेत्र में अन्य देश भी एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। पुतिन की प्योंगयांग यात्रा से पहले बोलते हुए स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि यूरोप में जो होता है वह एशिया के लिए मायने रखता है और एशिया में जो होता है वह हमारे लिए मायने रखता है।

चीन को समझ आता है कि इतने सारे देश जब एक साथ आते हैं। ब्राजील, अमेरिका, मैक्सिको, बेल्जियम जैसे देशों के लिए एक बाइंडिंग फैक्टर है। इस वर्ष के RIMPAC में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रशिक्षण भी शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और गैर-लाभकारी समूहों जैसे बाहरी संगठनों के साथ काम करने वाले आठ देशों के अभियान बल और 2,500 प्रतिभागी। प्रशिक्षण में राज्य-व्यापी सामूहिक हताहत अभ्यास और विदेशी आपदाओं के लिए संकट प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना, साथ ही एक शहरी खोज और बचाव अभ्यास शामिल होगा जो रमानवीय संकट के दौरान वास्तविक दुनिया के संचालनर को दर्शाता है। आयोजक साझेदार देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्लटडअउ की प्रशंसा करते हैं, यह पर्यावरण और जलवायु कार्यकर्ताओं, स्वदेशी समूहों और क्षेत्र के अन्य लोगों की आलोचना भी कर रहा है जो इस अभ्यास को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। भारत द्वारा पिछले दस सालों में इसमें हिस्सा लिया जाना शुरू हो गया है। इसके पीछे की वजह भारत को अमेरिका के साथ रिश्ते को कायम रखना भी है। रिमपैक के ड्राइविंग फोर्स अमेरिका ही है। भारतीय नौसेना की प्रभाव और क्षमता को सभी जानते हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना की उपस्थिति रणनीतिक आयाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत को भी खतरा है। चीन हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाता है तो भारत पैसेफिक में जाकर अपना दायरा बढ़ा रहा है। इंडो पैसेफिक के जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालें तो सारे महत्वपूर्ण बदलाव भारत को प्रभावित करते हैं। ताइवान की खाड़ी में अगर कुछ होता है तो वो भारत पर उसका असर पड़ेगा क्योंकि वहां से अंडरसी केबल जाता है, जिस पर हमारा पूरा आईटी, सॉफ्टवेयर निर्भर है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भाग लेने से सभी देशों की नेवी से संपर्क आना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर देखें तो इसका सभी देशों को बहुत फायदा होता है।

सुखबीर को अध्यक्ष पद से हटाना विपक्षी नेताओं के लिए आसान नहीं

लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल बादल के खराब प्रदर्शन के बाद शिरोमणि अकाली दल बादल के कई नेता पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही सुखबीर सिंह बादल को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कई नेता आवाज उठा रहे थे और इसी का नतीजा था कि उन्हें या तो पार्टी से बाहर कर दिया गया या फिर कुछ ने इस्तीफा दे दिया। अकाली दल बादल के कई बड़े नेताओं ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ बैठकें कीं। अनौपचारिक बैठक में सुखबीर सिंह बादल से इस्तीफे का अनुरोध पारित किया गया। अकाली दल का नया अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा हुई और नए अकाली दल को चलाने के लिए एक 11 या 21 सदस्यीय कमेटी बनाने पर भी चर्चा हुई। अगर यह अकाली नेता ऐसा करेंगे तो अकाली दल बादल का टूटना तय है और ऐसा पहली बार नहीं होगा। 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना के बाद 1928, 1939, 1942, 1960, 1967, 1969, 1971, 1980, 1985, 1989 से 1999 में अकाली दल में दो फाड़ पैदा रहा। और अकाली दल की सरकारों का टूटने का कारण भी बनता रहा। देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी अकाली दल का असली नाम शिरोमणि अकाली दल है, न कि अकाली दल बादल। शिरोमणि अकाली दल का नाम अकाली दल बादल तब लोकप्रिय हुआ जब 1999 में अकाली दल विभाजित हो गया क्योंकि प्रकाश सिंह बादल ने गुरचरण सिंह टोहरा को पार्टी से निकाल दिया और टोहरा ने नया अकाली दल बनाया। उस समय, गुरचरण सिंह टोहरा के नेतृत्व वाले अकाली दल (सर्ब हिंद अकाली दल) को टोहरा अकाली दल के नाम से जाना जाने लगा और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल को अकाली दल बादल के नाम से जाना जाने लगा। करीब 25 साल के अंतराल के बाद अकाली दल एक बार फिर टूट की स्थिति में पहुंच गया है। एक तरफ सुखबीर विरोधी अकाली नेता बैठकें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सुखबीर सिंह बादल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुखबीर विरोधी अकाली नेताओं ने जिसमें प्रेम सिंह चंदू माजरा, बीबी जगीर कौर, सिकंदर सिंह मलूका, सुरजीत सिंह रखड़ा, संता सिंह उम्मेदपुरी, परमिंदर सिंह ढींडसा, गुरप्रताप सिंह वडाला समेत करीब 60 अकाली नेता शामिल हुए, ने सुखबीर सिंह बादल के स्थान पर बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली धार्मिक शख्सियत को अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई है। इस तरह किसी जत्थेदार या संत को अध्यक्ष बनाने की योजना पर रोक लग रही है। हालांकि इससे पहले विरोधी गुट ने पांच सदस्यीय प्रिजिडियम बनाने पर भी विचार किया था और इसके लिए मनप्रीत अयाली, परमिंदर सिंह ढींडसा और गुरप्रताप सिंह वडाला समेत 3 नाम लगभग तय हो गए थे। सुखबीर बादल के विरोधियों ने सुखबीर को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नया अध्यक्ष बनाने की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन अकाली दल के कार्यकत्राओं और आम समर्थकों के बीच इस बात को लेकर गहरी चर्चा है कि यह सारी कवायद किन मुद्दों को लेकर की जा रही है। इसलिए नहीं कि उस मामले के लिए सुखबीर और खुद व्यभिचार करने वाले भी जिम्मेदार हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं द्वारा बनाए गए गुट पर आम जनता कितना विश्वास करेगी, यह सोचने की बात है।

लोकसभा चुनाव में राजस्थान हुए भाजपा में डाउन फॉल की खुल रही है परते!

अशोक भाटिया

हाल ही में राजस्थान के उदयपुर पहुंचीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित विशिष्ट जन सम्मान समारोह और व्याख्यान माला कार्यक्रम को वसुंधरा राजे संबोधित कर रही थी।उस दौरान उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह भंडारी ने चुन-चुनकर लोगों को भाजपा से जोड़ा। सुंदर सिंह भंडारी ने एक पौधे को वृक्ष बनाया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। कार्यकताओं को ऊंचा उठाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि भंडारी जी ने राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी अंगुली को पहले काटने का प्रयास करते हैं, जिसको पकड़ कर वह चलना सीखते हैं। अब वसुंधरा राजे के इस बयान के बाद तमाम तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से वसुंधरा राजे और पार्टी नेतृत्व के बीच तल्खी देखने को मिली थी, उसकी परते खुलने लगी हैं।

चुनाव के दौरान मन में जो कसक थी, वो अब धीरे-धीरे बयानों के जरिये सामने आ रही है। कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद रहे। राजे ने कहा कि गुलाबचंद कटारिया ने चुन-चुनकर लोगों को भाजपा से जोड़ा है। कटारिया अब असम के महामहिम हैं, लेकिन वह दूर रहकर भी हम लोगों के पास है और ख्याल रखते हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया के बीच भी तल्खी की खबरें सामने आयी थी। इसके अलावा चुनावी नतीजों के बाद पार्टी आलाकमान ने राजे को नजरअंदाज करके भजनलाल शर्मा को राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। ऐसे में दबे स्वर में ही सही भाजपा शीर्ष नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच मनमुटाव की खबरें गाहे-बगाहे सुर्खियां बनती रही हैं।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में ग्यारह सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा और मोदी का जादू नहीं चला। तमाम दिग्गज नेताओं का हालत खराब हो गई। कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगीं हुई थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 में कोटा सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिड़ला का लगातार दूसरी बार इस पद पर काबिज होना राजस्थान में बदलाव की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है, वहीं विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। पहले प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बड़ा पावर सेंटर हुआ करती थीं। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। अब एक पावर सेंटर बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। इससे अलग लोकसभा अध्यक्ष बिरला प्रदेश में नए पावर सेंटर के रूप में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिरला की गिनती मोदी-शाह के नजदीकी नेताओं में होती है।

दरअसल, राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा को नजरअंदाज करने का दौर चल रहा है। वसुंधरा राजे को चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री फेस घोषित नहीं किया। इसके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। लगातार नजरअंदाज किए जाने का दर्द हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की जुबान पर भी आ गया।

आपको बता दें कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी वे केवल अपने बेटे दुष्यंत के लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ तक ही सीमित रहीं। प्रदेश में स्टार प्रचारक की सूची में शामिल होने के बावजूद राजे झालावाड़ के अलावा एक या दो जगह ही प्रचार के लिए पहुंची थीं। जिसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद से राजे का कोई भी राजनीतिक बयान सामने नहीं आया था। लेकिन लंबे समय बाद अब राजे ने चुप्पी तोड़ी हैझ इस बयान के जरिए राजे उनके संरक्षण में आगे बढ़ने वाले नेताओं को निशाने पर लिया है। वहीं राजस्थान के सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कभी वसुंधरा राजे के नजदीकियों में हुआ करते थे। इन्हीं नजदीकियों के चलते पहली बार विधायक बनने पर ही बिरला वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव बनने में सफल रहे। वहीं जल्द ही बिरला ने दिल्ली में बेहतर संबंधों के आधार पर अपना अलग वजूद बना लिया।और 2023 में वसुंधरा के मुकाबले मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने जाने लगे। अब वे प्रदेश के राजनीति में वसुंधरा के बराबरी में आकर खड़े हो गए हैं,और वे एक नए पावर सेंटर बनकर उभरे हैं।

वहीं प्रदेश की राजनीति में भविष्य के निर्णयों में अब बिरला की अहम भूमिका होगी। इसके संकेत खुद गृहमंत्री अमित शाह ने 20 अप्रैल को कोटा की रैली के दौरान दिए थे। शाह ने कहा था कि आप ओम बिरला को संसद भेज दो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। बिरला के पदग्रहण के साथ ही प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता उन्हें बधाई देने दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि बिरला 2003 से अब तक तीन बार विधानसभा। और तीन बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पीएम मोदी की पसंद और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर पिछले कार्यकाल के बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए बिरला को दोबारा मौका मिला है। पीएम मोदी संसद में दिए भाषण में भी ओम बिरला की तारीफ कर चुके हैं। बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। यह पांचवी बार है जब कोई स्पीकर एक लोकसभा के कार्यकाल से अधिक इस पद पर रहेगा।

वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान के हाड़ौती की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। और विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा को हाड़ौती में कम नुकसान हुआ था। इसलिए 61 साल के ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद देकर एक बड़ा संकेत दिया है। अभी तक हाड़ौती क्षेत्र से वसुंधरा राजे बड़े नेता के तौर पर जानी पहचानी जाती थीं। वहीं बिरला इस बार बड़े मुश्किल से चुनाव जीतकर आए हैं और उन्हें 50 हजार से कम वोटों से जीत मिली है, जबकि, पिछली बार 2.5 लाख वोटों से जीत मिली थी। इसलिए इस बार उनकी असल परीक्षा थी।

आपको बता दें कि हाड़ौती में अभी तक वसुंधरा राजे को बड़ा नेता माना जा रहा था। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला अब इस क्षेत्र के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की पूरी राजनीति बदल जाएगी और हाड़ौती क्षेत्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो भी भितरघात हुआ था अब उसे ठीक करना भी बिरला के जिम्मे होगा। दूसरी तरफ, राजे के कई समर्थक विधायक अभी भी बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं, उन्हें संभालना भी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा।आपको बता दें कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद बसुंधरा राजे से किनारा कर लिया है जिससे राजे को बहुत ठेस पहुंचा है। वहीं अब राजे आने वाले दिनों में क्या फैंसला करती है। यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। पर अब यह तय है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में डाउन फाल की परते धीरे झ धीरे खुल रही है।

अपराजेय भारत बना टी-20 विश्वकप विजेता

-नरेंद्र तिवारी 'पत्रकार'

भारत टी-20 विश्वकप क्रिकेट टूनार्मेंट 2024 में विश्वकप विजेता बन गया है। 29 जून को बारबाडोस के कैंसिग्टन ओवल में भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को फायनल मैच में पराजित कर शानदार विजय हासिल की इस जीत में वैसे तो पूरी टीम का अहम योगदान रहा है, किंतु विजय सुनिश्चित करने वाले वह कौनसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने अफ्रीका के पक्ष में दिखाई दे रहे मैच के परिदृश्य को बदला और आखिरी ओवर में भारत ने जीत की इबारत लिखी। फायनल मैच अपनी रोमांचकता के सबाब पर था। अफ्रीका की टीम जीत के करीब थी, अंतिम 6 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी, फटाफट क्रिकेट में यह लक्ष्य कोई बड़ी बात भी नहीं है। हार्दिक पंड्या ने आखरी ओवर की पहली गेंद फैंकी जिसे डेविड मिलर ने सीमा रेखा के पार पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया, गेंद सीमा रेखा पर पहुंची भी जहां तैनात भारत के सूर्य कुमार यादव ने जो फायनल मैच की बैटिंग में खास प्रदर्शन नहीं कर पाएं, किंतु अंचभित करने वाला उनका कैच जिसे आखों देखा हाल सुना रहे नवजोत सिद्धू ने सूर्यकुमार के जीवन का सबसे शानदार कैच भी बताया। मिलर का कैच सूर्यकुमार के संतुलन, समझ और जज्बे का कैच है। कैच लेते समय बाउंड्री के अंदर सूर्या रहे, जब उनका पैर बाउंड्री के बाहर जाने लगा तो उन्होंने गेंद को उछाल कर सीमा के अंदर धकेला और जब वे सीमा रेखा के अंदर हुए तो कैच वापस लपक लिया। सूर्य कुमार के इस लाजवाब कैच ने अफ्रीका के पाले में जाती दिख रही जीत का रुख भारत की तरफ कर दिया। भारत की इस विजय में विराट कोली की महत्वपूर्ण पारी का भी योगदान रहा उन्होंने शुरूवात तेज की बीच में धीमे हुए फिर अपनी पारी की अंतिम कुछ गेंदों पर चौके छक्के जड़ कर 76 रनों का योगदान दिया। अक्षर पटेल की पारी भी विजय की नींव रखने में कामयाम रही। शुभम दुबे ने भी कुछ अच्छे शाट लगाकर भारत के स्कोर को बढ़ाया। गेंदबाजी में भी अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप द्वारा की गई गेंदबाजी जीत की लिखने में कामयाब हो सकी।

भारत ने 17 साल बाद टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया, रोहित की कप्तानी में विश्वकप विजेता बनने का यह पहला मौका है, इससे पूर्व यह अवसर महेंद्रसिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में प्राप्त हुआ था। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और दुनियां के शानदार बल्लेबाजों में शुमार विराट कोली ने टी-20 क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा की है। उनका टी-20 क्रिकेट से सन्यास विश्व विजय के साथ होना इन दोनो खिलाड़ियों की शानदार बिदाई का अवसर माना जा रहा है। फायनल मैच की आखरी गेंद पर मिली भारत की विजय पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा धरती पर लेट गए और ईश्वर को धन्यवाद दिया उनकी आंखों से खुशी की धारा फूट रही थी। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने कहा यह वही भारतीय कप्तान है जिनकी कप्तानी में भारत 2023 विश्वकप मैच के फायनल मैच में पराजित हुआ था तब उनकी आंखों से दुख के आंसू निकलें थे। उस समय भी भारत लगातार विजय हुआ था किंतु फायनल में पराजित हो गया था। रोहित अपना दुख छुपा नहीं पाए थे, आंसू उनकी आंखों से निकल रहे थे। बारबाडोस के आंसू खुशी के प्रसन्नता के गर्व और गौरव के आंसू है।

भारतीय टीम के कप्तान रोहित और पूर्व कप्तान विराट कोली की बिदाई का यह अवसर इन दोनो धाकड़ बल्लेबाजों के लिए अविस्मरणीय पल है। भारत ने टास जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया कप्तान रोहित जल्दी आउट हो गए। ऐसे समय विराट कोली ने संयम का परिचय दिया धीमे ही सही 76 बहुमूल्य रन जोड़े। सेमीफाइनल में जब इंग्लैंड के सामने विराट जल्दी आउट हो गए थे, तब रोहित ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर भारत के फायनल मैच पहुंचने के रास्ता साफ किया था। भारत के इन दोनो महान बल्लेबाजों की आईसीसी टी-20 क्रिकेट से सन्यास का अवसर बहुत बड़ा बन गया है। इस टूनार्मेंट की सबसे बड़ी बात यह रही की भारत अपने सभी मैच जीतकर अपराजेय रहा। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी भारत के मुकाबले कमजोर नहीं थी। इस टीम ने भी फायनल छोड़ सभी मैचों में जीत दर्ज की थी। फायनल मैच में भी अंतिम ओवर तक अफ्रीका मैच में बना हुआ था। उनकी गेंदबाजी, बल्लेबाजी, और क्षेत्ररक्षण बेहतरीन रहा।

अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में आयोजित टीझ20 विश्वकप की कुछ विषयों को लेकर आलोचना भी हुई। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारत कनाडा मैच रद्द होने पर आईसीसी की आलोचना करते हुए कहा फ्लोरिडा में पिच को कवर नहीं किया जा सका और भारत बनाम कनाडा का मैच रद्द हो गया। गीले आउट फील्ड के कारण मैच रद्द होना अव्यवस्थाओं को दशार्ता है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वान ने गीले आउट फील्ड को न ढकने को लेकर आयोजको की आलोचना की थी। कमियों, आलोचनाओं के बाद भी आईसीसी टी-20 विश्वकप अपने अंजाम तक पहुंचा। भारत बनाम अफ्रीका के मध्य रोमांचक फायनल मैच में भारत ने शानदार विजय अर्जित की। 29 जून को भारत के शहरो और गांवों में इस विजय के बाद उल्लास का वातावरण बन गया। भारतीय तिरंगा लेकर नागरिकों ने भारत माता की जय के उदघोष के साथ आसमान गूंजा दिया। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर सहित देश के बड़े शहरों में उत्सव का माहौल बन गया था। फायनल मैच की अंतिम गेंद पर मिली ऐतिहासिक विजय का आंखों देखा हाल बताते हुए बताते पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू ने कहा भारतीय तिरंगा आसमान में लहरा रहा है। भारतवासियों के चेहरों पर खुशी की लहर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। क्रिकेटर इरफान ने कहा भारत ही नहीं विजय हुआ, यह 150 करोड़ भारतीयों की जीत है।

भारत का टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट टूनार्मेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत अपराजेय रहा और अफ्रीका को पराजित कर विश्व चैंपियन बना। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोली की यह सर्वश्रेष्ठ बिदाई मानी जा सकती हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

योगी का कद घटाने से यू.पी. की सीटें घटीं

लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीटें कम मिलने के कारण भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसके बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। दरअसल प्रदेश और देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से उनके मंत्रिमंडल के ही कुछ लोग काफी परेशान हैं। इन मंत्रियों की मुख्यमंत्री बनने की लालसा भी हिलोरें मार रही है। जाने-अनजाने में कुछ केन्द्रीय नेताओं का भी इन्हें संरक्षण मिल रहा था। ये लोग नहीं चाहते थे कि योगी की लोकप्रियता बढ़े। इसलिए लोकसभा के चुनाव में भाजपा को जिताने और बढ़ाने में इनकी कोई विशेष सक्रियता भी दिखाई नहीं पड़ी।

अब पार्टी संगठन एक टास्क फोर्स बनाकर इसके कारणों की छानबीन कर रहा है। प्रदेश में भाजपा की सीटें घटने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण दो बार लगातार चुनाव जीतने वाले सांसदों का अपने-अपने क्षेत्र में भाजपा के कार्यकत्राओं के साथ-साथ जनता से सम्पर्क टूट गया था। यदि आप सांसद या विधायक हैं तो आपको अपने क्षेत्र का बराबर दौरा करना चाहिए। लोगों के दुःख दर्द में शामिल होना चाहिए। उनकी समस्याएं जाननी चाहिएं। जनता ह्यआपह्ल से यही अपेक्षा करती है। ये लोग मोदी और योगी के सहारे चुनाव जीतने की उम्मीदें लगाए बैठे थे, इसलिए अपने क्षेत्रों में जनता से सम्पर्क साधने की जरूरत नहीं समझी। ये लोग अपने घर पर ही ठेका-पट्टा पाने वालों का दरबार लगाते रहे। ऐसे लोगों को दोबारा टिकट देने वाले नेता भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण भाजपा प्रदेश और जिला संगठन भी जनता से दूर हो गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कितने जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए कितनी बार दौरा किया, इसका कोई ब्यौरा पार्टी संगठन के पास नहीं है। प्रदेश पार्टी का आई.टी. सैल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ब्राह्मणों-ठाकुरों को लड़ाया गया, दलितों और पिछड़ों को भरमाया गया। इनके जरिए आरक्षण खत्म करने से लेकर संविधान बदलते तक की बातें तक कही गईं। जिसका प्रदेश भाजपा का आई.टी. सैल कोई जवाब नहीं दे पाया। हर लोकसभा और विधानसभा चुनावों से 6 महीने पहले ही मतदाता सूची का पोङ्कषलग, बूथ स्तर पर संशोधन और परिवर्धन होता है। यदि भाजपा संगठन के कार्यकत्रा अपने-अपने पोलिंग बूथों पर सक्रिय रहते तो हजारों भाजपा समर्थकों के नाम मतदाता सूची से नहीं कटते। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का गारंटी कार्ड का फार्म खासतौर अल्पसंख्यक, अशिक्षित और निर्धन महिलाओं से भरवाया गया। उन्हें डर था कि 3 तलाक के मामले खत्म करने के कारण ये महिलाएं भाजपा को वोट दे सकती हैं। काट के लिए पार्टी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रमुखों की तमाम जिलों में फर्जी सूची बनाई गई जो वास्तव में कहीं थे ही नहीं।

बहरहाल पार्टी संगठन इस हार की समीक्षा के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की सूचनाओं का इंतजार कर रही है। पर यहां सवाल यह उठता है कि क्या कोई संगठन खुद अपनी कमियों को स्वीकार करेगा? इस टास्क फोर्स के काम के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को लगाया गया होता तो शायद सही जानकारी सामने आती। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 2019 में उसे जहां 62 सीटें मिली थीं, वहीं 2024 के आम चुनाव में 33 पर संतोष करना पड़ा है। भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 29 सीटें कम मिलने की पूरे देश में चर्चा है। अब पार्टी भी इस पर मंथन में जुटी है और पूरा फीडबैक लेने के बाद कुछ एक्शन हो सकता है। भाजपा को सबसे ज्यादा हैरानी अमेठी, फैजाबाद (अयोध्या वाली सीट), बलिया और सुल्तानपुर जैसी सीटों पर हार से है। इन सीटों को भाजपा के लिए मजबूत माना जाता था। अमेठी में स्मृति ईरानी की कांग्रेस के एक आम कार्यकत्रा से हार ने पूरे नरेटिव को चोट पहुंचाई है।

इसके अलावा अयोध्या की हार भी कान खड़े करने वाली है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी चुनाव हार गईं जो लगातार जीतती रही हैं। फिर अयोध्या की हार ने तो पूरे नरेटिव को ही चोट पहुंचाई है। भाजपा को उस सीट पर हारना पड़ गया, जहां ऐतिहासिक राम मन्दिर बना है। 500 सालों के इतिहास का चक्र जिस अयोध्या में घूमा, वहां ऐसी हार ने भाजपा को हैरान कर दिया है। अब पार्टी पूरे नरेटिव को कैसे सैट करे और अपनी हार को कैसे पचाया जाए, इसकी तैयारी में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा को आर.एस.एस. और उसके अनुषांगिक संगठनों से भी फीडबैक मिलेगा। संघ के लोगों से भी कहा गया है कि वे समीक्षा करके बताएं कि हार के क्या कारण रहे। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। ये चुनाव नतीजे प्रदेश सरकार के मंत्रियों के लिए सबक है। मंत्रियों को भाजपा के कार्यकत्राओं और जनता के सम्पर्क में रहना चाहिए और उनकी जनहित की समस्याओं का समाधान करते रहना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो आगामी विधानसभा के चुनाव में उनका और पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा।

-निरंकार सिंह

यहां आधी रात में किया गया स्नान देता है संतान प्राप्ति का वरदान

पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना के साथ उत्तर प्रदेश में कान्हा की नगरी मथुरा के राधाकुंड में अहोई अष्टमी की पूर्व संध्या पर कृष्ण भक्तों का जमावड़ा लगने लगता है। गोवर्धन तहसील के छोटे से कस्बे के बारे में मान्यता है कि मध्य रात्रि की बेला पर राधाकुंड में पति-पत्नी के साथ-साथ स्नान करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस बार अहोई अष्टमी का यह स्नान 5 नवंबर को होगा। राधाकुंड गोवर्धन होकर या छटीकरा होकर पहुंचा जा सकता है। गोवर्धन जाने के लिए मथुरा से उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से नए बस स्टैंड से जाया जा सकता है और वहां से राधाकुंड बस या आटो से पहुंचा जा सकता है क्योंकि गोवर्धन बस स्टैंड से राधाकुंड की दूरी मात्र साढ़े चार किलोमीटर ही है। द्वापर में भगवान श्रीकृष्ण अरिष्टासुर का वध करने के बाद जब राधारानी से उनके निज महल में मिलने गए तो राधारानी ने उनसे मिलने को मना कर दिया और निज महल का दरवाजा नहीं खोला बल्कि यह कहा कि चूंकि उन्होंने गोवंश की हत्या की है इसलिए वे हत्या के दोषी हैं और इसके लिए वे कम से कम सात तीर्थों में जाकर वहां स्नान करें और तब यहां आएं तो उन्हें निज महल में प्रवेश मिलेगा। उस समय उनका निज महल वहां था जहां पर आज राधाकुंड कस्बे में श्याम कुंड और कंगनकुंड का संगम है।

इसके बाद श्रीकृष्ण ने अपनी वंशी से गड्ढा खोदकर सात तीर्थों की जगह सभी तीर्थों का आह्वान किया और सभी तीर्थों का जल आने के बाद उन्होंने उस कुंड में स्नान किया। बाद में इसका नाम कृष्ण कुंड या श्याम कुंड पड़ गया। जिस समय श्रीकृष्ण तीर्थों का आह्वान कर रहे थे, उस समय राधारानी अन्य गोपिकाओं के साथ इसे देख रही थीं। इसके बाद वे गोपियों से बातचीत करने लगीं लेकिन इसी बीच श्रीकृष्ण स्नान करके निज महल में पहुंच गए और उसे अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद जब राधारानी ने निज महल में प्रवेश करना चाहा तो श्यामसुन्दर ने दरवाजा नहीं खोला। राधारानी के बहुत अनुरोध के बाद उन्होंने कहा कि चूंकि वे उनकी अर्धांगिनी हैं इसलिए अरिष्टासुर की हत्या का आधा पाप उन्हें भी लगा है इसलिए वे शुद्ध जल से स्नान करके आएं तभी उन्हें निज महल में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद राधारानी ने अपने कंगन से खोदकर कुंड को प्रकट किया और उसमें स्नान करने के बाद वे निज महल में पहुंची तो श्यामसुन्दर ने दरवाजा खोल दिया। चूंकि राधारानी ने इस कुंड को अपने कंगन से प्रकट किया था इसलिए इसका नाम कंगन कुंड हो गया। श्यामसुन्दर ने इस कुंड को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए बाद में श्यामकुंड से कंगन कुंड को जोड़ दिया। जिससे सभी तीर्थों का जल कंगन कुंड में मिल गया और दोनो ही कुंड तीर्थमय हो गए।

जिस दिन श्यामसुन्दर और राधारानी ने यह लीला की थी उस दिन अहोई अष्टमी थी इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कंगन कुंड में आज के दिन स्नान करेगा उसे अच्छी संतान की प्राप्ति होगी तथा जो व्यक्ति इस दिन के बाद अन्य दिनों में दोनों कुडों में से किसी कुंड में स्नान करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह स्थल बड़ा ही पावन एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इसी कारण देश के कोने-कोने से लोग सन्तान प्राप्ति की आशा में अहोई अष्टमी को अपनी पत्नी के साथ राधा कुंड पहुंचते हैं और दोनो ही साथ-साथ कंगन कुंड में आधी रात यानी रात के 12 बजे स्नान करते हैं और बाद में सन्तान के रूप में उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पेठे का दान (पेठा बनाने वाले कुहड़े का दान) किया जाता है। यह स्नान संतान प्राप्ति से जुड़ जाने के कारण इस दिन दोपहर से ही राधाकुंड में मेला लग जाता है, जो अगले दिन तक जारी रहता है। संतान प्राप्ति की आशा में लोग दूर प्रांतों से आते हैं। वातावरण धार्मिकता से भर जाता है तथा चारों ओर स्वर गूंजते हैं- राधे तेरे चरणों की अगर धूल भी मिल जाए। सच कहते हैं बस इतना तकदीर बदल जाए।

दैनिक इबादत सम्पादकीय

संसद में जय फिलीस्तीन पर विपक्ष का मौन समर्थन घातक

जहां भारत विश्व के देशों में अपनी अलग पहचान स्थापित करने, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने, विकसित राष्ट्र तथा विश्व गुरु बनने के लिए लगातार प्रयासरत है, वही देश के ही नेता अपनी गंदी सोच व मानसिकता से विश्व में भारत का नाम खराब करने से नही चूक रहे है। ये ऐसे नेता है जिनको लाखों लोगों ने अपना वोट देकर संसद इसलिए भेजा है कि वे देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले तथा गंदी सोच रखने वाले नेता जीतने के बाद जैसे मतदाताओं के मत की कीमत को समझते नही और खुद को ही सब कुछ मानकर मनमानी कार्य करते है। कुछ लोग बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर देश की मर्यादा, संस्कृति, सम्मान और संस्कार को भी भूल जाते हैं और मात्र कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कार्य करते है जिससे उनकी जगहसाई होती है लेकिन ऐसे नेताओं को क्या पड़ी है देश की संस्कृति और इज्जत से. उनको तो केवल तुष्टिकरण की राजनीति करके देश को तोड़ने में ही मजा आता है। 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण के दौरान देश के कुछ नेताओं ने भारत की छवि को धूमिल करके अपने अंदर भारत के प्रति छिपी सोच को भी उजागर कर दिया। कहने को तो हैदराबाद से पांचवी बार सांसद चुने गये असदुद्दीन ओवैसी एक शिक्षित मुस्लिम नेता है, ओवैसी अपने कट्टरता के लिए जाने जाते है और इसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहने के कारण फालतू बयान देकर देश को कमजोर करने की फिराक में रहते है लेकिन ओवैसी ने अपनी गंदी सोच और मानसिकता का सबसे वीभत्स उदाहरण तब पेश किया जब उसने भारतीय संसद में शपथ ग्रहण के दौरान 'जय भारत' की जगह पर 'जय फिलीस्तीन' का नारा लगा दिया। सत्ता पक्ष के लोग तो थोड़ा असहज देखे गये, कुछ ने विरोध किया लेकिन विपक्ष ने ओवैसी के देशविरोधी नारे पर एक बार भी विरोध करने की हिम्मत न जुटाई। सत्ता के लालच में और सत्ता पक्ष के विरोध में देशविरोधी नारा लगाने वाले का मूक समर्थन करने से विपक्ष के नेताओं की भी मानसिकता पर प्रश्न चिह्न लग गया है। वही भारतीय संसद में भाजपा के लोग जब जय श्री राम का नारा लगाते तो सपा के नेता और समर्थक जय अवधेश का नारा बुलंद करते रहे है। सपा समेत अन्य विरोधी दलों को भारत, भारतीय संस्कृति से इतनी एलर्जी क्यों है? भारतीय संसद में जिस तरह ओवैसी ने जय फिलीस्तीन का नारा लगा दिया, वैसे ही कोई अब जय पाकिस्तान, जय खालिस्तान, जय आतंकवाद समेत कोई भी नारा लगा सकता है और इसे बोलने की आजादी के डिब्बे में डालकर भुला दिया जाये। यदि ओवैसी के खिलाफ भारतीय संसद या माननीय न्यायालय सदस्यता रद्द करने तथा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नही चलाती तो देश विरोधी सोच रखने वाले ऐसे ही देश की संसद तथा विधानसभाओं में ऐसे ही नारा लगाते रहेंगे। ओवैसी द्वारा लगाये गये नारे जय फिलीस्तीन को हटाने मात्र से कुछ नही होगा। ओवैसी जैसे देशद्रोही नेताओं के खिलाफ कार्यवाही होनी जरूरी है।

सेंगोल पर संसद में संग्राम

– बाल मुकुन्द ओझा

सेंगोल एक बार फिर चर्चा में है। संसद भवन में स्थापित किया गया ऐतिहासिक राजदंड 'सेंगोल' पर एक बार फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। देशवासियों को सेंगोल की जानकारी होनी जरुरी है। सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नीतिपरायणता होता है। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य आधीनम यानि पुरोहितों का आशीर्वाद मिला हुआ है। बताया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद संभाला था, तब उन्हें यह सौंपा गया था। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार से भारत के हाथ में जब सत्ता आई थी, तब वह सौंपा गया था।

ऐसे में इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है। इसके जनक सी. राजगोपालचारी को कहा जाता है, जो कि चोल साम्राज्य से कफी प्रेरित थे। कहा जाता है कि चोल साम्राज्य में जब भी एक राजा से दूसरे राजा के पास सत्ता का हस्तांतरण होता था, तब इस तरह का सेंगोल दूसरे राजा को दिया जाता था । रामायण–महाभारत से भी इसके इतिहास को जोड़कर देखा जाता है। रामायण–महाभारत के कथा प्रसंगों में भी सेंगोल का उल्लेख मिलता है। कथाओं में राजतिलक के दौरान सत्ता सौंपने के प्रतीकों के तौर पर सेंगोल के उपयोग का उल्लेख मिलता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेंगोल सिर्फ राजदंड नहीं है बल्कि इसके साथ न्याय और धर्म भी जुड़ा हुआ है। सेंगोल का सबसे पहले इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य (322 से 185 ईसा पूर्व) में सम्राट की शक्ति के तौर पर किया जाता था।

मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य (320 से 550 ईस्वी), चोल साम्राज्य (907 से 1310 ईस्वी) और विजयनगर साम्राज्य (1336 से 1646 ईस्वी) में भी सेंगोल के प्रमाण मिलते हैं। अंग्रेजों ने भी सत्ता हस्तांतरित करने पर सेंगोल दिया था। 14 अगस्त 1947 की रात 11.45 बजे आजादी मिलने से सिर्फ 15 मिनट पहले थिरुवदुथुरै अधीनम मठ के पुजारी ने सेंगोल माउंटबेटन को दिया। चोल शासन परंपरा के अनुसार उस पर पवित्र जल छिड़का गया और मत्रोंच्चार के साथ ही माउंटबेटन ने यह राजदंड सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के माथे पर राख का लगाकर माला पहनाई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद सेंगोल की परंपरा खत्म हो गई थी और 76 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान सेंगोल को संसद में स्थापित किया। नेहरू युग में सेंगोल को ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नये संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की। इसके लिए तमिलनाडु के प्राचीन मठ के आधीनम महंत दिल्ली आए थे। उनकी उपस्थिति में सेंगोल नए संसद भवन की लोकसभा में स्थापना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को सिर्फ सत्ता का प्रतीक ही नहीं बल्कि नेताओं के लिए न्यायशील और जनता के प्रति समर्पित रहने का भी प्रतिक बताया था। पांच फीट लंबे सेंगोल के सबसे ऊपर नंदी हैं जो कि न्याय और धर्म के प्रतीक हैं। सेंगोल भारत की प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान को दर्शाता है। समृद्धि और खुशहाली के साथ ही न्याय और धर्म के प्रतीक सेंगोल का इतिहास बेहद पुराना है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेंगोल का निर्माण चेन्नई के एक सुनार वुमुदी बंगारू चेट्टी ने किया था, जिसके बाद इसे लॉर्ड माउंटबैटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। दिखने में सेंगोल पांच फीट लंबी छड़ी होती है, जिसके सबसे ऊपर भगवान शिव का वाहन कहे जाने वाली नंदी विराजमान होते हैं। नंदी न्याय व निष्पक्षता को दर्शाते हैं। गौरतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 28 मई को नई संसद में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित किया था।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

2030 तक भारत में बढ़ जाएगी पानी की समस्या

भारत में पानी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक,भारत को हर साल तीन हजार क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है। जबकि,सालाना इससे कहीं ज्यादा पानी बारिश से मिल जाता है। उसके बावजूद इसका एक-चौथाई पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पीने के पाने के लिए ग्राउंडवाटर सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन ग्राउंडवाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती-बाड़ी में होता है।

– अशोक भाटिया

हाल ही में हमने देखा कि देश में सूरज आग उगल रहा था और देश के कई हिस्सों में पारा 50 डिग्री को पार कर गया। राजधानी दिल्ली के मुंगेशपुर में भी पारा 52 डिग्री के ऊपर चला गया। इस चिलचिलाती गर्मी में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई इलाकों में पानी की किल्लत भी सामने आ रही है। दिल्लीवालों को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। मगर दिल्ली जल बोर्ड 97 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। हालात ये हैं कि पानी की बर्बादी करने पर अब दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी तरह, इस साल फरवरी–मार्च में पानी के भयानक संकट से जूझ रहे बेंगलुरु में हालात अब भी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी हालात और बिगड़ने का डर है। नीति आयोग का कहना है कि हो सकता है कि 2030 तक 40 फीसदी भारतीयों को पीने का पानी भी न मिले। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया था कि भारत के 21 बड़े शहरों में ग्राउंडवाटर खत्म होने की कगार पर है, जिससे लगभग 10 करोड़ आबादी प्रभावित होगी। दुनिया की 17% आबादी और 15% मवेशी भारत में रहते हैं, लेकिन यहां साफ पानी के संसाधन महज 4% ही हैं। पानी की जरूरतें सरफेस वाटर और ग्राउंडवाटर से पूरी होती है। सरफेस वाटर में नदियां, तालाब, झीलें आती हैं। जबकि, ग्राउंडवाटर यानी जमीन के अंदर मौजूद पानी। दोनों ही मॉनसून पर निर्भर हैं। लेकिन समस्या ये है कि सरफेस वाटर और ग्राउंडवाटर, दोनों ही तेजी से कम हो रहे हैं। नदियां–तालाब सूख रहे हैं और हर साल कम से कम 0.13 मीटर ग्राउंटवाटर कम होता जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण खेती–बाड़ी है। भारत में खेती–बाड़ी बहुत ज्यादा होती है और इसके लिए पानी की काफी जरूरत पड़ती है। अनुमान है कि भारत में हर साल जितना पानी उपयोग होता है, उसका लगभग 80 फीसदी खेती–बाड़ी में ही इस्तेमाल होता है।अनुमान है कि अभी भारत में हर साल 3,880 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बारिश से मिलता है। लेकिन इसमें से 1,999 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही उपलब्ध होता है। अब इसमें से भी 1,122 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही इस्तेमाल के लायक होता है, लेकिन हम 699 बिलियन क्यूबिक पानी ही उपयोग कर पाते हैं। (1 बिलियन क्यूबिक मीटर में 4 लाख ओलंपिक साइज स्विंमिंग पूल के बराबर पानी होता है।) अब समस्या ये भी है कि आबादी और लोगों की जरूरतें तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण पानी कम पड़ता जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि 1947 में हर व्यक्ति के लिए औसतन 6,042 क्यूबिक मीटर (60.42 लाख लीटर) पानी मौजूद था। लेकिन 2011 तक ये घटकर 1,545 क्यूबिक मीटर (15.45 लाख लीटर) हो गया। 2031 तक हर भारतीय के लिए औसतन 1,367 क्यूबिक मीटर (13.67 लाख लीटर) पानी ही रहेगा। जबकि, 2051 तक तो 1,140 क्यूबिक मीटर (11.40 लाख लीटर) पानी ही रह जाएगा। जब प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1,700 क्यूबिक मीटर यानी 17 लाख लीटर से कम होती है, तब माना जाता है कि देश में पानी की कमी हो रही है। लेकिन जब ये उपलब्धता 1,000 क्यूबिक मीटर यानी 10 लाख लीटर से कम हो जाएगी तो माना जाएगा कि भारत में पानी की भयानक किल्लत है।

सवाल यह भी है कि ऐसा क्यों है ? देखा जाए तो पानी की इस पूरी समस्या की जड़ मैनेजमेंट से जुड़ी है। भारत में पानी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक, भारत को हर साल तीन हजार क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है। जबकि, सालाना इससे कहीं ज्यादा पानी बारिश से मिल जाता है। उसके बावजूद इसका एक–चौथाई पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पीने के पाने के लिए ग्राउंडवाटर सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन ग्राउंडवाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती–बाड़ी में होता है। ये तब है जब बारिश, नदी और तालाबों से भी सिंचाई हो रही है। अनुमान है कि खेती–बाड़ी में 80% और इंडस्ट्रियों में 12% पानी ग्राउंडवाटर से लिया जाता है। किसान और इंडस्ट्री मालिक ग्राउंडवाटर को सबसे आसान जरिया मानते हैं। यही कारण है कि जमीन से पानी निकालने में भारत पहले नंबर पर बना हुआ है। और ग्राउंडवाटर का सिर्फ 8% ही पीने के लिए इस्तेमाल होता है। जमीन से निकले पाने को शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि बाकी जरियों से आए पानी को पीने लायक बनाना पड़ता है। इस हिसाब से खेती–बाड़ी और इंडस्ट्रियों में ग्राउंडवाटर का ज्यादा इस्तेमाल होने से पीने का बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। जब भी पानी की बर्बादी की बात होती है तो आमतौर पर इसके लिए खेती–बाड़ी और इंडस्ट्रियों को दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन भारत में घरों में भी हर दिन काफी पानी बर्बाद होता है।माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी जरूरतों के लिए हर दिन 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसमें से खाना खाने और पीने के लिए सिर्फ 5 लीटर पानी लगता है। स्टडी से पता चला है कि भारत में हर व्यक्ति हर दिन 45 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। घरों में पानी के बर्बाद होने की एक वजह वाटर प्यूरिफायर भी हैं। वाटर प्यूरिफायर 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, लापरवाही के कारण हर दिन भारत में 49 अरब लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। इसे लेकर एनजीटी ने जल शक्ति मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांगी है। एनजीटी का कहना है कि पानी बर्बाद करने वालों पर फाइन लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा बोतलबंद पानी से भी पानी की जबरदस्त बर्बादी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेचने वाली हर कंपनी जमीन से हर घंटे 5 से 20 हजार लीटर पानी निकालती है। बोतलबंद पानी ही नहीं, बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक भी पानी की बर्बादी का बड़ा कारण है। जनवरी 2017 में केरल सरकार ने इंडस्ट्रियों को मिलने वाले पानी में 75% की कटौती कर दी थी। इस कारण पेप्सिको को अपना प्लांट बंद करना पड़ गया था। क्योंकि पेप्सिको हर दिन जमीन से 6 लाख लीटर पानी निकाल रही थी। ड्ड्र।।ह्व और ह्वड्ढश्चश्वस्र की 2019 की रिपोर्ट में चेताया गया था कि 10 करोड़ भारतीयों के पास पानी की सप्लाई का कोई ठोस साधन भी नहीं है।2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक 60 करोड़ भारतीयों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। यानी, उस वक्त 40% आबादी ऐसी होगी जो पानी की समस्या से जूझ रही होगी। इसी रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया था कि पीने का साफ पानी नहीं मिल पाने के कारण हर साल दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, हम जो पानी पी रहे हैं, वो भी जहरीला है। दो साल पहले संसद में सरकार ने माना था कि देश के लगभग सभी राज्यों के ज्यादातर जिलों में ग्राउंडवाटर में जहरीली धातुओं की मात्रा तय मानक से ज्यादा है।संसद में सरकार ने उन रिहायशी इलाकों की संख्या का आंकड़ा भी दिया था, जहां पीने के पानी के स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। इसके मुताबिक, 671 इलाके फ्लोराइड, 814 इलाके आर्सेनिक, 14079 इलाके आयरन, 9930 इलाके खारापन, 517 इलाके नाइट्रेट और 111 इलाके भारी धातु से प्रभावित हैं। ज्यादातर स्टडी और रिपोर्ट में यही अनुमान है कि आने वाले वक्त में पानी की समस्या और गंभीर होती जाएगी। अगर आज कोई उपाय नहीं किए गए तो आने वाला समय और बुरा हो सकता है।इससे निपटने के लिए भारत को पानी की रिसाइकिलिंग करने की जरूरत है। रिसाइकलिंग न हो पाने के कारण अभी बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। दूसरे देशों के उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। सिंगापुर ने 2030 तक 70% पानी को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सिंगापुर कई किलोमीटर लंबी सुरंगे बना रहा है, जिससे सीवरों से निकलने वाले खराब पानी को पंप किया जाता है और तकनीक के जरिए रिसाइकिल किया जाता है। बहरहाल, नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक भारत के 21 शहरों में पानी की भयानक कमी हो सकती है। इनमें नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, रतलाम, इंदौर, गाजियाबाद, अजमेर, मोहाली, बीकानेर, आगरा, पटियाला, अमृतसर, जालंधर और गुरुग्राम जैसे शहर शामिल हैं। नीति आयोग का अनुमान है कि आज पानी की जितनी जरूरत है, आने वाले समय में ये दोगुनी हो जाएगी और इस कारण जीडीपी को कम से कम 6% नुकसान हो सकता है। इन सारी परेशानियों से बचने के लिए ग्राउंडवाटर का सही इस्तेमाल, पानी की कम से कम बर्बादी और नदी–तालाबों को प्रदूषण से बचाने की जरूरत है।

(वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार,लेखक, एवं टिप्पणीकार, वसई पूर्व, मुंबई)

विश्वगुरु बनी भारतीय क्रिकेट टीम

– राकेश अचल

एक लम्बे अरसे से मैंने न क्रिकेट का खेल देखा और न इसके बारे में लिखा। वैसे भी क्रिकेट के बारे में मेरा ज्ञान लगभग शून्य ही है। एक जमाना था जब जनसत्ता के सम्पादक स्वर्गीय प्रभाष जोशी ने मुझसे क्रिकेट के ग्वालियर में हुए अनेक अंतर्राष्ट्रीय मैचों का कव्हरेज जबरन कराया था। शनिवार की रात अमेरिका में टी–20 क्रिकेट का फाइनल देख रहे मेरे बेटे ने मुझे एक बार फिर खेल देखने के लिए प्रेरित किया और युगों बाद मैंने न केवल पूरा मैच देखा बल्कि उन स्वर्णिम क्षणों का साक्षी भी बना जो हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव के क्षण कहे जा सकते हैं। दरअसल पिछले अनेक वर्षों से सम–सामयिक विषयों पर लिखते–लिखते मेरी खेलों से रूचि लगभग समाप्त हो गयी थी। खेलों में राजनीति ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं अभी तक अपने शहर ग्वालियर में बनाये गए नए क्रिकेट स्टेडियम को देखने तक नहीं गया, क्योंकि हमारे यहां भी क्रिकेट एक परिवार की दासी बनी हुई है।। लेकिन शनिवार की रात मुझे लगा कि क्रिकेट के खेल में तो हम आज भी विश्व गुरु हैं, और इसका श्रेय उन क्रिकेटरों को जाता है जो सचमुच भारत के मान–सम्मान के लिए खेलते हैं। फाइनल मैच की कमेंट्री पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा शो के जज की ही तरह फुल फार्म में कर रहे थे। चूंकि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था इसलिए मुझे भी मैच ने बाँध लिया। एक लम्बे अरसे बाद मुझे चौके और छक्के देखने का रोमांच हुआ।

हालांकि रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके, मगर उसके बार विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच 72 रन की साझेदारी ने टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई। अक्षर पटेल ने 31 गेंद में 47 रन और विराट कोहली ने 59 गेंद में 76 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने भी 16 गेंद में 27 रन की पारी खेलकर भारत को 176 रन तक पहुंचने में मदद की। नवजोत सिंह का अनुमान था कि भारत 180 रन का लक्ष्य पार कर लेगा लेकिन भारत ये लक्ष्य पाने से 4 कदम पीछे रह गया।

अमूमन रात को 10 बजे सो जाने वाले इस बन्दे ने पूरे साहस के साथ फाइनल मैच देखा। मेरे ख्याल से दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स और कप्तान एडन मार्करम चार–चार रन बनाकर आउट हो गये। लेकिन क्विंटन डी कॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने 68 रन की साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीका की मैच में वापसी करवाई बल्कि मैच के रोमांच को भी बनाये रखा। स्टब्स ने 21 गेंद में 31 रन और डी कॉक ने 31 गेंद में 39 रन की पारी खेली। हेनरिक क्लासेन तब बैटिंग के लिए क्रीज़ पर उतरे जब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 70 रन था। क्लासेन ने यहां से ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू की और उन्होंने मात्र 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर दिखाया। क्लासेन ने 27 गेंद में 52 रन बनाए। 15वें ओवर में क्लासेन ने अक्षर पटेल के ओवर में 24 रन बटोरे जहां से मैच पूरी तरह पलटा हुआ नजर आने लगा था। भारत ने गेंदबाजी के दम पर वापसी की वो भी आखिरी 4 ओवरों में जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि 16 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए थे। अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 26 रन बनाने थे। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने क्लासेन को आउट कर दिया। अगले 2 ओवरों में सिर्फ 6 रन आए। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने केवल 4 रन दिए, जिससे मैच का रुख भारत की ओर हो गया। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने केवल 8 रन देकर भारत की 7 रन से जीत सुनिश्चित की। पूरे सत्रह साल बाद मिली इस विजय से मुझे एक बार लगा कि जैसे ये एक सपना है, लेकिन बारबाडोस से लेकर दिल्ली और ग्वालियर में जब आधी रात को जश्न शुरू हुआ तो यकीन करना ही पड़ा कि हम क्रिकेट के विश्व गुरु फिर बन गए हैं।

दरअसल खेलों में खिलाडी पुरुषार्थ दिखाते हैं। खेलों में अदावत नहीं होती, प्रतिस्पर्द्धा होती है। मैं भारतीय क्रिकेट टीम की इस महान उपलब्धि से गदगद हूँ। मै हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ की वो हमारे देश की सियासत को अदावत से बचाकर उसमें प्रतिस्पर्द्धा और खेल की भावना भर दे। सियासत में भी नेता अपनी पारी समाप्ति की घोषणा खुद करें। पूरी भारतीय टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई, क्योंकि वर्षों बाद हम भारतीयों का सीना एक बार फिर 56 इंच का हुआ है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कविता

विधाता

समर्पित मेरा हर शब्द हर भाव उसे,
बनाया है मुझे और तुम्हें जिसने,
प्रकृति में उसने इंद्रधनुषी रंग भरे,
हर कवि के हृदय में सागर से गहरे भाव भरे।

वह नौ रसों का रचनाकार सृजन कर्ता है,
'आनंद' अमृत उसकी कृपा से ही बरसता है,
गीत, दोहा, छंद, मुक्तक, गजल, कहानी
या शायरी,
या हो भजन, संस्मरण सब उसी की जादूगरी।

सुर, लय, ताल, ज्ञान और भाव वह देता है,
निमित्त बनाया उसने वो ही एक विधाता है,
यही सृजन शक्ति ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है,
धन्यवाद मेरा नमन जिसे कहते परमात्मा
है।

मोनिका डागा 'आनंद'
(चेन्नई, तमिलनाडु)

चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी यह जानकारी नहीं दे रहे हैं कि चुनाव ड्यूटी करते हुए देश में कितने पोलिंग कर्मचारियों की मौत हुई,कब तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल जाएगा,क्या तपती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए चुनाव आगे के लिए टाला जा सकता था,वरिष्ठ पत्रकारों ने ऐसे 6 सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को मेल के जरिए भेजे। 5 दिन बाद भी जवाब नहीं आया। यह बेहद शर्मनाक बात है कि देश का चुनाव आयोग चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अपनी जान गंवाने वाले ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की सही संख्या तक नहीं बता रहा है।

चुनाव ड्यूटी पर जान गंवाने वाले लोकसेवकों को नमन !

– मनोज कुमार अग्रवाल

अठारहवीं लोकसभा अस्तित्व में आ चुकी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के आयोजन के फलस्वरूप 543 सांसद चुने गए कुछ मंत्री बन गए प्रधानमंत्री लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के नेता बन गए लेकिन आपको बता दें कि इस लोकतंत्र के बुनियादी कार्यक्रम आम चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए कुल दस लाख से अधिक केंद्र व राज्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी इन चुनावों को सम्पन्न कराने के लिए अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर मतदान केंद्रों पर ड्यूटी देने गए 123 कर्मचारी अपने घर जीवित वापस नहीं आए वरन वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ड्यूटी पर ही विभिन्न कारणों से जान गंवा गए। चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की जरूरत होती है और ये कर्मी विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी स्कूल के शिक्षकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और एलआईसी सहित विभिन्न उद्यमों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लिए जाते हैं. मतदान दलों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी, सेक्टर और जोनल अधिकारी, माइक्रो–ऑब्जर्वर, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, चुनाव में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर आदि शामिल होतेसुरक्षा और कानून व्यवस्था में शामिल पुलिसकर्मी, सेक्टर और जोनल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी और उनके कर्मचारी, अन्य लोगों में से हैं जो देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने–अपने जिलों में चुनाव कराने में मदद करते हैं. चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त लोगों के अनुपस्थित रहने की कोई गुंजाइश नहीं है. अनुपस्थिति पर आयोग की ओर से दंड दिया जाता है. डयूटीचुनाव कार्य में केवल उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है जो केंद्र या राज्य के स्थायी कर्मचारी हैं. इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो उन कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है जो रिटायर होने के बाद प्रतिनियुक्ति पर हैं. चुनाव कार्य में कांट्रैक्ट या दैनिक वेतनभोगी की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है. अगर पति–पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो चुनाव ड्यूटी में एक को छूट मिल सकती है. ऐसे में पति–पत्नी दोनों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. दंपती में से कोई एक बच्चों या अपने बुजुर्ग मां–बाप की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी हटाने के लिए आवेदन दे सकता है। इस बार का लोकसभा चुनाव 45 डिग्री वाले गर्म मौसम में सम्पन्न हुआ यह गर्म मौसम की तपिश चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए बेहद भारी साबित हुयी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 54 कर्मचारियों की ड्यूटी करते हुए मौत हो गई। 33 मौतें तो वोटिंग के आखिरी दिन 1 जून को हुईं। मरने वालों में ज्यादातर होमगार्ड्स थे, जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ परिवार ऐसे हैं, जिन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं बचा।उनकी आखिरी उम्मीद 15 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा है, जो अब तक नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी चुनाव ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की मौत हुई। चुनाव आयोग से इसकी जानकारी मांगी, लेकिन जवाब नहीं मिला।एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों में अधिकारियों से बात की, तो पता चला कि मध्यप्रदेश में 27, असम में 15, राजस्थान–छत्तीसगढ़ में 8–8, पंजाब में 7 और दिल्ली में 4 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान गर्मी काफी अधिक रही और चुनाव कर्मियों को सुविधाओं का अभाव था यही कारण है कि 54 पोलिंग स्टाफ की मौत हो गई। ड्यूटी पर जान गंवाने वाले इन कर्मचारियों में से अभी तक सिर्फ 27 के आश्रितों को सरकार की ओर से मदद मिली है जबकि बाकी मृतकों के आश्रितों को अभी कोई मदद नहीं मिली है। इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मरने वाले पोलिंग स्टाफ का डेटा और उन्हें मिलने वाली आर्थिक मदद के बारे उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के असिस्टेंट चीफ इलेक्टोरल अफसर अरबिंद कुमार पांडेय के अनुसार 'चुनाव खत्म होने के बाद हमने यूपी के सभी जिलों से पोलिंग कर्मचारियों की मौत से जुड़ी रिपोर्ट मंगवाई थी। राज्य में 54 कर्मचारियों की मौत हुई। इनमें से 27 के परिवार तक मदद पहुंचा दी गई है। 10 लोगों का भुगतान अभी प्रक्रिया में है।' 17 मृतकों की पूरी रिपोर्ट अभी उनके जिलों से नहीं आई है। इसलिए उनका कुछ नहीं हो पाया। संबंधित जिला प्रशासन जैसे ही जानकारी भेज देगा, हम उनके अकाउंट में पैसे भिजवा देंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, जान गंवाने वाले कर्मचारियों में ज्यादातर होमगार्ड, सफाईकर्मी और वोटिंग कराने वाले कर्मचारी थे। इन सभी की 500 रुपए रोज के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई थी। सभी को वोटिंग से 3 से 4 दिन पहले तय लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचना था। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा के हवाले से बताया गया है कि यूपी में रिपोर्ट हुईं सभी मौतें नेचुरल डेथ की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए सभी पीड़ित परिवारों को 15 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। 7 जुलाई से पहले मदद राशि भेजने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार, चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग स्टाफ की मौत होने पर दो तरह से मदद दी जाती है। पहला– कर्मचारी की बीमारी से या फिर प्राकृतिक मौत होने पर 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। दूसरा–किसी भी तरह के उपद्रव या आतंकी हमले में पोलिंग स्टाफ की मौत होने पर 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी यह जानकारी नहीं दे रहे हैं कि चुनाव ड्यूटी करते हुए देश में कितने पोलिंग कर्मचारियों की मौत हुई, कब तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल जाएगा, क्या तपती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए चुनाव आगे के लिए टाला जा सकता था, वरिष्ठ पत्रकारों ने ऐसे 6 सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को मेल के जरिए भेजे। 5 दिन बाद भी जवाब नहीं आया। यह बेहद शर्मनाक बात है कि देश का चुनाव आयोग चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अपनी जान गंवाने वाले ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की सही संख्या तक नहीं बता रहा है। मध्यप्रदेश में 27, दिल्ली में 4 मौत होने की पुष्टि की गई है जब राज्यों के चुनाव अधिकारियों से इस सिलसिले में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि ड्यूटी के दौरान कितनी मौतें हुई हैं और कितने परिवारों को मुआवजा मिल चुका है। मध्यप्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम रंजन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान 27 कर्मचारियों की मौत हुई है। इनमें से 21 के परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए की मदद दी गई है। छत्तीसगढ़ में 8 कर्मचारियों की मौत हुई। सभी के परिवारों को मुआवजा मिल गया है। राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक, प्रदेश में 8 मौतें हुई हैं, जिनमें से 6 परिवारों को मुआवजा मिल गया है।

देश में कुल 28 राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अभी पूरे आंकड़े आने बाकी है जाहिर है कि यह संख्या दो सौ से अधिक हो सकती है क्योंकि चुनाव के दौरान व्यवस्था में लगे कई पुलिस कर्मियों व दूसरे कर्मियों की सडक दुर्घटना में व अन्य असाधारण कारण से भी मृत्यु हुई है वहीं अनेक कर्मचारी अराजक तत्वों के हमले में जख्मी हो गए हैं। यह सभी मृतक इस लोकतंत्र की नींव के लिए अपना बलिदान दे गए। एक ओर वह नेता हैं जो संविधान हाथ में लेकर संविधान में आस्था रखने का प्रदर्शन करते हैं और मौका मिलने पर सुविधानुसार संविधान का दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकते हैं वहीं दूसरी ओर यह नीव के पत्थर हैं जो अपनी जान ड्यूटी देते गंवा गए। इनके इस संविधान के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिए गए योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे विचार में नई लोकसभा के पहले सत्र में इन तमाम लोगों के परिश्रम और संवैधानिक व्यवस्था के लिए कर्तव्य परायणता के लिए स्मरण व श्रद्धांजली दी जानी चाहिए और इनके आश्रितों को यथा शीघ्र आर्थिक मदद दी जानी चाहिए इस मे देरी या अनावश्यक कागजी बाधाएं तत्काल दूर करने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र के इन पहरूओ को अंतिम सम्मान आत्मा को शान्ति मिल सके। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 1 जुलाई 2024

संतुलित हो विकास

JDU ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग दोहराई है, वह बदले राजनीतिक माहौल में खासी अहमियत रखता है। लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में बनी NDA सरकार की JDU पर निर्भरता को देखते हुए स्वाभाविक ही इस बात की पड़ताल शुरू हो गई है कि इस मांग पर जोर देने के पीछे JDU नेतृत्व की मंशा क्या हो सकती है।

पुरानी मांग | वैसे बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कोई नई नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी काफी पहले से यह मांग करते रहे हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा इस मांग के पक्ष में प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। खास बात यह कि 14वां वित्त आयोग विशेष राज्य के इस दर्जे को समाप्त कर चुका है।

विशेष दर्जे की मांग से होगा विवाद

नायडू पर नजरें | आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (TDP) ने अभी ऐसा कोई प्रस्ताव भले पास न किया हो, अपने राज्य के लिए वह भी ऐसी मांग करते रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो उनकी पार्टी का समर्थन भी केंद्र की NDA सरकार के लिए उतना ही अहम है। बल्कि, JDU के 12 सांसदों के मुकाबले 16 सांसद होने के नाते उनकी ज्यादा अहमियत मानी जाएगी। लेकिन समीकरण चाहे जो भी हो, अभी यह मानने की कोई वजह नहीं है कि ये दल अपनी विशेष राज्य के दर्जे की या किसी भी दूसरी मांग को लेकर ज्यादा आगे बढ़ेंगे।

तालमेल पर जोर | JDU की ताजा बैठक पर गौर करें तो उसमें भी जोर टकराव के बजाय सरकार से सही तालमेल बनाए रखने पर ही दिखता है। इस बात का संकेत BJP नेताओं से करीबी रिश्तों के लिए जाने जाने वाले संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से भी मिलता है। बैठक में खुद नीतीश कुमार का भी यह दोहराना अहम है कि वह अब NDA छोड़कर कही नहीं जाने वाले।

विशेष राज्य या विशेष पैकेज | राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव में भी विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज के जिक्र को इस मायने में अहम माना जा रहा है। कुछ हलकों में तो इसे पार्टी के विशेष राज्य के दर्जे की मांग से पीछे हटने की कोशिश तक बताई जा रही है। हालांकि JDU ने कहा है कि यह पीछे हटना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मांग तकनीकी उलझनों में न फंस जाए।

राजनीतिक स्थिरता | बहरहाल चुनावी और राजनीतिक प्राथमिकताएं अपनी जगह हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी पक्षों के लिए उचित यही है कि जनादेश को उपयुक्त सम्मान देते हुए राजनीतिक स्थिरता कायम रखें और पूरे देश के संतुलित विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सहयोग करें।

चक्र-व्यू

अचार की चटखार

राहुल पाण्डेय

जब तक यह संसार है, तब तक इसे भोजन की जरूरत पड़ती रहेगी। और जब तक इसे भोजन की जरूरत पड़ती रहेगी, इसे अचार भी चाहिए ही होगा। आम का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो इस संसार में बहुत कम ऐसी चीजें हैं, जिनका अचार नहीं बनाया जा सकता। पिछले दिनों मैंने एक व्यक्ति को खीरे का अचार बनाकर खाते देखा। न साथ में रोटी, न भात। बस गपागप खीरे का अचार खाता जा रहा है और चटखारे ले रहा है। जीभ से निकला हर चटखारा बताता है कि कोलकाता से कैलिफोर्निया तक अचार की महिमा बराबर बनी हुई है, मसाले भले सबके स्वादानुसार हों।

वैसे तो हर मौसम अचार का मौसम होता है। जाड़ों में लोग गोभी-गाजर का अचार बनाते हैं तो बसंत में भरा मिर्चा। मगर गरमी का मौसम अचार का सबसे खास मौसम होता है। आम-आंवला सब उपलब्ध है। शौकीन लोग गर्मी आने से पहले ही अचार के लिए बयाम या तो खरीदकर लाते हैं, या फिर पहले से मौजूद बयामों को धो-पोंछकर रखे रहते हैं। सौंफ, जीरा, मेथी, धनिया, मगरैल और मिर्च भूनी जा रही होती है। घर ही नहीं, गली तक से जो गुजर रहा है, क्या मजाल कि बगैर छींके गुजर जाए। अचार का मसाला भूनते हुए छींक और खांसी तो बहुत आती है, लेकिन अचार मुंह में जाते ही सारी भूल जाती है। फिर रहता है स्वाद और उसमें गोते लगाता हुआ चटोरा मन। संसार का ऐसा शायद ही कोई देश हो, जो अचार ना खाता हो। चटोरों की कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक वैसे ही, जैसे दूल्हों की कहीं कमी नहीं है। कमी है, तो बस दुल्हन की। उसमें भी सबसे ज्यादा कमी है ऐसी दुल्हन की, जो अचार का मसाला छौंक-छौंककर पूरी गली के मुंह में पानी ला दे।

खुशकिस्मत होते हैं वे लोग, जिन्हें चटपटा अचार प्राप्त होता है। वैसे गांव-गिरांव में लोग अचार के जरिए किसी के जीवन की बहुत ही महीन-महीन सूचनाएं भी प्राप्त करते हैं। मसलन किसी की शादी हुई, तो उसने कितने दिन बाद खाने में अचार लेना शुरू किया? जीवन में भोजन के बारे में यह एक बड़ी सूचना है। इस सूचना का यह मतलब है कि अब खाने में वह स्वाद नहीं बचा, या अब मियां-बीवी में वैसी नहीं बनती। कहते हैं कि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। अचार का एक पहलू आनंद है तो एक यह भी है कि जब सब कुछ ठीक नहीं होता, तभी इसकी जरूरत पड़ती है। अचार वह साथी है, जो हर किसी का तब भी साथ निभाता है, जब कुछ भी ठीक नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि इंसान का बच्चा किसी का नहीं होता, अचार का भी नहीं। स्वादी खाने की थालियों में मैंने अक्सर अधखाया अचार ही देखा है।

एकदा

मीर ने जब आगरा छोड़ा

पिता के निधन के बाद मीर तकी मीर को परिवार में दुत्कार मिलने लगी। उनका बड़ा भाई उनसे न केवल चिढ़ता बल्कि बात-बात पर फटकार लगाता और बाप के दुलार के ताने मारता। अब उनके गर्दिश के दिन शुरू हो गए। जो लोग पिता के जीते जी उन्हें सलाम करते थे, अब वे भी मुंह फेरने लगे। घर-बाहर, सब जगह उन्हें उपेक्षा मिलने लगी। मीर ने सोचा, कुछ काम की तलाश की जाए। आगरा की हर गली छानी, लेकिन कहीं पर कोई काम न मिला। मजबूर होकर उन्होंने आगरा छोड़ने का मन बना लिया। आगरा छोड़ने का मन नहीं था, पर परिवार और समाज की उपेक्षा ने उन्हें जन्मभूमि छोड़ने के लिए विवश कर दिया। वह रास्ते में दुख झेलते, ठोकरें खाते दिल्ली पहुंचे। पहचान थी, इसलिए एक दिन नवाब के सामने पेश हुए। नवाब को यह समझने में देर न लगी कि मीर के फकीर पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि इस लड़के को सरकारी खजाने से एक रुपये रोज दिए जाएं। मीर पहले से ही अर्जी लिखकर ले गए थे, इसलिए उसे सामने रखते हुए बोले, 'अगर इस पर दस्तखत कर देते तो रोड़ा अटकाने वालों का डर खत्म हो जाता।' नवाब ने कहा, 'यह कलमदान का वक्त नहीं है।' मीर हंसने लगे। कारण पूछा, तो मीर ने जबाव दिया, 'मेरी हंसी का कारण आपकी बात है। आप यह कहते कि नवाब के दस्तखत का समय नहीं है, तो ठीक था। कलमदान तो लकड़ी का एक टुकड़ा है, वह वक्त और बेवक्त कहां जानता है।' यह सुनकर नवाब भी हंस दिए। कलमदान मंगवाकर नवाब ने उनकी अर्जी पर दस्तखत कर दिए और बड़े आदर से मीर को विदा किया।

Subrata Dhar

संकलन : हरिप्रसाद राय

बढ़ते और विकसित होते भारत का आत्मविश्वास झलक रहा है टीम इंडिया के हर खिलाड़ी में

यह T20 वर्ल्ड कप का 'लगान' मोमेंट है

शैलेंद्र पांडेय

उस एक गेंद के पहले बीती सारी बातें घूम गईं उसकी आंखों के सामने। वे सारे लोग जो उसके साथ खड़े थे और वे भी जो इंतजार कर रहे थे उसकी असफलता का। जीत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था उसके सामने। भुवन जिस मनोभाव से गुजर रहा था वह आखिरी गेंद फेंके जाने से पहले, कुछ वैसी ही स्थिति रही होगी टीम इंडिया की। पूरा एक दशक, इस दरम्यान के तमाम फाइनल और सेमीफाइनल, एडिलेड-अहमदाबाद - इतिहास फिर से भूत बनकर आकार लेने लगा था। भुवन की तरह टीम इंडिया के पास भी बस एक ही विकल्प रह गया था, जीत।

लगान वसूली | फिल्म 'लगान' में आमिर खान के कैरेक्टर ने पूरे दम से बैट घुमाया। कैप्टन आंद्रे रसल के पास मौका था कि वह गेंद लपक कर उस कहानी को वहीं खत्म कर देते। उन्होंने गेंद लपकी, पर अपनी सीमा को भूल गए। बाउंड्री पार कर गए। वही मौका सूर्यकुमार यादव के पास भी आया फील्डिंग करते समय। आखिरी ओवर, दक्षिण अफ्रीका का आखिरी बल्लेबाज, एक आखिरी मौका - सूर्या ने दिखाया कि क्यों SKY की लिमिट नहीं, लेकिन अपनी हद में रहकर। उनका उछलकर गेंद को लपकना, बाउंड्री के पार जाने से पहले गेंद को मैदान की ओर उछाल देना और फिर वापस मैदान में जाकर कैच पूरा करना - हर एक लम्हा फ्रेम में मढ़कर रखने लायक है, जैसा कि 1983 विश्व कप में कपिल देव का लिया कैच और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी का विनिंग शॉट।

विश्व विजेता
- हार नहीं मानी इंडियन टीम ने
- एक-दूसरे पर विश्वास जताया
- क्लियर था सभी का रोल, विजन

इंडिया का कैरेक्टर | 30 गेंदों पर 30 रन, विन प्रिडिक्टर ने भी साथ छोड़ दिया था टीम इंडिया का। ग्राफ कह रहा था कि भारत की जीत की उम्मीद चार फीसदी से भी कम है। लेकिन इस टीम के लिए इतनी उम्मीद भी काफी थी वापसी के लिए। पहले भी ऐसी सिचुएशन से आकर मुकाबले जीते गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम ने मैच के बाद यही कहकर तो खुद को सांत्वना दी। लेकिन, इसी इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा कम से कम दो बार किया - पहले पाकिस्तान के खिलाफ और फिर फाइनल में। आखिरी वक्त तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना और लड़े बिना हार नहीं मानना - यह केवल टीम इंडिया नहीं बल्कि पूरे इंडिया का कैरेक्टर दिखाता है।

ग्लोबल लीडर | भारत इस जीत का हकदार था, विश्व विजेता कहलाने का हकदार था। और केवल इस बार ही नहीं, पिछले कई टूर्नामेंट से। वर्ल्ड टाइटल पहले ही आ जाना चाहिए था उसके पास। हालांकि कई बार जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता। मेहनत और प्रतिभा होती है, फिर भी कहीं कुछ कमी रह जाती है। शायद किस्मत का थोड़ा-सा साथ, जिसकी कमी बार-बार मुस्कुराने का मौका छीन ले रही थी। लेकिन किस्मत कब तक दगा देती, उसे बहादुरों के साथ आना ही था। खेलों के बाहर, ग्लोबल मंच पर भी भारत को अपना अधिकार बिना लड़े कहां मिला है। कोरोना के दौर में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, जब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अनाज की कमी आ खड़ी हुई थी, जब यूरोप पर ईंधन का संकट छाया था - तब हर बार भारत ने अपनी भूमिका निभाई। वे छोटे-छोटे कदम थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को ग्लोबल लीडर की श्रेणी में ला खड़ा किया।

AI Image, Courtesy : Sahixd

कॉन्फिडेंस से भरपूर | भारतीय क्रिकेट में वही आत्मविश्वास दिख रहा है, जो इस देश में है। जैसे-जैसे मुल्क ने अपना रास्ता बदला है, वैसे-वैसे हमारा खेल भी बदलता चला गया। 1991 में देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। वह समय था आर या पार के फैसले का। अब तीन दशक बाद देखिए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती और पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारतीय केवल अपनी ही नहीं, कई दूसरे देशों की जीडीपी में भी योगदान दे रहे हैं। यही बदलाव आया है इंडियन क्रिकेट में भी। इन तीन दशकों ने भारत को क्रिकेट वर्ल्ड का लीडर बना दिया है। बिग थ्री की बात अब नहीं होती, अब केवल बिग वन है। जिस धमक के साथ हमारे राजनेता वैश्विक मंचों पर खड़े होते हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ हमारे युवा मल्टिनैशनल कंपनियों को संभालते हैं, कुछ उसी धमक और वैसे ही आत्मविश्वास के साथ अब टीम इंडिया के प्लेयर्स उतरते हैं मैदान पर।

Clarity और भरोसा | जीत के बाद हजार मजबूतियां दिखने लगती हैं। फिर भी जो चीज इस टीम को अलग करती है, वह है क्लैरिटी। BCCI, टीम मैनेजमेंट और टीम - शुरू से आखिर तक इन सभी का रोल बिल्कुल स्पष्ट रहा। खिलाने वालों को पता था कि उन्हें क्या चाहिए और खेलने वालों को पता था कि क्या करना है। दूसरी बड़ी चीज रही भरोसा। ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर शख्स का एक-दूसरे के ऊपर अटूट भरोसा बना रहा। जब प्रॉसेस सही हो, तो रिजल्ट की चिंता नहीं रहती। और टीम को पता था कि सिलेक्शन प्रॉसेस सही है, उनका मेथड सही है, intention सही है। सभी ने अपने साथियों को बैक किया।

खेल का भविष्य | फाइनल देख रहे गूगल के CEO सुंदर पिचाई मुश्किल से सांसें ले पाए। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में ज्यादा क्रिकेट खेलने की अपील की है। नडेला ने अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग (MCL) में पैसा लगाया हुआ है। क्रिकेट का अमेरिकी जमीन पर फलना-फूलना उनके अपने कारोबारी हित में भी है। इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल भी यही चाहती है। लेकिन, यहां भी अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी।

बारिश को ओढ़कर देखिए, अद्भुत सुकून मिलेगा

'चींटी ले अंडा चले चिड़ी नहावे धूर, ऐसा बोले भड्डरी वर्षा हो भरपूर।' घाघ और भड्डरी की कहावतों के सहारे बारिश का इंतजार करती आंखें जब आकाश से गिरती पहली बूंद को जमीन पर गिरकर भाप बनते देखतीं तो उनमें कैसा भाव होता था, उसे वही बता सकता है जिसने उन आंखों को पढ़ा हो। बारिश का मौसम अपने आप में ही सुकून देने वाला होता है। उस पर पहली बारिश का कोई जोड़ नहीं।

बारिश का मतलब है जीवन, जब हरा रंग फिर से खिलखिलाने लगता है। खेतों में हरे-भरे पौधे, पेड़ों पर नई कोपलें और घास पर जमी ओस की बूंदें - ऐसा लगने लगता है कि प्रकृति अपने को नए सिरे से लिख रही हो और इसके लिए वह स्लेट को धो रही है। यही तरावट आती है हमारे जीवन में भी। घरों की छतों से फिसलता पानी, उसके बहने की आवाज, सड़कों पर बन आए छोटे-छोटे गड्ढे और उनमें बूंदों की छप-छप, मिट्टी की सोंधी महक - एक साथ इतनी चीजें घटती जाती हैं कि लगता है मन किस-किसको संभाले। यह अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता।

मशहूर कवि John Keats बारिश को उपचार मानते थे। ऐसा दोस्त जिसे ओढ़ा जा सके, जिसके साथ रहकर सुकून मिले। पूरी दुनिया इस समय गंभीर क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। इस बार जब मई-जून की गर्मी जान पर भी भारी पड़ने लगी, तब उस सुकून को और शिद्दत से महसूस किया जा सकता है, जो बारिश ने दी।

बारिश हमें सिखाती है एक मकसद के लिए जीना और उस मकसद के लिए खुद को भी भुला देना। हर बूंद अपना एक अलग वजूद लेकर आती है, लेकिन नीचे आकर वह अलग नहीं रह पाती। हम करना भी चाहें तो भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सकते। वह अपने को मिटाकर एक बड़ा स्वरूप ले लेती है। क्या किसी बड़े सपने के लिए खुद को ऐसे ही नहीं भूलना पड़ता? अगर हर बूंद बस अपने बारे में सोचे और अपने लिए ही लड़े तो क्या उस काम को पूरा कर पाएगी जिसके लिए इतना लंबा रास्ता तय किया?

AI Image

जीवन आनंद

बारिश सबूत है प्रकृति की शक्ति का, उसके चक्र का। सीख देती है हमें कि जीवन में सुख-दुख, दोनों आते रहते हैं। हर मुश्किल के बाद खुशियां भी जरूर आती हैं। कठिनाइयों की तपन कुछ समय के लिए राह को मुश्किल बन सकती है, पर फिर बारिश होगी और वही रास्ता पैरों को कोमल लगने लगेगा। बस धैर्य रखना है और भरोसा नहीं टूटने देना है। कवि Dorothy Parker ने ऐसी ही किसी बरसात में भीगकर लिखा होगा कि, 'बारिश रुकेगी, रात खत्म होगी, दर्द कम होगा। आशा इतनी खो नहीं सकती कि उसे दोबारा पाया न जा सके।'

बारिश कहती है कि आनंद में गोते लगाना है, तो चिंताओं को छोड़ना होगा। बिल्कुल बच्चा बन जाना होगा। बिना किसी फिक्र के दौड़ना होगा मैदानों पर, सांस लेना होगा खुली हवा में, कूदना होना, नाचना होगा, भीगना होगा। कभी-कभी ऐसा बचपना वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। जिस तरह पानी का कोई आकार नहीं होता, वैसे ही बारिश का आनंद लेने का कोई सेट फॉर्म्युला नहीं। पूरा भींग नहीं सकते तो बस हथेलियों को आगे बढ़ाकर दोस्ती कर लीजिए या फिर बालकनी में खड़े होकर एक गहरी सांस खींचकर देखिए। बारिश ने आपके आंगन में उतरकर पहल कर दी है और वहां से आगे बढ़कर रिश्ता आपको बनाना है। अगली बार जब बरसात हो, तो उसे ओट से छिपकर न देखें, बल्कि थोड़ा रुककर उसका आनंद लें। उसकी हर आवाज को सुनें, उसकी हर बूंद को महसूस करें और प्रकृति की इस खूबसूरत देन का भरपूर मजा लें।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesgroup.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- 'जीवन आनंद'

https://t.me/AllNewsPaperPaid

वेंकैया जैसे नेता ही बनाते हैं राष्ट्र को जीवंत

सिद्धांत, पार्टी और राष्ट्रहित को निजी हितों पर तरजीह देते रहे हैं नायडू

नरेन्द्र मोदी

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है। वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। देश में उनके लाखों चाहने वाले हैं। मैं उनके सभी शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बधाई देता हूं। वेंकैया जी का 75वां जन्मदिवस एक विशाल व्यक्तित्व की व्यापक उपलब्धियों को समेटे हुए है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए। राजनीति में अपने प्रारम्भिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आपमें एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है।

वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है, जीवन के हर पड़ाव पर लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला। वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था। लेकिन उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं BJP को मजबूत किया।

लगभग 50 साल पहले जब कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें लोकनायक जेपी को आंध्र में आमंत्रित करने के लिए जेल जाना पड़ा। 1980 के दशक के मध्य में, जब महान NTR सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त किया, तब वे फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे।

1978 में आंध्र ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, तब वेंकैया प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद, राज्य चुनाव में NTR की लोकप्रियता सर्वोच्च स्तर पर थी। तब भी वह BJP विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में BJP के लिए भविष्य के बीज बोये थे। युवा विधायक के रूप में ही, वे विधायी मामलों में अपनी दृढ़ता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित होने लगे।NTR उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वेंकैया गारू हमेशा की तरह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। उन्होंने आंध्र में BJP को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र BJP के अध्यक्ष भी बने।

1990 के दशक में BJP के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुए उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 में यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ। एक ऐसा व्यक्ति, जो किशोरावस्था में अटल जी और आडवाणी जी के दौरों की तैयारी करता था, उनके लिए ये कितना बड़ा मुकाम था। पार्टी महासचिव के रूप में, उनका एक ही लक्ष्य था कि BJP को सत्ता में कैसे लाया जाए! उनका एक ही संकल्प था कि कैसे देश को BJP का पहला प्रधानमंत्री मिले। दिल्ली आने के बाद, उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे तो वह वेंकैया गारू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो वेंकैया गारू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को चुना। उनकी पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था। क्योंकि, उसके पहले नेताओं के लिए दूसरे मंत्रालय पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन, वेंकैया गारू की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी- वह एक किसान पुत्र थे, उन्होंने अपने शुरुआती दिन गांवों में बिताए थे और इसलिए, कोई एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह काम करना चाहते थे, तो वह ग्रामीण विकास था। उस समय एक मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी।

PTI

2014 में NDA सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। शायद, वह उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए काम किया है।

2014 के उन शुरुआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे भी बहुत काम आया। मैं तब दिल्ली के लिए बाहरी व्यक्ति था। मेरा करीब डेढ़ दशक गुजरात में काम करते हुए बीता था। ऐसे समय में वेंकैया गारू का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। वो सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। साथ ही, जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात आती थी, तब वो नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नज़र आते थे। वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ये हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था। हम जानते थे कि वेंकैया गारू के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा। लेकिन हमें ये भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है। मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद किया तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है। उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ी। वह राज्यसभा के एक उत्कृष्ट सभापति थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा सांसदों, महिला सांसदों और पहली बार चुने गए सांसदों को बोलने का अवसर मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया, समितियों को अधिक प्रभावी बनाया। उन्होंने सदन में बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया। जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय राज्यसभा के पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वह युवा जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए जीवन समर्पित किय, जब वह सपना पूरा हुआ तो वह सभापति के पद पर आसीन था। किसी निष्ठावान देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा!

वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। दिल्ली के लोगों के बीच, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो शहर में गौरवशाली तेलुगु संस्कृति लेकर आए। उनके द्वारा आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं। मैं वेंकैया गारू को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं। लेकिन, पिछले कुछ समय से उनका संयम भी सबके सामने दिखने लगा है। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि वह अभी भी बैडमिंटन खेलना और ब्रिस्क वॉक करना पसंद करते हैं।

उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी, वेंकैया गारू सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं। वह लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को मुझसे बात करते रहते हैं। हाल ही में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाक़ात हुई थी। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

मिस्टर परफेक्ट की रेस छोड़िए गलतियां सुधारिए

गोपाल अग्रवाल

जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर देखते हैं कि सत्ता और धन का प्रभाव अधिक गहरा होता जा रहा है। किसी तरह का निर्णय लेने में भी ये ताकतें ही निर्णायक हो जाती हैं। इस वजह से जो सत्ता के स्वामी हैं, वे भी कई बार न्याय नहीं कर पाते। अपने हित में फैसले लेने लगते हैं। कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है।

कल्पना करें कि एक आदमी जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसके पास न तो सत्ता है, न ही धन, न ही प्रभाव। यदि वह अपने हक के लिए संघर्ष करता है, तब उसकी आवाज सत्ता की चौखट तक पहुंचते-पहुंचते शून्य हो जाती है। उसके पास अपनी आवाज बुलंद करने के लिए न तो धन है और न सत्ता तक पहुंच। अब ऐसी हालत में न्याय की परिभाषा ही बदल जाती है और वह व्यक्ति एक समय आवाज उठाना बंद कर देता है। अगर हम सच्चे न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हमारे निर्णय हमेशा कमजोर व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाना एक कठिन काम है, लेकिन यह काम हमारी नैतिकता को परखता है।

कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाने के प्रयास में हम खुद को तो बेहतर बनाते ही हैं, समाज को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी सतत क्रिया में सहभागी होने से हमें आत्म संतुष्टि मिलती है और इससे हम और अधिक नैतिक और मानवीय बनते हैं। कमजोर को न्याय दिलाना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। हमें धैर्य रखना होगा, न्याय के लिए लड़ना होगा और समाज में न्याय के लिए आवाज उठानी होगी। यह सब आसान नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इससे हमें सच्चे न्याय की गहनता तथा नैतिकता के मूल्य को समझने का भी अवसर मिलता है।

यह सब-कुछ समाज की भलाई के लिए जरूरी है। हम कमजोर के लिए आवाज उठाएं, कमजोर को न्याय दिलाने के लिए आवाज को प्रतिध्वनित करें और स्वयं भी बेहतर बनें। समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील होना ही हमारी कर्तव्यशीलता की पहचान है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाने का मार्ग बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है। उसके लिए हमें पूर्णतया अनुशासन में रहते हुए अपनी सीमाओं को समझना होगा और तकलीफों को भी सहन करना होगा। साथ-साथ यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि हर निर्णय में सबकी सहमति नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम न्याय के लिए लड़ना छोड़ दें। हमें अपने आपको बचाते हुए, कमजोर के लिए आवाज उठानी चाहिए और अपने समाज को बेहतर बनाने के प्रयास में जुट जाना चाहिए।

जिंदगी के इस सफर में हम सब एक-दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। हम सब मेल-जोल से कमजोर के लिए आवाज उठा सकते हैं। समाज में न्याय के लिए लड़ सकते हैं। यह हमारी नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। इसके अलावा यह भी याद रख सकते हैं कि हम केवल इंसान हैं और हमसे गलतियां स्वाभाविक हैं। हम सब मिस्टर परफेक्ट नहीं हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां ही सुधार की ओर बढ़ते कदमों का अभ्यास कराती हैं।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

नीतीश और बिहार के चुनाव

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल(यू) के सर्वेसर्वा श्री नीतीश कुमार देश के एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं जिनके अगले राजनैतिक दांव के बारे में कोई भी राजनैतिक विश्लेषक विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता। रंग बदलने में नीतीश बाबू का कोई सानी नहीं माना जाता और हर मोड़ पर मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखने में कोई जवाब भी नहीं समझा जाता। कभी वह भाजपा के साथ होते हैं तो कभी इंडिया गठबन्धन के साथ गलबहिया करते नजर आते हैं। सत्ता की राजनीति में वह जरह तरह से बेजोड़ समझे जाते हैं कि अपने दाएं हाथ को भी बाएं हाथ की कारगुजारियों की खबर तक नहीं होने देते। उनका यही निराला चरित्र उन्हें राजनीति में पलटूराम भी बनाता है मगर बिहार की राजनीति में उन्हें अप्रासंगिक बनाने की हिम्मत किसी भी राजनैतिक दल में नहीं है क्योंकि अपने अति पिछड़ों का वोट बैंक इस तरह तैयार किया हुआ है कि वह किसी अन्य पार्टी के पास जाने को तैयार नहीं होता। पिछड़ों में अति पिछड़ा वर्ग को पहचान देने का काम नीतीश बाबू ने ही अपनी राजनीति में किया और आज वही उनकी सबसे बड़ी सम्पत्ति है।

हाल ही में दिल्ली में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय समिति की बैठक कर नीतीश बाबू ने फैसला किया कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य श्री संजय झा होंगे। संजय झा की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की है। वह 2012 से पहले भाजपा के साथ ही थे। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नीतीश बाबू ने भाजपा आलाकमान को संदेश दे दिया है कि वह निकट भविष्य में अब पलटी नहीं मारेंगे और भाजपा के साथ ही बने रहेंगे, बशर्ते बिहार की राजनीति में भाजपा उन्हें खुला हाथ दे। इसकी वजह यह मानी जा रही है कि नीतीश बाबू ने केन्द्र की राजनीति में अपने 12 सांसदों का समर्थन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिना किसी शर्त के दिया है। जद (यू) के लल्लन सिंह को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जो मत्स्य पालन विभाग दिया गया है वह किसी भी मायने में महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। साथ ही राज्यमंत्री के रूप में जद (यू) सांसद को कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाया गया है। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह के बनने के बाद अन्य राज्य मंत्रियों का कोई खास महत्व नहीं माना जाता है। समझा जा रहा है कि नीतीश बाबू केन्द्र में भाजपा को पूरा समर्थन इसीलिए दे रहे हैं जिससे भाजपा बिहार में उनके साथ यही रवैया अपना सके। हालांकि राज्य विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या जद (यू) के विधायकों से ज्यादा है मगर राज्य की राजनीति में भाजपा की अपने दम पर ज्यादा ताकत नहीं समझी जाती है। इसका नजारा 2015 में सामने आ गया था जब नीतीश बाबू की पार्टी ने लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबन्धन करके चुनाव लड़ा था तो भाजपा की केवल 45 सीटें ही आई थीं। इस हकीकत को भाजपा भी पहचानती है और वह नीतीश बाबू का साथ छोड़ना नहीं चाहती है। मगर भाजपा आंखें मूंद कर नीतीश बाबू पर यकीन भी नहीं करना चाहती है क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ने के बावजूद नीतीश बाबू ने भाजपा का साथ छोड़कर लालू जी से हाथ मिला लिया था।

> **समझा जा रहा है कि नीतीश बाबू केन्द्र में भाजपा को पूरा समर्थन इसीलिए दे रहे हैं जिससे भाजपा बिहार में उनके साथ यही रवैया अपना सके। हालांकि राज्य विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या जद (यू) के विधायकों से ज्यादा है मगर राज्य की राजनीति में भाजपा की अपने दम पर ज्यादा ताकत नहीं समझी जाती है। इसका नजारा 2015 में सामने आ गया था जब नीतीश बाबू की पार्टी ने लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबन्धन करके चुनाव लड़ा था तो भाजपा की केवल 45 सीटें ही आई थीं। इस हकीकत को भाजपा भी पहचानती है और वह नीतीश बाबू का साथ छोड़ना नहीं चाहती है। मगर भाजपा आंखें मूंद कर नीतीश बाबू पर यकीन भी नहीं करना चाहती है**

ewsPaper Paid

हाल के लोकसभा चुनावों में जद (यू) व भाजपा गठबंधन ने राज्य की 40 में से 31 सीटों पर सफलता प्राप्त की है जिससे नीतीश बाबू गद्-गद् बताये जाते हैं, अत: उनकी योजना बताई जा रही है कि वह विधानसभा चुनाव जल्दी चाहते हैं। बिहार में कायदे से विधानसभा चुनाव अगले साल अक्तूबर महीने तक होने हैं। मगर सूत्रों की मानें तो नीतीश बाबू चाहते हैं कि चुनाव इसी साल के भीतर हो जाने चाहिए जिससे उनकी सत्ता बनी रहे क्योंकि फिलहाल माहौल जद (यू)-भाजपा गठबन्धन के पक्ष में है। अगले साल तक देरी हो जाने से माहौल बदल भी सकता है। इसके लिए नीतीश बाबू बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने उनकी पिछली महागठबन्धन सरकार द्वारा दिया गया 65 प्रतिशत पिछड़ी जाति का आरक्षण रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ वह सर्वोच्च न्यायालय में जाने की योजना बना रहे हैं। जाहिर है कि यह मामला लम्बा खिंचेगा मगर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का श्रेय उन्हीं की सरकार को मिलेगा।

इसके चलते वह राज्य में विधानसभा चुनाव करा लेना चाहते हैं। वह चुनौती देने में देरी नहीं करना चाहते क्योंकि यदि उन्होंने इसमें देरी की तो उच्च न्यायालय के फैसले को लालू जी की पार्टी राजद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। पिछली महागठबन्धन सरकार के उपमुख्यमन्त्री लालू जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि यदि नीतीश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं देती है तो उनकी पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा आरक्षण के मुद्दे पर खटखटायेगी। नीतीश बाबू बहुत चतुर सत्ता के खिलाड़ी माने जाते हैं अत: वह ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे जिससे उनके विरोधियों को वरीयता मिले। नीतीश बाबू जो चौपर बिछा रहे हैं उससे यही आभास होता है कि वह बिहार विधानसभा के चुनाव जल्दी करायेंगे। मुख्यमन्त्री रहते वह समय से पहले विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकते हैं, बशर्ते कि भाजपा उनका साथ दे।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

भ्रष्ट लोगों ने कर रखा है...

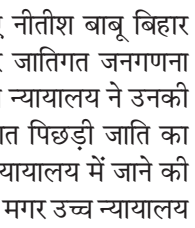

ढहते पुल, गिरती छतें कर रही हैं हमसे एक सवाल,
हम गिरना नहीं चाहते पर ये तो इंसानों द्वारा-
लगाए गए घटिया सामग्री का कमाल,
भ्रष्ट लोगों ने कर रखा है लोगों का जीवन बेहाल,
ये जांच का विषय है कौन भर है अपनी तिजोरी में इन घोटालों का माल।।

-गीता पाढा

वेंकैया गारू : भारत की सेवा में समर्पित जीवन

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री भारत

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक हमारे श्री एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है। वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। देश में उनके लाखों चाहते वाले हैं। मैं उनके सभी शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बधाई देता हूं।

वेंकैया जी का 75वां जन्मदिवस एक विशाल व्यक्तित्व की व्यापक उपलब्धियों को समेटे हुए है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है जिसके बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए। राजनीति में अपने प्रारम्भिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आपमें एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है। वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है, जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला।

वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था लेकिन उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं बीजेपी को मजबूत किया।

लगभग 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें लोकनायक जेपी को आंध प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए जेल जाना पड़ा। लोकतंत्र के लिए उनकी ये प्रतिबद्धता, उनके राजनीतिक जीवन में हर जगह दिखाई देती है। 1980 के दशक के मध्य में जब महान एनटीआर की सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था तब वे फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। 1978 में आंध प्रदेश ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद राज्य चुनाव में एनटीआर की लोकप्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। तब भी वे बीजेपी के विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में बीजेपी के लिए भविष्य के बीज बोये थे। युवा विधायक के रूप में ही वे विधायी मामलों में अपनी दृढ़ता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित होने लगे। उनकी वाकपटुता, शब्दशैली और संगठन सामर्थ्य से प्रभावित होकर एनटीआर जैसे दिग्गज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। एनटीआर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे लेकिन वेंकैया गारू हमेशा की तरह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई, गांवों में जाकर सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े।

उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। 1990 के दशक में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुये उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 में यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जो किशोरावस्था में अटल जी और अडवाणी जी के दौरों की तैयारी करता था, उनके लिए ये कितना बड़ा मुकाम था। पार्टी महासचिव के रूप में उनका एक ही लक्ष्य था कि अपनी पार्टी को सत्ता में कैसे लाया जाए। उनका एक ही संकल्प था कि कैसे देश को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री मिले। दिल्ली आने के बाद उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने।

> **राजनीति में अपने प्रारम्भिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आपमें एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है।**

वर्ष 2000 में जब अटल जी सरकार बना रहे थे तो वो वेंकैया गारू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो वेंकैया गारू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना। उनकी इस पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था। क्योंकि उसके पहले नेताओं के लिए दूसरे मंत्रालय पहली पसंद हुआ करते थे लेकिन वेंकैया गारू की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। वह एक किसान पुत्र थे, उन्होंने अपने शुरूआती दिन गांवों में बिताए थे और इसलिए अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह काम करना चाहते थे तो वह ग्रामीण विकास था। उस समय एक मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी।

2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। शायद, वह उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए काम किया है।

2014 के उन शुरूआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे भी बहुत काम आया था। मैं उस समय दिल्ली के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। मेरा करीब डेढ़ दशक गुजरात में ही काम करते हुए बीता था। ऐसे समय में वेंकैया गारू का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। वो सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। साथ ही जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात आती थी तब वो नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नजर आते थे।

वर्ष 2017 में हमारे गठबंधन ने उन्हें हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ये हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था। हम ये जानते थे कि वेंकैया गारू के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा लेकिन साथ ही हमें ये भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है। मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद किया तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है। उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ी। वह राज्यसभा के एक उत्कृष्ट सभापति थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा सांसदों, महिला सांसदों और पहली बार चुने गए सांसदों को बोलने का अवसर मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया, समितियों को अधिक प्रभावी बनाया। उन्होंने सदन में बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया।

जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय राज्यसभा के पटल पर रखा गया तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वह युवा जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, जब वह सपना पूरा हुआ तो वह सभापति के पद पर आसीन था। किसी निष्ठावान देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा।

काम और राजनीति के अलावा वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। दिल्ली के लोगों के बीच उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो शहर में गौरवशाली तेलुगू संस्कृति लेकर आए। उनके द्वारा आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं। मैं वेंकैया गारू को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं लेकिन पिछले कुछ समय से उनका संयम भी सबके सामने दिखने लगा है। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि वह अभी भी बैडमिंटन खेलना और ब्रिस्क वॉक करना पसंद करते हैं।

उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वेंकैया गारू सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं। वह लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर मुझसे बात करते रहते हैं। हाल ही में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं।

एक 'सेंगोल' नेतागणों के लिए

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

अब यह शिद्दत से महसूस होता है कि एक 'सेंगोल' देश के राजनेताओं के लिए भी स्थापित होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव तो हो चुके। इसी वर्ष देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने हैं। हमारे परिवेश में चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का पर्व नहीं होते। चुनाव 'कीचड़-फेंक' प्रतियोगिता से भी चलते हैं। अर्ध सत्य और असत्य की काली होली भी खुलेआम खेली जाती है। अधिकांश नेताओं को यह लगता है कि चुनावों के दिनों में जितना अधिक झूठ बोला जाएगा, जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग होगा, उतना ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का पुण्य मिलेगा।

ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ इतिहासकारों ने अपने कलम एक तरफ सरका दिये हैं। इस विषय पर 'माउस' एवं कम्प्यूटर बंद हैं। इतिहासकार महसूस करते हैं कि इन दिनों के इतिहास को ईमानदारी से लिखा तो सांसों की डोरी पर संकट खड़ा हो सकता है। वैसे भी आज के राजनेताओं का चाल-चलन, भावी पीढ़ियों को भी शर्मिंदगी और हताशा के सिवाय क्या दे पाएगा।

संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं का चीरहरण इससे ज्यादा क्या होगा कि नए सांसदों में एक ने अपनी शपथ को 'जय भीम', 'जय मीम', 'जय तेलंगाना', 'जय फिलस्तीन' के जयकारे के साथ पूरा किया तो एक ने 'जय संविधान' और कुछ ने 'जय भीम', 'जय हिन्दू राष्ट्र' के नारे के साथ। संसद में शपथ ग्रहण एक पवित्र एवं परम्परागत रस्म मानी जाती है। अब सदस्यगणों का एक वर्ग भी अराजक हो चला है। वह किसी पाकीज़गी, परंपरा या गरिमा को नहीं मानता।

'सेंगोल' तमिल संस्कृति का एक प्रतीक है। जिस दिन गत वर्ष यह 'सेंगोल' लोकसभा में स्थापित किया गया था उस दिन समाजवादी पार्टी व अन्य दलों के वे नेता भी सदन में मौजूद थे, जो आज इस 'सेंगोल' को हटाने की मांग उठा रहे हैं। संदेह तो यह भी होने लगा है कि आने वाले समय कभी इन नेताओं को सत्तासूत्र संभालने का मौका मिल गया तो ये लोग वाराणसी को फिर से बनारस या प्रयागराज को फिर से इलाहाबाद का नाम देने की मशक्कत शुरू कर दें। आएं थोड़ा 'सेंगोल' के बारे में शुरुआती जानकारी भी आपस में बांट लें। सेंगोल स्वर्ण परत वाला चांदी का एक राजदंड है जिसे 28 मई, 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। नए राजा के राजतिलक के समय सेंगोल भेंट किया जाता था।

वर्ष 1947 में धार्मिक मठ-'अधीनम' के प्रतिनिधि ने सेंगोल भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को सौंपा था। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक शासन होने के नाम पर इसे तब इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया और किसी सरकार ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सेंगोल मुख्यत: चांदी से बना है जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा है।

'सेंगोल' तमिल शब्द 'सेम्मई' (नीतिपरायणता) व 'कोल' (छड़ी) से मिलकर बना है। 'सेंगोल' शब्द संस्कृत के 'संकू' (शंख) से भी आया हो सकता है। सनातन धर्म में शंख पवित्रता का प्रतीक है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर एस. राजावेलु के अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ 'न्याय' है। तमिल राजाओं पास ये सेंगोल हो था जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। शिलप्पदिकारम् और मणिमेखलै, दो महाकाव्य हैं जिनमें सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

सेंगोल की लम्बाई लगभग पांच फीट (1.5 मीटर) है इसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना है। सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम सोने का प्रयोग किया गया था। इसे जटिल डिजाइनों से सजाया गया है और शीर्ष पर नंदी की नक्काशी की गई है। नंदी हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु और शिव का वाहन है। नंदी की प्रतिमा इसके शैव परंपरा से जुड़ाव दर्शाता है। हिंदू व शैव परंपरा में नंदी समर्पण का प्रतीक है। यह समर्पण राजा और प्रजा दोनों के राज्य के प्रति समर्पित होने का वचन है। दूसरा, शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिव के सामने स्थित मुद्रा में बैठे दिखते हैं। हिंदू मिथकों में ब्रह्मांड की परिकल्पना शिवलिंग से की जाती रही है। इस तरह नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नंदी के नीचे वाले भाग में देवी लक्ष्मी व उसके आसपास हरियाली के तौर पर फूल-पत्तियां, बेल-बूटे उकेरे गए हैं जो कि राज्य की संपन्नता को दर्शाती है।

प्राचीन काल में भारत में जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाने के बाद राजा राजदण्ड लेकर राजसिंहासन पर बैठता था। राजसिंहासन पर बैठने के बाद वह कहता था कि अब मैं राजा बन गया हूं, मैं अदण्ड्य हूं, मैं अदण्ड्य, अर्थात् मुझे कोई दण्ड नहीं दे सकता। पुरानी विधि ऐसी थी कि उनके पास एक संन्यासी खड़ा रहता था, लंगोटी पहने हुए। उसके हाथ में एक छोटा, पतला सा पलाश का डण्डा रहता था। वह उससे राजा पर तीन बार प्रहार करते हुए उसे कहता था कि राजा! यह 'अदण्ड्योऽस्मि अदण्ड्योऽस्मि' गलत है। 'दण्ड्योऽसि दण्ड्योऽसि दण्ड्योऽसि' अर्थात् तुझे भी दण्डित किया जा सकता है।

चोल काल के दौरान ऐसे ही राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण को दर्शाने के लिए किया जाता था। उस समय पुराना राजा नए राजा को इसे सौंपता था। राजदंड सौंपने के दौरान 7वीं शताब्दी के तमिल संत संबंध स्वामी द्वारा रचित एक विशेष गीत का गायन भी किया जाता था। कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल को प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं।

इन दिनों हम एक अजीब घुटन भरे माहौल से गुज़र रहे हैं। कल्पना करें कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए किसी भी कारण से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया और यू-ट्यूब हड़ताल पर चले जाएं तो छपास रोग से पीड़ित हमारे ये नेता कहां जाएंगे?

इन दिनों विश्वभर में 'यूएफओ' दिवस मनाया जाता है। 'यूएफओ-डे' यानि कि अन्य ग्रहों से आने वाली उड़न तश्तरियों को समर्पित दिवस। चर्चा यह भी चली थी कि पिछले दिनों एक उड़नतश्तरी एक अन्य से किसी भारतीय महानगर में उतरी उसमें किसी दूसरे लोक के प्राणी भी थे। मगर उतरते ही जब उन्हें एहसास हुआ कि यहां तो अराजक एवं शालीनता विहीन नेताओं का शोर चल रहा है तो वे सब उसी उड़न तश्तरी में वापिस लौट गए।

शिक्षा से भी ज्यादा शादी पर खर्च करते हैं भारतीय

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भारतीय विवाह उद्योग का आकार लगभग 10 लाख करोड़ रुपये है, जो खाद्य और किराना के बाद दूसरे स्थान पर है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया कि आम हिंदुस्तानी शिक्षा की तुलना में विवाह समारोह पर दोगुना खर्च करते हैं। भारत में सालाना 80 लाख से एक करोड़ शादियां होती हैं, जबकि चीन में 70-80 लाख और अमेरिका में 20-25 लाख शादियां होती हैं।

> **भारत में सालाना 80 लाख से एक करोड़ शादियां होती हैं**

एक रिपोर्ट में कहा, भारतीय विवाह उद्योग अमेरिका (70 अरब अमेरिकी डॉलर) के उद्योग के आकार का लगभग दोगुना है। हालांकि, यह चीन (170 अरब अमेरिकी डॉलर) से छोटा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खपत श्रेणी में शादियों का दूसरा स्थान है। अगर शादी एक श्रेणी होती, तो वे खाद्य और किराना (681 अरब अमेरिकी डॉलर) के बाद दूसरी सबसे बड़ी खुदरा श्रेणी होती। भारत में शादियां भव्य होती हैं और इनमें कई तरह के समारोह और खर्च होते हैं। इससे आभूषण और परिधान जैसी श्रेणियों में खपत बढ़ती है और अप्रत्यक्ष रूप से ऑटो तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लाभ मिलता है। खर्चीली शादियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद, विदेशी स्थानों पर होने वाली आलीशान शादियां भारतीय वैभव को प्रदर्शित करती रहती हैं। जेफरीज ने कहा, हर साल 80 लाख से एक करोड़ शादियां होने के साथ, भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा विवाह स्थल है। कैट के अनुसार इसका आकार 130 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

भारत का विवाह उद्योग अमेरिका के मुकाबले लगभग दोगुना है और प्रमुख उपभोग श्रेणियों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय शादी कई दिनों तक चलती हैं और साधारण से लेकर बेहद भव्य तक होती हैं। इसमें क्षेत्र, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में विवाह पर शिक्षा (स्नातक तक) की तुलना में दोगुना खर्च किया जाता है, जबकि अमेरिकी जैसे देशों में यह खर्च शिक्षा की तुलना में आधे से भी कम है।

पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्र शुरू करेगा अभियान

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केंद्र सरकार की ओर से पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण के लिए विशेष अभियान सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। इस विशेष अभियान की शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह करेंगे।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत 1-31 जुलाई, 2024 के दौरान पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाएगा। इसमें 46 मंत्रालय/विभाग भाग ले रहे हैं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 1 जुलाई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

गज में कब्जा करने से बेहतर है इंच में कब्जा करना।
-चीनी कहावत

चैंपियन इंडिया

भारत ने टी-20 विश्व कप चैंपियन बनकर आईसीसी ट्रॉफियों से लंबे समय से चली आ रही दूरी को आखिरकार, खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के तौर पर जीती थी। यहां तक विश्व कप की बात है तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे विश्व कप में चैंपियन बना था। इसके बाद करीब 13 साल के समय में भारतीय टीम कई बार नई ऊंचाइयां छूती नजर आई पर आखिरी समय में लड़खड़ा गई और ट्रॉफी से उसकी दूरी बनी रही। पिछले साल वनडे विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में हमें इस तरह की स्थिति का ही सामना करना पड़ा। वनडे विश्व कप के फाइनल में हारने के बाद तो टी-20 में रोहित की

कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे थे। पर बीसीसीआई ने करीब सात महीने पहले रोहित को ही कप्तान बनाने का फैसला किया। इसी दौरान अजित अगरकर भी मुख्य चयनकर्ता बन गए। इस तिकड़ी के बीच बेहतर रिश्तों ने टीम को चैंपियन टीम में बदल दिया। द्रविड़ और रोहित की कोच और कप्तान की जोड़ी ने टी-20 को उसके ही अंदाज में खेलने का फैसला किया। इस विश्व कप के दौरान मुश्किल हालात में भी आक्रामक अंदाज से खेलने की सोच साफ दिखी। इस विश्व कप के फाइनल के हीरो विराट कोहली को ही लें। वह आम तौर पर विकेट पर थोड़ा रुक कर धीरे-धीरे गियर बदलने के लिए जाने जाते हैं पर पहली ही गेंद से आक्रामक रुक अपनाने के फैसले के बाद वह इसमें ज्यादातर मैचों में बड़ा स्कोर बनाने में सफल नहीं हुए। विराट के रोहित के साथ पारी शुरू करने की आलोचना भी हुई पर टीम प्रबंधन इन आलोचनाओं से प्रभावित हुए बगैर अपनी योजना पर आगे बढ़ता रहा। भारत की इस सफलता की खूबी किसी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं रहा। भारत के चैंपियन बनने में जितनी अहमियत विराट की पारी की है, उतनी ही अहमियत अक्षर पटेल की पारी की भी है। बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी भी चैंपियन बनाने में अहम रही। सूर्यकुमार यादव का बाउंड्री लाइन पर आखिरी ओवर में डेविड मिलर का लपका शानदार कैच भी खास रहा। सही मायनों में द्रविड़ और रोहित द्वारा टीम को एक सूत्र में पिरोने का यह कमाल है पर द्रविड़ का कोच के तौर पर कार्यकाल खत्म होने, रोहित और विराट द्वारा अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के बाद अब आने वाले कोच की जिम्मेदारी होगी कि वह इस तरह जिम्मेदारी निभाने वाली यंग ब्रिगेड को तैयार करे।

बारिश ने खोली पोल

राजधानी दिल्ली में बारिश ने 88 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जन-जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले सात दिन तेज वर्षा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारी बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में भी काफी गिरावट आई है। मगर कई इलाकों में जल-भराव के चलते दिल्ली के सारे विकास की हालत पस्त हो गई है। मानसून आगमन के कारण हुई तीन घंटों तक मूसलाधार बरसात के कारण दिल्ली हवाई अड्डे में

छत का एक हिस्सा गिरने से एक वाहन चालक की मौत हो गई। साथ ही, अन्य संबंधित घटनाओं में भी सात अन्य लोगों की अलग-अलग मौत हो गई। पुलिस अभी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। भीषण गर्मी के मार झेल रहे दिल्ली वाले मानसून के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर सामान्य से दो दिन पूर्व हुई इस जबरदस्त बरसात ने रहवासियों को बुरी तरह भयभीत कर दिया है। मोहल्ले और बस्तियां ही पानी में नहीं डूबी हैं, बल्कि कई अति व्यस्त अंडरपास भी बरसात के पानी से लबालब भर गए। समूची दिल्ली ट्रैफिक जाम के चलते थम सी गई। यह कोई पहली बार नहीं है, जब दिल्लीवासियों को जल भराव जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। हर साल राज्य सरकार का तंत्र घोर लापरवाही करता रहता है और अंत में केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़कर अपने ढर्रे पर चल पड़ता है। दिल्ली ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रति वर्ष देश भर में जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों मौते होती हैं, और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। सिर्फ चमचमाती सड़कों, फ्लाईओवरों और दमकती रोशनी को विकास का पर्याय नहीं माना जा सकता। बल्कि पानी की उचित निकासी और बरसाती पानी के भंडारण की सटीक व्यवस्था की जरूरत ज्यादा है। दरअसल, यह दिल्ली की ही समस्या नहीं है, बल्कि देश के तमाम बड़े शहरों और महानगरों में बारिश होते ही सवाल उठते लगते हैं कि हमारे विकास में क्या खामियां हैं, जो एक ही बारिश में शहर पानी-पानी हो जाते हैं। बरसात में लोगों की परेशानी पर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि मौसम की मार से जनता को बचाने की पूर्व तैयारियों पर जोर दे। राज्य सरकारों को भी सख्ती से मुस्तैद रहने की नसीहतें दी जाएं।

परिधि/श्वेता गोयल

मानव जीवन में चिकित्सक

भारत में प्रति वर्ष एक जुलाई को डॉक्टरों के समर्पण और ईमानदारी के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए 'राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस' मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा यह दिवस सबसे पहले वर्ष 1991 में मनाया गया था। भारत में जहां प्रति वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वहीं कई दूसरे देशों में भी डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए अलग-अलग तारीखों पर यह दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में पहली बार मार्च, 1933 में डॉक्टर्स डे मनाया गया था। यह दिन चिकित्सकों को कार्ड भेज कर तथा मृत डॉक्टरों की कब्रों पर फूल चढ़ा कर मनाया जाता था। अमेरिका में यह दिवस 30 मार्च को, ईरान में 23 अगस्त तथा क्यूबा में 3 दिसम्बर को मनाया जाता है।

भारत में हर साल एक जुलाई को ही यह दिवस मनाए जाने का विशेष कारण है। दरअसल, देश के जाने-माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉ. बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि एक जुलाई को ही पड़ती है, और उन्हें श्रद्धांजलि एवं सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के लिए यही दिन निर्धारित किया गया। समाज में तो डॉक्टरों को भगवान के समान यूं ही नहीं माना जाता। कोरोना महामारी से देश को उबारने में तो डॉक्टरों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मरीजों की जान बचाते-बचाते प्राणघातक कोरोना वायरस के कारण सैकड़ों डॉक्टरों की मौत भी हुई। कई बार कुछ गंभीर मरीजों के मामलों में लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर सफल नहीं हो पाते और ऐसे कुछ अवसरों पर उन्हें ऐसे मरीज के परिजनों का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। हालांकि अधिकांश मामलों में मरीज की हालत इतनी गंभीर होती है कि डॉक्टर चाह कर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। प्रख्यात स्विस मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक कार्ल गुस्ताव जंग ने एक बार कहा था कि दवाइयां बीमारियों का इलाज करती हैं, लेकिन मरीजों को केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। मरीज की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए इलाज के लिए उपयुक्त दवाओं का चयन डॉक्टर ही करता है। कनाडा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर विलियम ऑस्लर ने कहा था कि अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है जबकि महान डॉक्टर उस मरीज का इलाज करता है, जिसे बीमारी है।

सेवा में समर्पित जीवन

वेंकैया नायडु

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक हमारे श्री एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है। वेंकैया जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। देश में उनके लाखों चाहते वाले हैं। मैं उनके सभी शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बधाई देता हूं। वेंकैया जी का 75वां जन्मदिवस एक विशाल व्यक्तित्व की व्यापक उपलब्धियों को समेटे हुए है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए।

राजनीति में अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आपमें एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है। वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है, जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला।

वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था। लेकिन उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं बीजेपी को मजबूत किया। लगभग 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें लोकनायक जेपी को आंध्र प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए जेल जाना पड़ा। लोकतंत्र के लिए उनकी ये प्रतिबद्धता, उनके राजनीतिक जीवन में हर जगह दिखाई देती है। 1980 के दशक के मध्य में, जब महान एनटीआर की सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था, तब वे फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे।

1978 में आंध्र प्रदेश ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद युवा विधायक के रूप में जीत कर आए थे। पांच साल बाद, राज्य चुनाव में एनटीआर की लोकप्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। तब भी वे बीजेपी के विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में बीजेपी के लिए भविष्य के बीज बोए थे। युवा विधायक के रूप में ही, वे विधायी मामलों में अपनी दृढ़ता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित होने लगे। उनकी वाकपटुता, शब्दशैली और संगठन सामर्थ्य से प्रभावित होकर एनटीआर जैसे दिग्गज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। एनटीआर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वेंकैया गारू हमेशा की तरह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई, गांवों में जाकर सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े। उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी बने।

1990 के दशक में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुए उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 में यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। एक ऐसे व्यक्ति, जो किशोरावस्था में अटल जी और आडवाणी जी के दौरों की तैयारी करता था, के लिए ये कितना बड़ा मुकाम था। पार्टी महासचिव के रूप में, उनका एक ही लक्ष्य था कि अपनी पार्टी को सत्ता में कैसे लाया जाए! एक ही संकल्प था कि कैसे देश को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री मिले। दिल्ली आने के बाद, उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने।

वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे तो वो वेंकैया गारू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो वेंकैया गारू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना। उनकी इस पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था। क्योंकि, उसके पहले नेताओं के लिए दूसरे मंत्रालय पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन, वेंकैया गारू की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी-वह एक किसान पुत्र थे, उन्होंने अपने शुरु आती दिन गांवों में बिताए थे और इसलिए अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह काम करना चाहते थे, तो वह ग्रामीण विकास था। उस समय मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी। 2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। शायद, वह उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक ग्रामीण और शहरी विकास, दोनों के लिए काम किया है। 2014 के उन शुरुआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे भी बहुत काम आया था। मैं उस समय दिल्ली के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। मेरा करीब डेढ़ दशक गुजरात में ही काम करते हुए बीता था। ऐसे समय में वेंकैया गारू का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण था। वह एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। साथ ही, जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात आती थी, तब वो नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नजर आते थे। वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ये हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था। हम जानते थे कि वेंकैया गारू के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा। लेकिन साथ ही, हमें यह भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है। मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद किया तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है। उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ी। वह राज्य सभा के एक उत्कृष्ट सभापति थे, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि युवा सांसदों, महिला सांसदों और पहली बार चुने गए सांसदों को बोलने का अवसर मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया, समितियों को अधिक प्रभावी बनाया। उन्होंने सदन में बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया।

जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय राज्य सभा के पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वह युवा जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, जब वह सपना पूरा हुआ तो वह सभापति के पद पर आसीन था। किसी निष्ठावान देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा! काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया गारू उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। दिल्ली के लोगों के बीच, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो शहर में गौरवशाली तेलुगू संस्कृति लेकर आए। उनके द्वारा आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं। मैं वेंकैया जी को हमेशा ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं। लेकिन, पिछले कुछ समय से उनका संयम भी सबके सामने दिखने लगा है। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि वह अभी भी बैडमिंटन खेलना और ब्रिस्क वॉक करना पसंद करते हैं।

उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी, वेंकैया गारू सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं। लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर मुझसे बात करते रहते हैं। हाल में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं, जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं। *(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)*

वेंकैया जी लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर मुझसे बात करते रहते हैं। हाल में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे व हमारी टीम को शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आखिर, दूरी हुई खत्म

आईसीसी ट्राफी | मनोज चतुर्वेदी

भारत आखिरकार, टी-20 विश्व कप में चैंपियन बन गया। उन्होंने बारबाडोस के केनसिंग्टन ओवल में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हरा कर यह सफलता हासिल की है। भारत ने टी-20 विश्व कप को दूसरी बार जीता है। इससे पहले 2007 में इसकी शुरुआत होने पर महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में चैंपियन बना था। धोनी की कप्तानी में ही भारत ने 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पर इसके बाद से सफलता रूठी रही। पिछले साल नवम्बर में भारतीय टीम वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारी तो लगा कि टीम में चैंपियन बनने का दम नहीं है। पर सात माह में ही टीम चैंपियन का सपना पूरा करने में सफल रही।

भारत जब वनडे विश्व कप में हारा तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा था कि किसी युवा को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन रोहित जब पहली बार चयन समिति से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम के खिलाड़ियों को खारिज करना सही नहीं होगा क्योंकि हमने लीग चरण में चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सहित हर टीम को हराया है। चयन समिति को इससे लगा कि रोहित टी-20 विश्व कप में कप्तानी करने को तैयार हैं। तब उन्हें ही विश्व कप में कप्तान बनाने का ऐलान हुआ। इसके बाद रोहित ने कोच राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिल कर टीम के खेलने के अंदाज को नया आयाम दिया। इसे बाद टीम ने मुश्किल में फंसने के बाद भी आक्रामक रुख नहीं छोड़ा और यह बदलाव ही टीम को चैंपियन बनाने में सफल रहा। इस सफलता ने कोच राहुल द्रविड़ हों या कप्तान रोहित शर्मा सभी की छवि को नया रूप दे दिया है। राहुल बेजोड़ खिलाड़ी होने के बावजूद कभी विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे। अपनी कप्तानी में बारबाडोस में ही वनडे विश्व कप में खराब प्रदर्शन से दो-चार हो चुके थे। लेकिन अब इसी मैदान से विश्व कप जिताने वाले कोच के तौर पर अपनी इस पारी को विराम दे रहे हैं। जहां तक बात रोहित की है तो वह अपनी कप्तानी में टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के फाइनल में ले जा चुके थे पर चैंपियन कप्तान का टेग उनके ऊपर नहीं लग सका था। वह भारत को वनडे और टी-20 रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंचाने में सफल रहे

पर फिर भी विश्व कप जीतने वाले कप्तानों कपिल देव की जमात में शामिल नहीं हो सके थे पर अब टी-20 विश्व कप जीत कर वह इस जमात में शामिल हो गए हैं।

रोहित और द्रविड़ की कप्तान-कोच की जोड़ी की तरह ही विराट और रवि शास्त्री की जोड़ी ने भी टीम को ढेरों सफलताएं दिलाईं पर टीम को विश्व कप नहीं जिता सकी। पर विराट इससे पहले वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीमों में शामिल रहे थे और उनकी कप्तानी में भारत अंडर-19 विश्व कप भी जीत चुका था। अब टी-20 विश्व कप भी उनकी झोली में आ गया है। वह चारों ट्रॉफियां जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं।

भारत ने जिस तरह से फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को फतह किया, उसे सालों-साल याद रखा जाएगा। भारत ने जब पहले बल्लेबाजी करके सात विकेट पर 176 रन बनाए तो यह लगा कि वह जरूरत से 10-15 रन पीछे रह गया। हालांकि यह विश्व कप फाइनल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। दक्षिण अफ्रीका के क्लासेन और क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे तो लगा कि भारत के रन कम रह गए। लेकिन हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आने पर पहले क्लासेन और फिर डेविड मिलर को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की तरफ झुके मैच को भारत के पक्ष में कर दिया। यह सही है कि उन्हें डेविड मिलर का विकेट उनके गेंदबाजी कमाल से ज्यादा सूर्यकुमार यादव द्वारा कैच पकड़ने में दिखाई सूझबूझ की ज्यादा भूमिका थी। पर अपने प्रदर्शन से उन्होंने दिखाया कि वह टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आईपीएल में खराब प्रदर्शन करने पर उन्हें टीम में शामिल करने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। विश्व कप में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया कि वह कितने अहम खिलाड़ी हैं।

कोच राहुल और कप्तान रोहित के अपने फैसलों पर अडिग रहने ने भी सफलता में अहम भूमिका निभाई। इस जोड़ी ने विराट से पारी शुरू कराने का फैसला किया और उनसे पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाने को कहा। इसमें विराट को थोड़ी दिक्कत हुई और वह कई बार दो-एक अच्छे शॉट लगाकर आउट होते रहे। फाइनल तक एक भी अर्धशतक नहीं बना पाने पर उनसे पारी शुरू कराने की आलोचना होने लगी। कहा जाने लगा कि यशस्वी जायसवाल से पारी शुरू कराकर विराट को तीसरे नंबर पर खिलाया जाए। पर द्रविड़ और रोहित अपने फैसले पर डटे रहे, क्योंकि उन्हें विराट की क्षमता का अंदाजा था। आखिर में फाइनल में कोहली ने अपना विराट रूप अपना कर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभा दी।

समर्पण | श्रीराम शर्मा आचार्य

मित्रो एक बार लैला ने मजनूं की परीक्षा लेनी चाही। जानना चाहा कि मजनूं कैसा है? पहले तो उसने ऐसा इंतजाम कर दिया कि उसको कुछ पैसे मिल जाया करे, दुकानदारों से खाने को मिल जाया करे। फिर उसने सोचा, ऐसा तो नहीं कि वह हरामखोर हो और फोकट का खा रहा हो। उसने अपनी बांदी से कहला भेजा कि लैला बहुत बीमार है। सुन कर मजनूं बड़ा दुःखी हुआ। बांदी ने कहा-दुःखी होने से क्या फायदा? आप कुछ मदद कीजिए न उनकी। उसने कहा-लैला को हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हो तो कुछ दीजिए न। मजनूं ने कहा-मैं क्या दूं? बांदी ने कहा-डॉक्टरों ने कहा है कि लैला की नसों में खून का एक प्याला चढ़ाया जाएगा, आप अपना खून देंगे क्या, जिससे कि लैला की जिंदगी बचाई जा सके। मजनूं ने जो कटोरा बांदी लेकर आई थी, खून से लबालब भर दिया। उसने बांदी से कहा-बांदी जल्दी आना, अभी कई कटोरे खून मेरे शरीर में है। वह मैं उसके सुपुर्द करूंगा क्योंकि उससे मैं मुहब्बत करता हूं और मुहब्बत का मतलब होता है-देना। बांदी जब एक कटोरा खून लेकर के गई, तो नकली मजनूं जो थे, सब भगा दिए गए। लैला ने अपने बाप से कह दिया-जो मुझसे इतनी मुहब्बत करता है और जो मुहब्बत की कीमत को समझता है, उसके ही साथ मैं रहूंगी। लैला और मजनूं की शादी हो गई। आपकी भी शादी भगवान के साथ में हो सकती है, लेकिन करना क्या चाहिए? सिर्फ एक बात करनी चाहिए कि भगवान की मर्जी पर चलने के लिए आप आमादा हो जाइए। आपको इनसान की ऐसी जिंदगी दी है कि आप मनमर्जी पूरी कर सकते हैं। आपके हाथ कितने बड़े हैं, जुबान और आंखें कितनी शानदार हैं, इसमें आप संतोष कर सकते हैं। अपनी हविश, तमन्नाओं, इच्छाओं, महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भगवान को मजबूर करेंगे कि कर्त्तव्य की बात को छोड़कर वह पक्षपात करने लगे और कर्मफल की महत्ता का परित्याग कर दे? अपने घिनौने चिंतन को बदल दीजिए, छोटे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दीजिए, लोभ और लालच से बाज आइए और भगवान की सुंदर दुनिया को ऊंचा, शानदार बनाने के लिए राजकुमार के तरीके से कमर बांधकर खड़े हो जाइए। समर्पित हो जाइए, शरणागति में आइए, विराजिए, विसर्जन कीजिए, फिर देखिए आप क्या पाते हैं?

रीडर्स मेल

अभूतपूर्व क्रांति के साक्षी हम

वर्तमान समय में हम एक अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति के साक्षी बन रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल प्रौद्योगिकी के तेज विकास ने हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया है। इस नये युग में हम एक ऐसी दुनिया में रहना शुरू कर रहे हैं, जहां वास्तविक और आभासी जगत के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। प्रौद्योगिकी की तेज प्रगति के बीच हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारा समाज मानवीय मूल्यों पर आधारित रहे। सहयोग, करुणा और रचनात्मकता जैसे मानवीय गुण और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाएंगे। हमें एक ऐसे भविष्य की कल्पना करनी होगी जहां प्रौद्योगिकी और मानवता एक-दूसरे के पूरक हों। हमारे ग्रह और समाज की दीर्घकालिक स्थिरता पर भी ध्यान दें। डिजिटल युग में नेताओं और नीति-निर्माताओं को दूरदर्शी और नैतिक निर्णय लेने की जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसी नीतियां और नियम बनाने होंगे जो नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की भी रक्षा करें। ऐसा भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हम सभी के हाथों में है।

चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

गले नहीं उतर रहा फैसला

मप्र की मोहन यादव सरकार ने एक निर्णय लिया था कि अब मंत्रियों का आयकर सरकारी खजाने से जमा नहीं किया जाएगा। प्रदेश की जनता को अपनी सरकार का यह निर्णय पसंद आया था। भारी-भरकम मंत्रिमंडल का आयकर जमा करना हमेशा ही परेशानी का सबब रहता है। लेकिन इसी सरकार ने अब निर्णय लिया है कि अपने मंत्रियों के लिए 30 नई गाड़ियां खरीदेगी। डेढ़ से 2 वर्ष पूर्व ही 2022 और 2023 मॉडल की नई इनोवा गाड़ियां सरकार ने खरीदी थीं। फिर नई गाड़ियों पर करोड़ों रुपये पुनः खर्च करना, यह कैसी सरकारी खरीद। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मप्र सरकार कर्ज में डूबी हुई है। आय कर न भरने के निर्णय को सबने पसंद किया था। मगर अब नई कारें खरीदने के लिए जो 6 करोड़ खर्च किए जाएंगे वे किस बात के हैं। इन दो निर्णयों में से किसे युक्तियुक्त ठहराया जाए? जनता की समझ से बाहर है।

मनमोहन राजावत, शाजापुर, मप्र

आकाश आनंद की चुनौती

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 23 जून को संपन्न समीक्षा बैठक में आकाश आनंद को फिर पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक एवं एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करके साफ कर दिया गया है कि देश की राजनीति में आकाश आनंद के आक्रामक तेवर दिखाई देने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरा मूल्यांकन है कि आकाश को राजनीति में लंबी पारी खेलनी है। उनको भाषण शैली में आक्रामकता का पुट और लचीलापन रखना होगा। अपने आप को विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए स्वयं को ढालना होगा एवं बहुजन के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक-धार्मिक एवं कर्मचारी संगठनों के साथ समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए काम करना होगा। बहुजन समाज के साहित्यकारों, पत्रकारों, लोक गायकों, यूट्यूबर्स को भी साथ लेकर चलना होगा। आकाश आनंद के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी देश के 40 करोड़ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों और 25 करोड़ अल्पसंख्यकों एवं 30 करोड़ अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में सत्ता की चाहत पैदा करने में वे कैसे सफल होते हैं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 317
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

वेंकैया गारू : भारत की सेवा में समर्पित जीवन

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री
https://x.com/narendramodi

राजनीति में अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वह अपने-आप में एक उदाहरण है. वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे है. हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है. मैंने देखा है, जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला.

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक हमारे एम वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है. वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गये हैं. उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है. मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं. देश में उनके लाखों चाहने वाले हैं. मैं उनके सभी शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बधाई देता हूं. वेंकैया जी का 75वां जन्मदिवस एक विशाल व्यक्तित्व की व्यापक उपलब्धियों को समेटे हुए है. उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए. राजनीति में अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वह अपने-आप में एक उदाहरण है. उनकी वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है. वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं. हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है. मैंने देखा है, जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला.

वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे. उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी. किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था. लेकिन उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी. उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं भाजपा को मजबूत किया. लगभग 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया. लोकनायक जेपी को आंध्र प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा. लोकतंत्र के लिए उनकी यह प्रतिबद्धता उनके राजनीतिक जीवन में हर जगह दिखायी देती है. अस्सी के दशक के मध्य में, जब महान एनटी रामाराव की सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था, तब वे फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे. वर्ष 1978 में आंध्र प्रदेश ने जब

एम वेंकैया नायडू

कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक युवा विधायक के रूप में जीत कर आये थे. पांच साल बाद, राज्य चुनाव में एनटीआर की लोकप्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर थी. तब भी वे भाजपा के विधायक चुने गये. उनकी जीत ने आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण में भाजपा के लिए भविष्य के बीज बोये थे. युवा विधायक के रूप में ही वे विधायी मामलों में अपनी दृढ़ता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित होने लगे.

उनकी वाकपटुता, शब्द-शैली और संगठन सामर्थ्य से प्रभावित होकर एनटीआर जैसे दिग्गज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना. एनटीआर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वेंकैया गारू हमेशा की तरह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे. उन्होंने आंध्र प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभायी, गांवों में जाकर सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़े. उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी बने. नब्बे के दशक में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुए उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया. वर्ष 1993 में यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था. एक ऐसा व्यक्ति, जो किशोरावस्था में अटल जी और आडवाणी जी के दौरों की तैयारी करता था, उनके लिए ये कितना बड़ा मुकाम था. पार्टी महासचिव के रूप में, उनका एक ही लक्ष्य था कि अपनी पार्टी को सत्ता में कैसे लाया जाये. उनका एक ही संकल्प था कि कैसे देश को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री मिले. दिल्ली आने के बाद, उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. कुछ ही समय बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने.

वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे, तो वे वेंकैया गारू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे. अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो वेंकैया गारू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना. उनकी इस पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था. क्योंकि, उसके पहले नेताओं के लिए दूसरे मंत्रालय पहली पसंद हुआ करते थे. लेकिन, वेंकैया गारू की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी. वह एक किसान पुत्र थे, उन्होंने अपने शुरुआती दिन गांवों में बिताये थे और इसलिए, अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र था, जिसमें वे काम करना चाहते थे, तो वह ग्रामीण विकास था. उस समय एक मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी. वर्ष 2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला. उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की. शायद, वे उन कुछ नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय तक ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए काम किया है. वर्ष 2014 के उन शुरुआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे भी बहुत काम आया था. मैं उस समय दिल्ली के लिए एक बाहरी व्यक्ति था. मेरा करीब डेढ़ दशक गुजरात में ही काम करते हुए बीता था. ऐसे समय में वेंकैया गारू का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था. वे एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे. वे सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे. साथ ही, जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात आती थी, तब वे नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नजर आते थे.

वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया. ये हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था. हम यह जानते थे कि वेंकैया गारू के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा. लेकिन साथ ही, हमें यह भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है. मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता. जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद किया, तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाये. इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है. उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाये, जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ी. वे राज्यसभा के एक उत्कृष्ट सभापति थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा सांसदों, महिला सांसदों और पहली बार चुने गये सांसदों को बोलने का अवसर मिले. उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया तथा समितियों को अधिक प्रभावी बनाया. उन्होंने सदन में बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया. जब अनुच्छेद-370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय राज्यसभा के पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे. मुझे यकीन है कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था. वह युवा, जिसने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, जब वह सपना पूरा हुआ, तो वह सभापति के पद पर आसीन था. किसी निष्ठावान देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा!

काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं. दिल्ली के लोगों के बीच, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो शहर में गौरवशाली तेलुगु संस्कृति लेकर आये. उनके द्वारा आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं. मैं वेंकैया गारू को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं, जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं. लेकिन, पिछले कुछ समय से उनका संयम भी सबके सामने दिखने लगा है. फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि वे अभी भी बैडमिंटन खेलना और ब्रिस्क वॉक करना पसंद करते हैं. उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी, वेंकैया गारू सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं. वे लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर मुझसे बात करते रहते हैं. हाल ही में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं. मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनायेंगे. यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं, जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं.

विश्व कप जीतने पर गौरवान्वित भारत

मनोज चतुर्वेदी
वरिष्ठ खेल पत्रकार
chaturvedi.manoj23@gmail.com

यह सही है कि द्रविड़ के कार्यकाल में भारत की यह पहली आइसीसी ट्रॉफी है, पर उनके ढाई साल के कार्यकाल में भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के फाइनल में खेला. यह प्रदर्शन शानदार ही है. अब द्रविड़ के कोच पद छोड़ने और विराट कोहली व रोहित शर्मा द्वारा टी-20 से संन्यास लेने की घोषणा कर देने से नये कोच को अपने हिसाब से इस प्रारूप के लिए नयी टीम खड़ी करने का मौका होगा.

बारबाडोस के केनसिंग्टन ओवल मैदान पर छाये बादल बरसते, इससे पहले ही भारतीय खिलाड़ियों की अश्रुधारा बह निकली. इसकी वजह भारत का 2007 के बाद पहली बार टी-20 विश्व कप जीतना था. फाइनल में खिलाड़ियों का ही नहीं, दर्शकों के लिए भी धड़कनों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था. मुकाबला इतना रोमांचक था कि आखिरी ओवर तक यह तय नहीं था कि कौन जीतेगा. पर भारतीय दल ने आखिरी ओवरों में सब कुछ झोंककर 13 सालों बाद विश्व कप जीतने का गौरव दिला दिया. भारत ने आखिरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धौनी की अगुआई में वनडे विश्व कप जीता था. साल 2007 में पहली बार आयोजित हुए टी-20 विश्व कप को भी भारत ने जीता था. विश्व कप में विजेता बनने की शुरुआत कपिलदेव के नेतृत्व में 1983 में हुई थी. इस विश्व कप में भारतीय टीम सही मायनों में एक चैंपियन की तरह खेली और अजेय रहकर विजेता बनी. इस तरह से विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम पहली है. फाइनल की प्रतिद्वंद्वी दक्षिण अफ्रीका टीम भी अजेय रहकर फाइनल में पहुंची थी. एडन मारक्रम की अगुआई वाली इस टीम के सामने अपने ऊपर से चौकर्स का टेग हटाने का दवाब था. फाइनल में पहुंचने से यह टेग किसी हद तक हट गया है.

दक्षिण अफ्रीका एक समय चैंपियन बनने की तरफ भी बढ़ गयी थी, जब उसे 24 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाने थे और उसके छह बल्लेबाज बाकी थे. तभी भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और उन्हें सूर्यकुमार यादव जैसे क्षेत्ररक्षकों का सहयोग मिला. भारतीय टीम को योजनाबद्ध ढंग से खेलने से यह सफलता मिली है. टीम ने पिछले साल घर में हुए आईसीसी वनडे विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था. इस विश्व कप के लिए रोहित शर्मा के हाथों में ही कमान रहने का सात महीने पहले फैसला होने के समय ही कोच द्रविड़ और कप्तान शर्मा ने तय कर लिया था कि इस बार टी-20 को उसके अंदाज में ही खेलेंगे. ऐसे में विराट कोहली चल नहीं सके और उन्हें लगातार ओपनर की भूमिका में रखने की आलोचना भी हुई. इसकी वजह यशस्वी जायसवाल के रूप में एक आक्रामक ओपनर होना था. पर द्रविड़ और रोहित जानते थे कि विराट की क्या क्षमता है. इस कारण उन्होंने आलोचनाओं पर ध्यान दिये बगैर विराट पर भरोसा रखा, जो भारत को फाइनल में सफलता दिलाने में अहम साबित हुआ. भारत के तीन प्रमुख बल्लेबाज सस्ते में निकल जाने के बाद विराट ने अक्षर पटेल के साथ पारी को न सिर्फ संवारा, बल्कि स्कोर को लड़ने लायक स्थिति में पहुंचाया.

भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तो लगातार कमाल कर ही रहे थे, पर इसमें हार्दिक पांड्या नये हीरो के रूप में उभरे. उन्हें जब आखिरी ओवर में गेंद थमायी गयी, तो दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 16 रन बनाने थे और उनके सामने डेविड मिलर थे, जिन्हें आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है. इस ओवर को करते समय हार्दिक ने तो अपनी धड़कनों को काबू में रखा ही, पर उन्हें सफल बनाने में सूर्यकुमार यादव की भूमिका भी अहम रही. मिलर ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया और गेंद सीमारेखा के पार भी जा रही थी. पर वहां खड़े सूर्यकुमार ने जिस अंदाज में कैच पकड़ा, उसे ही मैच को भारत के पक्ष में बदलने वाला माना जा रहा है. राहुल द्रविड़ के कोच के तौर पर कार्यकाल का यह आखिरी टूर्नामेंट था, इसे रोहित शर्मा की टीम यादगार बनाने में सफल रही. द्रविड़ खिलाड़ी के तौर पर विश्व कप जीतने का सपना साकार नहीं कर सके थे, वह उन्होंने कोच के तौर पर पूरा कर लिया है. इस सफलता में राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर की तिकड़ी की अहम भूमिका रही. इनके बेहतरीन निजी रिश्तों से टीम को तैयार करने का तरीका, सोच और लक्ष्य एक रहा. द्रविड़ और रोहित को जिस खिलाड़ी की जरूरत होती, उसे उपलब्ध कराने में आगरकर ने कभी आनाकानी नहीं की. यह सफलता द्रविड़ की हर खिलाड़ी के साथ आपसी समझ बनाने का भी परिणाम है. यही वजह है कि जिन रोहित और हार्दिक में आईपीएल के दौरान अनबन की खबरें आ रही थीं, वे एकजुट होकर टीम को सफल बनाने का प्रयास करते दिखे.

राहुल द्रविड़ को रोहित शर्मा और अजित आगरकर का साथ तो मिला ही, साथ ही उन्होंने सपोर्ट स्टाफ में भी उन सदस्यों को ही रखा, जो उनके साथ खेले थे और उनसे संबंध अच्छे थे. बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर और गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे उनके साथ खेले हुए हैं. इस कारण टीम को एक दिशा में चलाने में आसानी हुई. यह सही है कि द्रविड़ के कार्यकाल में भारत की यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है, पर उनके ढाई साल के कार्यकाल में भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के फाइनल में खेला. यह प्रदर्शन शानदार ही है. अब द्रविड़ के कोच पद छोड़ने और विराट कोहली व रोहित शर्मा द्वारा टी-20 से संन्यास लेने की घोषणा कर देने से नये कोच को अपने हिसाब से इस प्रारूप के लिए नयी टीम खड़ी करने का मौका होगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश | दुनिया

नेपाल के डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के मायने

डब्ल्यूटीओ, जो एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली है, में नेपाल की सदस्यता को अप्रैल 2024 में 20 साल पूरे हो गये. वर्ष 2003 में पांचवीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक ने नेपाल की सदस्यता को मान्यता दी. सरकार द्वारा इसकी पुष्टि के बाद अप्रैल 2004 में नेपाल औपचारिक रूप से इस संगठन में शामिल हो गया. अपनी जटिलताओं के बावजूद, नेपाल के पास बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में प्रवेश करने के दो मुख्य कारण थे. पहला, नेपाल के लिए भारत के साथ अपने व्यापार और पारगमन समझौतों की समाप्ति के कारण अपने बाहरी व्यापार में आये शून्य को भरना अपरिहार्य था, जो उस समय देश के विदेशी व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा साझा करता था. दूसरा, यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, नेपाल के बाहरी व्यापार को तीसरे देशों के साथ विकसित करने में मदद कर सकती थी, जैसा कि 80 के दशक के अंत तक इसकी योजनाओं और नीतियों में निर्धारित था. डब्ल्यूटीओ में शामिल होने का नेपाल का उद्देश्य अपने भागीदारों के साथ व्यापार में गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार के तहत पारगमन अधिकारों और व्यापार विविधीकरण की गारंटी देना था, जैसा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के बुनियादी मानदंडों द्वारा आश्वासन दिया गया था. वैसे डब्ल्यूटीओ से नेपाल की संबद्धता का मूल्यांकन अन्य कारणों से भी किया जा सकता है. जब नेपाल इसमें शामिल हुआ, तो 2001 में शुरू की गयी डब्ल्यूटीओ व्यापार वार्ता के दोहा राउंड पर विश्व की नजर थी, क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील दोनों देशों के हितों को शामिल किया गया था. दोहा राउंड से नेपाल की विशेष संबद्धता है. कृषि सब्सिडी और टैरिफ में कटौती के साथ-साथ गैर-कृषि उत्पादों के बाजार पहुंच को बेहतर बनाने की समझ के लिए जाने जाने वाले दोहा राउंड में नेपाल सहित अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत पहली बार तरजीही बाजार पहुंच की शुरुआत हुई.

-बिजेंद्र मान शाक्य

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस विशेष

विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले डॉक्टरों को नमन

रोहित कौशिक
टिप्पणीकार
rohitkaushikmzm@gmail.com

आम तौर पर हमारे समाज में डॉक्टरों को लेकर एक अजीब नकारात्मकता मौजूद रहती है. उनके खिलाफ अनेक धारणाओं में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन इनके आधार पर समूचे चिकित्सक जगत को बदनाम करना तर्कसंगत नहीं है. कई डॉक्टर समर्पण के साथ चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं. हम सबका यह कर्तव्य है कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले डॉक्टरों के जज्बे को नमन करते हुए चिकित्सा जगत में पनपती विसंगतियों का गंभीरता विश्लेषण हो. कोरोना काल में हमारे डॉक्टरों ने जिस समर्पण के साथ समाज की सेवा की है, वह बेहद सराहनीय है. हो सकता है कि इस आपदा को कुछ डॉक्टरों ने अवसर में तब्दील कर दिया हो, लेकिन इस आधार पर पूरी डॉक्टर बिरादरी को बदनाम करना ठीक नहीं है. कई बार डॉक्टरों के साथ मरीजों के परिजनों द्वारा मारपीट की घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं. इस वजह से डॉक्टर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है. यही कारण है कि वह पहले ही सब परीक्षण करा लेना चाहता है. कई बार सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टर संसाधनों के अभाव में भी बेहतर कार्य नहीं कर पाते हैं. ऐसे में डॉक्टरों के समर्पण को व्यवस्था की मार से बचाने की आवश्यकता भी है.

आज सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों को बेहतर माहौल देने

और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार की जरूरत है. पिछले दिनों नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च बढ़ाने की जरूरत बतायी थी. यह कटु सत्य है कि हमारे देश में आबादी के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं दयनीय स्थिति में हैं. भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का मात्र डेढ़ फीसदी ही खर्च होता है. हालांकि सरकार ने अगले पांच साल में इसे तीन फीसदी तक करने का लक्ष्य रखा है. हमारे देश के हिसाब से यह भी कम है. कई देश स्वास्थ्य सेवा मद में आठ से नौ फीसदी तक खर्च कर रहे हैं. यह सही है कि धीरे-धीरे हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है, लेकिन जब इस दौर में भी मरीजों को अस्पतालों में स्ट्रेचर जैसी मूलभूत सुविधाएं न मिल पायें, तो स्वास्थ्य सेवा पर सवाल उठना लाजमी है. इस प्रगतिशील दौर में भी ऐसी अनेक खबरें आयी हैं कि अस्पताल गरीब मरीज के शव को घर पहुंचाने के लिए एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा पाये. संसाधन सीमित होने तथा व्यवस्था में सुधार न होने के कारण डॉक्टर बेवजह बदनाम होते हैं.

पिछले दिनों अमेरिका के 'सेंटर फॉर डिजीज डाइनामिक्स, इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिसी' (सीडीडीईपी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में लगभग छह लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है. भारत में 10,189 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक हजार लोगों पर एक डॉक्टर की सिफारिश की है. हमारे देश में व्यवस्था की नाकामी और विभिन्न कारकों के कारण बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है. भारत में डॉक्टरों की उपलब्धता वियतनाम और अल्जीरिया जैसे देशों से भी कम है. हमारे देश में इस समय लगभग 7.5 लाख सक्रिय डॉक्टर हैं. इससे गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में देरी होती है. यह स्थिति अंततः पूरे देश के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर गठित संसदीय समिति ने पिछले दिनों जारी अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और तीव्र बनाने की जरूरत है. चीन ,ब्राजील और श्रीलंका जैसे देश भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमसे ज्यादा खर्च करते हैं. पिछले दो दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन के बाद सबसे अधिक रही है. इसलिए पिछले दिनों योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि सार्वजनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जाए.

दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी पीढ़ी बाजार के हाथ इस कदर बिक गयी है कि न्यूनतम मानवीय मूल्य भी संकट में पड़ गये हैं. इस बाजार आधारित व्यवस्था में हमारी संवेदना भी बाजारू हो गयी. यह कटु सत्य है कि बाजार के प्रभाव ने हर क्षेत्र में बिचौलिये और भ्रष्टाचारी पैदा किये हैं. डॉक्टरी का पेशा भी इससे मुक्त नहीं रह सका है. यह समाज और चिकित्सकों के लिए एक गंभीर चिंता की बात है. यह संतोषजनक है कि इस माहौल में भी अनेक डॉक्टर अपने पेशे की गरिमा को बचाये हुए हैं. अनेक कारणों से भविष्य में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ेगा तथा कई बीमारियों का प्रकोप भी अधिक होता जायेगा, इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए एक दीर्घकालिक नीति बनाये. सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिये जाने की जरूरत है. हमें यह ध्यान रखना होगा कि कठिन परिस्थितियों में डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर संसाधन मुहैया कराने से उनकी कार्यक्षमता तो बढ़ेगी ही, उनके अंदर आत्मविश्वास भी कायम होगा. इस संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को भी उच्चस्तरीय बनाने की आवश्यकता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

आपके पत्र

पर्यावरण की रक्षा का लें संकल्प

मानव जीवन के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना आवश्यक है. पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पेड़-पौधे जरूरी हैं. पर्यावरण की रक्षा के लिए धरती पर हरियाली जरूरी है. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से धरती का तापमान बढ़ गया है. इसके कारण समय पर बारिश नहीं हो रही है. पारंपरिक जलस्रोत सूख गये हैं. नदियों में पानी नहीं है, जिससे जीव-जंतुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए आनेवाले संकटों से बचने के लिए लोगों को पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना होगा. साथ ही सभी एक-एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए.

दिब्यनेत्री सिंह, मधेपुरा

पेपर लीक से चौपट हो रहा भविष्य

प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है. नीट में गड़बड़ी का असर लाखों छात्र-छात्राओं पर पड़ा है. योग्य व मेहनती छात्र निराशा के शिकार हो रहे हैं. इसलिए नीट पेपर लीक मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जानी चाहिए. क्योंकि यदि एक भी अयोग्य छात्र डॉक्टर बन जाता है, तो वह समाज के लिए खतरनाक है. इसलिए यदि नीट में पेपर लीक हुआ है, तो परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए. साथ ही परीक्षा लेनेवाली एजेंसी इसका ध्यान रखे कि भविष्य में कोई गड़बड़ी नहीं हो.

डॉ पवन कुमार, गया

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar .in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो . लिपि रोमन भी हो सकती है .

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बारिश का एक दुख

पहली बारिश में ही दिल्ली का जो हाल हुआ है, वह न केवल चिंताजनक, बल्कि दुखद भी है। जगह-जगह जाम, जल भराव, पेड़ों का गिरना अपनी जगह बहुत गंभीर है, पर सबसे सनसनीखेज घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर घटी है। शुक्रवार को भारी बारिश के बीच छत का एक हिस्सा वाहनों पर आ गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। जब हादसा हुआ, तब बारिश हो रही थी, सुबह करीब 5.30 का समय था, हादसा अकल्पनीय था। बीते मार्च में ही नई दिल्ली के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 का विस्तार किया गया है। इसका विस्तार करने-कराने वालों ने सुंदरता का तो ध्यान रखा, मगर मजबूती सुनिश्चित करना शायद वे भूल गए। इस टर्मिनल से लाखों लोग यात्रा करते हैं, पर रखरखाव में ऐसी लापरवाही अक्षम्य मानी जाए, तो ही न्याय है। एक बार सोचकर जरूर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश गया है? क्या भारत अपने एक सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को भी ढंग से नहीं रख पा रहा है?

राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर जब यह हाल है, तो बाकी जगहों पर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर न जाने कितने सवाल खड़े किए जा सकते हैं? न जाने कितने ऐसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे देश में होंगे, जिन्हें सिर्फ रंग-रोगन करके चमकाया गया होगा? जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, उनकी लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है? कहीं भवन ढह रहे हैं, तो कहीं पुल गिर रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर दरारें पड़ रही हैं? खूब लंबे-चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना जरूरी है, पर शहरों के अंदर की सड़कों का रखरखाव कौन करेगा? दिल्ली में केवल दो घंटे की बारिश के बाद अंडरपास और अंडर ब्रिज में पानी भर जाना क्या हमारी अक्षम नौकरशाही की ओर इशारा नहीं है? नौकरशाहों को भला कैसे निर्दोष मान लिया जाए और अगर उन्हें निर्दोष मान लिया जाए, तो फिर दोषी कौन है? यह शर्मनाक बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित मिंटो ब्रिज दशकों से लोगों को रुलाता आ रहा है, वहां से तमाम नेताओं, अफसरों, रसूखदारों की गाड़ियां गुजरती हैं, पर क्या मजाल कि मिंटो ब्रिज इलाके में पानी न भरे? देश में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं, जिनके बारे में यह मान लिया गया है कि यहां तो जल भराव एक सालाना आयोजन है। साल में दस-पंद्रह दिन जल भराव होगा, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या जहमत उठाएं?

एक बार सोचकर जरूर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश गया है? क्या भारत अपने एक सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को भी ढंग से नहीं रख पा रहा है?

क्या हम अपने देश में नागरिक सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? क्या अपने देश में लोगों की जिंदगी को बहुमूल्य माना जाता है? इस बार भी उदारता से मुआवजा दे दिया जाएगा, पर पुख्ता समाधान व सुरक्षा के इंतजाम के प्रति लापरवाही बरती जाएगी? यह दोषारोपण करने या आंखें चुराने का नहीं, बल्कि कमियों से दो-दो हाथ करने का वक्त है। सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी काबिले-गौर होनी चाहिए। गुणवत्ता या कानून से समझौता करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गतिवान है, वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है, पर अगर हम अपने नागरिकों की कद्र नहीं बढ़ाएंगे, तो वास्तव में विकास को ही अंगूठा दिखाएंगे। दुनिया के अच्छे देशों से सीखते हुए सुधार की जरूरत है, ताकि हमारा बेहद चमकदार होता बुनियादी ढांचा हमारे माथे पर ही न गिरने लगे और हम आश्वस्त होकर सिर उठाए चल सकें।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 29 जून, 1949

नरेशों की सम्पत्ति

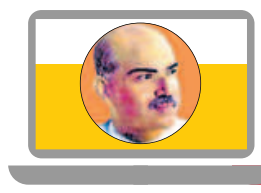

रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व का जब अन्त किया जा रहा है, तब नरेशों का महत्व भी पहले जैसा नहीं रह सकता। किन्तु रियासतें राजाओं की विरासत-सी रही हैं, इसलिए रियासत की कौन-सी सम्पत्ति राजा की मानी जाये और कौन-सी राज्य की, यह निश्चय करना सरल नहीं है। सभी रियासतों में यह समस्या रही है और प्रवृत्ति कुछ ऐसी पाई गई कि राजा अधिक-से-अधिक चीजें अपने पास रखने की कोशिश करते हैं और लोकपक्ष समझता है कि यह ठीक नहीं है। रियासती मंत्रालय के निर्णय द्वारा इस स्थिति का समाधान ही ऐसी हालत में विवाद को समाप्त कर सकता है। इस दृष्टि से रियासती मंत्रालय के इस विषयक निर्णय का हम स्वागत करते हैं।

जो निर्णय किया गया है, वह अभी अस्थायी है और तीन-चार रियासतों पर लागू नहीं होता, फिर भी एक अरब रुपये से अधिक सम्पत्ति का निश्चय उससे हो जाता है। आधार उसका यह रखा गया है कि (१) राजा जिस महल में रहता हो उसे वह अपने पास रख सकेगा, साथ ही समुद्रतटवर्ती या पहाड़ के एक मकान को भी वह रख सकता है, बाकी सब मकान राज्य के माने जायेंगे। (२) जमीन राजा के पास नहीं रहेगी और उसके पूर्वजों की सम्पत्ति साबित होने पर कोई जमीन राजा के पास रही भी, तो और लोगों की तरह उसे भी उस पर कर देना पड़ेगा। (३) सरकारी खजाने में जो रकम राजा की निजी सम्पत्ति के रूप में रहती आई है उनकी जांच कर उसका बहुत-सा भाग उन रियासतों से बने राज्यसंघों को दे दिया गया है और जो रकम सचमुच निजी मालूम पड़ी, वही राजा की निजी सम्पत्ति मानी गई है। (४) बाहर लगा रुपया या संकट के लिए सुरक्षित कोष कई राजाओं ने स्वयं राज्यों को दे दिया है। (५) जवाहरात को दो किस्मों में बांटा गया है और निजी उपयोग वाले निजी सम्पत्ति माने गये हैं तथा समारोहों पर काम आने वाले राज्य की। (६) पुरातत्व की चीजें भी सरकारी नियंत्रण में रहेंगी। (७) राजाओं द्वारा दी गई जागीरों (जमीन) के बारे में तय हुआ है कि विलीनीकरण के आसपास दी गई जागीरें मान्य नहीं की जायेंगी और उससे बहुत पहले दी गई जागीरें वहां की भूमि सम्बन्धी कानून के मातहत रहेंगी।

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव शुरू से राजनीतिक खींचतान का विषय रहा है। यही कारण है, देश की पहली लोकसभा में भी अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। विपक्ष के नेता चाहते थे कि लोकसभा अध्यक्ष कोई स्वतंत्र उम्मीदवार हो और आज भी कई लोग यही चाहते हैं।

आमने-सामने

दल छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष बनना चाहिए

यहां स्कैन करें

श्यामा प्रसाद मुखर्जी | वरिष्ठ नेता व सांसद

- अध्यक्ष का निर्वाचन जिस ढंग से हुआ है, मैं उससे अधिक प्रसन्न नहीं हूं।
- विरोधी दल से परामर्श करते, तो शायद निर्वाचन सर्वसम्मति से हो जाता।
- बहुमत के बल पर अगर कानून बनाए गए, तो उन्हें भंग किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय (जीवी मावलंकर) पूर्व वक्ताओं के साथ-साथ मैं भी आपको लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं तथा श्रद्धा अर्पित करता हूं। आप इस पद के लिए कोई नवागन्तुक तो नहीं हैं। आप भूतपूर्व केंद्रीय धारा सभा के अध्यक्ष तथा बाद में अस्थायी संसद के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिस हैसियत में आपको उचित परंपराओं तथा प्रथाओं की स्थापना करनी पड़ी है। अतः स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद का अध्यक्ष निर्वाचित होने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में, भारत के सांविधानिक इतिहास में आपका एक अपना विशिष्ट स्थान है।

मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि आपके हाथ में माननीय सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम सामान्यतः ब्रिटिश लोकसभा की प्रथाओं तथा परंपराओं का ही अनुसरण करते रहेंगे, किंतु ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना है, जब हमें उन परंपराओं में परिवर्तन करके अपनी स्वयं की प्रथाएं स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारा परम लक्ष्य जन-साधारण का कल्याण तथा देश की प्रगति है।

अध्यक्ष का निर्वाचन जिस ढंग से हुआ है, मैं उससे अधिक प्रसन्न नहीं हूं। यदि आप एक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े न होकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पुनर्निर्वाचन के लिए खड़े होते, तो हमें अधिक प्रसन्नता होती। सारे संसार की यह मानी हुई परंपरा है तथा अध्यक्ष का कोई विरोध नहीं करता है। यदि इस सदन के नेता निर्वाचन के लिए आपका नाम प्रस्तुत करने से पूर्व विरोधी दल से परामर्श कर लेते, तो शायद अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से हो जाता। मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। कहने का आशय यह है कि परंपराओं तथा प्रथाओं की स्थापना तथा पालन करना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए, चाहे हम सरकारी पक्ष में बैठे हों अथवा विरोधी पक्ष में।

स्वतंत्र भारत में यह पहला अवसर है, जब संसद में विरोधी दल के सदस्यों की संख्या काफी अधिक है, यद्यपि यह मानी हुई बात है कि सरकारी पक्ष के पास सदन में भारी बहुमत है। ऐसी दशा में श्रीमान, आप इस बात की ओर ध्यान देंगे कि सरकारी तथा विरोधी, दोनों पक्षों द्वारा परंपराओं तथा प्रथाओं का पालन किया जाए। लोकतंत्र के विकास के लिए यह आवश्यक है। ऐसे कठिन कार्य में, श्रीमान, यह आपका कार्य है कि आप सदन की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाएं, जिससे कि यद्यपि कुछ मामलों में हमारे पारस्परिक मतभेद हों, किंतु हमें अपने विचार सदन के समक्ष रखने का तथा सरकार की मनमानी कार्रवाइयों को किसी हद तक रोकने का मौका मिले। श्रीमान, मैं विरोधी दल के सदस्यों की ओर से आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सदन की शान तथा इसके अधिकारों के लिए उचित परंपराएं तथा प्रथाएं स्थापित करने के आपके प्रयत्न में वे सदैव आपको सहयोग देते रहेंगे।...

यहां पर अनेक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे दृष्टिकोण भिन्न हैं, किंतु देशहित के लिए हमें ऐसा निश्चय करना चाहिए, जिससे हमारी सामान्य जनता को लाभ पहुंचे। यदि हम अपने मतभेदों को दूर न कर सके, तो अवश्य ही तानाशाही का इस देश में राज्य होगा। ...हमें कानून का सम्मान करना चाहिए और यह बात ठीक भी है। इस संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, किंतु यहां पर कानून इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए, जिसमें उसे प्रत्येक दल का सहयोग प्राप्त रहे। यदि बहुमत के बल पर कानून बनाए गए- जिन्हें साधारण जनता पसंद नहीं करती- तो उन्हें अवश्य ही भंग किया जाएगा। कानूनों को हिंसक ढंग से नहीं, अहिंसक ढंग से भंग किया जाएगा, किंतु मैं आशा करता हूं, हम सब अपना-अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभा सकेंगे। मतभेदों के होते हुए भी हम ऐसे निश्चय पर पहुंचेंगे, जिससे जन साधारण को लाभ होगा।

(लोकसभा में दिए गए दो उद्बोधनों के अंश)

मैं अपने दल से कतई अलग नहीं रह सकता

यहां स्कैन करें

जीवी मावलंकर | प्रथम लोकसभा अध्यक्ष

- हमारा लक्ष्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व प्राप्त करना है।
- हमारे देश में निर्दलीय का अध्यक्ष रहना संभव नहीं है।
- मेरा धर्म होगा कि मैं सदन के सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करूं।

संविधान के अंतर्गत निर्वाचित भारतीय गणतंत्र की पहली संसद का अध्यक्ष चुनकर माननीय सदस्यों ने जो मेरा सम्मान किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस पद के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा कठिनाइयों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं, तो मुझे एक प्रकार की घबराहट अथवा संभ्रांति हो जाती है, किंतु सदन की उदारता तथा आपके सहयोग की बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह भार उठाने के लिए उत्साहित हूं।...

हमें ध्यान में रखना होगा कि हम यहां जनता के प्रतिनिधि होकर आए हैं तथा हमारा लक्ष्य उनके लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व प्राप्त करना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि में हमें अपनी संपूर्ण गतिविधियों को देखना है तथा यदि हम इसके बारे में सचेत रहें, तो संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित वातावरण तैयार हो सकता है। लोकतंत्र का अर्थ चर्चा द्वारा शासन करना है। प्रत्येक सदस्य को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसी तरह उसे स्मरण रखना चाहिए कि दूसरे सदस्य को भी यही अधिकार प्राप्त है। इसलिए वाद-विवादों को उपयोगी, लाभकर तथा प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम संयम, सद्भावना तथा उदारता से काम करें। इसका परिणाम एक अनुशासित मन होगा, जो असंख्य संसदीय नियमों का पालन करेगा, जितनी ही सदस्यों में सहिष्णुता होगी तथा एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा होगी, संसदीय शासन उतना ही सफल हो सकता है।

हमारे संविधान ने हमारी संसद का ढांचा अंग्रेजी नमूने के आधार पर बनाया है। हमारे विधानमंडल ऐतिहासिक कारणों के लिए उसी ढांचे के आधार पर बने हैं। ब्रिटिश लोकसभा की प्रक्रिया, नियम आदि उस संस्था के चिरकाल के अनुभव का परिणाम हैं। जहां तक उन प्रथाओं और परंपराओं का मानव प्रकृति से संबंध है, वे हमारे लिए लाभकर हो सकती हैं, किंतु ऐसी भी परंपराएं तथा प्रथाएं हैं, जिनका संबंध उनके स्वतंत्रता आंदोलन से है...।

हमारे देश में संसदीय जीवन हाल ही में शुरू हुआ है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वस्थ परंपराएं स्थापित करें, उनका आदर तथा पालन करें, क्योंकि वे आने वाली संततियों के लिए पूर्व प्रथा का काम देंगी। देश में स्थिर सरकार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

इंग्लैंड में अध्यक्ष एक निर्दलीय व्यक्ति होता है, किंतु यह परंपरा वर्षों के संघर्ष के पश्चात स्थापित की गई है तथा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। जहां मैं इस आदर्श की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, वहीं हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में इंग्लैंड के स्पीकर जैसा निर्दलीय व्यक्ति का अध्यक्ष रहना संभव नहीं है। भारत की लोकसभा का अध्यक्ष इस रूप में पूर्णतः निर्दलीय व्यक्ति रहता है कि वह पार्टी की कार्यवाहियों व झगड़ों से अलग-थलग रहता है, परंतु उसका राजनीतिक जीवन केवल इसी कारण से समाप्त नहीं हो जाता है कि उसे अध्यक्ष चुन लिया गया है।

अध्यक्ष पद के लिए अभी हमें अपनी परंपराएं स्थापित करनी हैं, जिसका सिद्धांत यह है कि अध्यक्ष जब तक अपने पद पर रहना चाहता हो, उसके चुनाव का न उसके निर्वाचन क्षेत्र में विरोध किया जाए और न ही सदन में। इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं उस महान संस्था अखिल भारतीय कांग्रेस से, जिसमें रहकर मैंने गत 40 वर्ष तक किसी न किसी रूप में काम किया है, अलग नहीं रह सकता हूं। मैं अब भी एक कांग्रेस जन हूं, जैसे कि कोई व्यक्ति भारतीय होते हुए भी हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि रह सकता है। इसी तरह से यद्यपि मैं एक कांग्रेस जन हूं, मेरा यह कर्तव्य तथा धर्म होगा कि मैं सदन के सभी पक्षों के साथ न्याय तथा समानता के आधार पर व्यवहार करूं। निष्पक्ष रहूं, दलबंदी अथवा राजनीतिक अभिलाषाओं से ऊपर रहूं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

सोशल मीडिया के शोर-शराबे में जिगरी दोस्तों का टोटा

यहां स्कैन करें

बीजू डोमिनिक | सीईओ, फाइनल माइल कंसल्टिंग

अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने हाल ही में सभी सोशल मीडिया मंचों के लिए यह चेतावनी जारी किए जाने का प्रस्ताव रखा है कि 'यह किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है'। मूर्ति द्वारा सिगरेट को लेकर दिया गया इसी तरह का सुझाव कि 'धूम्रपान आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है', इसकी लत से निपटने के प्रयासों की शुरुआत थी। क्या सोशल मीडिया को लेकर उनका सुझाव सुखद अंजाम पा सकेगा?

दरअसल, सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यह सामाजिक नहीं है। मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का पहला गहन अध्ययन ब्रिटिश मानव विज्ञानी रॉबिन डनबर ने किया था। उनका निष्कर्ष था कि एक इंसान की पांच से यारी, 15 से गहरी दोस्ती, 50 से मित्रता, 150 से सार्थक रिश्तेदारी और लगभग 500 से मामूली परिचय हो सकता है। यह अध्ययन सोशल मीडिया के आने से पहले किया गया था। अब जब ऑनलाइन मंचों ने हमारे रिश्ते बदल दिए हैं, तब डनबर ने पाया है कि सोशल मीडिया ने कमजोर संबंधों, मामूली परिचितों और जिनको आप पहचानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या तो बढ़ाई है, लेकिन करीबी रिश्तों के लिए यहां जगह सिमट गई है। यह चिंतनीय आंकड़ा है कि आज के करीब 33 फीसदी नौजवान एक जिगरी दोस्त के लिए तरस रहे हैं। इस लिहाज से इसे अब तक के इतिहास की संभवतः सबसे अकेली पीढ़ी कह सकते हैं। मूर्ति ने अपनी रिपोर्ट में इस अकेलेपन को तंबाकू के सेवन जैसी महामारी बताया है। उनके मुताबिक, अकेलापन लोगों के लिए उतना ही बुरा है, जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना।

जैसे-जैसे सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, वैसे-वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के दिग्गजों की तरफ से प्रतिरोध की आशंका बढ़ने लगी है। हालांकि, यह विडंबना ही है कि आज सोशल मीडिया विशेषकर युवा पीढ़ी में संदेशों के आदान-प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम है, जिसका मतलब है कि इसकी लत के बारे में कोई भी संदेश हमें इसी माध्यम से प्रसारित करना होगा। यानी, किसी व्यक्ति को तभी इस तरह के चेतावनी भरे संदेश मिलें, जब वह सोशल मीडिया में डूबा हो। यह धूम्रपान का आनंद लेते हुए व्यक्ति से इसके खतरों के बारे में बात करने जैसा होगा। बहरहाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एल्गोरिद्म लिखने वालों को व्यसन संबंधी व्यवहार की अच्छी समझ होती होगी। चूहों पर किए गए एक अध्ययन से भी इसके संकेत मिले हैं।

स्मार्टफोन स्क्रीन को हम इसीलिए स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगली बार कुछ अप्रत्याशित दिखेगा। इसी मानसिक व्यवहार को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया में सामग्रियां परोसी जाती हैं।

इस अध्ययन में चूहों के दो गुट बनाए गए थे, जिनमें एक गुट को लीवर दबाने पर हर बार मीठा पानी दिया जाता था, जबकि दूसरे को कई बार दबाने के बाद मीठा पानी मिलता था। यह अध्ययन बताता है कि पहले गुट के चूहों ने कुछ समय के बाद लीवर दबाना बंद कर दिया, जबकि दूसरे गुट के चूहों ने अपना काम जारी रखा। ऐसा इसलिए, क्योंकि अनिश्चित पुरस्कार मस्तिष्क को पुरस्कार को लेकर संवेदनशील बनाता है और इनाम पाने के लिए अनवरत कार्य करने को प्रेरित करता रहता है।

सोशल मीडिया पर परोसी जाने वाली सामग्रियां इसी मानसिक व्यवहार पर काम करती हैं। स्मार्टफोन स्क्रीन को हम इसीलिए लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगली बार कुछ अप्रत्याशित दिखेगा।

मस्तिष्क विज्ञान के अध्ययनों के अनुसार, किसी व्यसन में रासायनिक व मनोवैज्ञानिक रूप से दो अलग-अलग प्रकार के सुख मिलते हैं। मनोचिकित्सक डोनाल्ड क्लेन इसे 'शिकार का सुख' व 'दावत का सुख' बताते हैं। व्यसन के समय ज्यादातर ध्यान दावत के सुख, यानी किसी नशीले पदार्थ के सेवन के बाद की भावनाओं पर रहता है। शिकार का सुख इच्छा जनित उत्साह, शक्ति की भावना और नशा करने के बाद पैदा आत्मविश्वास पर आधारित होता है। स्मार्टफोन निर्माता व सोशल मीडिया मंच अपने उपयोगकर्ताओं में इसी प्रत्याशा को बढ़ाकर 'शिकार का सुख' बढ़ाते हैं। किसी संदेश के आने पर बजने वाली ध्वनि इस प्रत्याशा को बढ़ाने का काम करती है। बेशक वह संदेश क्रेडिट कार्ड कंपनी से आया हो, लेकिन इंसानी दिमाग अगले संदेश का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। यही शिकार का आनंद है।

निस्संदेह, सोशल मीडिया की लत से निपटा जाना चाहिए, मगर करीब से देखने पर यही लगता है कि हम अलग ही तरह के दिमागी खेल से निपट रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

प्रेम और वासना का फर्क

प्रेम में एक वस्तु भी जीवंत हो उठती है। पत्थर और वृक्ष तुमसे बातें करते हैं। समस्त सृष्टि सजीव और दिव्य हो जाती है। वासना में एक सजीव प्राणी भी केवल वस्तु बनकर रह जाता है। वासना तनाव लाती है, प्रेम विश्राम लाता है। वासना में कपट और छल है, प्रेम में विनोदिता, लीला है। वासना एक अंग पर केंद्रित होती है, प्रेम पूरे अस्तित्व पर। वासना में तुम झपटना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो; प्रेम में तुम देना चाहते हो, समर्पण करते हो।

वासना में प्रयत्न है, प्रेम प्रयत्नहीन है। वासना हिंसा लाती है, प्रेम बलिदान लाता है। वासना में मांग है, प्रेम में अधिकार है। वासना तुम्हें दुविधा देती है, प्रेम तुम्हें केंद्रित करता है। प्रेम के अनेक रूप और रंग हैं। वासना कहती है, 'जो मैं चाहूं, वही तुम्हें मिले'; प्रेम कहता है, 'जो तुम चाहो, वही तुम्हें मिले।' वासना जकड़ती है, विनाश करती है; प्रेम स्वतंत्रता लाता है, मुक्त करता है। वासना में बाधा होने पर व्यक्ति क्रोधित होता है और नफरत करने लगता है। आज संसार में फैली घृणा प्रेम के कारण नहीं, बल्कि वासना के कारण है।

भोलेपन और प्रेम के प्रतीक शिव एक बार ध्यान में बैठे थे। कामदेव ने फूलों के बाण से उनके ध्यान में खलल डाला। ध्यान से उठने पर शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और कामदेव (मन को मथने वाले, मनमथ) को भस्म कर दिया। वासना मन को जकड़ती है, शरीर को थकाती है और बुद्धि को क्षीण करती है। वासना कुछ और नहीं, केवल अनियंत्रित आदी ऊर्जा है। नियंत्रित होने पर यही ऊर्जा उत्साह, चमक, तीव्र बुद्धि और प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होती है।

श्री श्री रविशंकर

उदय प्रकाश | हिंदी साहित्यकार

सन् 1968 के फ्रांसीसी छात्र आंदोलन ने जनरल देगाल की सत्ता को डिगा दिया था। 1974 में गुजरात के छात्र आंदोलन ने अंततः जेपी की अगुआई में इंदिरा गांधी को अपदस्थ किया। छात्र शक्ति को कम न आंकें!

जांच एजेंसियां सिर्फ परेशान कर रहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का यह आरोप सोलह आने सच है कि पूरा सिस्टम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके पति जेल से बाहर न आएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सब 'तानाशाही' और 'आपातकाल' है। वाकई, दो दिन पहले हम सब 1975 में लगाए गए 21 महीनों के आपातकाल को कोस रहे थे। संसद तक में इसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी और लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था जताई गई, लेकिन दावे और हकीकत में जमीन-आसमान का फर्क है। 1975 में सब कुछ घोषित था। सभी को पता था कि आपातकाल लगा हुआ है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। लोगों को संभलने और सोच-समझकर कदम उठाने का मौका दिया गया था। मगर अब तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र प्रशासनिक नियमों तले दबा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का इशारा कर चुकी थी, तब भी रात के अंधेरे में पहले मुख्यमंत्री से सीबीआई ने पूछताछ की और फिर अगले दिन रिमांड की मांग कर डाली। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि उनका बाहर आना संभव न हो सके। ऐसा हुआ भी। आखिर क्या चल रहा है यह सब? निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए जमानत दे दी थी कि उनके खिलाफ ठोस सुबूत नहीं हैं। केवल गवाहों के आरोप को बतौर सुबूत पेश किया जाता रहा है। साफ है, इस मामले से जुड़ी जांच एजेंसियां अपने रसूख का फायदा उठा रही हैं, जो भारत जैसे लोकतंत्र में उचित नहीं जान पड़ता। इसका हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल के साथ इंसाफ होना चाहिए।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

अपराधियों जैसा व्यवहार

एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को किस हद तक परेशान किया जा सकता है, इसकी नजीर हैं केजरीवाल। उनके विरुद्ध ऐसा कोई सुबूत नहीं है कि उनके साथ दुर्दांत अपराधियों जैसा व्यवहार हो। फिर भी, जांच एजेंसियां उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, जो बदले की कार्रवाई जान पड़ती हैं। जिस तरह से उन्हें कानूनी छिद्रों का फायदा उठाकर जेल में रखने की साजिश रची गई है, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उनको जैसे ही निचली अदालत से जमानत मिली, तुरंत ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी डाल दी गई। इतना ही नहीं, उस पर कोई फैसला आता कि तुरंत एक दूसरी जांच एजेंसी ने अपनी दबिश बढ़ा दी और उनको गिरफ्तार कर लिया। यह सही नहीं है।

सुनीत कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
अरविंद केजरीवाल

कानून की निगाह में सभी आरोपी बराबर

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जैसा कर्म किया है, वह उसी का फल भोग रहे हैं। शराब घोटाले को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। यह विडंबना ही है कि इस घोटाले के दाग उस मुख्यमंत्री पर लगे हैं, जो खुद को कट्टर ईमानदार होने की बात कहते नहीं थकते थे। यहां तक कि अपने दल के लोगों को भी वह ईमानदार बताते थे और दावा करते थे कि राजनीति बदलने के लिए वह आए हैं, यानी देश में जरूरी वैकल्पिक राजनीति के वही मूलाधार हैं। मगर सत्ता मिलते ही आप संयोजक के रंग ऐसे बदले कि पहले उनके अपने संगी-साथी पीछे छूटते गए और फिर उन पर घोटाले के दाग लग गए। कोई सरकार शराब बिक्री पर ऐसी नीति लाती है, जिससे राजस्व की आनुपातिक रूप से भारी हानि हो और इस विषय पर कई राजनेताओं व व्यापारियों की बातचीत सामने आती हो, तो संदेह होता ही है। यह शक तब और बढ़ जाता है, जब पता चलता है कि मोबाइल फोन नष्ट किए गए हैं। साफ है, यह सब यूं ही नहीं किया गया होगा। कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी? आम भाषा में कहें, तो बिना आग के यह धुआं तो नहीं फैला होगा?

कुछ लोग जांच एजेंसियों को कोस रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि ये एजेंसियां बिना सुबूत किसी पर हाथ नहीं डालतीं, वह भी उस शख्स पर, जो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो। जाहिर है, कोई बड़ा सुबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, जिसे जुटाने में एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून से अनजान जान पड़ते हैं। बेशक बौद्धिक रूप से वह काफी समृद्ध हैं, पर जांच एजेंसियां कानून से ही चलती हैं और भारतीय कानून इस तरह बनाए गए हैं कि कोई निर्दोष सजा पा ही नहीं सकता। ईडी, सीबीआई जैसी नामी एजेंसियां स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ पुख्ता सुबूत हैं, तो फिर हम उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे?

यह कानूनी प्रावधान ही था, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने चुनाव में जमकर प्रचार किया और यह भी कानूनी प्रावधान ही है, जिसके तहत उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया और रिमांड पर लिया, इसलिए जांच एजेंसियों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। कानून अपना काम करेगा ही, क्योंकि उसकी नजर में सभी बराबर हैं। अगर कोई कानूनी छिद्रों से बेजा लाभ उठाने की कोशिश में है, तो उसको मात ही मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि 'कानून से सबको कुछ न कुछ इसरार चाहिए/ मजलूम को इंसाफ तो मुलजिम को दरार चाहिए।'

दिनेश सिंह, चिकित्सक

दैनिक जागरण

साहस वीरों का आभूषण है

चमत्कृत करने वाली विजय

भारत का टी-20 विश्वकप का विजेता बनना इसलिए कहीं अधिक बड़ी और हर भारतीय को उत्साहित करने वाली उपलब्धि है, क्योंकि यह 17 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हासिल हुई। भारत ने इसके पहले 2011 में एक दिवसीय विश्वकप का खिताब जीता था। इस बार भारत ने अजेय रहते हुए टी-20 का विश्वकप अपने नाम कर लिया और क्रिकेट प्रेमियों समेत अन्य लोगों को भी उत्साह-उमंग से भर दिया। भारत यह खिताब इसलिए अपने नाम कर सका, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम जोश और आत्मविश्वास से तो भरी हुई थी, अंतिम क्षण तक हार न मानने के जज्बे से भी लैस थी। इसी कारण वे हार के जबड़े से जीत खींच लाए। इस चमत्कृत करने वाली कामयाबी के लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर सकी तो इसीलिए कि उसने इस अवसर के लिए कहीं बेहतर तैयारी की थी इस तैयारी को बड़ा आधार प्रदान किया आइपीएल ने। आइपीएल के मुकाबलों ने न केवल युवा क्रिकेटरों की नई पौध तैयार की है, बल्कि उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा किया है। वास्तव में आइपीएल से केवल भारतीय क्रिकेट ही लाभान्वित नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया भर की टीमें अपने खेल कौशल को निखार रही हैं।

इस पर आश्चर्य नहीं कि टी-20 का विश्व विजेता बनते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने क्रिकेट के इस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ऐसा करके उन्होंने न केवल एक उदाहरण स्थापित किया है, बल्कि नई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर भी दिया है। इस खिताब ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की वर्षों की साध तो पूरी की ही, कोच राहुल द्रविड़ के गुरु ज्ञान को भी सार्थक कर दिया। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि भारतीय क्रिकेट के तीनों दिग्गज एक वैश्विक खिताब के साथ शानदार विदाई ले रहे हैं। इसी विदाई में रवींद्र जडेजा ने भी भागीदार होकर सही कदम उठाया। अब जब टी-20 विश्व कप का विजेता बनकर भारत ने क्रिकेट जगत में फिर से अपनी धाक जमाई तब हमें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर देश-दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता देश के बढ़ते आत्मविश्वास का परिचायक है और इसका आधार पिछले कुछ दशकों में भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आया व्यापक बदलाव है। जब भी कोई देश आर्थिक रूप से सबल बनता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखता है। भारत को क्रिकेट और अन्य खेलों में अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल करने की अपनी ललक और बढ़ानी होगी। इस क्रम में देश के युवाओं को संयम, अनुशासन और कठिन परिश्रम की महत्ता को भी समझना होगा, क्योंकि टी-20 की यह ट्राफी हमारे क्रिकेटरों के इन्हीं गुणों से मिल सकी।

वैकल्पिक व्यवस्था

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को बरसात के मौसम में भी सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार ने संबंधित जिलों से वैकल्पिक मार्गों के संबंध में सूचनाएं मांगी हैं। इन मार्गों की मरम्मत और इन्हें यात्रियों की आवाजाही की दृष्टि से सुगम बनाने से यात्रा को सुव्यवस्थित रखने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की व्यवस्था का स्वयं अनुश्रवण करते रहे हैं। अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं। शुरुआती दौर में यात्रा व्यवस्था को लेकर कुछ कठिनाइयां सामने आईं, लेकिन समय रहते इनका समाधान भी किया गया। बरसात के चार महीनों में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव सड़कों पर ही पड़ता है। भूस्खलन से सड़कें बाधित होने के कारण स्थानीय नागरिक और ग्रामीण समुदाय भारी परेशानी उठाने को विवश रहते हैं। बरसात से पहले खाद्यान्न समेत आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की चुनौती से जूझना पड़ता है। यह अलग बात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भंडारण के लिए बड़े गोदामों का अभाव राज्य बनने के 23 वर्ष बाद भी बना हुआ है। ऐसे में वैकल्पिक मार्गों को लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक चिंतन के साथ ठोस कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड आपदा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। आपदा का कहर भी सड़कें अधिक झेलती हैं। बेहतर यही होगा कि प्रत्येक पर्वतीय शहर और बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैकल्पिक मार्गों का नेटवर्क विकसित किया जाए, ताकि मुख्य मोटर मार्गों के बाधित होने पर इनका उपयोग किया जा सके। प्रदेश सरकार के पास वित्तीय संसाधन सीमित हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और आपदा के मद में इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया जा सकता है। केंद्रपोषित योजनाओं और आपदा मद में केंद्र से मिलने वाली सहायता के मानकों में इन्हें भी सम्मिलित कराने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने होंगे।

संसद चलाने की साझा जिम्मेदारी

हृदयनारायण दीक्षित

अब यह धारणा बन रही है कि संसद को चलाने का दायित्व केवल सरकार का है, जबकि यह जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है, जो पिछले कुछ समय से निभाई नहीं जा रही

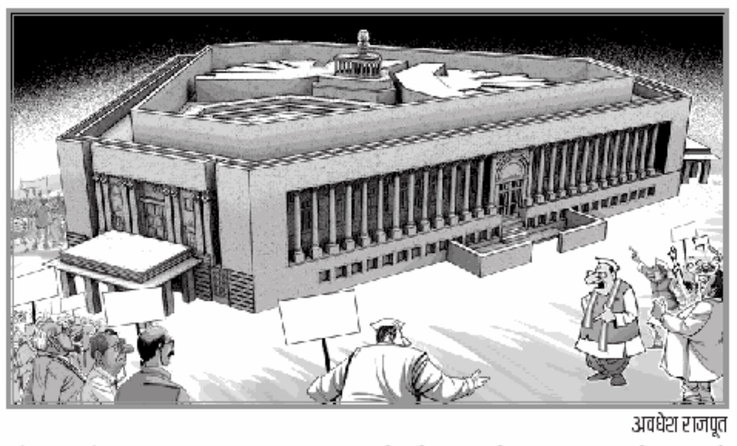

अवधेश राजपूत

नई लोकसभा गठन के साथ ही संसदीय कार्यवाही पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। संसद लगभग डेढ़ अरब लोगों की भाग्य-विधाता है। देश की इच्छा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष राष्ट्रीय समृद्धि के लिए संसद में प्रेमपूर्ण संवाद करें, लेकिन सत्र के पहले दिन ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीन बार हंगामा किया गया। दूसरे दिन से अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित थी। भारी शोरगुल हुआ। व्यवधान के कारण सदन स्थगित हो गया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति निर्मित हो गई। संसदीय प्रणाली भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का मूल आधार है। जनता ने एक समूह को बहुमत देकर सरकार चलाने का जनादेश दिया है। साथ ही राष्ट्रहित में सुझाव देने एवं आलोचना करने की जिम्मेदारी दूसरे क्रम पर आए अल्पमत जनसमूह को सौंपी है।

लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष के नेता की विशिष्ट भूमिका होती है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हेरल्ड मैकमिलन ने कहा था, 'विपक्ष के नेता की स्थिति कठिन होती है। दोष निकालना एवं आलोचना करना उसका काम है। संसद और राष्ट्र के प्रति विपक्ष की विशेष जिम्मेदारी है।' बीते कुछ वर्षों से भारत में विपक्ष की भूमिका ने निराश किया है। सदनों में व्यवधान हैं। बीते कुछ वर्षों से धारणा बनी है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है, जबकि सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक लिखा था कि, 'संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोधी पक्ष की आवश्यकता होती है, बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के बीच सहयोग भी आवश्यक होता है। हम जहां तक ऐसा करने में सफल होंगे, वहां तक हम संसदीय जनतंत्र की ठोस नींव रखने में सफल होंगे।' हंगामा, नारेबाजी, बहस के दौरान सदन से बहिर्गमन और सदन के भीतर प्लेकार्ड प्रदर्शित करना विपक्ष का अधिकार मान लिया गया है। व्यवधान के कारण विपक्ष भी जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाता। महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण भी नहीं हो पाता। ऐसे तरीकों से जनोपयोगी मुद्दे भी उपेक्षित हो जाते हैं।

भारतीय संविधान में शासन की स्थिरता के बजाय जवाबदेही को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय पद्धति को अपनाया। संसद में प्रश्न, ध्यानाकर्षण और इसी तरह के अन्य प्रस्ताव संसदीय कार्यवाही के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं। संसद सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का श्रेष्ठ मंच है। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को सौंपी गई है। संसदीय कार्यवाही को विपक्ष ही आदर्श स्थिति में पहुंचा सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष परस्पर शत्रु नहीं होते। विधान बनाना जटिल काम है। सरकार जरूरी विधायन के लिए यथाविधि प्रस्ताव लाती है। विपक्ष यथाविधि विरोध करता है। संशोधन प्रस्ताव रखता है। संसदीय कार्यवाही को उत्कृष्ट बनाना सत्ता पक्ष एवं विपक्ष का साझा कर्तव्य है।

दुनिया के अनेक देशों में संसदीय जनतंत्र सफल हो रहा है। ब्रिटिश संसद में हंगामा नहीं होता। बीबीसी के अनुसार सैकड़ों वर्षों से ब्रिटिश हाउस आफ कामंस को एक मिनट के लिए भी स्थगित नहीं किया गया। कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिकी कांग्रेस, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जापान की डायट और फ्रांस की संसद प्रायः सुचारु रूप से चलती हैं। भारत जैसा हंगामा इन जनप्रतिनिधि संस्थाओं में नहीं होता। शोर और हंगामे से राष्ट्रीय क्षति होती है। दुर्भाग्य से 18वीं लोकसभा की शुरुआत ही स्थगन व्यवधान से हुई है। यहां शपथ ग्रहण के दौरान ही अप्रिय प्रसंग देखने को मिले। कुछ सांसदों ने शपथ में अपनी ओर से अनावश्यक शब्द जोड़े। इससे संवैधानिक शपथ की गरिमा का उल्लंघन हुआ है। तमाम अवरोधों के बावजूद 17वीं लोकसभा की उत्पादकता संतोषजनक रही है, लेकिन शोर शराबा और अप्रिय शब्द प्रयोग के चलते कार्यवाही निराश करती है। मूलभूत प्रश्न है कि शोर और बाधा डालकर क्या हम कार्यपालिका को ज्यादा जवाबदेह बना सकते हैं या तथ्य और साक्ष्य रखते हुए प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। सदन में शालीन और मर्यादित आचरण एवं भाषा का कोई विकल्प नहीं है।

भारत में संसदीय प्रणाली का इतिहास काफी प्राचीन है। वैदिक काल में भी यहां सभा और समितियां थीं। संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान कई धारदार बहस हुई थीं। संविधान सभा की कार्यवाही 165 दिन चली थी। 17 सत्र हुए थे। लोकसभा में भी 1968 तक सदस्य धैर्य से सुनते थे। मर्यादा में बोलते थे। फिर हंगामा आदि कारणों से संसद की कार्यवाही पर ग्रहण लगता गया। संसद का समय घटता गया। सदस्यों की शिकायत रहती है कि सदन की बैठकें कम होती हैं। उन्हें बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। संविधान सभा में प्रो. केटी शाह ने संसद को कम से कम छह माह तक चलाने का प्रस्ताव किया था। अध्यक्ष मावलंकर का विचार भी वर्ष में सात-आठ माह सदन संचालन का था।

ब्रिटिश हाउस आफ कामंस की विशेषाधिकार समिति ने 1939-40 में सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों के पीछे कारण बताया था कि सदस्य संसद में बिना किसी बाधा के अपना कर्तव्य पालन कर सकें। शोर-शराबा और सदन के वेल में जाना विशेषाधिकार नहीं है। विशेषाधिकार जिम्मेदारी बढ़ाते हैं। हाउस आफ कामंस की एक समिति ने 1951 में दिलचस्प टिप्पणी की थी, 'विशेषाधिकारों के कारण सदस्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाते, बल्कि संसद सदस्य होने से अन्य नागरिकों की तुलना में उनके दायित्व और बढ़ जाते हैं।' विशेषाधिकार असामान्य उन्मुक्ति हैं। वे कार्यवाही में मर्यादा पालन में साधक हैं। इन सबके बावजूद कार्यवाही में व्यवधान होते हैं। विशेषाधिकार सहित सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं एवं अधिकार सदन में मर्यादापूर्वक और परिपूर्ण वाक् स्वातंत्र्य के प्रयोग को शक्ति देने के लिए हैं। सदन में अमर्यादित आचरण उचित नहीं। विश्वास है कि 18वीं लोकसभा में जनोपयोगी राष्ट्रीय विमर्श होगा। पक्ष-प्रतिपक्ष साथ मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। सभी सदस्य परस्पर आत्मीयता के परिवेश में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

नए बजट का मजबूत आधार

डा. जयंतीलाल भंडारी

आगामी बजट में सरकार को अटके हुए वित्तीय एवं श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

वित्तीय अनुशासन पर अडिग सरकार। फाइल

पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट ऐतिहासिक होगा। इसमें आर्थिक तथा सामाजिक मोर्चे पर बड़े एलान किए जाएंगे। इस बजट से सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करेगी। यह नई सरकार की नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज होगा। इसके लिए देश में कई क्षेत्रों में मजबूत आधार तैयार हो गए हैं, जैसे कि विगत में किए गए विभिन्न सुधारों से भारतीय बैंकिंग जगत विश्व के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में शुमार हो गया है। सरकार ने सार्वजनिक हिस्सेदारी वाले बैंकों को मजबूत किया और उनकी गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को कम किया है। गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से इन वर्गों का तेजी से उत्थान हो रहा है। जीएसटी संग्रह औसतन दो लाख करोड़ रुपये मासिक हो गया है। मोदी सरकार ने विनिर्माण, सेवा और कृषि जैसे क्षेत्रों को भी बराबर तवज्जो दी है। पिछले दस वर्षों में सरकार के मंत्र-रिफार्म, परफार्म एंड ट्रांसफार्म ने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। भारत ने 2021 से 2024 के बीच आठ प्रतिशत सालाना की दर से वृद्धि की है। यह दर अब और तेज होने की उम्मीद है। सरकार को वित्तीय एवं श्रम सुधारों को बजट में आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, वैश्विक बाजार में भारतीय खाद्यान्नों की मांग बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने तथा रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के विकास पर फोकस करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि गत एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट एक लेखानुदान की तरह था। इसका उद्देश्य नई सरकार बनने तक की व्यय जरूरतों को पूरा करना था। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने लोकलुभावन योजनाओं और रियायतों के रूप में कोई तोहफे नहीं दिए, बल्कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अहम कदम उठाए गए। इसने पूर्ण बजट के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक और वित्तीय आधार तैयार करने का काम किया है। देखा जाए तो देश में पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में तेज वृद्धि हुई है। जहां पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से भी अधिक हुए हैं, वहीं आय की असमानता में भी कमी आई है। देश में कर सुधारों से आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने और आयकर संग्रहण के साथ-साथ जीएसटी में लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले वर्षों में मोदी सरकार वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए राजकोषीय घाटे को बजट लक्ष्य के मुताबिक नियंत्रित रखने में काफी हद तक सफल रही है। ऐसे में आगामी बजट में गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों के कल्याण के लिए नए उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। नए बजट में विनिवेश का लक्ष्य भी बढ़ाया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहनमूलक राहत दी जा सकती है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार पीएलआइ योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे नए क्षेत्रों तक विस्तृत कर सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत दे सकती है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न उत्पादों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए अधिक पूंजीगत व्यय के प्रविधान भी हो सकते हैं।

इन दिनों वेतनभोगी वर्ग का एक बड़ा तबका यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि पिछले बजट में उसे टैक्स संबंधी कोई उपयुक्त राहत नहीं मिली है। इस बीच महंगाई के साथ-साथ उनके जरूरी खर्चे बढ़ गए हैं। इस कारण उन्हें आयकर में राहत की अपेक्षा है। इसे देखते हुए बजट में छोटे आयकरदाताओं को राहत का एलान किया जा सकता है। वेतनभोगी वर्ग को राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों एवं कारोबारियों द्वारा चुकाए गए कुल आयकर से काफी अधिक होता है। वेतनभोगी वर्ग के आयकर की कटौती आमदनी अर्जित करने के स्रोत पर की जाती है। इसे टीडीएस के रूप में जाना जाता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी अपने वेतन पर ईमानदारीपूर्वक आयकर चुकाते हैं और आमदनी को कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश की कुल आबादी के दो प्रतिशत से भी कम लोग ही आयकरदाता हैं। देश में शून्य आयकर देयता वाले आइटी रिटर्न की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नए बजट में आयकर से बचने वाले लोगों की खोज के साथ-साथ नए आयकरदाताओं को खोजने के लिए भी पुख्ता व्यवस्था करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने लगातार वित्तीय अनुशासन दिखाया है। ऐसे में आगामी बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में इसे 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य सराहनीय होगा। उम्मीद करें कि आगामी बजट आर्थिक सुधारों, आर्थिक कल्याण और तेज विकास का आधार बनने वाला होगा। साथ ही यह भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने की एक मजबूत बुनियाद तैयार करने का काम करेगा।

(लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अपूर्णता

प्रभु, सबको सब कुछ नहीं देते। जीवन के बहुरंगी उद्यान में कोई न कोई मोहक एवं लुभावना पुष्प अवश्य लुप्त कर देते हैं, जिसको प्राप्त कर अपनी जीवन बगिया को श्रेष्ठ बनाने की महत्वाकांक्षा जीव को परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहती है। कुछ न कुछ गोपनीयता, विशिष्टता, दुर्लभ, अप्राप्य संपत्ति, सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा की कुंजी वह अवश्य स्वयं के पास सुरक्षित रख देते हैं जिसे प्राप्त करने की चाह में मनुष्य आजीवन परिश्रम करने में लगा रहता है। यदि प्रभु सभी को सब कुछ दे दें तो जीव के पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति पंगु हो जाएगी और वह स्वयं को अकर्मण्य एवं कर्महीन मानने लगेगा।

ईश्वर अपने प्रिय भक्त को सतत कर्मशील रख उसके जीवन में कठिन एवं विषम परिस्थितियों के जटिल प्रश्न डाल उसे निष्णात बनाते रहते हैं। इस प्रकार से वह नितांत अपनों को क्षण-क्षण मांजते रहते हैं। आरंभ में यह प्रक्रिया कष्टप्रद लगती है, किंतु अंततः उसे सुख प्रदान करती है। अपनों की सक्रियता को बनाए रखने के लिए ही भविष्य के निर्माण की गोपनीयता को सदैव प्रभु गुप्त रखते हैं।

असंख्य सांसारिक उपलब्धियां हों, लेकिन प्रभुकृपा बिन सब शून्य। इसके बिना जगत के संपूर्ण वैभव अर्थरहित हैं। परमसत्ता की अनुकंपा, दया, दृष्टि के अभाव में असीमित सांसारिक वैभवों के उपरांत भी व्यक्ति अथवा जीव हर पल तड़पता ही रहता है, जबकि उनकी स्नेहछाया में पलने-बढ़ने वाला गरीब भी अत्यंत आनंद में जीवन का पल-पल गर्व से व्यतीत करता है। अतः उसकी कृपा में ही यश, वैभव, बुद्धि, सामर्थ्य, शक्ति एवं जीवन की संपन्नता एवं पूर्णता है। इससे इतर सब कुछ अपूर्णता, अतृप्ति, छलावा और असंतोष मात्र। मनुष्य तब तक अपूर्ण है जब तक वह स्वयं प्रभु और उनके परमानंद के दिव्य रूप, दर्शन एवं अनुकंपा से परिपूर्ण नहीं है।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति

लकी कुमार

देश को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि पुराने कानून भारतीय समाज के अनुरूप नहीं थे

आज यानी एक जुलाई से देशभर में नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं, जिन्होंने आइपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, 1860, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया है। इन तीनों कानूनों को पिछले साल दिसंबर में भारतीय संसद ने पारित किया था। इनमें पिछले कानूनों की तुलना में बहुत बदलाव किए गए हैं। जैसे-भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रह गई हैं। इसमें 20 नए अपराध शामिल किए हैं तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रविधान है तो वहीं छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रविधान किया गया है।

वास्तव में देश में लंबे समय से आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि औपनिवेशिक काल में बने कानून भारतीय समाज की गतिशीलता और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। भारतीय विधि आयोग, बेजबरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमथ समिति, माधव मेनन समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। भारत को आजादी मिले 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लेकिन भारत ब्रिटिश काल में बने आपराधिक कानूनों को अपनाए हुए था। ये कानून भारत में औपनिवेशिक शासन की निशानी के तौर पर विद्यमान थे। अब नए आपराधिक कानूनों के जरिये देश में औपनिवेशिक काल के प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया गया है। नए आपराधिक कानूनों भारतीय समाज और परिवेश के अनुरूप बनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर आपराधिक कानूनों में विभिन्न परिवर्तन किए। जहां कुछ प्रविधानों की व्याख्या करके उनका विस्तार किया वहीं कुछ प्रविधानों को हटा दिया। नए आपराधिक कानूनों से ऐसे प्रविधानों को अपडेट किया गया है।

नए आपराधिक कानूनों में कुछ ऐसे प्रविधान किए गए हैं जिससे समय पर और सुगम तरीके से न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी। भारतीय न्याय प्रणाली अपनी लेटलतीफी के लिए जानी जाती है। पूर्ण रूप से न्याय प्राप्त करने में एक व्यक्ति को बहुत अधिक इंतजार करना पड़ता है। न्याय मिलने की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है। इसलिए समय और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आपराधिक कानूनों को सरल और सहज बनाया गया है। ये तीनों कानून दंड पर नहीं, बल्कि न्याय पर ध्यान केंद्रित हैं। अब यह देखना होगा कि ये भारतीय न्याय प्रणाली के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी छवि को सुधारने में सक्षम होते हैं या नहीं?

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

प्रतिपक्ष का विरोधाभासी आचरण

'विपक्ष की अनावश्यक आपत्ति' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त के इस प्रश्न का विपक्षी दलों के पास कोई जवाब नहीं है कि 'आखिर कोई दल आपातकाल के स्मरण का विरोध करते हुए यह दावा कैसे कर सकता है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है?' कदाचित इसीलिए आपातकाल के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर सपा जैसे वे विपक्षी दल मौन रहे जिन्होंने 1975 में आपातकाल के पीड़ादायक दंश को झेला था। 2024 के आम चुनाव में संविधान बचाने का शिगूफा छोड़ने वाली कांग्रेस भी यदि आपातकाल के स्मरण प्रस्ताव पर सहयोगी दलों का अनुसरण करते हुए प्रतिपक्ष की मर्यादा का निर्वाह करती तो अच्छा रहता, लेकिन कांग्रेस बीते 50 वर्षों में इस सच्चाई को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाई कि 1975 में स्वयं की संसद सदस्यता बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल देश के संविधान और लोकतंत्र को बंधक बनाने वाला तानाशाही कृत्य था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का धीर-गंभीर दायित्व ग्रहण करने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव का विरोध करना देश को इसलिए अनुचित लगा, क्योंकि उन्होंने संविधान की प्रति को हाथ में लेकर संसद सदस्य की शपथ ग्रहण की थी। संविधान बचाने की शपथ और संविधान कुचलने वाले आपातकाल का समर्थन दोनों विरोधाभासी हैं। प्रतिपक्ष का यह विरोधाभासी आचरण देश देख रहा है। 2024 के आम चुनाव में 99 सीटें जीतकर लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित होने वाली कांग्रेस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

भारत की अखंडता पर चीन की बुरी नजर

'भारतीय हितों के समक्ष नया संकट' शीर्षक से लिखे आलेख में कैप्टन आर विक्रम सिंह ने म्यांमार में छिड़े गृह युद्ध का पूर्वोत्तर भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की ओर देशवासियों का ध्यान खींचा है, जो हमारा पूर्व का प्रवेश द्वार है, पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह भूभाग भारतीय एकता और अखंडता का आधार स्तंभ है, जिस पर पश्चिमी देश और चीन अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति हेतु बुरी निगाह डाले हुए हैं, जो हिंद महासागरीय देश सहित संपूर्ण विश्व की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। यही कारण है कि चीन सहित पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत में मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में न आए। यह संयोग की बात है कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई है। ऐसे में चीन द्वारा म्यांमार के विद्रोहियों को सैन्य साजो-सामान उपलब्ध कराकर पूर्व में पाकिस्तान की तरह मित्र की जो तलाश की जा रही है, उसकी कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देगी मौजूदा सरकार। पश्चिमी देशों को ईसाई राज्य बनाने जैसे संकीर्ण सोच से छुटकारा पाना होगा। भारत का सहयोग करना होगा। तभी जाकर इस क्षेत्र में वैश्विक शांति एवं स्थिरता कायम होगी।

मुकेश कुमार मनन, पटना

कितने कामयाब होंगे नए आपराधिक कानून

समय के साथ परिवर्तन जरूरी होता है। आपराधिक कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं अपराध करने वाले लोगों को इस बदलाव से कितना खौफ पैदा होगा यह तो आने वाला ही समय बताएगा, लेकिन इस बदलाव का कोई दुरुपयोग न कर पाए, इसकी चर्चा भी जरूरी है। अगर किसी अपराधी के अपराध के सुबूत मिल जाते हैं तो उसे फांसी के फंदे पर लटकाने में जरा भी देर नहीं लगानी चाहिए। हमारे देश में पहले भी सख्त कानून अपराधों को रोकने के लिए बने हैं, लेकिन उनका पालन सख्ती से नहीं होता है, अगर होता तो देश की राजनीति में दोष न आता, देश भ्रष्टाचार के दलदल में न धंसता। कानून जब तक राजनेताओं, पैसे वालों के हाथों की कठपुतली बना रहेगा और अपराध के मामलों पर भी ओछी राजनीति होती रहेगी, तब तक कानूनों में जितना बदलाव हो जाए, तब तक देश में अपराध कभी कम नहीं हो सकते।

raju09023693142@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

साहस वीरों का आभूषण है

चमत्कृत करने वाली विजय

भारत का टी-20 विश्वकप का विजेता बनना इसलिए कहीं अधिक बड़ी और हर भारतीय को उत्साहित करने वाली उपलब्धि है, क्योंकि यह 17 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हासिल हुई। भारत ने इसके पहले 2011 में एक दिवसीय विश्वकप का खिताब जीता था। इस बार भारत ने अजेय रहते हुए टी-20 का विश्वकप अपने नाम कर लिया और क्रिकेट प्रेमियों समेत अन्य लोगों को भी उत्साह-उमंग से भर दिया। भारत यह खिताब इसलिए अपने नाम कर सका, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम जोश और आत्मविश्वास से तो भरी हुई थी, अंतिम क्षण तक हार न मानने के जज्बे से भी लैस थी। इसी कारण वे हार के जबड़े से जीत खींच लाए। इस चमत्कृत करने वाली कामयाबी के लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर सकी तो इसीलिए कि उसने इस अवसर के लिए कहीं बेहतर तैयारी की थी इस तैयारी को बड़ा आधार प्रदान किया आइपीएल ने। आइपीएल के मुकाबलों ने न केवल युवा क्रिकेटरों की नई पौध तैयार की है, बल्कि उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा किया है। वास्तव में आइपीएल से केवल भारतीय क्रिकेट ही लाभान्वित नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया भर की टीमें अपने खेल कौशल को निखार रही हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि टी-20 का विश्व विजेता बनते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने क्रिकेट के इस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ऐसा करके उन्होंने न केवल एक उदाहरण स्थापित किया है, बल्कि नई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर भी दिया है। इस खिताब ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की वर्षों की साध तो पूरी की ही, कोच राहुल द्रविड़ के गुरु ज्ञान को भी सार्थक कर दिया। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि भारतीय क्रिकेट के तीनों दिग्गज एक वैश्विक खिताब के साथ शानदार विदाई ले रहे हैं। इसी विदाई में रवींद्र जडेजा ने भी भागीदार होकर सही कदम उठाया। अब जब टी-20 विश्व कप का विजेता बनकर भारत ने क्रिकेट जगत में फिर से अपनी धाक जमाई तब हमें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर देश-दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता देश के बढ़ते आत्मविश्वास का परिचायक है और इसका आधार पिछले कुछ दशकों में भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आया व्यापक बदलाव है। जब भी कोई देश आर्थिक रूप से सबल बनता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखता है। भारत को क्रिकेट और अन्य खेलों में अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल करने की अपनी ललक और बढ़ानी होगी। इस क्रम में देश के युवाओं को संयम, अनुशासन और कठिन परिश्रम की महत्ता को भी समझना होगा, क्योंकि टी-20 की यह ट्राफी हमारे क्रिकेटरों के इन्हीं गुणों से मिल सकी।

पीड़ितों को मिले मदद

मानसून पूरे प्रदेश में छा गया है। प्रदेश के सभी जिलों में वर्षा हो रही है। नेपाल में हो रही लगातार वर्षा के कारण पश्चिम चंपारण की पहाड़ी नदियां उफनाने लगी हैं। सुपौल, खगड़िया में कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। कोसी बराज से पानी छोड़ा गया है। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में गाइड बांध टूट गया। कई घरों में पानी घुस गया है। शिवहर में बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं, गौनाहा में हरबोड़ा नदी में बाढ़ से रुपौलिया गांव के ब्रह्मस्थान का आधा हिस्सा कटकर नदी में विलीन हो गया है। सीतामढ़ी में नदी पर बना डायवर्सन डूब गया है। महानंदा नदी का जलस्तर गिरने से कटिहार में भी कटाव शुरू हो गया है।

जो लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल जरूरी मदद पहुंचाने में प्रशासन तत्परता बरते।

धीरे-धीरे बाढ़ का पानी नए इलाकों में फैल रहा है। अच्छी बात है कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास पहले ही शुरू कर दिए गए थे। जगह-जगह तटबंधों की मरम्मत की गई। नदियों के बढ़ रहे जलस्तर और कटाव पर स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार की नजर होने का दावा किया जा रहा है। अभी मानसून की शुरुआती वर्षा है। जहां-जहां बाढ़ की स्थिति बन रही है, वहां राहत कार्य में भी तेजी दिखाने की जरूरत है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। बराज से वाटर डिस्चार्ज की सतत निगरानी हो, ताकि इससे जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो, वहां के लोगों को पहले ही सूचित किया जा सके। बाढ़ की विभीषिका का प्रभाव कम करने के लिए स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड में रहना होगा, ताकि प्रभावितों को बहुत परेशानी न झेलनी पड़े।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दिल्ली में रिकार्ड बारिश जलवायु परिवर्तन का नतीजा है?

आज का सवाल

क्या आप मानते हैं कि टी-20 विश्व कप में भारत की जीत के पीछे आइपीएल जैसे ढांचे का योगदान है?

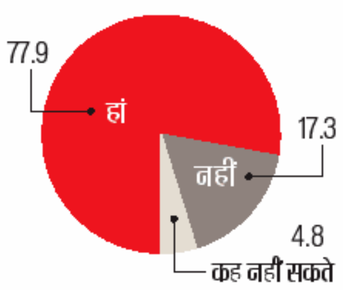

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

संसद चलाने की साझा जिम्मेदारी

हृदयनारायण दीक्षित

अब यह धारणा बन रही है कि संसद को चलाने का दायित्व केवल सरकार का है, जबकि यह जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है, जो पिछले कुछ समय से निभाई नहीं जा रही

नई लोकसभा गठन के साथ ही संसदीय कार्यवाही पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। संसद लगभग डेढ़ अरब लोगों की भाग्य-विधाता है। देश की इच्छा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष राष्ट्रीय समृद्धि के लिए संसद में प्रेमपूर्ण संवाद करें, लेकिन सत्र के पहले दिन ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीन बार हंगामा किया गया। दूसरे दिन से अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित थी। भारी शोरगुल हुआ। व्यवधान के कारण सदन स्थगित हो गया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति निर्मित हो गई। संसदीय प्रणाली भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का मूल आधार है। जनता ने एक समूह को बहुमत देकर सरकार चलाने का जनादेश दिया है। साथ ही राष्ट्रहित में सुझाव देने एवं आलोचना करने की जिम्मेदारी दूसरे क्रम पर आए अल्पमत जनसमूह को सौंपी है।

लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष के नेता की विशिष्ट भूमिका होती है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हेरल्ड मैकमिलन ने कहा था, 'विपक्ष के नेता की स्थिति कठिन होती है। दोष निकालना एवं आलोचना करना उसका काम है। संसद और राष्ट्र के प्रति विपक्ष की विशेष जिम्मेदारी है।' बीते कुछ वर्षों से भारत में विपक्ष की भूमिका ने निराश किया है। सदनों में व्यवधान हैं। बीते कुछ वर्षों से धारणा बनी है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है, जबकि सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक लिखा था कि, 'संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोधी पक्ष की आवश्यकता होती है, बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के बीच सहयोग भी आवश्यक होता है। हम जहां तक ऐसा करने में सफल होंगे, वहां तक हम संसदीय जनतंत्र की ठोस नींव रखने में सफल होंगे।' हंगामा, नारेबाजी, बहस के दौरान सदन से बहिर्गमन और सदन के भीतर प्लेकार्ड प्रदर्शित करना विपक्ष का अधिकार मान लिया गया है। व्यवधान के कारण विपक्ष भी जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाता। महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण भी नहीं हो पाता। ऐसे तरीकों से जनोपयोगी मुद्दे भी उपेक्षित हो जाते हैं।

भारतीय संविधान में शासन की स्थिरता के बजाय जवाबदेही को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय पद्धति को अपनाया। संसद में प्रश्न, ध्यानाकर्षण और इसी तरह के अन्य प्रस्ताव संसदीय कार्यवाही के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं। संसद सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का श्रेष्ठ मंच है। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को सौंपी गई है। संसदीय कार्यवाही को विपक्ष ही आदर्श स्थिति में पहुंचा सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष परस्पर शत्रु नहीं होते। विधान बनाना जटिल काम है। सरकार

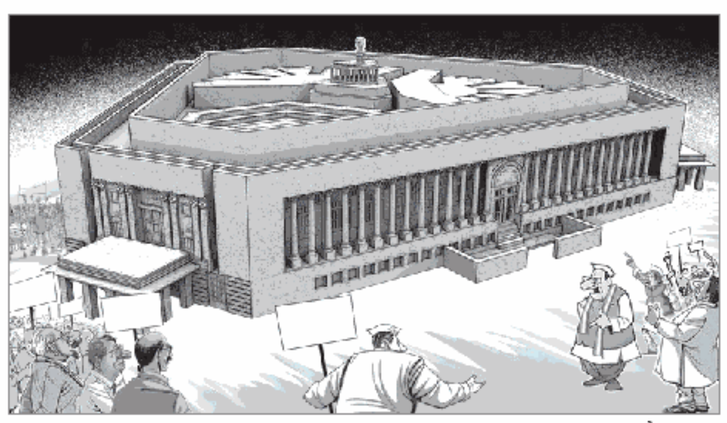

अवधेश राजपूत

जरूरी विधायन के लिए यथाविधि प्रस्ताव लाती है। विपक्ष यथाविधि विरोध करता है। संशोधन प्रस्ताव रखता है। इसी तरह बजट के पारण में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की साझा भूमिका होती है। संसदीय कार्यवाही को उत्कृष्ट बनाना सत्ता पक्ष एवं विपक्ष का साझा कर्तव्य है। दोनों की आत्मीयता से सदन में विचार-विमर्श का परिवेश बनता है। हंगामे का कोई औचित्य नहीं है।

दुनिया के अनेक देशों में संसदीय जनतंत्र सफल हो रहा है। ब्रिटिश संसद में हंगामा नहीं होता। बीबीसी के अनुसार सैकड़ों वर्षों से ब्रिटिश हाउस आफ कामंस को एक मिनट के लिए भी स्थगित नहीं किया गया। कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिकी कांग्रेस, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जापान की डायट और फ्रांस की संसद प्रायः सुचारु रूप से चलती हैं। भारत जैसा हंगामा इन जनप्रतिनिधि संस्थाओं में नहीं होता। शोर और हंगामे से राष्ट्रीय क्षति होती है। दुर्भाग्य से 18वीं लोकसभा की शुरुआत ही स्थगन व्यवधान से हुई है। यहां शपथ ग्रहण के दौरान ही अप्रिय प्रसंग देखने को मिले। कुछ सांसदों ने शपथ में अपनी ओर से अनावश्यक शब्द जोड़े। इससे संवैधानिक शपथ की गरिमा का उल्लंघन हुआ है। तमाम अवरोधों के बावजूद 17वीं लोकसभा की उत्पादकता संतोषजनक रही है, लेकिन शोर शराबा और अप्रिय शब्द प्रयोग के चलते कार्यवाही निराश करती है। मूलभूत प्रश्न है कि शोर और बाधा डालकर क्या हम कार्यपालिका को ज्यादा जवाबदेह बना सकते हैं या तथ्य और साक्ष्य रखते हुए प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। सदन में शालीन और मर्यादित आचरण एवं भाषा का कोई विकल्प नहीं है।

भारत में संसदीय प्रणाली का इतिहास काफी प्राचीन है। वैदिक काल में भी यहां सभा और समितियां थीं। संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान कई धारदार बहस हुई थीं। संविधान सभा की कार्यवाही 165 दिन चली थी। 17 सत्र हुए थे। लोकसभा में भी 1968 तक सदस्य धैर्य से सुनते थे। मर्यादा में बोलते थे। फिर हंगामा आदि कारणों से संसद की कार्यवाही पर ग्रहण लगता गया। संसद का समय घटता गया। सदस्यों की शिकायत रहती है कि सदन की बैठकें कम होती हैं। उन्हें बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। संविधान सभा में प्रो. केटी शाह ने संसद को कम से कम छह माह तक चलाने का प्रस्ताव किया था। अध्यक्ष मावलंकर का विचार भी वर्ष में सात-आठ माह सदन संचालन का था।

ब्रिटिश हाउस आफ कामंस की विशेषाधिकार समिति ने 1939-40 में सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों के पीछे कारण बताया था कि सदस्य संसद में बिना किसी बाधा के अपना कर्तव्य पालन कर सकें। शोर-शराबा और सदन के वेल में जाना विशेषाधिकार नहीं है। विशेषाधिकार जिम्मेदारी बढ़ाते हैं। हाउस आफ कामंस की एक समिति ने 1951 में दिलचस्प टिप्पणी की थी, 'विशेषाधिकारों के कारण सदस्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाते, बल्कि संसद सदस्य होने से अन्य नागरिकों की तुलना में उनके दायित्व और बढ़ जाते हैं।' विशेषाधिकार असामान्य उन्मुक्ति हैं। वे कार्यवाही में मर्यादा पालन में साधक हैं। इन सबके बावजूद कार्यवाही में व्यवधान होते हैं। विशेषाधिकार सहित सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं एवं अधिकार सदन में मर्यादापूर्वक और परिपूर्ण वाक् स्वातंत्र्य के प्रयोग को शक्ति देने के लिए हैं। सदन में अमर्यादित आचरण उचित नहीं। विश्वास है कि 18वीं लोकसभा में जनोपयोगी राष्ट्रीय विमर्श होगा। पक्ष-प्रतिपक्ष साथ मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। सभी सदस्य परस्पर आत्मीयता के परिवेश में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

नए बजट का मजबूत आधार

डा. जयंतीलाल भंडारी

आगामी बजट में सरकार को अटके हुए वित्तीय एवं श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

वित्तीय अनुशासन पर अडिग सरकार ● फाइल

पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट ऐतिहासिक होगा। इसमें आर्थिक तथा सामाजिक मोर्चे पर बड़े एलान किए जाएंगे। इस बजट से सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करेगी। यह नई सरकार की नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज होगा। इसके लिए देश में कई क्षेत्रों में मजबूत आधार तैयार हो गए हैं, जैसे कि विगत में किए गए विभिन्न सुधारों से भारतीय बैंकिंग जगत विश्व के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में शुमार हो गया है। सरकार ने सार्वजनिक हिस्सेदारी वाले बैंकों को मजबूत किया और उनकी गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को कम किया है। गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से इन वर्गों का तेजी से उत्थान हो रहा है। जीएसटी संग्रह औसतन दो लाख करोड़ रुपये मासिक हो गया है। मोदी सरकार ने विनिर्माण, सेवा और कृषि जैसे क्षेत्रों को भी बराबर तवज्जो दी है। पिछले दस वर्षों में सरकार के मंत्र-रिफार्म, परफार्म एंड ट्रांसफार्म ने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। भारत ने 2021 से 2024 के बीच आठ प्रतिशत सालाना की दर से वृद्धि की है। यह दर अब और तेज होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार को अटके पड़े वित्तीय एवं श्रम सुधारों को आगामी बजट में आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, वैश्विक बाजार में भारतीय खाद्यान्नों की मांग बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने तथा रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के विकास पर फोकस करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि गत एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट एक लेखानुदान की तरह था। इसका उद्देश्य नई सरकार बनने तक की व्यय जरूरतों को पूरा करना था। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने लोकलुभावन योजनाओं और रियायतों के रूप में कोई तोहफे नहीं दिए, बल्कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अहम कदम उठाए गए। इसने पूर्ण बजट के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक और वित्तीय आधार तैयार करने का काम किया है। देखा जाए तो देश में पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में तेज वृद्धि हुई है। जहां पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से भी अधिक हुए हैं, वहीं आय की असमानता में भी कमी आई है। देश में कर सुधारों से आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने और आयकर संग्रहण के साथ-साथ जीएसटी में लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले वर्षों में मोदी सरकार वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए राजकोषीय घाटे को बजट लक्ष्य के मुताबिक नियंत्रित रखने में काफी हद तक सफल रही है। ऐसे में आगामी बजट में गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों के कल्याण के लिए नए उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। नए बजट में विनिवेश का लक्ष्य भी बढ़ाया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहनमूलक राहत दी जा सकती है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार पीएलआइ योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे नए क्षेत्रों तक विस्तृत कर सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत दे सकती है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न उत्पादों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए अधिक पूंजीगत व्यय के प्रविधान भी हो सकते हैं।

इन दिनों वेतनभोगी वर्ग का एक बड़ा तबका यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि पिछले बजट में उसे टैक्स संबंधी कोई उपयुक्त राहत नहीं मिली है। इस बीच महंगाई के साथ-साथ उनके जरूरी खर्चे बढ़ गए हैं। इस कारण उन्हें आयकर में राहत की अपेक्षा है। इसे देखते हुए बजट में छोटे आयकरदाताओं को राहत का एलान किया जा सकता है। वेतनभोगी वर्ग को राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों एवं कारोबारियों द्वारा चुकाए गए कुल आयकर से काफी अधिक होता है। वेतनभोगी वर्ग के आयकर की कटौती आमदनी अर्जित करने के स्रोत पर की जाती है। इसे टीडीएस के रूप में जाना जाता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी अपने वेतन पर ईमानदारीपूर्वक आयकर चुकाते हैं और आमदनी को कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश की कुल आबादी के दो प्रतिशत से भी कम लोग ही आयकरदाता हैं। देश में शून्य आयकर देयता वाले आइटी रिटर्न की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नए बजट में आयकर से बचने वाले लोगों की खोज के साथ-साथ नए आयकरदाताओं को खोजने के लिए भी पुख्ता व्यवस्था करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार ने लगातार वित्तीय अनुशासन दिखाया है। ऐसे में आगामी बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में इसे 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य सराहनीय होगा। उम्मीद करें कि आगामी बजट आर्थिक सुधारों, आर्थिक कल्याण और तेज विकास का आधार बनने वाला होगा। साथ ही यह भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने की एक मजबूत बुनियाद तैयार करने का काम करेगा।

(लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अपूर्णता

प्रभु, सबको सब कुछ नहीं देते। जीवन के बहुरंगी उद्यान में कोई न कोई मोहक एवं लुभावना पुष्प अवश्य लुप्त कर देते हैं, जिसको प्राप्त कर अपनी जीवन बगिया को श्रेष्ठ बनाने की महत्वाकांक्षा जीव को परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहती है। कुछ न कुछ गोपनीयता, विशिष्टता, दुर्लभ, अप्राप्य संपत्ति, सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा की कुंजी वह अवश्य स्वयं के पास सुरक्षित रख देते हैं जिसे प्राप्त करने की चाह में मनुष्य आजीवन परिश्रम करने में लगा रहता है। यदि प्रभु सभी को सब कुछ दे दें तो जीव के पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति पंगु हो जाएगी और वह स्वयं को अकर्मण्य एवं कर्महीन मानने लगेगा।

ईश्वर अपने प्रिय भक्त को सतत कर्मशील रख उसके जीवन में कठिन एवं विषम परिस्थितियों के जटिल प्रश्न डाल उसे निष्णात बनाते रहते हैं। इस प्रकार से वह नितांत अपनों को क्षण-क्षण मांजते रहते हैं। आरंभ में यह प्रक्रिया कष्टप्रद लगती है, किंतु अंततः उसे सुख प्रदान करती है। नितांत अपनों की सक्रियता और कर्मठता को बनाए रखने के लिए ही प्रारब्ध और भविष्य के निर्माण की गोपनीयता को सदैव प्रभु गुप्त रखते हैं।

सांसारिक उपलब्धियां शून्य की तरह हैं एवं ईशसत्ता एक अंक की तरह। असंख्य सांसारिक उपलब्धियां हों, लेकिन प्रभुकृपा बिन सब शून्य। इसके बिना जगत के संपूर्ण वैभव अर्थरहित हैं। परमसत्ता की अनुकंपा, दया, दृष्टि के अभाव में असीमित सांसारिक वैभवों के उपरांत भी व्यक्ति अथवा जीव हर पल तड़पता ही रहता है, जबकि उनकी स्नेहछाया में पलने-बढ़ने वाला गरीब भी अत्यंत आनंद में जीवन का पल-पल गर्व से व्यतीत करता है। अतः उसकी कृपा में ही यश, वैभव, बुद्धि, सामर्थ्य, शक्ति एवं जीवन की संपन्नता एवं पूर्णता है। इससे इतर सब कुछ अपूर्णता, अतृप्ति, छलावा और असंतोष मात्र। मनुष्य तब तक अपूर्ण है जब तक वह स्वयं प्रभु और उनके परमानंद के दिव्य रूप, दर्शन एवं अनुकंपा से परिपूर्ण नहीं है।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

प्रतिपक्ष का विरोधाभासी आचरण

'विपक्ष की अनावश्यक आपत्ति' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त के इस प्रश्न का विपक्षी दलों के पास कोई जवाब नहीं है कि 'आखिर कोई दल आपातकाल के स्मरण का विरोध करते हुए यह दावा कैसे कर सकता है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है?' कदाचित इसीलिए आपातकाल के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर सपा जैसे वे विपक्षी दल मौन रहे जिन्होंने 1975 में आपातकाल के पीड़ादायक दंश को झेला था। 2024 के आम चुनाव में संविधान बचाने का शिगूफा छोड़ने वाली कांग्रेस भी यदि आपातकाल के स्मरण प्रस्ताव पर सहयोगी दलों का अनुसरण करते हुए प्रतिपक्ष की मर्यादा का निर्वाह करती तो अच्छा रहता, लेकिन कांग्रेस बीते 50 वर्षों में इस सच्चाई को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाई कि 1975 में स्वयं की संसद सदस्यता बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल देश के संविधान और लोकतंत्र को बंधक बनाने वाला तानाशाही कृत्य था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का धीर-गंभीर दायित्व ग्रहण करने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव का विरोध करना देश को इसलिए अनुचित लगा, क्योंकि उन्होंने संविधान की प्रति को हाथ में लेकर संसद सदस्य की शपथ ग्रहण की थी। संविधान बचाने की शपथ और संविधान कुचलने वाले आपातकाल का समर्थन दोनों विरोधाभासी हैं। प्रतिपक्ष का यह विरोधाभासी आचरण देश देख रहा है। 2024 के आम चुनाव में 99 सीटें जीतकर लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित होने वाली कांग्रेस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

त्वरित न्याय की आशा

संपादकीय आलेख 'नए आपराधिक कानून' में उचित लिखा गया है कि तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के क्रम में आ रही चुनौतियों को पार करके ही त्वरित न्याय की आशा की जा सकती है। तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई, 2024 से लागू हो रहे हैं। तीनों नए कानून वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराध क प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले हैं। इन कानूनों के नाम हैं, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 'जीरो एफआइआर', पुलिस में आनलाइन शिकायत दर्ज कराना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रविधान शामिल होंगे। इन कानूनों के माध्यम से अपराधों से प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र उपलब्ध कराया गया है। बार काउंसिल आफ इंडिया ने कहा है कि नए कानूनों को 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। स्कूली शिक्षा विभाग अक्टूबर से मार्च के बीच कक्षा छह से ऊपर के छात्रों के लिए विशेष माड्यूल बनाएगा।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

सकारात्मक विपक्ष बने कांग्रेस

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख 'विपक्ष की अनावश्यक आक्रमकता' पढ़ा। नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इस बार भाजपा बहुमत से थोड़ी दूर रह गई, लेकिन राजग को पूर्ण बहुमत है। नरेन्द्र मोदी को पहली बार गठबंधन सरकार चलाने का अवसर मिला है, उन्हें मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में लगभग दोगुनी सीट प्राप्त की है, इसलिए उनका उत्साहित होना स्वाभाविक है। पहली बार राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। उत्साह के दौरान कांग्रेस को संवैधानिक गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर अपनी आगे की राजनीति का परिचय दे दिया है। एक ओर राहुल गांधी संविधान बचाने का दिखावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति जता रहे हैं। आपातकाल लोकतंत्र का एक काला अध्याय है, जिसे कभी नहीं भूला जा सकता है। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया था। कांग्रेस के कई सहयोगी दलों को आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपातकाल के दौरान मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद जैसे नेता भी जेल गए थे। कांग्रेस को अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य है। कांग्रेस पार्टी को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए।

ई. हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह सीमित ओवरों के क्रिकेट के सर्वकालिक महानतम गेंदबाज हैं।

माइकल वान@MichaelVaughan

कुछ महीने पहले तक जिन हार्दिक पांड्या की जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही थी, वही अब हीरो हैं। यही जिंदगी है।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

क्रिकेट और जीवन का एक ही फसाना, गुरु के आशीर्वाद से ही जीता जाता है जमाना। गुरु पूर्णिमा से पहले ही टीम इंडिया ने कोच राहुल द्रविड़ को दी- गुरु दक्षिणा।

आनंद महिंद्रा@anandmahindra

पाकिस्तान के विरुद्ध अक्षर पटेल को पहले भेजना, सेमीफाइनल में जडेजा को ऊपर उतारना और फाइनल में दुबे पर यही दांव लगाना, इस विश्व कप में टीम प्रबंधन का ऐसा हर एक फैसला कारगर सिद्ध हुआ।

आकाश चोपड़ा@cricketaakash

राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछो तो वह सवाल पूछने वाले को भाजपा का एजेंट बताने लगते हैं। उन्हें अगर कुछ कह दिया जाए तो कांग्रेस शासित राज्य की पुलिस आपको पकड़ने आ जाएगी और हैरानी इस बात की है कि वह पीएम मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं।

अशोक श्रीवास्तव @AshokShrivasta6

जनपथ

विश्वविजेता फिर बने दिखा गजब का खेल,
खेले बनकर चैम्पियन रहा न जिसका मेल।
रहा न जिसका मेल विजय जा छीनी मुख से,
झर झर झर झर अश्रु बहे तब अपार सुख से।
दिखता सारा देश बधाई सबको देता,
बने पुन : इक बार क्रिकेट के विश्वविजेता!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 80

****

सोच-समझकर जोखिम उठाएं। यह जल्दबाजी करने से बिल्कुल अलग है। -जॉर्ज एस. पैटन

संयुक्त राष्ट्र की ताजा एसडीजी रिपोर्ट को एक चेतावनी की तरह लिया जाना चाहिए, जो सावधान करती है कि सात अरब लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए तय किए गए वैश्विक लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। जरूरी है कि सभी देश इन लक्ष्यों की गंभीरता को समझें और तदनुरूप प्रयासों का पुनर्मूल्यांकन भी करें।

इसे चेतावनी मानें

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट को एक चेतावनी के तौर पर लिया जाना चाहिए कि जो सावधान करती है कि बेहतर दुनिया की उम्मीद में तय किए गए सतत विकास लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा जारी रिपोर्ट साफ कहती है कि दुनिया के सात अरब से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए 169 लक्ष्यों में से केवल 17 फीसदी लक्ष्य ही 2030 तक पूरे होने की संभावना है, बाकी 83 फीसदी लक्ष्यों पर प्रगति या तो रुकी हुई है या स्थिति पहले से भी खराब हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के प्रारूप को स्वीकारा गया था, जिनके तहत निर्धारित लक्ष्यों को 2015 तक पूरा किया जाना था। लेकिन जब निर्धारित अवधि में ये लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, तब 2015 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की सत्रहवीं बैठक में सदस्य देशों द्वारा सत्रह सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्हें फिर 169 लक्ष्यों में बांटा गया और इनके लिए 2030 की समय-सीमा भी तय की गई, जो एक बार फिर कम पड़ती दिख रही है। ताजा रिपोर्ट का यह कहना कि कोरोना के चलते 2019 की तुलना में 2022 में गरीबी और भुखमरी की चपेट में आए लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, साथ ही, ऊर्जा व शिक्षा संबंधी लक्ष्यों में भी हम काफी पीछे हैं, दर्शाता है कि शांति, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय वित्त सहित गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में दुनिया की विफलता, विकास को कमजोर कर रही है और भावी पीढ़ियों के लिए इन लक्ष्यों को पाना और भी मुश्किल बना रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के एक दिन बाद जारी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि चुनौतियां अब भी बेशक बड़ी हैं, पर भारत कई संकेतकों पर अच्छा काम कर रहा है। नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा 2015 के 25 से 2020 में 20 प्रति हजार पहुंच गया है, तो पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों (12-23 महीने की उम्र के बीच) की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 76.6 प्रतिशत हो गई है। उच्चतर माध्यमिक में प्रवेश करने वाले बच्चों का अनुपात भी बढ़ा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में एसडीजी दुनिया के सामने मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का एक समावेशी प्रयास है, जिनमें नाकामी चिंताजनक है। ऐसे में, एक समृद्ध, सुरक्षित व न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए जरूरी है कि सभी देश इन लक्ष्यों की गंभीरता को समझते हुए अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें।

इस दांव में जोखिम बहुत है

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पहली प्रेसिडेंशियल बहस में जो बाइडन याद की गई पंक्तियां और आंकड़े भूल रहे थे। यह दिल दहलाने वाला है, क्योंकि वह परमाणु कोड भी नियंत्रित करते हैं। भले ही उनके सहयोगी रक्षात्मक दीवार और ऊंची कर दें, लेकिन उन्हें समझना होगा कि इस दांव में जोखिम बहुत है।

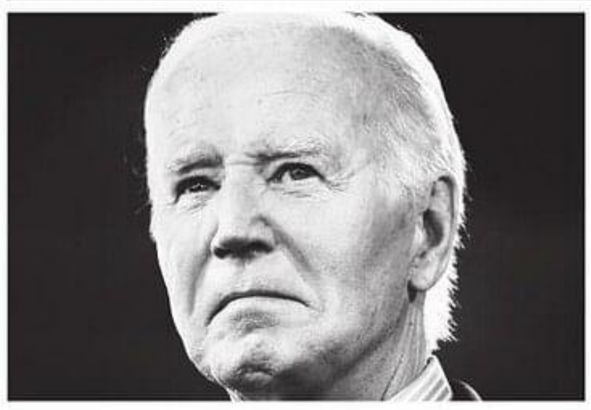

वह स्वार्थी हो रहे हैं। वह खुद को देश के आगे रख रहे हैं। वह अवसरवादी समर्थकों से घिरे हैं। वह वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जहां हमें कहा जाता है कि जो साफ दिख रहा है, उस पर भरोसा न करें। उनका अभिमान क्रोधित करने वाला है। वह कहते हैं कि वह यह सब हमारे लिए करते हैं, जबकि वास्तव में अपने लिए कर रहे हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि दूसरे राष्ट्रपति की बात कर रही हूं। वाशिंगटन में लोग अक्सर वही बन जाते हैं, जिसकी वे शुरुआत में निंदा करते हैं। ठीक यही बाइडन के साथ हुआ। दूसरे कार्यकाल की गुमराह खोज (जिसके अंत में वह 86 वर्ष के हो जाएंगे) में वह ट्रंप के जैसा ही व्यवहार करने लगे हैं। और वह उसी लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, जिसे बचाने का दावा करते आए हैं। बाइडन से मेरा पहला परिचय 1987 में हुआ, जब वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के अग्रणी नेता के रूप में सराहा जाता था। मैंने उन्हें उस दौड़ से बाहर कर दिया, जब मैंने लिखा कि किस तरह वह नील किन्नॉक की नकल करते हैं, जो ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता और एक प्रखर वक्ता थे और किस तरह उन्होंने शायद अनजाने में ही रॉबर्ट एफ. कैनेडी (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई) और अमेरिका के अड़तीसवें उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री की बातों का अपने भाषण में उपयोग किया। मुझे याद है कि मैं बाइडन से सीनेट की सीढ़ियों पर मिली थी, जब वह भाषण देने के लिए जा रहे थे। वह अकेले थे और अपने भाषण की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उस पल के बोझ से दबे हमने खामोशी से एक-दूसरे को देखा और अलग-अलग रास्तों से एक ही न्यूज कॉन्फ्रेंस में पहुंचे।

मौरीन दाउद
द न्यूयॉर्क टाइम्स

बाइडन काफी उत्साही व्यक्ति थे, जिन्हें शुरुआत से ही यह बताया गया कि उन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए, क्योंकि वह महज 29 वर्ष की उम्र में ही सीनेट चुने गए थे। ऐसे में, भाषण चोरी के आरोप और स्वास्थ्य समस्याओं के बाधा बनने का कोई सवाल ही नहीं था। 1998 में उन्हें दो बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं और बाद में उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि अगर वह चुनाव प्रचार जारी रखते हैं, तो जीवित नहीं बचेंगे। उन्होंने मुझसे मजाक में कहा था कि मैंने उनकी जान बचाई। उन्होंने अन्य समस्याओं को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं हैरान तो थी, पर खुश भी कि बाइडन ने मुझे माफ कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेहतर होगा कि हम अच्छे संबंध बनाए रखें। मैं घृणित सुनवाइयों के दौरान सीनेट न्यायिक समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके काम की आलोचक रही हूं। लेकिन उन्होंने मुझसे नाता नहीं तोड़ा। जब वह उपराष्ट्रपति बने, तो कई अवसरों पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। ओबामा के सहयोगी, पत्रकारों के सामने बाइडन की बुराई करते थे।

बाइडन एक अच्छे और वफादार उपराष्ट्रपति थे और मुझे लगता है कि यह ओबामा की गलती थी कि उन्होंने 2016 में उनके बजाय हिलेरी को प्राथमिकता दी। हिलेरी एक अभिजात्य एवं यथास्थितिवादी उम्मीदवार थीं, और मतदाता अभिजात्य एवं यथास्थितिवाद के खिलाफ थे।

ओबामा की टीम ने इस विचार को प्रसारित किया कि ब्यू (बाइडन के पुत्र) की मौत से बाइडन इतने दुखी थे कि उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन बाइडन अकेले ऐसे व्यक्ति थे, जो अपने दुख का इस्तेमाल अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में सहानुभूति जुटाने के लिए कर सकते थे। अगर उस समय बाइडन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता, तो वह जीत जाते और अब अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करते हुए स्वर्णिम सेवानिवृत्ति के लिए तैयार होते।

इसके बजाय उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत बहुत देर से शुरू की। पिछले कुछ वर्षों से उनका प्रदर्शन स्पष्ट रूप से गिरता जा रहा है, जो लगातार अस्थिर होती दुनिया में खतरनाक बात है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश में क्रांति ला रही है और धार्मिक कट्टरपंथियों से भरा सुप्रीम कोर्ट अमेरिकियों के जीवन को बदल रहा है। यही वजह है कि लगभग दो साल पहले एक कॉलम में मैंने बाइडन को सुझाव दिया था कि आप अपने अच्छे कामों के लिए जीत हासिल करें और पार्टी के युवा सितारों को मौका दें।

लेकिन वह यह साबित करना चाहते थे कि वह उस व्यक्ति से बेहतर राष्ट्रपति हो सकते हैं, जिसने उन्हें किनारे कर दिया था। उनकी पत्नी जिल बाइडन अपने पति को जरूरत से ज्यादा प्रेरित कर रही हैं और उन्हें बचा रही हैं। बृहस्पतिवार की बहस में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद उन्होंने बाइडन को प्रोत्साहित करते हुए कहा-'आपने बहुत अच्छा बोला! आपने हर सवाल का जवाब दिया! आप सब कुछ जानते हैं!' यह उस व्यक्ति से कहा गया, जो परमाणु कोड को नियंत्रित करता है।

सीएनएन के वैन जोन्स ने कहा कि एक अश्वेत नेता ने उन्हें फोन कर इस घटना का सही आकलन करने के लिए खरी-खोटी सुनाई। इस बहस को 'आपदा' बताने वाले डेमोक्रेटिक रणनीतिकार पॉल बेगाला ने सीएनएन पर कहा कि 'जो भी डेमोक्रेटिक नेता बाइडन को पहले पद छोड़ने के लिए कहेगा, उसका कॅरिअर खत्म हो जाएगा। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडन एक प्रिय व्यक्ति हैं।'

बहस के वक्त वह याद की गई पंक्तियां और आंकड़े भूल रहे थे। वह उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो केवल एक ही दिशा में जाती हैं। यह दिल दहलाने वाला है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हैं और बच्चों की तरह हकला रहे हैं। भले ही उनकी पत्नी और उनके कर्मचारी रक्षात्मक दीवार को और ऊंची कर देंगे और पत्रकारों को भगा देंगे, लेकिन बाइडन, जिल और डेमोक्रेटिक नेताओं को इस तथ्य का सामना करना पड़ेगा कि इस दांव में असाधारण जोखिम है। दांव पर लोकतंत्र है। जेम्स कॉर्विल, जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि राष्ट्रपति को दूसरे कार्यकाल को त्याग देना चाहिए, ने कहा कि बाइडन को चार जुलाई को अपने भाषण में घोषणा कर देनी चाहिए कि वह डेमोक्रेटिक नेताओं की अगली पीढ़ी को मौका देना चाहेंगे। 79 वर्षीय रणनीतिकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'आप उम्र के साथ रेस नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि मैं उम्र को हराने के लिए हर संभव कोशिश करता हूं, पर कोई फायदा नहीं है।'

लेकिन बाइडन और जिल अगर टिके रहे, तो क्या होगा? इस प्रश्न के जवाब में कॉर्विल ने पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर्ड के अधीन काम कर चुके शीर्ष अर्थशास्त्री हर्ब स्टेन के उद्धरण को दोहराया-'जो जारी नहीं रह सकता, वह जारी नहीं रहेगा।'

©The New York Times 2024

वेंकैया गारू : भारत की सेवा में समर्पित जीवन

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है। वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की यात्रा है। अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, उन्होंने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी विनम्रता से पार किया, वह अपने आपमें एक उदाहरण है। उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम कभी नहीं बदला।

वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और जनसंघ एवं भाजपा को मजबूत किया। लगभग 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए। 1980 के दशक के मध्य में, जब एनटीआर सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था, तब वह फिर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे।

वेंकैया नायडू आज 75 वर्ष के हो गए हैं। राजनीति में अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, उन्होंने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी विनम्रता से पार किया, वह अपने आपमें एक मिसाल है।

वर्ष 1978 में आंध्र प्रदेश ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद भी वह भाजपा विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में भाजपा के लिए भविष्य के बीज बोए थे। उनसे प्रभावित होकर एनटीआर जैसे दिग्गज उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, पर वह अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी बने।

1990 के दशक में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुए उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे, तो अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय को चुना। एक मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी।

2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। वह एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। जब संसदीय मानदंडों और नियमों की बात होती थी, तब वह नियमों को लेकर भी उतना ही स्पष्ट नजर आते थे। वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा, महिला और पहली बार चुने गए सांसदों को बोलने का मौका मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर दिया, समितियों को अधिक प्रभावी बनाया और बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया।

जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। वह युवा, जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' के संकल्प के लिए जीवन समर्पित किया था, जब वह सपना पूरा हुआ, तो वह सभापति के पद पर आसीन था।

काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं, जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं।

दूसरा पहलू

अफ्रीका की सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में भोजन, ईंधन और दवा की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।

गरीब मरीजों को साग-पात अमीरों को हड्डियों का शोरबा

अफ्रीका की सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में भोजन, ईंधन और दवा की कीमत सातवें आसमान पर है। दो साल पहले तक अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा नाइजीरिया आज चौथे स्थान पर खिसक गया है। स्थिति यह है कि मुफ्त का चावल लेने के चक्कर में अनेक नाइजीरियाई भगदड़ में मारे जा चुके हैं। कैल्शियम के अभाव में शरीर ऐंठ जाने की बीमारी वाली महिला मरीजों से देश के तमाम अस्पताल भरे पड़े हैं। नाइजीरिया की इस बदतर स्थिति के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो करीब पंद्रह महीने पहले चुने गए राष्ट्रपति ने ईंधन की सब्सिडी खत्म कर दी है। इसके अलावा, मुद्रा के अवमूल्यन से भी स्थिति खराब हो गई है।

रुथ मैक्लीन

पोषण के अभाव में बीमार महिलाओं से नाइजीरिया के अस्पताल भरे पड़े हैं। डॉक्टर महिलाओं को उनकी आर्थिक हैसियत के मुताबिक पोषण लेने के लिए कह रहे हैं।

नाइजीरिया की इस बदतर स्थिति के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो करीब पंद्रह महीने पहले चुने गए राष्ट्रपति ने ईंधन की सब्सिडी खत्म कर दी है। इसके अलावा मुद्रा के अवमूल्यन से भी स्थिति खराब हो गई है।

नाइजीरिया के लोगों को उद्यमिता में महारत हासिल है। वे बिजली के उत्पादन से लेकर पानी के इंतजाम तक का काम खुद करते हैं, और सरकार पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। जब जरूरत पड़ती है, वे हथियार लेकर अपने देश की रक्षा में जुट जाते हैं, और इस काम में अपने सुरक्षा बलों को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन बदतर आर्थिक स्थिति के कारण फिलहाल वे कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। पोषण के अभाव में बीमार महिलाओं से नाइजीरिया के अस्पताल भरे पड़े हैं। उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि डॉक्टर महिलाओं को उनकी आर्थिक हैसियत के मुताबिक पोषण लेने के लिए कह रहे हैं। जैसे, गरीब महिलाओं को टाइगर नट्स जैसी वनस्पति का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है, तो अपेक्षाकृत समृद्ध स्त्रियों को हड्डियों का शोरबा पीने के लिए कहा जा रहा है। देश में दूध की इतनी कमी है कि बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी यह सुलभ नहीं है।

नाइजीरिया में 8.7 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। लेकिन विश्व बैंक का मानना है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से नाइजीरिया में गरीबों की संख्या में और वृद्धि होगी। इस महीने की शुरुआत में यूनियनों ने निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए अस्पतालों, बैंकों, स्कूलों और अदालतों में ताला लगाने के साथ-साथ संसद और हवाई अड्डों तक को बंद कर दिया था। हालांकि वास्तविकता यह है कि नाइजीरिया के 92 फीसदी लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, और उनके समर्थन में कोई यूनियन नहीं है। लोगों को इतना कम पैसा मिलता है कि परिवार चलाने के लिए अनेक लोग एक से अधिक काम करने के लिए मजबूर हैं। *-साथ में, इस्माइल ओउवॉल।*

©The New York Times 2024

आंकड़े

शीर्ष दूरसंचार सेवा प्रदाता

भारतीय दूरसंचार में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के मामले में इन पांच शीर्ष सेवा प्रदाता कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 98.35 फीसदी है।

आंकड़े करोड़ में, फरवरी, 2024 तक के | स्रोत : TRAI

ऋषि शृंग की सलाह पर यज्ञ कराने से अंगदेश में वर्षा हुई, जिससे खुश होकर राजा रोमपद ने शांता का विवाह ऋषि से करा दिया।

शांता का विवाह

अंतर्यात्रा
संकलित

माता कौशल्या की बेटी शांता बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। एक बार महारानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी उनसे मिलने आई थी। वर्षिणी का विवाह अंगदेश के राजा रोमपद के साथ हुआ था, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिणी ने शांता की शालीनता से मोहित होकर कहा, 'मेरी कोई भी संतान नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि शांता जैसी ही मेरी भी एक पुत्री हो।'

वर्षिणी की इस बात पर राजा दशरथ ने उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंगदेश के राजा रोमपद की पुत्री बन गई। एक दिन राजा रोमपद किसी काम में इतना खोए थे कि उन्हें चौखट पर आए एक ब्राह्मण की आवाज सुनाई ही नहीं दी। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटना पड़ा।

देवराज इंद्र को ब्राह्मण का यह अपमान ठीक नहीं लगा। उन्होंने अंगदेश में वर्षा न करने का निश्चय कर लिया। ऐसे में, बिना वर्षा के अंगदेश में सूखा पड़ गया और अकाल की स्थिति पैदा हो गई। राजा रोमपद ऋषि शृंग के पास उपाय पूछने गए। ऋषि ने राजा को यज्ञ कराने की सलाह दी, ताकि रूठे इंद्र देव को मनाया जा सके। राजा रोमपद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद अंगदेश में पुनः वर्षा हुई। ऋषि शृंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने उनसे शांता का विवाह करा दिया। उसी ऋषि शृंग ने राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कामाक्षी यज्ञ कराने की सलाह दी थी।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 1 अक्तूबर, 1990

पाक सीमा पार कर कुवैत से 265 शरणार्थी अमृतसर पहुंचे

पिछले दो दिनों में भारत-पाक सीमा पर बाघा सीमा चौकी पार कर कम से कम 265 कुवैती शरणार्थी अमृतसर पहुंच चुके हैं। भारतीय शरणार्थियों का यह पहला जत्था कारों से यहां पहुंचा है। इससे पहले 200 बांग्लादेशी नागरिक यहां पहुंचे थे।

चांदी हो रही सोना

सोने की बढ़ती कीमतों से चांदी की मांग तो बढ़ी ही है, इलेक्ट्रिक वाहन व सोलर पैनल इत्यादि को बढ़ावा दिए जाने से भी इसकी मांग बढ़ रही है।

ऋषभ मिश्रा | **धातु**

बीते कुछ महीनों में गर्मी की तरह ही चांदी ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह 92,873 हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई और भारत में ऑलटाइम हाई का रिकॉर्ड बना दिया। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में बुलियन बाजार में चांदी की इसी तरह से चांदी चलती रहेगी। वैसे बीते चार दशकों के दौरान इसके दाम 26 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं।

गौरतलब है कि उद्योगों-खासकर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों, सोलर पावर के सोलर पैनल्स और 5-जी टेक्नोलॉजी में चांदी की खपत ज्यादा हो रही है। इससे चांदी की सालाना मांग में सात से आठ फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इस तरह मांग बढ़ने से इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। मांग की तुलना में चांदी की खनन गतिविधियां लगभग स्थिर हैं, बल्कि इसमें आंशिक गिरावट भी आई है। 2015 में जहां चांदी का वैश्विक खनन 89.7 करोड़ आउंस (एक आउंस यानी 28.34 ग्राम के बराबर) हुआ था। वहीं, 2023 में यह गिरकर 82.4 करोड़ आउंस रह गया। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब कई लोग, खासकर माध्यम वर्ग आभूषणों के लिए चांदी की तरफ देख रहे हैं। वस्तुतः पिछले दो दशक में उद्योगों और प्रौद्योगिकी में चांदी की उपयोगिता बढ़ी है।

'इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी' की हालिया रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक साल में सोलर पावर में इस्तेमाल होने वाले फोटोवोल्टेइक पैनल्स में निवेश एक साल पहले की तुलना में दोगुना होकर 80 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फोटोवोल्टेइक पैनल्स में चांदी का काफी इस्तेमाल होता है। साल 2024 में ही चांदी की वैश्विक मांग में 1.2 अरब आउंस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लिहाजा, चांदी की कीमतों के भी लगातार ऊंचे होते चले जाने की संभावना है। दरअसल, चांदी दुनिया की सबसे बढ़िया सुचालक धातु है। इसलिए सोलर पैनल्स पर चांदी का पेस्ट किया जाता है। जब सूरज का प्रकाश उसके पैनल्स पर गिरता (स्ट्राइक) है, तब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और चांदी विद्युत को तुरंत गतिशील कर देती है।

आज भी सिनेमा को सिल्वर स्क्रीन कहकर संबोधित किया जाता है। दरअसल सिनेमा की शुरुआत में फिल्में प्रोजेक्टर के जरिये दिखाई जाती थीं। इसके लिए जिस परदे पर तस्वीर प्रोजेक्ट की जानी होती थी, उसका चमकदार होना जरूरी था, ताकि परावर्तन (रिफ्लेक्शन) बढ़ने से तस्वीरों की गुणवत्ता बढ़ सके। परदे को ज्यादा चमकदार बनाने के लिए तब स्क्रीन को 'मैटेलिक सिल्वर' से 'कोट' किया जाता था। उसी से यह शब्द उत्पन्न हुआ और आज भी अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है।

दरअसल, चांदी सबसे ज्यादा सूर्य की किरणों को परावर्तित करने वाली धातु है। भारत में चांदी का 50.7 प्रतिशत इस्तेमाल उद्योगों में, 17.8 प्रतिशत आभूषणों में, 24.5 प्रतिशत कॉइन्स-बार्स निवेश में, 2.8 प्रतिशत फोटोग्राफी में और 4.2 प्रतिशत चांदी के बर्तनों में उपयोग किया जाता है।

चार मई, 1989 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह की सतह की 'मैपिंग' के लिए 'मैगलेन' स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था। चूंकि चांदी में प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसके मद्देनजर इसे घातक सौर विकिरण से बचाने के लिए इस पर 'सिल्वर कोटेड क्वार्टर्स टाइल्स' लगाई गई थीं। इसके बाद से सभी स्पेस क्राफ्ट के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाने लगी है। इससे स्पेस क्राफ्ट के तापमान को कम करने में मदद मिलती है। दुनिया में छोटी-बड़ी मिलाकर कुल 757 सक्रिय चांदी की खदानें हैं। इनमें से भारत में केवल छह हैं।

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, चांदी के उत्पादन में सबसे ऊपर मेक्सिको है, जो कि 6,400 टन चांदी का उत्पादन करता है, जो कुल वैश्विक चांदी उत्पादन का 21 फीसदी है। इसके बाद क्रमशः चीन, पेरू, चिली और फिर पोलैंड का स्थान आता है। चीन चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यह कुल उत्पादित चांदी का 18 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल करता है। तो वहीं 'इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा 43 टन चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है। इसके बाद 11 टन आंध्र प्रदेश, छह टन तेलंगाना, पांच टन हरियाणा और चार टन का उत्पादन झारखंड करता है।

edit@amarujala.com

कल्पमेधा

क्रोध करने का मतलब है, दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो।

– कन्फ्यूशियस

हौसले की जीत

कहते हैं कि हौसला और सब्र कायम रहे तो हारी हुई बाजी को भी जीत में तब्दील किया जा सकता है। बारबाडोस में टी-20 क्रिकेट विश्वकप के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर जो जीत दर्ज की, वह मौजूदा क्रिकेट की दुनिया की एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, मगर इस खिताब को हासिल करने के क्रम में मैदान में जिस तरह का रोमांच पैदा हुआ, उसने भारत के लिए इस जीत को बेहद अहम और यादगार बना दिया। दरअसल, मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने अपने दमखम के जरिए एक दूसरे पर हावी होने की हर स्तर पर कोशिश की। कभी दक्षिण अफ्रीका की टीम भारी पड़ती दिखी तो कभी भारत की टीम जीत के करीब दिखी। अपनी पारी में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के सामने एक मजबूत चुनौती रखी थी। हालांकि अतीत में दक्षिण अफ्रीका की टीम के प्रदर्शन को देखते हुए इस लक्ष्य को बहुत मुश्किल काम नहीं माना जा रहा था और एक समय वह जीत के बेहद करीब पहुंच भी गई थी, मगर अंतिम पांच ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने बाजी पलट दी।

यों बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण तक के मामले में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन किया, लेकिन मैच के आखिरी दौर में भारत ने मैदान में गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर पूरा जोर लगा दिया और एक तरह से हाथ से छूटती बाजी को दक्षिण अफ्रीका से आखिरकार छीन लिया। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बीस ओवरों के मैच में पंद्रह ओवर तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने जैसी पकड़ बना रखी थी, उसमें उसे रोक पाना एक मुश्किल चुनौती थी। मगर यह कहा जा सकता है कि इस मैच के आखिरी ओवरों में भारतीय खिलाड़ियों ने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के मामले में जैसा प्रदर्शन किया, उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदों से एक ओर विपक्षी टीम के हाथ बांध दिए, दूसरी ओर उनके मजबूत खिलाड़ियों को मैदान बाहर भी भेज दिया। इसमें हार्दिक की गेंद पर मिलर के छक्का मारने की कोशिश को सीमा रेखा पर सूर्यकुमार यादव ने जिस तरह शानदार और यादगार कैच पकड़ कर रोका, उसने मैच की बाजी पलट दी।

गौरतलब है कि टी-20 में यह दूसरा मौका है, जब भारत ने खिताबी जीत हासिल की है और जाहिर है इसके साथ ही एक तरह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय दावेदारी एक बार फिर पुष्ट हुई है। मगर इस मैच के साथ ही टी-20 के इस प्रारूप में भारत के मजबूत स्तंभों- विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब ये तीनों खिलाड़ी इसके अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में मैदान में नहीं दिखेंगे, मगर उनसे प्रेरणा हासिल कर एक नई पीढ़ी विश्व क्रिकेट के इस मोर्चे पर उतरेगी। विराट कोहली ने अपने संन्यास की घोषणा के मौके पर कहा भी कि अब समय आ गया है कि अगली पीढ़ी टी-20 मैचों में भारत को आगे ले जाएं। बहरहाल, इस खिताबी जीत के साथ भारत ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वह आज भी क्रिकेट की दुनिया में बादशाहत का रुतबा रखता है और मैच में रोमांच और उत्तेजना बनाए रखते हुए जीत को अपने हिस्से कर सकता है।

बहस में बाइडेन

अमेरिका में इसी वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और मैदान में मुख्य रूप से दो उम्मीदवार हैं- मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसके लिए चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी है और अलग-अलग चरणों में प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। गुरुवार को अमेरिका में बाइडेन और ट्रंप के बीच इस चुनाव की पहली बहस हुई, जिसमें सवाल-जवाब के दौरान दोनों उम्मीदवारों की कोशिश एक दूसरे पर हावी होने की रही, मगर इसमें बाइडेन की प्रस्तुति जैसी रही, उसके मुताबिक माना जा रहा है कि उनके लिए आगे की लड़ाई थोड़ी मुश्किल साबित होने वाली है। हालांकि सितंबर में अगली बहस होगी, मगर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उस समय हालात में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा।

दरअसल, बहस में उठे कई मुद्दों पर राय जाहिर करने के क्रम में बाइडेन के भीतर जिस तरह की अस्पष्टता और कमियां देखी गईं, उसके मद्देनजर अब उनके भविष्य को लेकर चिंता जताई जाने लगी है। खुद बाइडेन का खेमा अब शायद इन चुनावों में उनकी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। मसलन, कई सवालों के जवाब में ट्रंप ने जहां सबका ध्यान खुद पर केंद्रित रखा, मुद्दों पर स्पष्ट रहे, वहीं बाइडेन एक तरह से बहस में चूक गए। कई बातों का जवाब देते हुए बाइडेन अटक रहे थे और काफी अस्पष्ट तरीके से बोल रहे थे। काफी समय तक उनकी जबान फिसलती रही। कई सवालों का उन्होंने जो जवाब दिया, उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आया। उनके लिए अभियान चलाने वाले समूह को यह सफाई देनी पड़ी कि वे सर्दी से जूझ रहे हैं।

दूसरी ओर, कई तरह के आरोपों से घिरे होने के बावजूद ट्रंप ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। यह बेवजह नहीं है कि राष्ट्रपति पद के लिए हुई पहली बहस के बाद बाइडेन के खेमे में एक तरह की आशंका पैदा हो गई है और अब उनके विकल्पों पर भी बात होने लगी है। संभव है कि इक्यासी वर्ष की उम्र में बाइडेन स्वास्थ्य संबंधी या अन्य किसी बाधा से गुजर रहे हों। मगर अमेरिका का नेतृत्व करने के लिए जिन कसौटियों पर खरा उतरना जरूरी है, उन पर अगर बाइडेन कमजोर दिखने लगे हैं तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वे खुद ही देश के शीर्ष पद की दौड़ से बाहर हो जाएं!

पिघलते हिमनद, बढ़ती मुसीबत

इस वर्ष मई के अंतिम दिनों में उत्तराखंड के पांच जिलों के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसके बुझने के बाद हिमालय के हिमखंडों पर अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखने में आए हैं।

प्रमोद भार्गव

इस बार बढ़ते तापमान और जंगल में आग के चलते उत्तराखंड की नदियां उफान पर हैं। अमूमन ये नदियां मानसून में उफनती हैं, लेकिन इनमें पहली बार मई-जून माह में उफान देखा गया है। बदरीनाथ धाम के आगे अल्कापुरी हिमखंड से निकलने वाली अलकनंदा नदी में पांच दिन में दो से तीन फुट पानी बढ़ गया। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर असमय 150 घनमीटर प्रति सेकंड बढ़ता हुआ दर्ज किया गया है। इसी तरह कुमांऊ मंडल के कालापानी हिमखंड से निकली काली नदी, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी में भी पानी बढ़ा है। सभी नदियों का पानी मटमैला दिखाई दिया। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि इस बार लंबे समय तक निरंतर गर्मी बनी रही, इसलिए ये हालात उत्पन्न हुए हैं। इन संकेतों से स्पष्ट है कि इस बार की गर्मी और जंगल की आग ने हिमालय के इन चारों हिमखंडों की सेहत बिगाड़ दी है।

इस वर्ष मई के अंतिम दिनों में उत्तराखंड के पांच जिलों के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसके बुझने के बाद हिमालय के हिमखंडों पर अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखने में आए हैं। वाडिया भू-विज्ञान संस्थान की ताजा रपट के मुताबिक आग से हिमखंडों पर कार्बन की मात्रा सामान्य से ढाई गुना बढ़कर 1899 नैनोग्राम ज्यादा हो गई है। औसत से कम हिमपात और अब आग के कारण वायु प्रदूषण से हिमखंड काले कार्बन की चपेट में आ गए हैं। कार्बन के कण गरम होते हैं, जो हिमखंड की ऊपरी परत पर चिपक कर उसके पिघलने की गति बढ़ा देते हैं। ये सूर्य की किरणों को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। नतीजतन, हिमखंड की ऊपरी परत गरम होकर पिघलने लगती है। इस बार उत्तराखंड के सात जिलों में बाईस दिन आग लगी रही। इससे 1450 हेक्टेयर जंगल साफ हो गया। 'यूसेफ' की रपट के मुताबिक बीते 37 वर्षों में जंगल की आग और कार्बन कणों के चलते हिमालयी बर्फ से ढंके रहने वाले क्षेत्र 26 वर्ग किमी घट चुके हैं। 'नंदादेवी बायोस्फियर रिर्जव' के ऋषिगंगा जलभराव क्षेत्र का कुल 243 वर्ग किमी क्षेत्र बर्फ से ढंका रहता था, जो अब 215 वर्ग किमी रह गया है। उत्तराखंड राज्य वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीस वर्ष में 44554 हेक्टेयर वन आग की भेंट चढ़ चुके हैं। तापमान में अगर एक डिग्री का मामूली बदलाव भी होता है तो हिमखंडों के साथ बर्फ के आवरण वाले क्षेत्र में बड़ी कमी दर्ज की जाती है।

इन्हीं कारणों और वैश्विक बढ़ते तापमान के चलते हिमखंडों वाली झीलों पर खतरा बढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी से ये झीलें लगातार पिघल रही हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल की 28043 हिमखंड झीलों में से 188 झीलें कभी भी तबाही का कारण बन सकती हैं। ऐसा हुआ तो तीन करोड़ की आबादी पर संकट गहरा जाएगा। गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग और हिमालय पर्यावरण विशेषज्ञ दलों द्वारा एक वर्ष तक किए अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण 1.5 डिग्री पारा बढ़ने से हिमालय क्षेत्र

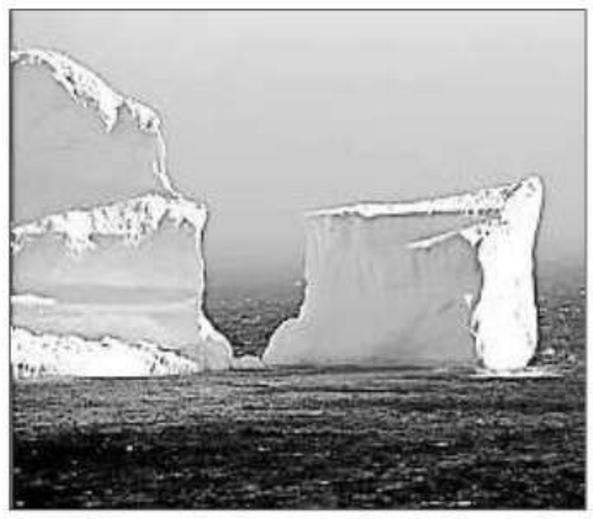

में हिमखंड पिघलने की रफ्तार 1.5 फीसद तक बढ़ जाती है। भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदा में हिमखंड झीलों के फटने से बड़ी मात्रा में पानी का बहाव बढ़ जाता है। ऐसी गंभीर अवस्था वाली 188 झीलें आपदा प्रबंधन द्वारा चिह्नित की गई हैं। अगर हिमालयी राज्यों में सात रिक्टर का

> हिमालय के बर्फ से आच्छादित हिमखंडों से ही ज्यादातर नदियां निकलकर समतल धरती पर बहकर जीवनदायिनी बनी हुई हैं। इसलिए यहां की बर्फ का निरंतर पिघलना नदियों के प्रवाह के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। इस समय जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया के महाद्वीप और समुद्र भी बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं। इसलिए हिमखंडों का पिघलना बड़े खतरे का संकेत है। इससे तत्काल नदियों और समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा ही, इससे उत्तरी गोलार्ध पर भी असर पड़ेगा, जहां बड़ी आबादी निवास करती है।

भूकम्प आता है, तो अत्यधिक संवेदनशील 188 हिमखंड की झीलें टाइम बम की तरह फूट पड़ेंगी। पानी के बेहताशा प्रवाह से बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है।

हिमालय के बर्फ से आच्छादित हिमखंडों से ही ज्यादातर नदियां निकलकर समतल धरती पर बहकर जीवनदायिनी बनी हुई हैं। इसलिए यहां की बर्फ का निरंतर पिघलना नदियों के प्रवाह के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। इस समय जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया के महाद्वीप और समुद्र भी बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं। इसलिए हिमखंडों का पिघलना बड़े खतरे का संकेत है। इससे तत्काल नदियों और समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा ही, इससे उत्तरी गोलार्ध पर भी असर पड़ेगा, जहां बड़ी आबादी निवास करती है। ये पिघलती बर्फ की चादरें वायुमंडलीय परिसंचरण को भी बदल देती हैं, जो भूमध्य रेखा और उससे आगे अमेजन और अफ्रीका तट के बदलते मौसम को प्रभावित कर सकती है।

विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) के अनुसार बीते वर्ष और पिछले दशक में धरती पर तेजी से गर्मी बढ़ी है। अमेरिका की पर्यावरण संस्था वैश्विक विटनेस और कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि तेल और गैस के अधिकतम मात्रा में उत्पादन से ये हालात बने हैं। अगर इन ईंधनों के उत्सर्जन का यही हाल रहा तो 2050 तक गर्मी अपने चरम पर होगी। इस गर्मी से जीव-जगत की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार धरती पर प्रलय बाढ़ से नहीं, आसमान से बरसने वाली आग से आएगी। इसके संकेत प्रकृति लगातार दे रही है। इस संकट से निपटने के उपायों को तलाशने के लिए 198 देश जलवायु सम्मेलन करते हैं। इन सम्मेलनों का एक ही प्रमुख लक्ष्य रहा है कि दुनिया उस रास्ते पर लौटे, जिससे बढ़ते वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रखा जा सके। मगर अब जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे स्पष्ट है कि कुछ ही सालों के भीतर गर्मी तापमान की इस सीमा का उल्लंघन कर लेगी। इस बार तीन सप्ताह लगातार गर्मी का तापमान 40 से 55 डिग्री तक बना रहा है।

बदलते हालात में हमें जिंदा रहना है, तो जिंदगी जीने की शैली को भी बदलना होगा। हर हाल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। कार्बन उत्सर्जन में 43 फीसद कमी लानी होगी। अगर कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी और तापमान में 1.5 डिग्री से ऊपर वृद्धि हो जाती है तो असमय अकाल, सूखा, बाढ़ और जंगल में आग की घटनाओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का असर केवल धरती पर नहीं होगा, समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा और कई शहरों के अस्तित्व के लिए समुद्र संकट बन जाएगा। इसी सिलसिले में जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी समिति की ताजा रपट के अनुसार सभी देश अगर जलवायु बदलाव के सिलसिले में हुई क्योतो संधि का पालन करते हैं, तब भी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक 10.6 फीसद की वृद्धि होगी। नतीजतन, तापमान भी 1.5 से ऊपर जाने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया में बढ़ती कारें भी गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। 2024 में वैश्विक स्तर पर कारों की संख्या 1.475 अरब आंकी जा रही है। मसलन, प्रति 5.5 व्यक्ति पर एक कार है, जो आजकल गांव-गांव प्रदूषण फैलाने का काम कर रही हैं। इन पर भी नियंत्रण जरूरी है।

सेवा की मिसाल वेंकैया नायडू गारू

नरेंद्र मोदी

आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक हमारे श्री एम वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिवस है। वेंकैया नायडू जी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रसेवा और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वेंकैया जी का 75वां जन्मदिवस एक विशाल व्यक्तित्व की व्यापक उपलब्धियों को समेटे हुए है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए। राजनीति में अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, वेंकैया नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आपमें एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता, और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है।

वेंकैया गारू और मैं दशकों से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है, और मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा है। वेंकैया जी सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने राजनीति के पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की अलग छाप छोड़ी थी। किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था। लेकिन उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि उनकी आस्था राष्ट्र प्रथम के विजन में थी। उन्होंने विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और बाद में जनसंघ एवं भाजपा को मजबूत किया।

लगभग 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब युवा वेंकैया गारू ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें लोकनायक जेपी को आंध्र प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए जेल जाना पड़ा। लोकतंत्र के लिए उनकी ये प्रतिबद्धता, उनके राजनीतिक जीवन में हर जगह दिखाई देती है। 1978 में आंध्र प्रदेश ने जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, तब वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद, राज्य चुनाव में एनटीआर की लोकप्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। तब भी वे भाजपा के विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में भाजपा के लिए भविष्य के बीज बोए थे। उन्होंने विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व किया और आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी बने।

1990 के दशक में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वेंकैया गारू के परिश्रम और प्रयासों को पहचानते हुए उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। 1993 में यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति, जो किशोरावस्था में अटल जी और आडवाणी जी के दौरों की तैयारी करता था, उनके लिए ये कितना बड़ा मुकाम था। पार्टी महासचिव के रूप में, उनका एक ही लक्ष्य था कि अपनी पार्टी को सत्ता में कैसे लाया जाए! उनका एक ही संकल्प था कि कैसे देश को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री मिले। दिल्ली आने के बाद, उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने।

वर्ष 2000 में, जब अटल जी सरकार बना रहे थे तो वो वेंकैया गारू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। अटल जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो

> राजनीति में अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद तक, नायडू गारू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वह अपने आप में एक उदाहरण है। उनकी वाकपटुता और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति उनकी सक्रियता के कारण उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर हर पार्टी में सम्मान मिला है।

वेंकैया गारू ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना। उनकी इस पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था। वेंकैया गारू की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी- वे एक किसान पुत्र थे, उन्होंने अपने शुरुआती दिन गांवों में बिताए थे और इसलिए, अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वे काम करना चाहते थे, तो वह ग्रामीण विकास था। उस समय एक मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी। 2014 में राजग सरकार ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। 2014 के उन शुरुआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे भी बहुत काम आया था। मैं उस समय दिल्ली के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। ऐसे समय में वेंकैया गारू का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण था। वे एक प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री थे। वे सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे।

वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ये हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था। हम ये जानते थे कि वेंकैया गारू के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा। लेकिन साथ ही, हमें ये भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है। मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद किया तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है। उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ी।

जब अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने का निर्णय राज्यसभा के पटल पर रखा गया, तो वेंकैया गारू ही सभापति थे। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वह युवा जिसने डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, जब वह सपना पूरा हुआ तो वे सभापति के पद पर आसीन थे। किसी निष्ठावान देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा! काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया गारू एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। दिल्ली के लोगों के बीच, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो शहर में गौरवशाली तेलुगु संस्कृति लेकर आए। उनके द्वारा आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं। मैं वेंकैया गारू को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं। लेकिन, पिछले कुछ समय से उनका संयम भी सबके सामने दिखने लगा है।

उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी, वेंकैया गारू सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं। वे लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को मुझसे बात करते रहते हैं। हाल ही में जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे।

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

धांधली के जिम्मेदार

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए का कायाकल्प हो या उसे भंग कर दिया जाए। नीट में चौबीस लाख परीक्षार्थी बैठे, लेकिन नंबर और मनचाहे केंद्र देने जैसी धांधलियों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और परीक्षार्थी के संतुष्ट नहीं होने से मामला फिलहाल कोर्ट में ही विचाराधीन है। पालक, परीक्षार्थी और एनटीए की खामियों से उपजे सदमे से उबरे नहीं थे कि 317 शहरों में ग्यारह लाख में से नौ लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने नेट की आफलाइन परीक्षा दी और वह परीक्षा भी धांधलियों की गिरफ्त में चली गई। सीबीआइ से जांच की मांग होने के बाद अब परीक्षा दोबारा होगी। अब यह एजंसी भरोसेमंद नहीं रही और परीक्षा का कोई कार्य इससे लेना मुश्किल ही होगा। बेहतर यह हो कि सभी विभाग अपनी विभागीय परीक्षाएं आयोजित करें, क्योंकि परीक्षा और परीक्षार्थियों के साथ दोहरा खिलवाड़ हुआ है और इसे वे ध्यान में रखें। दोषियों को दंडित करना भी अनिवार्य है। इस तरह परीक्षाएं लीक, निरस्त होती रहीं, दोषी बचते रहे और सरकार की बदनामी होती रही तो पता नहीं, कैसे दिन आएं।

– बीएल शर्मा अकिंचन, उज्जैन

उम्मीदों के बरक्स

केंद्र में नई सरकार के गठन और मंत्रियों के विभागों के आबंटन के बाद सरकार से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। युवा रोजगार की उम्मीद लगा कर बैठा है। गरीब को महंगाई कम होने, किसान को फसलों की उचित दाम मिलने की ललक है। सबसे अधिक परीक्षार्थी सरकार के सामने याचक बनकर खड़े हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं तो कम से कम पारदर्शी हों, जिससे मेहनत करने वालों को उचित प्रतिफल मिले। आज परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर जिस प्रकार अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, उसे सरकार को सबसे पहले जन विश्वास में तब्दील करना होगा।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

आय का आधार

वनोंपज आजीविका का साधन और नारी सशक्तीकरण को एक नई दिशा दे रहा है। हाल ही में एक खबर आई थी कि अब आनलाइन मिलेंगे आदिवासी महिलाओं के बनाए उत्पाद। घरेलू नुस्खों से औषधि बनाने के लिए जगलों की जड़ी-बूटियों से कारोबार कर महिला समूह अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर रही है। वन आर्थिकी सुधारने के लिए जरूरी है कि ग्रामीण समुदाय वनों के मालिक बनें। महिलाओं को सभी स्तर पर प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए और सरकार से ऋण दिलवाकर जंगल से रोजगार उपलब्धि का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार, मप्र

www.readwhere.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

बरकरार रहे जोश, जुनून और मनोयोग का संगम

आइसीसी टी-20 विश्व कप जीतकर हमारी क्रिकेट टीम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। महासागर की गहराई और विशाल पहाड़ों की ऊंचाई को नापा जा सकता है, पर यह गर्व पैमानों से परे है। इस बार यह इसलिए भी सघन है, क्योंकि 11 साल बाद टीम इंडिया ने कोई आइसीसी खिताब जीता है। टी-20 विश्व कप में तो 17 साल बाद यह कारनामा हुआ है। सवाल उठ रहे थे कि दो बार वनडे और एक बार टी-20 विश्व कप जीत चुकी टीम इंडिया लगातार आइसीसी खिताब से क्यों चूक रही है? पिछले साल वनडे विश्व कप का खिताब जीतने की उम्मीद बंधी थी, पर ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीतकर टीम इंडिया का सपना तोड़ दिया था। इस बार टी-20 विश्व कप में भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम भी सेमी-फाइनल तक अजेय रही, इसलिए फाइनल में कड़े मुकाबले के आसार थे। वही हुआ। मैच आखिरी ओवर तक रोमांचक बना रहा। टीम इंडिया के मनोयोग, जोश, जुनून व तालमेल ने प्रतिद्वंद्वी टीम की आंखों में आंखें डाल फिसलती जीत को अपनी ओर मोड़ लिया। सूर्यकुमार यादव ने आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के शॉट को बाउंड्री पर करिश्माई अंदाज में लपककर टूर्नामेंट में बाजी पलट दी। इसी तरह 1983 के वनडे विश्व कप के फाइनल में कपिल देव का वेस्ट इंडीज के विवियन रिचर्ड्स का कैच लपकना भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। क्रिकेट प्रेमियों में यह बहस चल पड़ी है कि सूर्यकुमार और कपिल देव में से किसका कैच बेहतर था? यह सवाल 'सेब और संतरे में कौन बेहतर' जैसा ही है। इस बार के टी-20 विश्व कप का सबसे अहम पहलू यह है कि भारतीय टीम ने शुरू से आखिर तक गजब के आत्मविश्वास और आपसी तालमेल का प्रदर्शन किया। विभिन्न वाद्य यंत्रों के समवेत स्वर वाली मधुर सिम्फनी की तरह हमारे खिलाड़ियों ने अपनी लय बरकरार रखी। किसी भी काम में जब लय इस तरह बरकरार रहती है, तभी 'विजयी भव:' फलीभूत होता है।

टी-20 विश्व कप में खिताबी जीत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की धाक और बढ़ेगी। यह इस परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा मायने रखता है कि कभी क्रिकेट में दबदबा रखने वाली श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की टीमें बुरी तरह लड़खड़ा रही हैं। क्रिकेट में हमारे पुरुष खिलाड़ी ही नहीं, महिला खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ध्रुव तारे की तरह चमक रही हैं। चेन्नई के टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने 603 रन की पारी खेल कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्कोर के सारे रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। संयोग से यह कारनामा भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय क्रिकेट में 'सितारों से आगे जहां और भी हैं' का भरोसे से भरपूर जज्बा आगे भी बरकरार रहेगा।

डॉक्टर्स डे विशेष | **चिकित्सकों में तनाव के मसले का भी हो समाधान**

आजीविका के साथ मानवीय संवेदनाओं के लिए खास जगह रखने वाले चिकित्सीय पेशे में आने वाले लोगों और मरीजों के बीच आज विश्वास के रिश्ते को मजबूती देने की जरूरत है तो चिकित्सक समुदाय को 'बर्न आउट' से बचाने के लिए सामूहिक पहल की भी आवश्यकता है

औरों को दवा दें, पर अपनी भी सुध लें

चिकित्सक को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है जो कि उसके सेवा भाव, मरीज के प्रति पूर्ण समपर्ण एवं जवाबदेही के बदौलत हासिल हुआ है, पर वर्तमान में यह नेक पेशा एवं स्वयं चिकित्सक बढ़ते काम के बोझ एवं समाज की बढ़ती अपेक्षाओं से शारीरिक व मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर वर्ष 706 पंजीकृत मेडिकल कालेजों से 1,08,915 छात्र एमबीबीएस कर निकलते हैं, जिनमें से 40,000 छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला नहीं मिल पाता है एवं 1.2 लाख चिकित्सक बेरोजगार हैं। कई युवा चिकित्सकों को कई घंटों की सेवाएं देने के बावजूद उसके अनुपात में उपयुक्त वेतन नहीं मिल पाता है। कई चिकित्सक अब गांवों में भी सेवाएं देने के इच्छुक हैं किन्तु वहां पर उनके लिए सुविधाओं एवं अवसरों का नितान्त अभाव है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 1000 की आबादी पर एक चिकित्सक होना चाहिए, किन्तु हमारे देश में आज भी दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में यह आदर्श अनुपात दूर की कौड़ी है। इस कारण मौजूदा कार्यरत चिकित्सकों पर कार्यभार बढ़ता है। चिकित्सकों में तनाव व असंतोष के अन्य कारणों में कार्य की लम्बी अवधि, नौकरी की एकरसता, परिजन व स्वयं के लिए समय का अभाव, कार्य की तुलना में कम पारिश्रमिक व खराब कामकाजी परिस्थितियां शामिल हैं। इस से चिकित्सक 'बर्न आउट' के शिकार हो जाते हैं। 'बर्न आउट' एक दीर्घकालिक तनाव प्रतिक्रिया है जो भावनात्मक थकावट, व्यक्तित्वहीनता और व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना की कमी को इंगित करती है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव चिकित्सकों में चिंता, उदासी, अवसाद, चिड़चिड़ापन, कार्यस्थल एवं पारिवारिक असंतुलन व शारीरिक व्याधियों के रूप में परिलक्षित होता है। हर वर्ष डॉक्टर्स डे मनाने का उद्देश्य समाज द्वारा चिकित्सक समुदाय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हो सकता है, पर यही मौका है कि घाव भरने वालों के घावों पर मरहम लगाने की भी चर्चा की जाए। इसके लिए नीति निर्माताओं, समाज, आमजन एवं स्वयं चिकित्सकों द्वारा पहल की दरकार है।

नीति निर्माताओं के स्तर पर जरूरी है कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और बढ़े, कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार हो, युवा चिकित्सकों के लिए नए अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। चिकित्सक मरीज अनुपात में सुधार हो। समाज व आम जन भी समझे कि कुछ गंभीर मामलों में चिकित्सक व चिकित्सकीय विधा की अपनी सीमाएं होती हैं। इससे चिकित्सकों पर अनावश्यक तनाव कम होगा। चिकित्सक के स्तर पर भी कई कोशिशें जरूरी हैं जिसमें सबसे अहम है चिकित्सक व मरीज के परिजनों के बीच संवाद, ताकि संवाद की कमी के चलते उत्पन्न होने वाली भ्रांतियों से बचा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि चिकित्सक स्वयं ही सबसे बुरा मरीज होता है, क्योंकि वे खुद सब जानते हुए भी खुद के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाते हैं। आवश्यक है कि चिकित्सक भी एक स्वस्थ जीवनशैली का अनुसरण करें।

डॉ. पंकज जैन
एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, कोटा
@patrika.com

चिकित्सक स्वयं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित रवैया न अपनाएं

कहा जाता है कि चिकित्सक स्वयं ही सबसे बुरा मरीज होता है, क्योंकि वे खुद सब जानते हुए भी खुद के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाते हैं। आवश्यक है कि एक स्वस्थ जीवनशैली का अनुसरण करते हुए चिकित्सक भी नियमित रूप से अपना परीक्षण कराते रहें और कार्य एवं परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें।

डॉक्टर और मरीज के बीच भरोसे की डोर हो मजबूत

समाज में पीड़ित और रोगी की सहायता करना सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचायक रहा है। डॉक्टर होना महज धनोपार्जन का एक साधन मात्र न होकर एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में समाज व चिकित्सक की परस्पर जवाबदेही बढ़ जाती है। डॉक्टर और मरीज के बीच संबंध बहुत ही निजी और जरूरत भरे होते हैं पर इन दिनों इसमें कुछ दरार आने लगी है। कई बार मरीज की मौत होने पर चिकित्सक के साथ मारपीट व अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाएं तक हो जाती हैं। इन सबके चलते अब कई चिकित्सक जटिल व जोखिम वाले ऑपरेशन करने से कतराने लगे हैं। आपसी अविश्वास की यह स्थिति किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अपना कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व दक्षता से करने के बावजूद कई बार परिणाम चिकित्सक के नियंत्रण में नहीं होते।

ऐसे कुछ लोग तो हर व्यवसाय में हैं जो अवांछित तरीके से कमाने की भावना रखते हैं। यह मूलतः व्यक्ति विशेष की प्रवृति होती है। फायदे-नुकसान के गणित व शॉर्टकट में ही सब कुछ आरामदायक पाने की प्रवृति ने कई युवाओं का मन इस प्रोफेशन से भटकाया है, जो अवांछनीय है।

डॉ. शुभकाम आर्य
सीनियर ईएनटी कंसलटेंट
@patrika.com

समाज में डॉक्टर का जीवन सम्पन्न व वैभव वाला माना जाता है। उनकी अतिरिक्त मेहनत, ज्ञान व कौशल की कसौटी पर यदि विचार करें तो दूसरा पहलू भी सामने आता है। प्रतियोगी परीक्षा में कड़ी मेहनत से अच्छे अंक लाने के बाद लंबा कोर्स करना होता है। रेजीडेंसी ट्रेनिंग के दौरान काम का अत्यधिक दबाव रहता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई तरह के सरकारी नियम, सीमित संसाधन, आर्थिक विसंगतियां, रोग की जटिलता में सामंजस्य बैठाकर जूझना पड़ता है। आधुनिक तकनीक व नवाचारों के अनुरूप अपने को अपडेट रखना होता है। भारत जैसे देश में जहां मरीजों के अनुपात में डॉक्टर की संख्या काफी कम है, ज्यादातर चिकित्सक खुद व परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, कई सामाजिक व पारिवारिक समारोह में भाग नहीं ले पाते। सेहत के लिए जरूरी पर्याप्त नींद खुद ही पूरी नहीं ले पाते। लगातार काम का तनाव व मानसिक दबाव बना रहता है। स्वस्थ रहने के बारे में अधिक जानते हुए भी आम व्यक्ति की तुलना में डॉक्टर की औसत आयु कई अध्ययनों में कम पाई गई है।

यह मुद्दा भी उठता रहता है कि चिकित्सा पेशा एक सेवा है, यह व्यवसाय नहीं बनना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि समाज में व्याप्त व्यवसाय की गलत अवधारणा के कारण ऐसा कहा जाता है। व्यवसाय करना गलत नहीं है, बशर्ते उसमें व्यावसायिक शुचिता का पालन हो। उचित-अनुचित का ध्यान न रखते हुए येन-केन-प्रकारेण लाभ कमाने की प्रवृति व्यावसायिक शुचिता का उल्लंघन है, जो गलत है। व्यवसाय का अर्थ जैसे यह बिल्कुल नहीं है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को कम तोले, सामान में मिलावट करे, उसी तरह यह भी नहीं है कि एक चिकित्सक अनावश्यक जांचें या दवा लिखे। यह भी सही है कि अन्य पेशों से यह एक अधिक संवेदनशील व जिम्मेदारी वाला व्यवसाय है जिससे किसी की जिंदगी जुड़ी है इसलिए हमेशा लाभ-हानि की दृष्टि से ही नहीं सोचा जा सकता। मानवीय पहलू इस पेशे का अभिन्न और विशिष्ट अंग है। अब जरूरत है कि समाज व चिकित्सक का एक-दूसरे के प्रति भरोसा कायम हो। एक चिकित्सक समाज को अपना श्रेष्ठ देने की सोचे।

- भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल ***1 जुलाई को भारत रत्न डॉ. बिधान चंद्र रॉय की विरासत को याद करने और चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों के उल्लेखनीय योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए*** मनाया जाता है।
- हर साल यह दिन एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। ***इस साल की थीम है 'हीलिंग हैंड्स, केयरिंग हार्ट्स'।*** *यह थीम डॉक्टर द्वारा अपने दैनिक अभ्यास में किए जाने वाले समर्पण पर जोर देती है। डॉक्टर अपने जीवनकाल में लाखों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।* ***यह थीम उनके कार्य की सराहना व मानव जीवन में डॉक्टर की भूमिका का सम्मान करती है।***
- डॉ. बिधान चंद्र रॉय एक प्रतिष्ठित चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। डॉ. रॉय 14 साल से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें कई प्रमुख ***शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 'बंगाल के निर्माता' के रूप में जाना जाता है।***
- 1 जुलाई, 1962 को डॉ. राय के निधन के बाद, समाज में ***उनके महान योगदान को मान्यता देते हुए, इस तिथि को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में चुना*** गया।
- पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी शामिल कर लें और सक्रिय सेवा के लिए उनमें से 80 प्रतिशत को उपलब्ध मानें तो एक अनुमान के मुताबिक, **देश में चिकित्सक और आबादी का अनुपात 1:850 (लगभग) है**।

बढ़ती चुनौतियों का दौर और बुलंद हौसले

यह सम्मान और स्वाभिमान का दिवस है। कर्त्तव्य के साथ निष्ठा के लिए भी जाना जाता है। बढ़ती चुनौती के बीच मजबूत हौसले ही हैं जिससे डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। त्याग के साथ दूसरों की स्वास्थ्य रक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी को ही निभाने में लगे हैं अपने देश के अनगिनत डॉक्टर्स। आज उन्हीं का दिन है जो हर रोज दिन-रात दूसरों की तकलीफ दूर करने में बिता देते हैं। अपने देश में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था और इसी दिन साल 1962 में 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। दुनियाभर में चिकित्सा क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

साधन-संसाधन बढ़े तो आमजन की डॉक्टर्स से अपेक्षाएं भी बढ़ीं, ऐसे में मुश्किल हालात में भी डॉक्टर्स ने उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना महामारी इसका बड़ा उदाहरण रहा है, जब अपनों से ही मिलने के लिए मास्क लगाना पड़ रहा था तब देश के डॉक्टर कोरोना रोगियों को स्वस्थ करने के लिए दिन-रात एक किए हुए थे। कोरोना संक्रमण के समाधान तलाशने में तो दवा हर घर/रोगी तक पहुंचाने में डॉक्टर्स पीछे नहीं हटे। यह वह दौर था जब सिर्फ खुद की जिंदगी बचाने की मशक्कत चल रही थी तब अपने देश के डॉक्टर दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपने तमाम सपने भुला चुके थे। दिन-रात हॉस्पिटल और कोरोना संक्रमितों के बीच महीनों गुजराने वाले डॉक्टरों के त्याग को कौन भुला सकता है। यही जज्बा धीरे-धीरे कोरोना को हराकर जनजीवन को पटरी पर ले आया।

डॉ. ईश मुंजाल
सदस्य, सीडब्ल्यूसी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
@patrika.com

समाज में डॉक्टरों की आवश्यकता और उनके महत्त्व को कैसे भुलाया जा सकता है? छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी या फिर आपातकाल में डॉक्टर ही हैं जो हर व्यक्ति को स्वस्थ करने में जोर लगा देते हैं। परिवार/समाज में इनकी मेहनत/त्याग को पूरा सम्मान भी मिलता है। पूरी शिद्दत से अपनी भूमिका निभाने वाला डॉक्टर बड़े शहर का हो या गांव का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर घर तक बेनाम रिश्ते बन गए हैं, डॉक्टर परिवार के सदस्य जैसा है जो हमेशा अच्छा ही सोचता है, रोगी के दर्द पर कराहता भी है तो ठीक होने पर उसकी खुशी को दोगुना-चौगुना भी करता है।

डॉक्टर्स डे केवल एक दिन का सम्मान नहीं है, यह डॉक्टरों के लिए विश्वास बढ़ाने वाला टॉनिक है। डॉक्टर सरकारी हो या प्राइवेट, मुश्किलें किसी के लिए भी कम नहीं हैं। आबादी के हिसाब से कम संख्या तो कभी-कभार लोगों की नाराजगी/गुस्से का भी शिकार होना पड़ता है। सुरक्षा के लिए कानून भी हो, तो संख्या में बढ़ोतरी की भी देश को दरकार है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2030 तक देशभर में बीस लाख और डॉक्टर होने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में साधन-संसाधन कम हों या फिर स्टाफ कम, डॉक्टर ही हैं जो रोगी के लिए अपनी ड्यूटी के घंटे नहीं देखता। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की खामियां दूर करनी होंगी तो आम रोगियों के लिए साधन-संसाधन भी बढ़ाए जाने होंगे। देश-दुनिया में भारत के डॉक्टर अपना नाम रोशन करते रहेंगे। जन-जन के सम्मान का पात्र बने रहने वाले ये डॉक्टर भी बखूबी समझते हैं अपनी ड्यूटी और आपका प्यार।

वेंकैया नायडू

भारत की सेवा में समर्पित जीवन

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

हर जगह दिखाई दी लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता

आज 1 जुलाई को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक एम. वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिन है। वे 75 वर्ष के हो गए। मैं उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मैं उनके शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बधाई देता हूं। वेंकैया जी का जीवनकाल उपलब्धियों को समेटे है। यह सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में देशवासियों को जानना चाहिए। राजनीति में अपने प्रारम्भिक दिनों से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक, नायडू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वह भी एक उदाहरण है।

वाकपटुता, हाजिरजवाबी और विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति सक्रियता के कारण उन्हें हर पार्टी में सम्मान मिला है। वेंकैया गारू और मैं दशकों से जुड़े रहे हैं। हमने लंबे समय तक अलग-अलग दायित्वों को संभालते हुए साथ काम किया है। मैंने हर भूमिका में उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने देखा, जीवन के हर पड़ाव पर आम लोगों के प्रति उनका स्नेहभाव कभी नहीं बदला। वे सक्रिय राजनीति से आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े। पहले पड़ाव पर ही प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की छाप छोड़ी। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था। लेकिन राष्ट्र प्रथम के विजन में आस्था रखते हुए उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया। विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हुए जनसंघ एवं बीजेपी को मजबूत किया।

पचास साल पहले जब कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया तब युवा वेंकैया जी ने आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। लोकनायक जेपी को आंध्र प्रदेश में आमंत्रित करने पर उन्हें जेल जाना पड़ा। लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता हर जगह दिखाई दी। 1980 के दशक के मध्य में, जब आंध्र प्रदेश में एनटीआर की सरकार को कांग्रेस ने गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया था, तब वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुए आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। वर्ष 1978 में आंध्र प्रदेश में वेंकैया जी प्रतिकूल परिस्थितियों में युवा विधायक के रूप में जीतकर आए थे। पांच साल बाद, राज्य के चुनाव में एनटीआर की लोकप्रियता चरम पर थी तब भी वे विधायक चुने गए। उनकी जीत ने आंध्र समेत दक्षिण में बीजेपी के लिए भविष्य के बीज बोये थे। युवा विधायक के रूप में ही, वे विधायी मामलों में अपनी दृढ़ता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए सम्मानित होने लगे। वाकपटुता, शब्दशैली और संगठन सामर्थ्य से प्रभावित होकर एनटीआर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी विचारधारा पर अडिग रहे और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। वे विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व करते हुए आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे।

बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 1990 के दशक में वेंकैया जी को पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया। यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में उनका कार्यकाल शुरू हुआ। किशोरावस्था में अटल जी और आडवाणी जी के दौरों की तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए सचमुच यह बड़ा मुकाम था। पार्टी महासचिव के रूप में, उनका एक ही संकल्प था कि कैसे देश को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री मिले। दिल्ली आने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्ष 2000 में, अटल जी वेंकैया नायडू को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। अटल जी ने उनकी इच्छा पूछी तो वेंकैया जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को चुना। उनकी इस पसंद ने तब कई लोगों को हैरान किया था। क्योंकि, पहले नेताओं के लिए दूसरे मंत्रालय ही पहली पसंद हुआ करते थे। किसान पुत्र वेंकैया जी ने अपने शुरुआती दिन गांवों में बिताए थे और इसलिए उनके काम करने का क्षेत्र भी ग्रामीण विकास का था। मंत्री के रूप में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका थी।

वर्ष 2014 में उन्होंने शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही हमने 'स्वच्छ भारत मिशन' और शहरी विकास से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं। वे उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने लंबे समय तक ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए काम किया है। 2014 के उन शुरुआती दिनों में वेंकैया जी का अनुभव मेरे बहुत काम आया। मैं तब दिल्ली के लिए बाहरी व्यक्ति था। मेरा करीब डेढ़ दशक गुजरात में ही बीता था। ऐसे समय में वेंकैया जी का सहयोग मेरे लिए महत्त्वपूर्ण था। वे प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सदन में पक्ष-विपक्ष की बारीकियों को समझते थे। संसदीय मानदंडों और नियमों को लेकर भी वे उतना ही स्पष्ट नजर आते थे। वर्ष 2017 में, हमारे गठबंधन ने उन्हें देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। यह हमारे लिए एक कठिन और दुविधा से भरा निर्णय था। हम यह जानते थे कि वेंकैया जी के स्थान को भरना बेहद कठिन होगा। लेकिन साथ ही, हमें यह भी पता था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है। मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव और इसे बनाने के प्रयासों को याद

***सक्रिय** राजनीति से वैंकेया जी आंध्र प्रदेश में छात्र नेता के रूप में जुड़े। पहले पड़ाव पर ही उन्होंने प्रतिभा, वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल की छाप छोड़ी। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल में उन्हें कम समय में बड़ा स्थान मिल सकता था। लेकिन राष्ट्र प्रथम के विजन में आस्था रखते हुए उन्होंने संघ परिवार के साथ काम करना पसंद किया। विचार को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हुए जनसंघ एवं बीजेपी को मजबूत किया।*

किया तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। इससे उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून की झलक मिलती है। उपराष्ट्रपति बनने पर उनके कई कदमों से इस पद की गरिमा और बढ़ी। राज्यसभा के उत्कृष्ट सभापति के रूप में उन्होंने यह निश्चित किया कि युवा-महिला और पहली बार चुन कर आए सांसदों को बोलने का अवसर मिले। उन्होंने सदन में उपस्थिति पर बहुत जोर देते हुए संसदीय समितियों को अधिक प्रभावी बनाकर सदन में बहस के स्तर को भी ऊंचा उठाया।

जब अनुच्छेद 370 और 35(ए) को हटाने का निर्णय राज्यसभा के पटल पर रखा गया, तो वेंकैया जी ही सभापति थे। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए भावनात्मक क्षण था। वह युवा जिसने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प के लिए अपना जीवन समर्पित किया और जब वह सपना पूरा हुआ तो वह सभापति के पद पर आसीन था। किसी देशभक्त के जीवन में इससे बड़ा समय और क्या होगा! काम और राजनीति के अलावा, वेंकैया जी एक उत्साही पाठक और लेखक भी हैं। दिल्ली में उन्हें गौरवशाली तेलुगु संस्कृति लेकर आने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनकी ओर से आयोजित उगादी और संक्रांति कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शहर के सबसे पसंदीदा समारोहों में से एक हैं। मैं उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो भोजन प्रेमी हैं और शानदार मेजबानी करना जानते हैं। पिछले कुछ समय से संयम भी दिखने लगा है। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि वे अभी भी बैडमिंटन खेलना और ब्रिस्क वॉक करना पसंद करते हैं।

उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी, वेंकैया जी सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय हैं। वे लगातार देश के लिए जरूरी मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर मुझसे बात करते रहते हैं। हाल ही जब हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे व हमारी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि युवा कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवा करने का जुनून रखने वाले सभी लोग उनके जीवन से सीख लेंगे और उन मूल्यों को अपनाएंगे। यह वेंकैया गारू जैसे लोग ही हैं जो हमारे राष्ट्र को बेहतर और अधिक जीवंत बनाते हैं।

आपकी बात

गठजोड़ को तोड़ना होगा

सर्वविदित तथ्य है कि भू-माफिया राजनीतिक संरक्षण के चलते ही सार्वजनिक भूमि पर बेधड़क अतिक्रमण करता है और नेताओं के नाम से नगर बसाकर, अवैध कालोनियां बसाकर पैसा बनाता है। बिना संरक्षण के उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। इसे रोकने के लिए भू-माफिया और नेताओं के गठजोड़ को सख्ती से तोड़ना होगा। - **वसंत बापट**, भोपाल

देशद्रोह जैसा अपराध

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध शासन को समय-समय पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भय व्याप्त हो। जनता को जागरूक करना चाहिए ताकि समय पर जानकारी मिल सके। सरकारी जमीन देश की संपदा होती है यह आम जन के लिए होती है। ऐसे में इस पर अतिक्रमण देशद्रोह जैसा अपराध है। - **दिलीप शर्मा**, भोपाल

कठोर कानून और कड़ी सजा हो

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए। ताकि भूमाफिया उन जमीनों को आम जनता को न बेच सके और सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग ना कर सके। सरकार को कठोर से कठोर कानून बनाकर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए ताकि इस तरह की वारदातों से निजात पाई जा सके। - **सुरेंद्र बिंदल**, जयपुर

आज का सवाल

नए आपराधिक कानून लागू होने से क्या समाज में आपराधिक प्रवृत्ति कम होगी?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कैसे रोका जा सकता है?' कई प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। कुछ ऑनलाइन भी दी जा रही हैं।

इसे स्कैन करें

https://rb.gy/woz6so

चिंतन

टीम भारत की 'विराट' जीत ने रचा कीर्तिमान

टीम भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। टी-20 विश्व कप अपने नाम किया है। यह दूसरा मौका है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने 20 ओवर के फॉर्मेट में विश्व कप जीता है। इससे पहले वर्ष 2007 में जीता था। वर्ष 2007 में ही टी-20 विश्व कप की शुरूआत हुई थी। उस वर्ष भारत ने विश्व में इस फास्ट फार्मेट में अपना सिक्का जमाया था। विश्व को यह फटाफट क्रिकेट फॉर्मेट में जोश व जुनून भारत की ही देन है। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार कपिलदेव की कप्तानी में टीम इंडिया ने वर्ष 1983 में एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था। उसके बाद टीम भारत की यात्रा कठिन रही। दूसरी आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी वर्ष 2007 में मिली, उसके बाद चार वर्ष के अंतराल में ही वर्ष 2011 में टीम भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे विश्व कप जीत कर फिर से कीर्तिमान बनाया। महेंद्र सिंह धोनी भारत के ऐसे कप्तान बने, जिनके नाम वनडे व टी-20 दोनों क्रिकेट विश्व कप जीतने का रिकार्ड दर्ज है। अब वर्ष 2011 के 13 साल बाद वर्ष 2024 में टीम भारत ने कोई मेन्स क्रिकेट विश्व कप जीता है। भारत ने दूसरा टी-20 विश्व कप 17 वर्ष बाद जीता है, यह दिखाता है कि एक बेहतरीन टीम होने के बावजूद टीम भारत को कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी है। भारतीय क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा की टीम ने आईसीसी टी-20 विश्व कप के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर रोमांचक जीत हासिल करने का कारनामा किया। यह कप्तानी की जीत है, टीम स्पिरिट की जीत है, सभी खिलाड़ियों के एक टीम के रूप में उम्दा प्रदर्शन की जीत है, खिलाड़ियों के जोश, जज्बे और जुनून की जीत है। खिलाड़ी से लेकर पर्दे के पीछे टीम प्रबंधन के सभी स्टाफ की सामूहिक मेहनत की जीत है। टीम भारत के प्लइंग इलेवन-रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जाडेजा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बूमराह, रिषभ पंत, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव, सभी ने विश्व कप के सभी मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कोच राहुल द्रविड़ की मेंटर के रूप में जितनी भी तारीफ की जाय कम है। इस विश्व कप की खास बात है कि भारत ने अपना एक भी मैच नहीं हारा। बीसीसीआई का अधिक भरोसा विदेशी कोचों पर रहा है, लेकिन जैसे जैसे भारत में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पौध बढ़ती गई है, टीम प्रबंधन में भारतीय प्रतिभाओं पर भरोसा बढ़ता गया है। रिजल्ट भी दिख रहा है। भारतीय टीम में कभी दि वाल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने अपने खेल के समय विश्व कप जीतने वाली टीम के हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन उनका सपना एक कोच के रूप में जरूर पूरा हुआ है। वर्ष 2024 में आईसीसी टी-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कोच महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ हैं। आगे वे कोच रहेंगे या नहीं, लेकिन यह कप उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। यह विश्व कप एक उदास क्षण भी लेकर आया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जाडेजा ने टी-20 फार्मेट के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब अगले किसी टी-20 आईसीसी टूर्नामेंट में विराट, रोहित जैसे महान खिलाड़ी खेलते नजर नहीं आएंगे। वर्ष 1983 में भारत एक अंडरडॉग टीम थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत फाइनल में वेस्टइंडीज को हरा देगा। लेकिन ऑलराउंडर कपिलदेव ने अपने बूते टीम इंडिया की नैया पार लगाई थी। उसके बाद बहुत देर लगही। भारतीय क्रिकेट में जीत का जुनून पैदा करने का श्रेय कप्तान सौरभ गांगुली को जाता है, बेशक उनकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप न जीता हो, पर जीतने वाली टीम का आधार उन्होंने ही तैयार किया। आज टीम भारत विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। धोनी, विराट और रोहित शर्मा ने सौरभ की जुनूनी धारा को आगे बढ़ाया है। बोर्ड के रूप में बीसीसीआई का योगदान भी अहम है। वेस्ट इंडीज में बारबाडोस की भूमि भारतीय विश्व कप जीत के इतिहास में अंकित हो गई है। टीम भारत को इस रोमांचक जीत के लिए बधाई।

न्याय संहिता

कृष्णमोहन झा

न्यायिक व्यवस्था में मील के पत्थर साबित होंगे नए कानून

आज एक जुलाई है। यह तारीख भारतीय न्यायिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी। आज से ही देश में पुराने आपराधिक कानून को समाप्त करके नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले देश की संसद में इसका मसौदा पेश किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी एक एक बात सांसदों के समक्ष रखी। सदन ने जब इसे पास कर दिया, उसके बाद देश में यह कानून लागू होने जा रहा है। पुराने आपराधिक कानूनों को निरस्त करना और नए कानूनों को अपनाना देश की वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाता है। भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए इन कानूनों का नाम बदला गया। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पुरातन ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से प्रस्थान का प्रतीक है, जिसमें सजा पर नहीं न्याय पर जोर दिया जाता है। भारत सरकार ने जो तीन नए कानून बनाए हैं, इसका उद्देश्य राष्ट्र की अद्वितीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करना तथा उसे पुष्ट करना है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए और अंग्रेज़ी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (1898), 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 कानूनों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। इनको लेकर राज्यसभा में हुई चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम इन पर अगस्त, 2019 से ही विचार-विमर्श, चर्चा, सलाह कर रहे थे। सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले हैं, बल्कि इनके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इन तीनों कानून का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, बल्कि न्याय देने का है, इनमें न्याय का विचार है। भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अंब्रेला टर्म है। 'न्याय' शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित करके न्याय की एक संपूर्ण कल्पना है। अमित शाह के अनुसार, कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। खासतौर से इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है, अपराधियों को सज़ा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया है, दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने और मॉब लिंचिग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का काम भी किया है। शाह ने सदन में आश्वस्त किया कि 1860 से 2023 तक अंग्रेज़ी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा। अब इन तीनों कानूनों की जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून स्थापित होंगे। 15 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री, मोदी ने विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत जैसे विकासशील देश में एक स्वस्थ समाज के लिए एक त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि न्याय देने में देरी सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह लंबे समय से गांवों में उपयोग में लाया गया है और अब इसे राज्य स्तर पर प्रचारित किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि इसे राज्यों में स्थानीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा कैसे बनाया जाए। आपराधिक कानूनों में इन नए संशोधनों का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, और आधुनिक बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के तहत, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नागरिकों को न्याय मिले और अपराधियों को उचित दंड मिले। इन सुधारों का उद्देश्य समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपराधों को कम करना है।

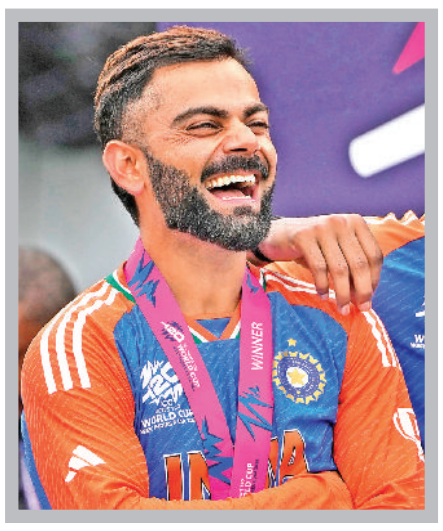

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

उपलब्धि

विवेक शुक्ला

विराट कोहली शनिवार को जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, तब राजधानी के पश्चिम विहार की एलआईसी कॉलोनी में रहने वाले दुआ कर रहे थे कि उनका विराट बेहतरीन पारी खेले। इस कॉलोनी वालों ने विराट कोहली को यहां सुबह-शाम खेलते हुए देखा है। इधर ही विराट कोहली का बचपन बीता। इधर अभी सामाजिकता बची हुई है। विराट कोहली 2011 की वर्ल्ड कप विजयी टीम इंडिया का सदस्य थे। वर्ल्ड कप जीत कर वापस घर आया तो एलआईसी कॉलोनी के दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। उसके घर में ही यंग ब्रिगेड का जमावड़ा लगा रहता। विराट सुनाता और सुनते बाकी सब।

युवा भारत की विराट प्रतिभा

विराट कोहली ने टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार पारी खेलकर एक बार फिर से सिद्ध किया कि वे बिग मैच प्लेयर हैं। वे कभी भी फॉर्म में वापसी करने की कुव्वत रखते हैं। वे इसलिए ही महान नहीं हैं, क्योंकि उनके आंकड़े बेहद शानदार हैं। वे पेले और डिएगो माराडोना के कद के महान खिलाड़ी इसलिए बनते हैं,क्योंकि वे सेमीफाइनल और फाइनल जैसे अहम मैचों में छा जाते हैं। देखिए मेहनत बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं, पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी सब महान नहीं कहलाए जाते। वे ही महान खिलाड़ी माने जाते हैं, जो विपरीत हालात और उन मैचों में शानदार खेल दिखाते हैं जब उनसे उनकी टीम और उनक चाहने वाले अपेक्षा करते हैं। विराट कोहली का भी जलवा बड़े कांटे के मैचों में देखते ही बनता है। पेले और माराडोना के करियर को देख लें। आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये खास मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे।

विराट कोहली शनिवार को जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, तब राजधानी के पश्चिम विहार की एलआईसी कॉलोनी में रहने वाले दुआ कर रहे थे कि उनका विराट बेहतरीन पारी खेले। इस कॉलोनी वालों ने विराट कोहली को यहां सुबह-शाम खेलते हुए देखा है। इधर ही विराट कोहली का बचपन बीता। इधर अभी सामाजिकता बची हुई है। विराट कोहली 2011 की वर्ल्ड कप विजयी टीम इंडिया का सदस्य थे। वर्ल्ड कप जीत कर वापस घर आया तो एलआईसी कॉलोनी के दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। उसके घर में ही यंग ब्रिगेड का जमावड़ा लगा रहता। विराट सुनाता और सुनते बाकी सब। अब उसके पास पैसा आ गया था, इसलिए खेल के बाद वो अपने दोस्तों को पश्चिम विहार की एच-9 की या फिर ज्वालाहेड़ी की मार्केट में लेकर जाने लगा। ये सब कभी-कभी राजौरी गार्डन भी जाने लगे। वहां पर जाकर खाई जाती आइसक्रीम। स्टारडम से कोसों दूर बसती थी उसकी दुनिया। वो यहां पर रहते हुए सुपर स्टार बन गया था, पर वो एलआईसी कॉलोनी के किसी अंकल जी या आंटी जी के चरण स्पर्श करने से कभी पीछे नहीं हटा। शादी से पहले ही विराट कोहली ने अपनी मां के साथ गुरुग्राम में शिफ्ट कर लिया था। वहां पर बना लिया किले जैसा घर, पर उसका पश्चिम विहार से रिश्ता बना हुआ है। उसका बड़ा भाई विकास अब भी एलआईसी कॉलोनी में ही सपरिवार रहता है। उसे विराट 'वीर जी' कहता है। विराट कोहली कितनी ही बुलंदियों को छू ले पर एलआईसी कॉलोनी वालों के लिए वह अब भी चीकू ही है। वे उसे चीकू ही कहते हैं। विराट कोहली सरीखे खिलाड़ी कमजोर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन जब चुनौती बड़ी होती है तब ये रंग में आ जाते हैं। विराट कोहली टी-20 वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। हां, वे फाइनल में छा गए। विराट कोहली विश्व नागरिक बन चुके हैं। उन्हें उन सब देशों में पसंद किया जाता है, जहां पर क्रिकेट खेला जाता है। विराट कोहली का क्रिकेट के मैदान में जुझारू तरीके से खेलने के अलावा एक दूसरा

भी चेहरा है। वे जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं या कहें कि फुर्सत में होते हैं तो वे सपरिवार वृंदावन जाना पसंद करते हैं। विराट कोहली वृंदावन में परमानंद जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। वे ऋषिकेश में दयानंद गिरि आश्रम में भी जाते हैं। दयानंद गिरि आश्रम में विराट और उनकी पत्नी अनुष्का कई बार यात्रा कर चुकी हैं। वे कुछ समय पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने सुबह चार बजे भस्म आरती की और भगवान का आशीर्वाद लिया। विराट कोहली ने आरती के बाद मंदिर के गर्भगृह में जाकर पंचामृत पूजन अभिषेक किया। विराट कोहली ने गले में रुद्राक्ष की माला भी धारण की।

विराट कोहली ने टी-20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनकी इस घोषणा से उनके करोड़ों चाहने वाले उदास तो जरूर हुए होंगे। बस इतनी गनीमत है कि वे अभी एक दिवसीय क्रिकेट और टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। विराट कोहली क्रिकेट और ब्रांड की दुनिया के बादशाह हैं। विराट कोहली स्मार्ट और हैंडसम हैं। उन्हें सुपर फिट रहने का जुनून है। उनसे एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी फिटनेस के बारे में पूछा। विराट कोहली का कहना था कि मुझे लगा कि अगर अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। वह बहुत नपा-तुला खाना खाते हैं। जिस व्यक्ति से प्रधानमंत्री फिटनेस के बारे में पूछे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कद क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी उनके विवाह में भी शामिल हुए थे। अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद विराट कोहली की विनम्रता अनुकरणीय है। वे बिशन सिंह बेदी के सार्वजनिक रूप से चरण स्पर्श करते थे। दिल्ली क्रिकेट के केन्द्र फिरोजशाह कोटला मैदान में होने वाले कार्यक्रमों में विराट कोहली कई बार बेदी के चरण स्पर्श करते हुए देखे गए। उन्होंने यह मुकाम परिश्रम, साधना और पक्के इरादे से पाया था। विराट कोहली का संबंध दिल्ली के एक सामान्य बिजनेस करने वाले परिवार से है। विराट के पापा प्रेम कोहली और मां सरोज ने उन्हें अभावों के बावजूद हरसंभव आगे बढ़ने के अवसर दिए। आजकल शांत दिखने वाले विराट कोहली कुछ साल पहले तक काफी अलग थे। वे बात-बात पर आवेश में आ जाया करते थे। आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च के महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टेस्ट शुरू होने से पहले जब भारत का राष्ट्रगान हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी, विराट कोहली और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा साथ-साथ खड़े थे।

विराट कोहली से बड़े-बड़े ब्रांड जुड़ने के लिए बेकरार रहते हैं। विराट कोहली ने अपना पहला एड कैम्पेन 2010 में किया था। फास्ट्रैक का ये कैम्पेन उन्होंने अभिनेत्री जिनिलिया डिसूज़ा के साथ किया था। वो डील थी सिर्फ 25 लाख की और आज कोहली 7 करोड़ रुपये रोज के हिसाब से लेते हैं किसी ब्रांड के विज्ञापन के लिए। विराट कोहली पैसे कमाने के लिए ही किसी भी उत्पाद को प्रमोट नहीं करते हैं। विराट कोहली शीतल पेय पदार्थ पेप्सी और गोरा बनाने वाली एक उत्पाद के प्रचार करने से मना कर दिया था। विराट कोहली मानते हैं कि ये उत्पाद जंक फूड और नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं। आप चाहें तो ऊपर वाले का धन्यवाद कर सकते हैं कि आप विराट कोहली को मैदान में खेलते हुए देख रहे हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

ध्यान और विवेक से साधा जा सकता है मन

संकलित

दर्शन

मन की कोई एक जगह शरीर में पक्की नहीं है। मन तो फैला हुआ है। मन वह अदृश्य शक्ति है, जो चुपचाप से अपना काम करती चली जाती है। इस शक्ति के ऊपर हम सजगता और होश के द्वारा जरूर नियंत्रण पा सकते हैं। अच्छा-बुरा, शुभ-अशुभ, ज्ञान-अज्ञान सब तरह के संस्कार आपके मन के ऊपर अपनी छाप छोड़ते रहते हैं और ये संस्कार ही समय आने पर विचार के रूप में प्रकट होते हैं। अब आप जब भी ध्यान में बैठें, तो उस समय अपने विचारों को होशपूर्वक पकड़ना। धीरे-धीरे होश जगने लगेगा, थोड़े-थोड़े विचार पकड़ में आने लगेंगे। जैसे विचारों की धारा शुरू करने से पहले मन अनुमति मांग रहा हो कि विचार करूं या न करूं। जहां तुम सजग हुए, वहीं विचार ठहरेंगे। जहां विचार ठहरेंगे, तब ऐसा लगेगा कि मन तो कुछ है ही नहीं। एक ने पूछा कि 'मन को हटाए बिना आत्मज्योति की झलक नहीं पा सकते हैं। तो मन को बीच में से हटाएगा कौन? इस मन को मारेगा कौन? यह 'मैं' कौन है? इस शरीर में कौन-सा ऐसा तत्व है, जो मन को मार सकता है? उसका अनुभव कैसे होगा?' तुम पूछते हो, कौन मारेगा मन को? मैं कहती हूं, तुम्हारा ही होश मारेगा इस मन को। तुम्हारी ही सजगता इसको मारेगी। अब यह सवाल उठ सकता है कि मन कहां है? मन बायीं ओर है या दायीं ओर है? या फेफड़ों के बीच में है? नहीं! मन तो पूरे शरीर में और शरीर के बाहर भी व्याप्त है। लेकिन हर्ष, भय जैसी हर भावना के उठने पर तुम सीने में कुछ महसूस करते हो।

ऐसा घर जहां, कोई मृत्यु न हुई हो

संकलित

प्रेरणा

भगवान बुद्ध के समय में, किसागोतमी नाम की एक महिला के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। दुख से परेशान होकर, वह अपने मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दवा पूछती हुई एक घर से दूसरे घर घूमने लगी। किसी ने उसे कह दिया कि भगवान बुद्ध के पास ऐसी दवा है। किसागोतमी भगवान बुद्ध के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, क्या आप ऐसी दवा बता सकते हैं, जिससे मेरा मृत पुत्र जीवित हो उठे? मुझे ऐसी दवा के बारे में पता है,' बुद्ध ने कहा। 'परंतु उसके लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। महिला ने राहत की सांस लेते हुए पूछा, 'आपको क्या चाहिए? मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए,' बुद्ध ने कहा। महिला ने बुद्ध को वह सामग्री लाकर देने का वादा किया किंतु ज्यों ही वह जाने लगी, बुद्ध ने कहा, 'सरसों के बीज उसी घर से लेकर आना, जहां कभी किसी संतान, पति-पत्नी, माता-पिता या सेवक की मृत्यु न हुई हो। महिला ने हामी भरी और वह सरसों के बीज की तलाश करती हुई एक घर से दूसरे घर भटकने लगी। उसने पाया कि ऐसा कोई घर नहीं था, जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। कहीं पुत्री, कहीं सेवक, कहीं पति, तो कहीं पिता की मृत्यु हो चुकी थी। किसागोतमी को वहां एक भी घर ऐसा नहीं मिला, जहां कभी मृत्यु न हुई हो। यह देखकर कि वह अकेली इस दुख से पीड़ित नहीं थी, उसने अपने मृत पुत्र के शव का मोह छोड़ दिया और बुद्ध के पास लौट आई। तब बुद्ध ने अत्यंत करुण भाव से कहा, 'तुमने सोचा कि सिर्फ तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई है।

अंतर्मन

आज की पाती

आवारा कुत्तों से परेशानी

सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कालोनी में इन दिनों आवारा कुत्तों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में रात को आने-जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। आवारा कुत्ते राहगीरों को दौड़ा देते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को इनसे बचना मुश्किल होता है। यह कालोनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती है। ऐसे में यहां की परेशानी को हल करने वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाउसिंग का दफ्तर भी यहां की समस्याएं सुलझाने में नाकाम साबित हो रहा है।

- शाहीन बेगम

करंट अफेयर

महासागर अध्ययन के बारे में देखा सपना, बनाया रॉकेट

पोर्ट ब्लेयर में पली-बढ़ी होने के चलते महासागर अध्ययन की असीम संभावनाओं के बारे में सपने देखने से लेकर रॉकेट बनाने के क्षेत्र में अग्रणी होने तक युवा इंजीनियर सरनिया पेरियास्वामी के लिए विभिन्न चीजें सीखने का एक रोमांचक दौर रहा। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्ट-अप 'अग्निकुल कॉसमॉस' की इंजीनियर 30 वर्षीय पेरियास्वामी ने 3-डी मुद्रित प्रक्षेपण यान 'अग्निबाण सब-ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर' (एसओआरटीईडी) को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसओआरटीईडी ने 30 मई को अपनी पहली उड़ान भरी थी। 'अग्निबाण-एसओआरटीईडी' का प्रक्षेपण पहले 22 मार्च को निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे बाद के लिए टाल दिया गया था। सरनिया पेरियास्वामी ने यहां एसआईए-इंडिया द्वारा आयोजित 'इंडिया स्पेस कांग्रेस' के इतर मीडिया से कहा, जब भी कोई प्रक्षेपण होता है, तो बहुत अधिक बाहरी दबाव होता है। हर कोई प्रक्षेपण का इंतजार कर रहा होता है और यदि आप इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं विफल हो रहे हैं। पेरियास्वामी ने अपनी स्कूली शिक्षा और स्नातक की पढ़ाई अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी एवं अपने जन्म स्थान पोर्ट ब्लेयर में की।

ऑफ बीट

प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल कर बेचने की नई पहल

जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक उत्पादों (एसयूपी) को सीमेंट निर्माण संयंत्रों को बेचकर इसे लाभप्रद उद्यम बना दिया है। निगम ने अभियान के दौरान जब्त हजारों टन एसयूपी को दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाकर बेचने की नयी पहल की है। निगम ने प्रकृति के लिए हानिकारक पॉलीथिन को नष्ट करने के बजाय लांगड़ियावास और मथुरादापुरा 'डंप यार्ड' में 'रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल' (आरडीएफ) मशीन लगाई हैं, ताकि प्लास्टिक को कुचलकर उसे दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाकर सीमेंट निर्माण संयंत्रों को बेचा जा सके और इससे कुर्सियां, मेज आदि जा सकें। अधिकारियों ने बताया कि निगम ने पिछले तीन-चार महीनों में अपनी कार्रवाई के दौरान करीब 6,000 किलोग्राम एसयूपी को जब्त किया है और इसे दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाने के बाद सीमेंट संयंत्रों को बेचकर राजस्व अर्जित किया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने कहा, अभियान के दौरान जब्त इस प्लास्टिक का निस्तारण हमारे सामने बड़ी समस्या थी। 'डंप यार्ड' में आरडीएफ मशीनें लगाई गईं, ताकि प्लास्टिक को काटकर सीमेंट बनाने वाले संयंत्रों को इन्हें बेचा जा सके। इससे निगम को राजस्व भी मिलने लगा है।

ट्रेंड

द्रविड़ ने टीम को बदल दिया

राहुल द्रविड़ की अविश्वसनीय कोचिंग यात्रा ने भारतीय क्रिकेट की सफलता को आकार दिया है। उनके अटूट समर्पण, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सही प्रतिभा के पोषण ने टीम को बदल दिया है। हम उसे विश्व कप उठाते हुए देखकर खुश हैं। उन्हें बधाई देकर खुशी हुई।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आश्चर्यजनक परिणाम

वैसे तो जिंदगी में कोई भी फैसला सही नहीं होता. यदि आप कोई निर्णय लेते हैं और उसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं, तो यह आश्चर्यजनक रूप से परिणाम देगा। मृत्यु दर को नज़रअंदाज़ करना सबसे बड़ी अज्ञानता है।

-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

जीत पर हर भारतीय को गर्व

रोमांचक फाइनल में टीम इंडिया ने 17 साल बाद जीता टी20 वर्ल्डकप! नीले रंग के परिधानों में पुरुषों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए बहुत-बहुत बधाई। मैच में विराट कोहली, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह चमके। इस अविश्वसनीय जीत पर हर भारतीय को गर्व है।

-मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

हर लड़ाई में नया हीरो

हर लड़ाई में एक नया हीरो, एक अलग मैन ऑफ द मैच था - टीम वर्क की जीत हुई... कोई भी सिम्फनी की सीटी नहीं बजा सकता, इसे बजाने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा की जरूरत होती है।

-नवजोत सिंह सिद्धू, क्रिकेट एक्सपर्ट

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid